

# सम-सामयिक घटना चक्र



मासिक करेन्ट नोट्स एवं सामयिक आलेख

वर्ष : 26 सितम्बर, 2018 अंक : 6 मूल्य : 60/-

इस अंक के साथ  
निःशुल्क

Website : <http://www.ssgcp.com/>

<https://www.facebook.com/ssgcpl>

<https://www.facebook.com/ssgc.gs.qa>

<https://plus.google.com/+Ssgcpssgcp>

<https://twitter.com/SamsamyikGhatna>



**असम राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टरः  
पूर्ण मसौदा प्रकाशित**

# सम-सामयिक घटना चक्र

वर्ष - 26

अंक - 06

सितंबर, 2018

मूल्य - 60/-

▶ संपादकीय कार्यालय :

## सम-सामयिक घटना चक्र

188A/128 एलनगंज, चर्चलेन,  
इलाहाबाद - 211002

▶ फोन : 0532-2465524, 9335140296

▶ ई-मेल : ssgcald@yahoo.co.in

▶ वेबसाइट : ssgcp.com

▶ संपर्क समय : प्रातः 12 से सायं  
8 बजे तक (सोमवार से शुकवार)

▶ © सम-सामयिक घटना चक्र - किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित।  
▶ सभी विवादों का निबटारा इलाहाबाद की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरम में किया जाएगा।

▶ संपादक - संतोष कुमार चौधरी

▶ उप संपादक - सौरभ मेहरोत्रा

▶ सदस्य संपादक मण्डल - कालीशंकर 'शारदेय',  
विकास कुमार शुक्ल, गोपाल कृष्ण पाण्डेय

▶ संपादकीय समन्वयक -

राजकुमार श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार तिवारी

▶ कंप्यूटर सहयोग -

फैजुल इस्लाम अंसारी, बृजेश पटेल

▶ लेखा प्रबंधक - आर.पी. भट्ट

▶ विज्ञापन प्रबंधक - जितेन्द्र द्विवेदी

▶ प्रबंध संपादक - ममता चौधरी

सम-सामयिक घटना चक्र प्रकाशित लेखों में लेखकों के अपने विचार हैं। उनके विचारों से संपादकीय सहमति जरूरी नहीं है। संपादक की लिखित अनुमति के बिना इस पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सामग्री को उद्धृत या उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता है। पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका में छपे किसी भी विज्ञापन की सूचना की समुचित जांच स्वयं करके संतुष्ट हो लें।

मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी संतोष कुमार चौधरी द्वारा उन्हीं के लिए अमर मुद्रणालय 15/1/7, कटरा रोड, माधो कुंज, इलाहाबाद से मुद्रित एवं 188A/128, एलनगंज चर्चलेन इलाहाबाद से प्रकाशित। संपादक - संतोष कुमार चौधरी

## अनुक्रमणिका

### आवरण आलेख

(पृ.सं. : 5 - 8)

असम राष्ट्रीय

नागरिकता रजिस्टर :

पूर्ण मसौदा प्रकाशित



### सामयिक आलेख - 1

(पृ.सं. : 9 - 13)

त्रिक्स की

दसवीं



### सामयिक आलेख - 2

(पृ.सं. : 14 - 18)

पाकिस्तान

आम चुनाव, 2018



### सामयिक आलेख - 3

(पृ.सं. : 19 - 24)

मॉब लिंगिंग : कानून

व्यवस्था के समक्ष चुनौती



### फोकस

● अटल बिहारी वाजपेयी : निधन ● भारत स्मार्ट शहर अध्येतावृत्ति और प्रशिक्षुता कार्यक्रम ● खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, वर्ष 2018-19 ● उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों की घोषणा ● वैश्विक दासता सूचकांक, 2018 ● विश्व बैंक : जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट ● इरीट्रिया-इथियोपिया सीमा समझौता ● यू.एन. : दक्षिण सूडान को हथियार आपूर्ति पर प्रतिबंध ● अमेरिका द्वारा ईरान पर पुनः प्रतिबंध ● डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग)

विनियमन विधेयक, 2018 ● केरल में बाढ़ ● ट्रम्प-पुतिन शिखर वार्ता ● मंगल ग्रह पर जलीय झील की खोज ● उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2018

### राष्ट्रीय परिदृश्य

● भगोज़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 ● पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, 2018 ● विदर्भ, मराठवाड़ा : सिंचाई परियोजना विशेष पैकेज ● विपो कॉपीराइट, प्रदर्शन व फोनोग्राम संधि, 1996 ● 'खुशी' (हेप्पीनेस) पाठ्यक्रम ● भूटान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा ● उत्तर प्रदेश : वन महोत्सव, 2018 ● प्रवासियों और स्वदेश वापसी करने वाले लोगों हेतु वृहद योजना ● दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा ● स्वास्थ्य मंत्रालय-इग्नू सहयोग समझौता ● बेनामी लेन-देन मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018

### अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

● भारत-नेपाल थिंक टैंक सम्मेलन ● दिल्ली संवाद का 10वां संस्करण ● वैश्विक दिव्यांगता शिखर सम्मेलन, 2018 ● विश्व शहर शिखर सम्मेलन, 2018 ● विश्व धरोहर समिति की 42वां बैठक ● म्यांमार अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल ● भारत : एआईबीडी का नया अध्यक्ष ● भारत-अमेरिका : '2+2 वार्ता'

### आर्थिक परिदृश्य

● तृतीय द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19 ● भारत में बैंक ऑफ चाइना की शाखा ● फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची ● फॉर्च्यून की 40 अंडर 40 सूची, 2018 ● द सॉफ्ट पॉवर 30, 2018 ● भारतीय राज्यों की कारोबार सुगमता रैंकिंग ● वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2018

### वैज्ञानिक परिदृश्य

● मेराह पुतिह उपग्रह ● सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल प्रक्षेपण ● स्वदेशी परमाणु घड़ी ● S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली ● विकास इंजन का सफल परीक्षण ● चालक दल बचाव प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण ● एसईएस-12 उपग्रह ● चीन द्वारा पाकिस्तान के उपग्रहों का प्रक्षेपण ● विश्व का पहला मानवीय फोरेंसिक केंद्र ● कॉर्पेट : भारत-बांग्लादेश नौसैन्य समन्वित गश्त

### स्थायी स्तंभ

□ संक्षिप्तियां □ खेल परिदृश्य □ विशेष  
□ संवाद □ ज्ञानिकी □ सामयिक प्रश्नकोश

(पृ.सं. : 25 - 44)



(पृ.सं. : 45 - 51)



(पृ.सं. : 52 - 56)



(पृ.सं. : 57 - 63)



(पृ.सं. : 64 - 69)




(पृ.सं. : 70 - 144)

	रजिस्टर्ड डाक द्वारा	कोरियर द्वारा
सदस्यता शुल्क		
अर्द्धवार्षिक (6 अंक)	₹400/-	₹500/-
वार्षिक (12 अंक)	₹800/-	₹1000/-
द्विवार्षिक (24 अंक)	₹1600/-	₹2000/-
त्रिवार्षिक (36 अंक)	₹2400/-	₹3000/-

सदस्यता शुल्क मनीऑर्डर द्वारा कार्यालय को प्रेषित करें। ग्राहक मनीऑर्डर फार्म पर अपना नाम, पता एवं मांग स्पष्ट लिखें। पते के साथ अपना मोबाइल अथवा फोन नंबर (यदि हो) भी लिख दें।




## समरंभ

 असम समझौते (1985) के लगभग 33 वर्षों बाद इस समझौते की मूल भावना के अनुरूप असम के लिए राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के अंतिम मसौदे का प्रकाशन 30 जुलाई, 2018 को हो सका है। मसौदे में शामिल नामों के सत्यापन के पश्चात ही अंतिम नागरिकता रजिस्टर सूची का प्रकाशन संभव हो सकेगा। इस अंतिम प्रकाशन से पूर्व ही मसौदे को लेकर धार्मिक आधार पर मतभेद प्रारंभ हो गए हैं। मतभेद इस बात को लेकर है कि कट ऑफ डेट 24 मार्च, 1971 के बाद आए सभी बांग्लादेशी प्रवासियों को असम से बाहर किया जाए या फिर धर्म के आधार पर विभेद करते हुए यहां के बहुसंख्यकों अर्थात् मुस्लिम धर्मावलंबियों को ही निष्कासित किया जाए। असम के सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दल तो सभी अवैध प्रवासियों के यहां से जाने के पक्षधर हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 पेश कर रखा है जिसके अनुसार अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इस अंक के आवरण आलेख में असम के राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और उसकी पेचीदगियों का विश्लेषण किया गया है।


### FRONTLINE

### Business Line

 'मॉब लिंग्विंग' या भीड़ द्वारा की गई हिंसा पर विमर्श जारी है। प्रायः देखा गया है कि बहसों में इस हिंसा को किसी अन्य हिंसा की परिणिति बताते हुए न्याय संगत बताने की कोशिश की जाती है। ऐसी कोशिशें प्रायः धर्म, जाति एवं क्षेत्र की गोलबंदी के आधार पर होती हैं। अब लाख टके का सवाल यह है कि क्या धार्मिक, जातीय एवं क्षेत्रीय गुटबंदी के आधार पर प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप ऐसी घटनाएं और बढ़ती जा रही हैं या फिर कारण कुछ और है? यदि हम कारणों के पीछे के कारण में जाएं, तो हम पाते हैं कि निरंतर बढ़ती भीड़ ही कहीं न कहीं, भीड़-हिंसा का कारण है। बढ़ती भीड़ में व्यक्ति का अपना स्पेस कहीं खो गया है। अपना स्पेस पाने के लिए वह जाति, धर्म या क्षेत्र के नाम पर अन्यो को बाहर करना चाहता है। बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारों की बढ़ती भीड़ में बड़ी आसानी से किसी नाम पर लोगों को लामबंद किया जा सकता है। आज भीड़ 'हिंसा' के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखती है। फिरोजाबाद में एक युवक को पीटने में वहां खड़ी भीड़ शामिल हो गई बिना यह जाने कि उसका दोष है या नहीं, जबकि इलाहाबाद में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग को पीटते देख भीड़ तमाशबीन ही रही। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए बुजुर्ग को बचाने भीड़ आगे नहीं आयी। इस अंक में भीड़-हिंसा के मनोविज्ञान पर सामयिक आलेख प्रस्तुत किया गया है।

 भारतीय रिजर्व बैंक  
Reserve Bank of India

 nature.com  
International weekly journal of science

 पाकिस्तान में इमरान खान के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद राजनीति के जानकारों का कहना है कि वे अचम्भित ही करेंगे। या तो बहुत कुछ करेंगे या फिर कुछ न करेंगे। इस अंक में पाकिस्तान आम चुनाव, 2018 पर भी सामयिक आलेख प्रस्तुत किया गया है।

### THE HINDU

इस अंक में एक अन्य सामयिक आलेख ब्रिक्स की दसवीं शिखर बैठक भी प्रस्तुत है।

 BBC NEWS

इस अंक के साथ निःशुल्क पुस्तिका के रूप में आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर अध्ययन सामग्री दी जा रही है, जो आगामी परीक्षा हेतु उपयोगी सिद्ध होगी। उम्मीद है यह अंक पाठकों को पसंद आएगा। पाठकों से अनुरोध है कि इस अंक पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।

 नीति आयोग NITI AAYOG  
National Institute of Transforming India

# आवरण आलेख

सम-सामयिक

विचार

वैचारिक आलेखों का स्तम्भ

## असम राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर : पूर्ण मसौदा प्रकाशित

**ए**न.आर.सी. यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens) का संबंध केवल असम से ही क्यों जोड़ा जाता है, जबकि इसमें 'राष्ट्रीय' शब्द जुड़ा हुआ है। दरअसल 'राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर' सर्वप्रथम वर्ष 1951 में असम के लिए तैयार हुआ था और पुनः 30 जुलाई, 2018 को इसका संशोधित ड्राफ्ट संस्करण प्रकाशित हुआ, तो यह भी केवल असम के लिए ही है। असम के लिए यह नागरिक रजिस्टर नागरिकता अधिनियम, 1955 तथा नागरिकता विनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत संशोधित किया गया है। इन्हीं प्रावधानों के तहत संपूर्ण देश के लिए 'राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर' (National Population Register) बनाना प्रस्तावित है, किंतु अभी यह प्रक्रियाधीन है और किसी भी राज्य में न तो पूर्ण हुआ है और न ही प्रकाशित किया गया है, यद्यपि कई राज्यों में 'डेटा अपलोड' का काम पूरा हुआ है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पूरे देश के लिए राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर बनाने की दिशा में पहला कदम है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में किसी क्षेत्र में रहने वाले सभी निवासियों का विवरण होता है, जबकि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर में वास्तविक नागरिकों का विवरण प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

### □ असम में नागरिक रजिस्टर की जरूरत

अपने नाम के अनुरूप 'असम' भौगोलिक असमानता (जंगल, पठार, पहाड़, मैदान एवं घाटी) के साथ-साथ जातीय एवं धार्मिक विभिन्नता का भी धनी है। मौजूदा असमिया समाज आर्य-अनार्य, जनजाति-गैर जनजाति, मूल निवासी और आब्रजकों से मिलकर बना है। यहां क्रमशः ऑस्ट्रेलायड, द्रविड़, तिब्बती-बर्मी, मंगोल, आर्य एवं आब्रजक (बांग्लाभाषी हिंदू एवं मुस्लिम, बिहार एवं

ओडिशा से आए चाय बागान मजदूर) आए। प्रत्येक जाति समूह अपने से बाद आए जाति समूह को असम का मूल नागरिक नहीं मानता है और उन्हें अपने इलाकों से दूर खदेड़ना चाहता है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के उत्तरी क्षेत्रों में केंद्रित भारतीय चीनी समूह के अंतर्गत तिब्बती-बर्मी कुल के बोडो स्वयं को असम का मूलवासी मानते हैं और इसके लगभग 50 प्रतिशत भू-भाग पर अलग बोडो राज्य की मांग करते हैं। वर्ष 2003 में बोडो क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक समझौता हुआ था। इसी प्रकार असम अधिवासित अन्य समूह बांग्लाभाषी

आब्रजकों को अपनी संस्कृति एवं सभ्यता के लिए खतरा मानते हैं और इन्हें असम से बाहर करना चाहते हैं। इसके लिए असम के अनेक संगठनों ने वर्ष 1979 से 1985 तक असम आंदोलन चलाया। अंततः 15 अगस्त, 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी एवं असम के संगठनों के मध्य यह समझौता हुआ कि 24 मार्च (मध्य रात्रि), 1971 के बाद आए आब्रजकों को असम से बाहर किया जाना चाहिए। असम समझौते को लागू करने के लिए यह आवश्यक था कि 24 मार्च, 1971 तक असम में वैध रूप से अधिवासित नागरिकों की पहचान का डेटा एकत्र किया जाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु असम के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को संशोधित करके डेटा का प्रस्तुतीकरण किया गया है।

### □ राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अपडेशन

असम समझौता वर्ष 1985 के अनुपालन हेतु असम के नागरिकों का डेटा एकत्रण किया जाना अनिवार्य था और इसके लिए कट ऑफ डेट 24 मार्च, 1971 निर्धारित की गई थी।



आरेखीय चित्र : असम राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर : पूर्ण मसौदा प्रकाशित

चूंकि असम के लिए नागरिक रजिस्टर, 1951 बन चुका था, इसलिए इसी रजिस्टर को कट ऑफ डेट तक संशोधित कर लक्ष्य प्राप्ति संभव थी। जैसे तो यह कार्य 15 अगस्त, 1985 के बाद कभी भी शुरू हो जाना चाहिए था, किंतु राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी एवं अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के चलते वर्ष 2015 से ही अपडेशन कार्य की शुरुआत हो सकी। यदि हालिया पृष्ठभूमि की बात करें तो हम कह सकते हैं कि बात कुछ आगे तब बढ़ी जब 5 मई, 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्र, असम सरकार तथा ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बीच संपन्न त्रि-पक्षीय वार्ता में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2009 में एक गैर-सरकारी संगठन **असम पब्लिक वर्क्स** ने सर्वोच्च न्यायालय में असम की मतदाता सूची से अवैध प्रवासियों का नाम हटाने के लिए एक याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 16 जुलाई, 2013 तक अपडेशन की प्रविधियां निर्धारित कर लेने का निर्देश दिया। वर्ष 2014 में न्यायालय ने सरकार को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का अपडेशन प्रारंभ करने के लिए निर्देशित किया तथा तभी से न्यायालय इस प्रक्रिया की मॉनीटरिंग भी कर रहा है।

**श्री प्रतीक हजेला** राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अपडेशन के लिए राज्य समन्वयक बनाए गए। 31 अगस्त, 2015 तक इसके लिए आवेदन लिए गए और 1 सितंबर, 2015 से सत्यापन कार्य प्रारंभ हो गया।

असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर संशोधन के प्रावधान नागरिकता अधिनियम, 1955 तथा नागरिकता विनियम, 2003 द्वारा शासित हैं। नागरिकता केंद्र सूची का विषय है, अतः नीतिगत निर्णय, दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय के लिए केंद्र सरकार उत्तरदायी है। भारत के महारजिस्टर के अधीन राज्य सरकार की प्रशासनिक मशीनरी ने अपडेशन कार्य संपन्न किया।

## □ राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मसौदा

असम सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के प्रकाशन हेतु इसके सभी नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए गए। आवेदन-पत्रों के सत्यापन के बाद 31 दिसंबर, 2017 को रजिस्टर का आंशिक मसौदा प्रकाशित किया गया। 30 जुलाई, 2018 को नागरिक रजिस्टर का पूर्ण मसौदा प्रकाशित किया गया। इस मसौदे में कुल प्राप्त 3,29,91,384 आवेदन-पत्रों में से 2,89,83,677 नाम शामिल किए गए। शेष 40,07,707 नाम मसौदे में शामिल न किए जाने योग्य घोषित कर दिए गए। अयोग्य घोषित 40,07,707 नामों में से 37,59,630 को खारिज कर दिया गया तथा शेष 2,48,077 को **डी वोटर** (D for Doubtful or disputed) के रूप

में विचाराधीन के अंतर्गत रखा गया है।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के पूर्ण ड्राफ्ट के प्रकाशित होते ही 40 लाख से अधिक लोग अवैध नागरिकता के भय से आशंकित हो उठे

## □ गैर-नागरिक हो जाने की आशंका

पूर्ण एन.आर.सी. मसौदा के प्रकाशित होते ही असम में अधिवासित लगभग 40 लाख लोगों को गैर-नागरिक हो जाने का भय सताने लगा है। एक ही परिवार के कुछ लोगों के नाम सूची में हैं और कुछ नाम सूची में नहीं भी हैं। इसका कारण बताते हुए राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला ने कहा है, “**नागरिकता की योग्यता**” व्यक्तिगत है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी नागरिकता स्वयं प्रमाणित करनी होगी। परिवार महत्वपूर्ण है, किंतु यह परिवार आधारित नहीं है। एक ही परिवार में पति कट ऑफ डेट (24 मार्च, 1971) के पूर्व का हो सकता है और पत्नी कट ऑफ डेट के बाद की हो सकती है। इसके विपरीत स्थिति भी हो सकती है। यह वंशधरता आधारित है। पत्नी को नागरिक होने के लिए अपने पूर्वजों के साथ अपनी वंशधरता पृथक्कृत: प्रमाणित करनी होगी। नागरिक पुरुष से विवाह के आधार पर उसे नागरिकता नहीं प्राप्त होगी।

असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में शामिल होने के लिए पात्रता निम्न व्यक्तियों की है—

- ◆ जिनके नाम वर्ष 1951 में प्रकाशित राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर में शामिल हों।
- ◆ जिनके नाम 24 मार्च (मध्यरात्रि), 1971 तक प्रकाशित किसी मतदाता सूची में शामिल हों।
- ◆ उपर्युक्त व्यक्तियों के वंशज।
- ◆ वे सभी व्यक्ति, जो असम में 1 जनवरी, 1966 को या बाद में लेकिन 25 मार्च, 1971 से पूर्व आए हैं तथा उन्होंने स्वयं को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत विदेशी पंजीकरण क्षेत्रीय अधिकारी (FRRO) के सक्षम पंजीकृत करवाया हो और सक्षम अधिकारी द्वारा अवैध प्रवासी या विदेशी न घोषित किए गए हों।
- ◆ जो असम के देशज अधिवासी हों।
- ◆ सभी **डी वोटर** के नाम सूची में शामिल किए जाएंगे, यदि सक्षम विदेशी प्राधिकरण द्वारा उन्हें गैर-विदेशी घोषित कर दिया जाता है।



- ◆ सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार भारत के सभी नागरिक एवं उनके बच्चे जो 24 मार्च, 1971 के बाद असम में प्रवेश किए हों और भारत के किसी क्षेत्र की नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत करें, नागरिक रजिस्टर में शामिल होने के पात्र होंगे।
- ◆ चाय जनजाति (Tea Tribe) के सभी सदस्य भी असम के मूल अधिवासी माने जाएंगे तथा उनके नाम रजिस्टर में शामिल किए जाने के लिए पात्र होंगे।

## □ गृह युद्ध! खून-खराबा?

असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के ड्राफ्ट में 40 लाख से अधिक लोगों को बाहर कर देने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने गृह युद्ध एवं खून-खराबे की स्थिति पैदा होने की चेतावनी देते हुए कहा, “यह बांग्लाभाषी लोगों और बिहारियों को निकाल फेंकने की योजना है।” वास्तविक स्थिति पर दृष्टिपात किया जाए, तो गृह युद्ध एवं खून-खराबा का वक्तव्य अतिरंजित ही प्रतीत होता है, क्योंकि एक तो कानूनन किसी भी देशवासी को नागरिक रजिस्टर की सूची से बाहर नहीं किया जा सकता है और दूसरी बात यह कि जो लोग बाहर हो गए हैं, वे 30 अगस्त, 2018 से 28 सितंबर, 2018 के बीच अपना दावा और अपनी आपत्तियां दोबारा दाखिल कर सकते हैं। फिर भी यदि उनकी आपत्तियां स्वीकार नहीं होती हैं, तो वे विदेश पंचाट या अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं, जहां से अनुतोष प्राप्त होने पर पुनः नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। अंततः गैर-नागरिक यानी विदेशी अवैध प्रवासी ही राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर में स्थान नहीं पा सकेंगे। कुछ ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि राजनीतिक शह प्राप्त कर अवैध प्रवासी हिंसक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, तो उसके लिए देश के कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होगी।

### अवैध प्रवासी

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 2(1)(ख) अवैध प्रवासी को इस प्रकार परिभाषित करती है- ‘अवैध प्रवासी’ उस एक विदेशी से अभिप्रेत है, जिसने भारत में प्रवेश किया है-

- (i) एक विधिमन्य पासपोर्ट या अन्य किसी प्राधिकार या यात्रा दस्तावेज के बिना।
- (ii) एक विधिमन्य पासपोर्ट या निर्धारित यात्रा दस्तावेज के साथ लेकिन समय की अनुज्ञात अवधि के परे भारत में रहता है।

### अवैध प्रवासियों के बच्चे

अवैध प्रवासियों के बच्चे भारत के विधिमन्य नागरिक हो भी सकते हैं और नहीं भी। इस संबंध में नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3 में प्रावधान दिए गए हैं-

- (i) 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई, 1987 से पूर्व भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके माता-पिता की राष्ट्रियता क्या है।
- (ii) 1 जुलाई, 1987 को या उसके बाद, लेकिन 3 दिसंबर, 2004 के पूर्व जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, यदि उसके माता-पिता में से कोई एक उसके जन्म के समय भारत का नागरिक रहा हो।
- (iii) 3 दिसंबर, 2004 को या उसके बाद जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, यदि उसके जन्म के समय माता-पिता दोनों ही या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा उसके जन्म के समय अवैध प्रवासी न हो।

## □ सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने पर प्रभाव

एक बार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का अंतिम प्रकाशन हो जाने तथा यह निर्धारित हो जाने कि कितने लोग असम के अर्थात भारतीय नागरिक हैं, के बाद राज्य के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने पर गहरे प्रभाव पड़ने की आशंका/संभावना है।

- ◆ असम, असम और भारतीय नागरिकों के लिए होगा। यहां से बांग्लादेशी प्रवासियों को जाना होगा। इससे यहां के मूल निवासियों की रोजगार संभावनाएं बढ़ेंगी।
- ◆ गैर-असमी यहां जमीनें न खरीद सकेंगे, जिससे यहां की भाषायी एवं सांस्कृतिक अक्षुण्णता बनाए रखने में मदद मिलेगी तथा बढ़ते जनसंख्या घनत्व पर भी रोक लगेगी।
- ◆ संभावना व्यक्त की जा रही है कि नागरिक रजिस्टर निर्मित हो जाने के बाद सरकार सभी निवासियों को पहचान-पत्र जारी कर सकती है। इससे गैर-नागरिकों की पहचान संभव हो सकेगी।
- ◆ आशंका व्यक्त की जा रही है कि 40 लाख से अधिक लोग जो वो बाहर हुए हैं, जिन्होंने नागरिकता रजिस्टर में स्थान पाने के लिए आवेदन किया था। बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने आवेदन ही न किया हो।
- ◆ इतनी बड़ी संख्या में लोगों को राज्य से बाहर कर दिए जाने पर यहां चाय-बागानों में मजदूरों की भारी किल्लत हो सकती है। दरअसल चाय-बागानों में मजदूरों के रूप में काम करने के अवसरों से आकर्षित होकर ही लोग बाहर से असम में आए थे। सरकार ऐसे लोगों को दीर्घकालिक वर्क परमिट जारी कर सकती है, जिन्हें मताधिकार और अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं होगा।
- ◆ गैर-नागरिकों का यथोचित रिकॉर्ड न रहने पर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है।
- ◆ नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 के अधिनियम बन जाने के पश्चात जब बांग्लादेश के हिंदू प्रवासियों को नागरिकता दी जाएगी तब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खतरा भी विद्यमान रहेगा।
- ◆ इतनी बड़ी जनसंख्या के शरणार्थी के रूप में ज्यादा समय तक रहने पर राज्य की आर्थिक स्थिति पर भारी बोझ पड़ सकता है।
- ◆ एक अन्य सामाजिक पहलू भी विचारणीय है जिसमें एक ही परिवार के कुछ सदस्य भारत के नागरिक घोषित होंगे और कुछ अवैध प्रवासी। उदाहरण के लिए एक केस में यदि पिता 24 मार्च, 1971 से पूर्व बांग्लादेश से प्रवासी के रूप में भारत आया हो और माता 1980 में बांग्लादेशी विस्थापित के रूप में अवैध प्रवासन करके भारत आयी हो। इनका एक पुत्र 30 जून, 1987 को पैदा हुआ हो और एक पुत्री का जन्म 1988 में हुआ हो, तो प्रश्न उठेगा कि पिता को किस तिथि से भारत का नागरिक माना जाएगा? यदि पिता को पुत्री के जन्म के बाद भारत का नागरिक माना जाता है तो नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अनुसार पिता एवं पुत्र भारत के नागरिक होंगे तथा माता एवं पुत्री भारत के नागरिक नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में एक ही परिवार के कुछ

सदस्यों को बांग्लादेश भेजा जाएगा। ऐसी परिस्थितियों का सामना करने वाला एक व्यक्ति मार्मिक अपील करते हुए कहता है, “मुझे गोली मार दी जाए, उधर भी मुझे गोली मार दी जाएगी। कम-से-कम यहां मेरी अंत्येष्टि क्रिया करने वाले लोग तो होंगे।” इन सामाजिक पहलुओं के कारण यह मसला अत्यंत जटिल हो उठा है।

## □ कुछ अनसुलझे सवाल?

**सबसे बड़ा सवाल**-अंतिम राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर सूची से भी बाहर होने वाले अवैध प्रवासियों का क्या होगा? क्या उन्हें वापस भेजना संभव होगा? इन नागरिकता विहीन लोगों के क्या अधिकार होंगे? अगर उन्होंने संपत्तियां खरीद रखी हैं, तो उसका क्या होगा? आदि। इन प्रश्नों के जवाब में कहा जा सकता है कि हमारे देश में शरणार्थियों के लिए भी कानून है। भले ही राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को सूचीबद्ध करने का कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीक्षण में हो रहा है, बाद की परिस्थितियों के लिए सभी राजनैतिक दल मिल-बैठकर तरीके निश्चित कर सकते हैं। बेशक इसमें मानवीय दृष्टिकोण की भी अहम भूमिका होगी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से भी विचार-विमर्श किया जाना अनुचित न होगा।

## □ असमिया पहचान का मुद्दा

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मूल में असमिया पहचान का मुद्दा ही सर्वोपरि है। असम समझौते के अनुच्छेद 6 में असम की भाषायी और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा का उल्लेख है। इस मूल भावना के विपरीत केंद्र में सत्तासीन भाजपा द्वारा लाए जा रहे उस कानून को माना जा रहा है, जिसमें मुस्लिम अवैध प्रवासियों के अतिरिक्त अन्य धर्मों के अवैध प्रवासियों के लिए अलग प्रावधान की व्यवस्था की जा रही है।

नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इस विधेयक के समर्थकों का कहना है कि वे हमारे अपने लोग हैं, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारणों से वे भारत में शरणार्थी बन गए हैं। वस्तुतः असम के राजनीतिक दल इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि अवैध प्रवासियों का धर्म के आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए और सभी धर्मों के अवैध प्रवासियों को असम से बाहर भेजा जाना चाहिए। यहां ध्यान देने की बात यह है कि फिलहाल यह विधेयक वर्ष 2019 के चुनावों तक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और साथ ही विधेयक पूरे भारत के लिए लागू होगा। यदि इन शरणार्थियों को नागरिकता दी जाती है, तो उन्हें संपूर्ण भारत में कहीं भी बसने का अधिकार प्राप्त होगा न कि केवल असम में। लेकिन अधिकांश के असम में ही बसने का खतरा तो विद्यमान है ही।

## □ कट ऑफ 1971 या 1951

पूरे देश में अवैध विदेशी प्रवासियों की पहचान के लिए कट ऑफ वर्ष 1948 है जबकि असम में यह 1971 है। 1948 से 1971 तक असम ने अकेले ही पूरे देश के विदेशी अवैध प्रवासियों का बोझ वहन किया है। इसी कारण यहां के मूल निवासियों का इस बात पर जोर है कि वे 1971 के बाद किसी भी बांग्लादेशी प्रवासी को स्वीकार नहीं करेंगे,

चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम। मूल निवासी संगठनों की सामूहिक संस्था असम सम्मिलिता महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष मोतिउर रहमान ने 2012 में सर्वोच्च न्यायालय में कट ऑफ वर्ष 1971 बनाने के विरुद्ध याचिका दाखिल की हुई है। श्री रहमान के अनुसार, यह कट ऑफ वर्ष 1951 होना चाहिए क्योंकि ऐसा न करने पर 1951 से 1971 के बीच असम में दाखिल हुए लाखों विदेशियों को नागरिकता मिलना पक्का हो जाएगा और इससे देशज लोगों के वजूद के लिए खतरा पैदा होगा। सर्वोच्च न्यायालय में इस पर भी सुनवाई शुरू हो रही है। यदि श्री रहमान की दलील स्वीकार होती है तो असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की संपूर्ण कवायद ही बे-मतलब की सिद्ध हो सकती है।

## □ मानवीय दृष्टिकोण सर्वोपरि

मूल असमी अपनी भाषा एवं जनसंख्या में बदलाव से आशंकित हैं। वर्ष 1991 में असम में असमी एवं बांग्ला बोलने वालों का प्रतिशत क्रमशः लगभग 58 एवं 22 था, जो वर्ष 2011 में क्रमशः लगभग 48 एवं 28 हो गया। इसी प्रकार वर्ष 2001 में असम की जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत 30.9 था, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 34.2 प्रतिशत हो गया। बेशक असमी पहचान का संकट बढ़ रहा है। लेकिन इस संकट के बावजूद यह ध्यान रखना जरूरी है कि संकट के समाधान में मानवीय दृष्टिकोण को तिलांजलि न दे दी जाए। विश्व में शायद यह पहला अवसर होगा, जब किसी एक ही दिन इतनी बड़ी जनसंख्या नागरिकता से महरूम हो रही है। इतनी बड़ी जनसंख्या को ऐसे ही इनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता है। हम इतिहास प्रसिद्ध **कामागाटामारू प्रकरण** को विस्मृत नहीं कर सकते हैं, जब 376 भारतीय यात्रियों को लेकर कामागाटामारू नामक जहाज ब्रिटिश कोलम्बिया (कनाडा) पहुंचा, तो 24 को छोड़कर शेष भारतीयों को जहाज से उतारने से मना कर दिया गया। जब सितंबर, 1914 में यह जहाज वापस कोलकाता पहुंचा, तो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इन यात्रियों के साथ कानून के उल्लंघनकर्ता के तौर पर व्यवहार किया। अधिकारियों के व्यवहार से दंगा भड़क गया। प्रत्युत्तर में ब्रिटिश सरकार ने यात्रियों पर गोलीबारी कर दी और 19 निरीह यात्रियों की मौत हो गई। तत्कालीन कनाडा सरकार ने यदि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इन यात्रियों को शरण दी होती और बाद में बातचीत से मामले को सुलझाने का प्रयास किया होता, तो शायद यह घटना न घटी होती। मई, 2016 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में वर्ष 1914 की इस घटना के लिए आधिकारिक क्षमा याचना भी की थी। आज असम के नागरिकता रजिस्टर के ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों के गैर-नागरिक हो जाने की परिस्थिति उत्पन्न हुई है। समस्या का समाधान जल्दबाजी में, केवल कानूनी प्रावधानों के तहत ही नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण के साथ किए जाने की महती आवश्यकता है। बांग्लादेश से भी सहानुभूतिपूर्वक अपने इन नागरिकों के प्रति व्यवहार अपेक्षित है। समस्या का समाधान भले ही देर से हो, इसे तर्कपूर्ण एवं सोच समझकर अंजाम दिया जाना चाहिए अन्यथा कोई अवांछित घटना इसमें नए पहलुओं को जन्म दे सकती है।

■■■

# सामयिक आलेख - 1

## सम-सामयिक विचार

## वैचारिक आलेखों का स्तम्भ

### ब्रिक्स की दसवीं शिखर बैठक

— धीरेन्द्र त्रिपाठी

**व**र्तमान विश्व व्यवस्था विचारधारा आधारित न होकर, आर्थिक आधार पर संचालित हो रही है। युद्धोन्माद कम हुआ है और सामाजिक-आर्थिक प्रगति को तरजीह मिली है। विकासशील देशों, जिन्हें तीसरी दुनिया या वैश्विक दक्षिण के नाम से भी जाना जाता है, ने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और बहुपक्षीय मंचों पर अपने हितों को मुखरता से रखा है। फिर बात चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की हो या फिर वैश्विक व्यापार का संचालन करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था, विश्व व्यापार संगठन (WTO) की।

गौरतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत गठित ब्रेटन वुड्स संस्थाओं यथा-विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पर अमेरिका और प्रमुख यूरोपीय देशों का ही प्रभुत्व रहा है। इन विकसित देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से विकासशील देशों का लंबे समय तक शोषण किया। बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में विश्व के अधिकतर हिस्सों में बड़े आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू हुए। अर्थव्यवस्था के दरवाजे निजी क्षेत्रों और विदेशी निवेश के लिए भी खोल दिए गए। इससे अनुसंधान एवं विकास (R&D) हेतु मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने से नई तकनीकों का विकास हुआ। उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कम कीमत पर भारी मात्रा में उपलब्ध हो गए। इन आर्थिक सुधारों का फायदा विकासशील देशों का नेतृत्व करने वाले एशिया, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिकी

महाद्वीप स्थित देशों को भी मिला। एशिया महाद्वीप के दो सबसे बड़े देशों चीन व भारत ने संपूर्ण विश्व में सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में अपना नाम दर्ज कराया। वहीं अफ्रीका

एवं दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में क्रमशः दक्षिण अफ्रीका व ब्राजील आर्थिक विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़े। सोवियत संघ के विघटन के उपरांत, रूस भी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाने की जद्दोजहद में लग गया।

इसी क्रम में विकसित देशों के संगठन जी-7 के मुकाबले, विकासशील देशों को भी अपने हितों को सामूहिक रूप से सुरक्षित

रखने हेतु एक समूह के गठन की आवश्यकता महसूस हुई। वर्ष 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर ब्रिक (BRIC) की नींव रखी। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के भी इस समूह में सम्मिलित होने से 'ब्रिक' (BRIC), ब्रिक्स (BRICS) बन गया। तब से प्रतिवर्ष ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन, क्रमिक रूप से सदस्य देशों में आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2009 में प्रारंभ हुए प्रथम शिखर सम्मेलन का सिलसिला बढ़ते हुए दसवें शिखर सम्मेलन तक पहुंच गया है।

### ब्रिक्स की दसवीं शिखर बैठक

ब्रिक्स की दसवीं शिखर बैठक 25-27 जुलाई, 2018 के मध्य दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर के सैंडटन कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुई। शिखर बैठक की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सेरिल रामफोसा ने की। ज्ञातव्य है कि इस समूह की वर्ष 2013 की शिखर बैठक का आयोजन भी दक्षिण अफ्रीका

में ही हुआ था। दसवीं शिखर बैठक की थीम थी "अफ्रीका में ब्रिक्स : चौथी औद्योगिक क्रांति में समावेशी विकास और साझा समृद्धि के लिए सहयोग"।

25-27 जुलाई, 2018 के मध्य दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में  
BRICS की दसवीं शिखर बैठक संपन्न



102 बिंदुओं का जोहान्सबर्ग घोषणा-पत्र जारी

अफ्रीकी महाद्वीप के आर्थिक एकीकरण के लिए 'एजेंडा 2063' पर साथ कार्य करने पर सहमति



नेल्सन मंडेला के जन्म शताब्दी अवसर पर ब्रिक्स शिखर बैठक

आरेखीय चित्र : ब्रिक्स की दसवीं शिखर बैठक



## □ शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी

दसवीं शिखर बैठक के मुख्य आयोजन में मेजबान राष्ट्र दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एवं ब्राजील के राष्ट्रपति माइकल टैमर ने प्रतिभाग किया। इसके अतिरिक्त तुर्की और अर्जेंटीना के राष्ट्राध्यक्षों ने विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

## □ दसवीं शिखर बैठक की उपलब्धियां

ब्रिक्स की दसवीं शिखर बैठक ऐसे समय में आयोजित हो रही है, जब संपूर्ण विश्व दक्षिण अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला की जन्म शताब्दी के अवसर पर मानवीय मूल्यों और लोकतंत्र को बचाने के लिए उनके द्वारा किए गए संघर्ष को याद कर रहा है। ब्रिक्स की यह बैठक अंतरराष्ट्रीय मीडिया में काफी चर्चित रही।

ब्रिक्स देशों ने अपनी उपलब्धियों और कार्ययोजना को अपने घोषणा-पत्र के माध्यम से दुनिया के समक्ष रखा। इस घोषणा-पत्र को "जोहान्सबर्ग घोषणा-पत्र" का नाम दिया गया। घोषणा-पत्र 102 बिंदुओं का है, जिसको पांच भागों में बांटा गया, जिसका विवरण इस प्रकार है :-

**(1) प्रस्तावना :** ब्रिक्स देशों ने जोहान्सबर्ग घोषणा-पत्र के माध्यम से तकनीकी आधारित औद्योगिकीकरण और संवृद्धि के संदर्भ में समावेशी विकास और साझा समृद्धि प्राप्त करने पर जोर दिया। इसके साथ ही ब्रिक्स नेताओं ने पिछले दस वर्षों में शांति, सामंजस्य, साझा विकास और समृद्धि की प्राप्ति में अपने मजबूत सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। समूह के सदस्य देशों में तीन स्तंभों यथा-आर्थिक, शांति एवं सुरक्षा पर आधारित सहयोग और लोगों के आदान-प्रदान पर सहमति बनी।

ब्रिक्स देशों ने घोषणा-पत्र के माध्यम से वैश्विक शांति और स्थिरता की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ की केंद्रीय भूमिका हेतु सहयोग, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वर्णित उद्देश्यों एवं सिद्धांतों पर प्रतिबद्धता, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान, लोकतंत्र को प्रोत्साहन और संधारणीय विकास लक्ष्यों, 2030 को लागू करने पर जोर दिया।

**(2) बहुध्रुवीयता को मजबूत करने, वैश्विक शासन में सुधार तथा साझा चुनौतियों से निपटने पर सहमति :** दसवें शिखर सम्मेलन के

माध्यम से ब्रिक्स सदस्य देशों ने विश्व व्यवस्था (world order) को बहुध्रुवीय बनाने पर जोर दिया।

जोहान्सबर्ग घोषणा-पत्र के माध्यम से ब्रिक्स सदस्य देश प्रमुख वैश्विक चुनौतियों की पहचान कर, उनके समाधान हेतु साझा दृष्टिकोण का निर्माण करने पर सहमत हुए। प्रमुख वैश्विक साझा चुनौतियों के रूप में जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, कालेधन का प्रवाह, शुद्ध पेयजल की कमी, बढ़ती ऊर्जा मांग, संरक्षणवाद, प्राकृतिक आपदा, समुद्री यातायात की सुरक्षा, जनसंख्या वृद्धि, रासायनिक एवं जैविक आतंकवाद, बढ़ते साइबर हमलों आदि की पहचान की गई।

ब्रिक्स के दसवें शिखर सम्मेलन की एक बड़ी उपलब्धि सदस्य देशों का वैश्विक आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के विरुद्ध दृढ़तापूर्वक मुकाबला करने हेतु एकजुट होना है। सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों सहित, दुनिया भर में हो रही आतंकी घटनाओं की कठोर शब्दों में निंदा की गई। ब्रिक्स देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (Comprehensive Convention on International Terrorism) को शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप देने और उसे अपनाने के लिए जोर दिया। इसके साथ ही रासायनिक और जैविक आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन और बहुपक्षीय वार्ता की आवश्यकता पर बल दिया गया।



आरेखीय चित्र : ब्रिक्स की दसवीं शिखर बैठक

**(3) अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करने पर सहमति :** दसवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की एक बड़ी उपलब्धि सदस्य देशों का अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु

ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करने पर सहमत होना है। सदस्य देशों ने विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे हेतु राजनयिक, कूटनीतिक एवं राजनीतिक प्रयासों को अपनाने पर जोर दिया। वहीं अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका को चिह्नित किया।

अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा बने वैश्विक मुद्दों यथा – मध्य-पूर्व में हिंसा और आतंकवाद, इज़राइल-फिलीस्तीन समस्या, यमन गणराज्य एवं सऊदी अरब के मध्य संघर्ष, खाड़ी देशों में चल रहे राजनयिक संकट, अफगान समस्या, सीरियाई गृह युद्ध, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु युद्ध की आशंका का समाधान शांतिपूर्ण तरीके एवं बातचीत के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता में कराने पर जोर दिया गया।

इसके अतिरिक्त ब्रिक्स नेताओं ने घोषणा-पत्र के माध्यम से बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए मौजूदा कानूनी व्यवस्था का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग की।

**(4) वैश्विक आर्थिक सुधार के लिए ब्रिक्स साझेदारी :** विगत वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था की मंद गति से उबरकर, वर्तमान में लगातार हो रहे सुधार पर ब्रिक्स देशों ने संतोष व्यक्त किया। इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के सुधार के मार्ग में आ रही बाधाओं यथा - देशों के मध्य बढ़ते व्यापारिक विवाद, भू-राजनीतिक खतरों, वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में उच्च ऋण-ग्रस्तता, असमानता और अपर्याप्त समावेशी विकास को चिह्नित कर उन्हें दूर करने के लिए साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता पर सहमति बनी।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उचित उपयोग, बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) का सख्ती से अनुपालन, चौथी औद्योगिक क्रांति की मांग के अनुरूप कौशल विकास प्रशिक्षण और खुली अर्थव्यवस्था की जरूरत पर बल दिया गया।

वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में विकासशील देशों की प्रभावी भूमिका के लिए इन संस्थाओं में सुधार की मांग की गई। इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के कोटे में विकासशील देशों का हिस्सा

बढ़ाने की अपील ब्रिक्स घोषणा-पत्र के माध्यम से की गई। इसके अतिरिक्त अफ्रीकी महाद्वीप के आर्थिक एकीकरण के लिए एजेंडा 2063 पर साथ कार्य करने पर सहमति बनी।

**(5) नागरिकों के मध्य सहयोग पर सहमति :** ब्रिक्स देशों ने अपने कार्यक्रमों के केंद्र में ब्रिक्स नागरिकों को रखा है। इस संबंध में खेल, युवा-कार्यक्रमों, संस्कृति, शिक्षा, फिल्म और पर्यटन के क्षेत्र में निरंतर सहयोग बढ़ाने के साथ ही, नागरिकों के आदान-प्रदान का स्वागत किया गया।

जोहान्सबर्ग घोषणा-पत्र के अनुसार, थिंक टैंक परिषद, अकादमिक मंच, ब्रिक्स नागरिक मंच, युवा राजनयिक मंच, युवा वैज्ञानिक मंच और युवा शिखर सम्मेलन इत्यादि माध्यमों से ब्रिक्स नागरिक सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी।

## □ शिखर बैठकों से इतर द्विपक्षीय बैठकें

ब्रिक्स शिखर बैठक के अवसर पर एकत्र नेताओं के मध्य इतर द्विपक्षीय बैठकें भी संपन्न हुईं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई मुलाकात को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत उपयोगी बताया। दोनों नेताओं के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control) पर शांति बनाए रखने के लिए अपनी सेनाओं को उचित दिशा-निर्देश देने पर सहमति बनी।

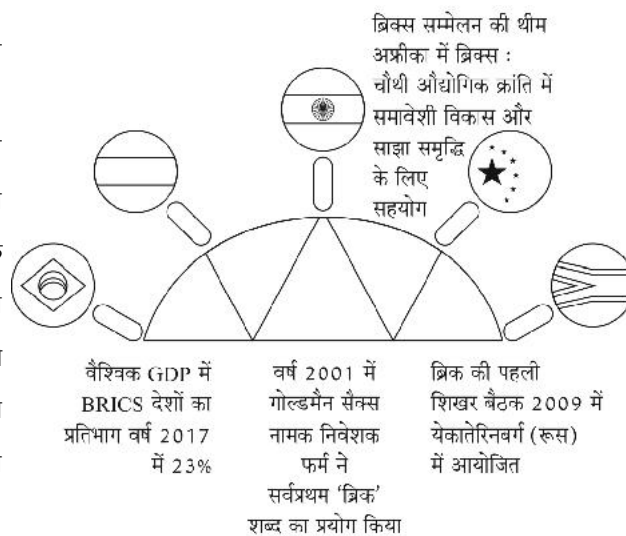
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर बैठक से इतर द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेता अपने

ऐतिहासिक संबंधों को याद करते हुए सहयोग के अन्य क्षेत्रों में भी साथ कार्य करने पर सहमत हुए।

## □ ब्रिक्स में भारतीय प्रधानमंत्री का उद्बोधन

ब्रिक्स के मंच से अपने उद्बोधन में भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा, कि आज दुनिया अनेक प्रकार के बदलावों से गुजर रही है। उन्होंने नई औद्योगिक तकनीक और डिजिटल इंटरफेस (Digital Interface) को अवसर के साथ एक चुनौती की संज्ञा दी। इससे

नई प्रणालियों और उत्पादों का निर्माण होगा और आर्थिक प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे।



**आरेखीय चित्र : ब्रिक्स की दसवीं शिखर बैठक**

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथी औद्योगिक क्रांति की मांग के अनुरूप कौशल विकास प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। इस संबंध में औद्योगिक उत्पादन, डिजाइन और विनिर्माण (Manufacturing) में आ रहे मौलिक बदलावों को स्वीकार करने के साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म, आटोमेशन (Automation) और डाटा फ्लो (Data flow) के माध्यम से भौगोलिक दूरी कम करने की बात कही।

बेहतर सेवा की उपलब्धता, उत्पादकता स्तर में वृद्धि और श्रम संबंधी मुद्दों के प्रभावी प्रबंधन के लिए तकनीकी नवाचार की सहायता लेने की बात भारतीय प्रधानमंत्री ने कही। इसके साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री ने विकास और प्रगति के केंद्र में मानवीय मूल्यों को अपनाने पर जोर दिया।

## □ ब्रिक्स की पृष्ठभूमि

वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स नामक निवेशक फर्म ने सर्वप्रथम 'ब्रिक' शब्द का प्रयोग किया। वर्ष 2003 में इस निवेशक फर्म के अर्थशास्त्री जिम ओ' नील द्वारा प्रस्तावित थीसिस - 'ड्रीमिंग विद ब्रिक्स (BRICs) : द पाथ टू 2050' में कहा गया था कि ब्राजील, रूस, भारत एवं चीन की संभाव्य आर्थिक क्षमता इतनी अधिक है कि चारों राष्ट्र वर्ष 2050 तक विश्व की सर्वाधिक प्रभुत्व वाली अर्थव्यवस्थाएं बन सकते हैं।

ब्रिक/ब्रिक्स शिखर बैठकें एक नजर में		
शिखर बैठक	स्थान	वर्ष
पहली	येकातेरिनबर्ग (रूस)	2009
दूसरी	ब्रासीलिया (ब्राजील)	2010
तीसरी	सान्या (चीन)	2011
चौथी	नई दिल्ली (भारत)	2012
पांचवीं	डरबन (द. अफ्रीका)	2013
छठवीं	फोर्टलेज़ा (ब्राजील)	2014
सातवीं	उफा शहर (रूस)	2015
आठवीं	गोवा (भारत)	2016
नवीं	शियामेन (चीन)	2017
दसवीं	जोहान्सबर्ग (द. अफ्रीका)	2018

ब्रिक राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की प्रथम पूर्ण बैठक 16 मई, 2008 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित की गई थी। 16 जून, 2009 को इसी रूसी नगर में ब्रिक राष्ट्रों के शीर्ष नेताओं की प्रथम शिखर बैठक आयोजित की गई। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी इस समूह में सम्मिलित करने से 'ब्रिक' (BRIC), 'ब्रिक्स' (BRICS) बन गया। इसके बाद से प्रतिवर्ष ब्रिक्स देशों का वार्षिक शिखर सम्मेलन क्रमिक रूप से सदस्य देशों में आयोजित किया जा रहा है।

## □ भारत और ब्रिक्स

भारत ब्रिक्स की स्थापना के समय से ही इससे जुड़ा रहा है। ब्रिक्स की पिछली सभी शिखर बैठकों में भारतीय प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया है। दसवीं शिखर बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंत्रियों एवं अधिकारियों के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भी सम्मेलन में शिरकत की।

ब्रिक्स के मंच के माध्यम से भारत ने अन्य ब्रिक्स सदस्य देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर किया। इस संबंध में चीन का उदाहरण उल्लेखनीय है, जिससे भारत के सर्वाधिक जटिल संबंध हैं। रूस और चीन के अमेरिका और यूरोपीय देशों से संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। इसी स्थिति में दोनों देश ब्रिक्स समूह की मजबूती के लिए प्रयासरत हैं, जो कि भारत के हित में है।

## □ समीक्षा

ब्रिक्स समूह ने अपने गठन के पिछले 10 वर्षों में बेहतर प्रदर्शन किया है। वर्ष 2000 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (World GDP) में ब्रिक्स देशों का प्रतिभाग 8.27 प्रतिशत था, जो वर्ष 2018 में बढ़कर लगभग 23 प्रतिशत हो गया है। भारत और चीन वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था की आपूर्ति शृंखला का अहम हिस्सा हैं। भारत, सेवाओं के लिए, वहीं चीन विनिर्माण के लिए वैश्विक केंद्र बन गया है। दूसरी ओर ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका अपने प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दुनिया के लिए उपलब्ध कराकर वैश्वीकरण का लाभ उठा रहे हैं। ब्रिक्स देशों सहित अन्य विकासशील देशों के आर्थिक एवं राजनीतिक उभार ने परंपरागत विकसित देशों यथा-अमेरिका और यूरोपीय देशों के समक्ष कड़ी चुनौती पेश की है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, संरक्षणवाद एवं सीरिया जैसे मुद्दों पर ब्रिक्स राष्ट्रों के अमेरिका और यूरोपीय देशों से विरोधी दृष्टिकोण के बावजूद वैश्वीकरण के वर्तमान युग में इस समूह के अमेरिका-विरोधी स्वरूप की संभावना क्षीण ही है।

किंतु ब्रिक्स के कुछ अंतर्विरोध भी हैं, जो इसे राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से कमजोर भी करते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है। समूह के अन्य राष्ट्रों की तुलना में चीन की अर्थव्यवस्था बहुत विशाल है, तो दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था नगण्य।

इस अंतरमहाद्वीपीय समूह में संवाद एवं सहयोग का सशक्त मंच बनने की शक्तियां एवं संभावनाएं निहित हैं। इसकी प्रगति विश्व व्यवस्था को बहुध्रुवीय बनाने में सहायक सिद्ध होगी, जो कि न केवल ब्रिक्स राष्ट्रों, बल्कि सभी विकासशील राष्ट्रों एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए उपयोगी रहेगी।

## पाकिस्तान आम चुनाव, 2018

— कालीशंकर 'शारदेय'

**भा**रतीय उपमहाद्वीप में क्रिकेट की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कहा करती थीं कि "इस क्षेत्र की जनता को सिर्फ दो माध्यमों से मूर्ख बनाया जा सकता है, पहला धर्म और दूसरा क्रिकेट"। पता नहीं वे यह बात मजाक में कहती थीं या फिर संजीदगी के साथ। फिलहाल जो भी हो, वर्तमान में भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित देशों की स्थिति पर गौर किया जाए, तो उनकी बात अक्षरशः सत्य प्रतीत होती है।

एक ऐसे समय में जब क्रिकेट की पिच अपने अनुकूल तैयार कर दी गई हो, तो किसी भी टीम के लिए मैच का परिणाम अपने पक्ष में करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त जब अम्पायरों का निर्णय भी अपने पक्ष में हो, तो फिर जीत लगभग सुनिश्चित हो जाती है। ठीक यही स्थिति वर्तमान पाकिस्तान चुनाव में देखी जा सकती है, जहां जमींदार और अमीर लोगों में सेना का दबदबा, पाकिस्तानी सेना और इमरान खान के बीच का गठजोड़ और नवाज शरीफ के प्रति गद्दी गई लुटेरे, डाकू वाली छवि आदि ने मिलकर पाकिस्तानी चुनावी राजनीति की पिच पहले से ही तैयार कर दी थी। अनुकूल पिच पर गेंदबाजी करते हुए इमरान खान ने मैच जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हैट्रिक (नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो एवं हाफिज सईद को आउट करके) लेते हुए चुनाव परिणाम को काफी हद तक अपने पक्ष में कर लिया। इमरान ने नवाज को आउट करने के लिए उन्हें मोदी की भाषा बोलने वाला बताया, कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए इस्लामिक वेल्फेयर स्टेट के खाब दिखाए और बाकियों के लिए नए पाकिस्तान के निर्माण का

सपना दिखाया। पिछले 22 वर्षों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली छवि ने भी बहुत हद तक उनकी जीत आसान कर दी।

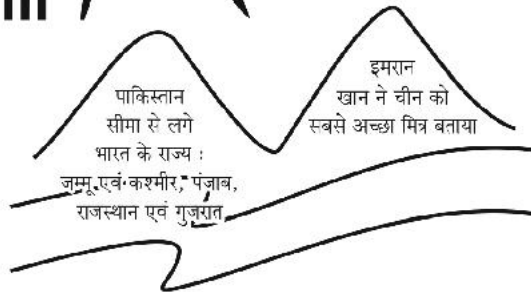
### □ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

आजादी के बाद से ही भारत और पाकिस्तान दो विपरीत दिशाओं में अग्रसर हुए। एक ओर भारत में संविधान के अनुरूप संसदीय लोकतंत्र एवं देश के विकास को सही दिशा की ओर ले जाने वाले नीतिवान राजनीतिज्ञों ने देश के मान एवं नागरिकों के सम्मान को अक्षुण्ण बनाए रखने का हरसंभव प्रयत्न किया। उन्हीं प्रयासों का ही परिणाम है कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हालांकि भारत की यह लोकतांत्रिक यात्रा आसान नहीं रही। इसे तमाम छोटे-बड़े व्यवधानों का सामना करना पड़ा, लेकिन समय के साथ लोकतांत्रिक जड़ें और गहरी होती गईं।

वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान, आजादी के इतने वर्षों बाद भी राजनीतिक स्थिरता की प्राप्ति हेतु संघर्षरत है। 14 अगस्त, 1947 को स्वतंत्र होने के बाद भी सिद्धांततः वहां ब्रिटिश महारानी का राज वर्ष 1956 तक चलता रहा। आजादी के बाद पाकिस्तान को मुहम्मद अली जिन्ना का नेतृत्व प्राप्त हुआ। लियाकत अली इसके प्रथम प्रधानमंत्री बने। परंतु जिस देश की नींव असहिष्णुता,

कट्टरपंथ, जातीय उन्माद पर टिकी हो, उसकी इमारत कैसी होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सेना में पनपती महत्वाकांक्षाओं के चलते 16 अक्टूबर, 1951 को लियाकत अली की हत्या कर दी गई। यह पाकिस्तानी सेना की ऐसी कुत्सित महत्वाकांक्षी परंपरा का

पूर्व क्रिकेटर इमरान खान ने 18 अगस्त, 2018 को पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली



आरेखीय चित्र : पाकिस्तान आम चुनाव, 2018

दुष्परिणाम था, जिसकी छाया आज तक पाकिस्तानी लोकतांत्रिक संस्थाओं को डराती रहती है। अभी भी पाकिस्तानी जनमानस उससे उबर नहीं पाया है।

वर्ष 1956 में पाकिस्तान को एक इस्लामिक गणराज्य घोषित किया गया। वर्ष 1958 में मार्शल लॉ की घोषणा हुई तथा जनरल अयूब खान ने कार्यभार संभाला। वर्ष 1960 में अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। वर्ष 1969 में उनके इस्तीफा देने के बाद जनरल याह्या खान ने कार्यभार संभाला। वर्ष 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश के रूप में नया देश बना। वर्ष 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। वर्ष 1977 में जनरल जिया उल हक ने तख्तापलट कर दिया तथा वर्ष 1978 में वह स्वयं राष्ट्रपति बने। वर्ष 1979 में अंतरराष्ट्रीय विरोधों के बावजूद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। अगस्त, 1988 में विमान दुर्घटना में जनरल जिया उल हक की मृत्यु हो गई। नवंबर, 1988 में बेनजीर भुट्टो (जुल्फिकार अली भुट्टो की पुत्री) की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने आम चुनाव में जीत हासिल की। अगले कुछ वर्षों तक बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ क्रमशः प्रधानमंत्री बनते और हटते गए। अक्टूबर, 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में सेना ने एक बार फिर तख्तापलट किया।

27 दिसंबर, 2007 को बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद 13वीं नेशनल असेंबली के लिए हुए चुनावों के पश्चात मार्च, 2008 में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेतृत्व में बनी सरकार लोकतांत्रिक पद्धति से जनता द्वारा निर्वाचित पहली ऐसी सरकार साबित हुई, जिसने अपना पांच वर्षों का संवैधानिक कार्यकाल पूरा कर इतिहास रचा था। तब से अब तक पाकिस्तान में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों का दौर जारी है।



आरेखीय चित्र : पाकिस्तान आम चुनाव, 2018

## □ पाकिस्तान आम चुनाव प्रक्रिया

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्यों की संख्या 342 है, लेकिन इनमें से सिर्फ 272 सदस्यों को आम चुनाव के जरिए सीधे जनता चुनती है। नेशनल असेंबली की जिन 70 सीटों पर चुनाव नहीं होता, उनमें से 60 सीटें महिलाओं के लिए और 10 सीटें पारंपरिक और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षित हैं। इन आरक्षित सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इसका फैसला आनुपातिक प्रतिनिधित्व नियम के तहत होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व नियम के जरिए आम चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा विजित सीटों के अनुपात में 70 आरक्षित सीटों को विभाजित कर दिया जाता है, अर्थात् जिस दल ने सबसे अधिक सामान्य सीटें जीती हैं, उसके उसी अनुपात में उम्मीदवार आरक्षित सीटों से सांसद बनते हैं। इन सांसदों को बिना किसी मतदान प्रक्रिया के सीधे नेशनल असेंबली के लिए चुन लिया जाता है।

एक समय पर कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों अथवा किसी एक संसदीय सदन व किसी अन्य प्रांतीय विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय सभा या किसी प्रांतीय विधायिका के भंग हो जाने के पश्चात 90 दिनों के अंदर ही उस सदन के लिए चुनाव करवाना जरूरी है एवं ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा 14 दिनों के भीतर की जाती है।

## □ वर्तमान चुनाव एवं परिणाम

पाकिस्तान निर्वाचन आयोग द्वारा 15वें नेशनल असेंबली के लिए चुनाव की अधिसूचना 31 मई, 2018 को जारी की गई। इसी अधिसूचना में ही प्रांतीय सभाओं (Provincial Assemblies) के चुनाव की भी घोषणा सन्निहित थी। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथि 25 जुलाई, 2018 नियत की गई थी। इस तिथि को पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा (National Assembly) तथा पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत की प्रांतीय सभाओं के चुनाव संपन्न हुए।

नेशनल असेंबली की 342 सीटों में से 272 सीटों पर चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। वर्तमान चुनाव में 270 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। कुल सीटों के हिसाब से बहुमत के लिए 172 सीटें, जबकि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सीटों के परिप्रेक्ष्य में बहुमत 137 सीटें प्राप्त करना जरूरी है। पाकिस्तान की जनगणना, 2017 के आधार पर सीमांकित किए गए निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 2018 का आम चुनाव आयोजित किया गया।

पाकिस्तान के नेशनल असेंबली की सीटों का प्रांतवार वितरण		
1.	पंजाब	141
2.	सिंध	61
3.	खैबर पख्तूनख्वा	39
4.	बलूचिस्तान	16
5.	संघशासित जनजातीय क्षेत्र	12
6.	संघीय राजधानी	3

चुनाव के दौरान कुल 51.6 प्रतिशत मतदान हुआ। चुनाव परिणामों के तहत पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसे 116 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग (PML-N) तथा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) को क्रमशः 64 और 43 सीटें प्राप्त हुईं वहीं अन्य को 47 सीटों पर विजय प्राप्त हुई, जबकि 2 सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। इस प्रकार किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल सका।

पाकिस्तान निर्वाचन आयोग द्वारा आरक्षित सीटों (60+10) को विभिन्न पार्टियों में, उनके द्वारा जीती गई सीटों के आधार पर बांटा गया। पीटीआई को महिलाओं के लिए आरक्षित 60 सीटों में से 28 सीटें तथा गैर-मुस्लिमों के लिए आरक्षित 10 सीटों में से 5 सीटें आवंटित की गईं। इससे पीटीआई के सीटों की संख्या बढ़कर 149 हो गई। आवंटन के बाद पीएमएल-एन की सीटें बढ़कर 82 तथा पीपीपी की सीटें बढ़कर 54 हो गई हैं।

पाकिस्तान चुनाव, 2018					
प्रमुख पार्टियां	नेशनल असेंबली	प्रांतीय असेंबली			
		पंजाब	सिंध	खैबर पख्तूनख्वा	बलूचिस्तान
कुल सीट	272	297	130	99	51
पीटीआई	116	123	23	65	4
पीएमएल-एन	64	129	-	5	1
पीपीपी	43	6	76	4	-
इंडिपेंडेंट	13	29	-	6	6
एमएमए	12	-	1	10	9
एमक्यूएम (पी)	6	-	16	-	-
पीएमएल	4	7	-	-	-
बीएपी	4	-	-	-	15
बीएनपी	3	-	-	-	5
जीडीए	2	-	11	-	-
जे डब्ल्यूपी	1	-	-	-	1
एएनपी	1	-	-	6	3
एएमएल	1	-	-	-	-

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के महेश कुमार मलानी दक्षिणी सिंध प्रांत के थरपरकर से नेशनल असेंबली सीट जीतने वाले पहले हिंदू हैं। ये वर्ष 2013 के आम चुनाव में सिंध में प्रांतीय असेंबली सदस्य निर्वाचित हुए थे।

इस बार के चुनाव में धार्मिक रुझान रखने वाली पार्टियों को अधिक फायदा होता नहीं दिखा। लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद की नई पार्टी अल्लाह-हू-अकबर तहरीक पार्टी ने चुनाव में 265 उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन इनमें से कोई भी जीत हासिल नहीं कर सका।

### □ महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास

पाकिस्तान के वर्ष 2018 के इस आम चुनाव में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। पाकिस्तान चुनाव अधिनियम, 2017 की धारा 206 के अनुसार, चुनाव में सभी दलों को 5 प्रतिशत टिकट महिलाओं को देना आवश्यक किया गया था। यही वजह है कि नेशनल असेंबली की कुल 272 सीटों पर विभिन्न दलों द्वारा कुल 171 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था।

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने सर्वाधिक 19 महिलाओं को मैदान में उतारा। इसके बाद दक्षिणपंथी दल मुत्ताहिद मजलिस-ए-अमल ने 14 महिलाओं को उम्मीदवारी सौंपी। पाकिस्तान के चुनावी इतिहास में

पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने भागीदारी की। इससे पूर्व ~~2013~~ 2013 के आम चुनाव में 135 महिलाएं चुनावी मैदान में उतरी थीं।

वर्ष 2018 के चुनाव में महिला उम्मीदवारों में एक नाम अली बेगम का भी है, जो पुरुष प्रधान कबायली इलाके से चुनाव लड़ने वाली पहली महिला उम्मीदवार हैं। वर्तमान चुनाव में जीत हासिल करने वाली कुछ प्रमुख महिलाओं में जुगनू मोहसिन (पंजाब प्रांत, निर्दलीय), जुरजात गुल (दक्षिणी पंजाब, पीटीआई), शम्स उन निशा (थाटा, पीपीपी), डॉ. फहमीदा मिर्जा (सिंध प्रांत, जीडीए), मरियम शरीफ (नवाज शरीफ की बेटी), हिना रब्बानी खार (पूर्व विदेश मंत्री) आदि शामिल हैं।

### □ नई सरकार एवं चुनौतियां

18 अगस्त, 2018 को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के चैयरमैन, क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह इस्लामाबाद स्थित राष्ट्रपति ममनून हुसैन के आवास पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर एवं राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू उपस्थित थे। इमरान खान 22 गज की क्रिकेट की पिच से निकलकर 22 वर्षों के संघर्ष के बाद देश के 22वें (कार्यकाल के अनुसार) प्रधानमंत्री बने हैं।

इससे पूर्व 17 अगस्त, 2018 को नेशनल असेंबली के 176 सदस्यों ने इमरान खान के पक्ष में मतदान किया था, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी शाहबाज शरीफ ने 96 मत प्राप्त किए थे।

20 अगस्त, 2018 को प्रधानमंत्री इमरान खान के 21 सदस्यीय मंत्रिमंडल के 16 सदस्यों ने संघीय मंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि 5 सदस्यों को सलाहकार नियुक्त किया गया है। पीटीआई के उपाध्यक्ष मखदूम शाह महमूद कुरैशी, देश के नए विदेश मंत्री नियुक्त किए गए। इससे पूर्व भी वे 2008-13 के दौरान पीपीपी सरकार में विदेश मंत्री रह चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व मुख्यमंत्री परवेज खट्टक को रक्षा मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल में तीन (शिरीन मजरी, जुवैदा जलाल और फहमीदा मिर्जा) महिलाओं को स्थान मिला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के मंत्रिमंडल के कम से कम 12 सदस्य, परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में कार्य कर चुके हैं।

प्रधानमंत्री के रूप में अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर चुके इमरान खान के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने तथा सेना और कट्टरपंथियों के प्रभाव से बाहर निकलने की है। चीन, अमेरिका सहित भारत के साथ संबंधों को संतुलित करने की समस्या भी बरकरार है। अब तक इमरान खान भारत के खिलाफ बोलते आए हैं, जो कि उनकी राजनीतिक मजबूरी भी हो सकती है। देखना यह है कि प्रधानमंत्री के रूप में भारत के प्रति उनके रुख में कोई परिवर्तन आता है या नहीं। चुनाव जीतने के बाद इमरान ने चीन को सबसे अच्छा मित्र बताया था। लेकिन क्या वे चीनी कर्ज में उलझे पाकिस्तान को और अधिक उलझाएंगे या फिर इससे मुक्ति का साहस दिखाएंगे? चीनी मलहम पाकिस्तान के दर्द का इलाज है या उसके फैलते जख्म को छुपाने का तरीका, यह इमरान खान को तय करना होगा। अमेरिका के साथ वर्तमान कड़वाहट भरे संबंध को भी सुधारने की चुनौती होगी। अमेरिका, पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में तालिबान को काबू करने के लिए दबाव बनाता रहा है, ऐसे में 'तालिबान खान' के नाम से प्रसिद्ध इमरान खान का कदम क्या होगा, यह देखने वाली बात है।

#### इमरान खान : राजनीतिक यात्रा

- 25 अप्रैल, 1996 को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) की स्थापना।
- वर्ष 2002 में संसद सदस्य निर्वाचित।
- वर्ष 2007 में पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ की आलोचना के कारण जेल।
- वर्ष 2013 में इमरान खान द्वारा 'नया पाकिस्तान' भ्रष्टाचार मुक्त कल्याणकारी राज्य का वादा।
- वर्ष 2018 के आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पीटीआई।
- 18 अगस्त, 2018 को 65 वर्षीय इमरान खान बने पाकिस्तान के 22 वें प्रधानमंत्री।

#### □ पाकिस्तान चुनाव और भारत

पाकिस्तान में आम चुनाव हो और भारत का जिक्र न हो, ऐसा संभव नहीं। पाकिस्तान में जब भी चुनाव होता है, तो भारत के प्रति जनता में गुस्सा पैदा कर वोट हथियाने की कोशिशें राजनीतिज्ञों द्वारा की जाती रही हैं।

पाकिस्तान का चिंतन ही दो स्तंभों पर टिका है- पहला, इस्लाम तो दूसरा, भारत के प्रति नफरत की भावना। इतिहास साक्षी है जिसने भी भारत के प्रति कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, आम जनता में भारत के संदर्भ में घृणा फैलायी, उसने वहां सत्ता का सुख भोगा है। इस बार के चुनाव के दौरान तथा इसके पहले भी इमरान खान ने भारत के खिलाफ बोलने से कतई गुरेज नहीं किया है, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। लेकिन इस बार के चुनाव में भारत की चर्चा अन्य कारणों से भी हो रही है। पाकिस्तानी नेताओं द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान भारत के विकास का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को भारत से आगे ले जाने की बातें की गईं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र भी बार-बार किया गया।

भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण आचरण का कारण पाकिस्तान की आंतरिक समस्याएं और सत्ता को प्राप्त करने की उत्कट लालसा भी है। जब-जब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, आंतरिक व्यवस्था चरमराने लगती है, स्थिरता पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं, तब-तब भारत का हौआ दिखाया जाता है। भारत विरोधी जनमत तैयार किया जाता है तथा जनता का ध्यान सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्ट कारनामों से हटाने की कोशिश की जाती है।

#### □ एक राष्ट्र, एक चुनाव

भारत में एक राष्ट्र, एक चुनाव पर भले ही इस समय चर्चा जोरों पर है, लेकिन पाकिस्तान में पहले से ही आम चुनाव और प्रांतीय चुनाव एक साथ ही कराए जाते रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान के 15वें आम चुनाव के साथ ही इसके चार प्रांतों यथा - सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के चुनाव भी आयोजित किए गए। भारत की विशालता को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्र, एक चुनाव का मुद्दा व्यावहारिक प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसे में आधे-आधे राज्यों का प्रत्येक ढाई वर्ष पर अलग चुनाव कराए जाने पर चर्चा जोर पकड़ रही है।

#### □ निष्कर्ष

पाकिस्तान के इतिहास में यह दूसरी बार हो रहा है, जब देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सत्ता का हस्तांतरण हुआ। पाकिस्तान जैसे अस्थिर लोकतंत्र वाले देश के लिए यह बड़ी उपलब्धि है, अन्यथा यह देश तो वर्षों तक सैन्य तानाशाही का दंश झेल चुका है। प्रत्येक निर्वाचित सरकार भ्रष्टाचार के आरोप में सत्ता से बेदखल कर दी जाती थी और सेना शासन संभालने लगती थी। पिछली नवाज शरीफ की सरकार पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। पनामा पेपर्स में उनका नाम आने से जैसे सेना को और मौका मिल गया। नतीजा नवाज शरीफ के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के साथ उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। लेकिन इस बार सेना पर्दे के पीछे से अपनी भूमिका का निर्वहन करती दिख रही है। सरकार बनाने के लिए बाकायदा चुनाव आयोजित किए गए। हालांकि पाकिस्तान के इस चुनाव में सेना की भूमिका किसी से छिपी नहीं है, फिर भी पाकिस्तानी दमघोटू लोकतंत्र में यह सांस लेने जैसी खबर है कि सेना सामने न आकर नेपथ्य में रहकर दावेदारी करने के लिए मजबूर हुई है। अंजाम चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तान का चुनाव से गुजरना ही उसकी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक जीत है। ■■■

## मॉब लिंगिंग : कानून व्यवस्था के समक्ष चुनौती

— डॉ. विकास कुमार शुक्ल

**न्याय** का सार्वभौमीकरण तो सर्व स्वीकार्य है, परंतु बात जब न्यायाधिकार के सार्वभौमीकरण की हो, तो स्थिति इसके उलट होती है। सभी की हर समय न्याय तक पहुंच जहां व्यवस्था को बनाए रखती है, वहीं सभी को न्याय करने का अधिकार व्यवस्था को मत्स्य न्याय की स्थिति में ले जाता है। यहां बलशाली खुद की रची परिभाषा के अनुसार, किसी को भी दोषी/निर्दोष सिद्ध करने लगता है तथा अपने ही अनुसार उसके लिए दण्ड और पुरस्कार का निर्धारण भी। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है, जहां लोगों ने अपने अनुसार न्याय किया और पूरी मानवता को दांव पर लगा दिया। जहां हिटलर ने प्रजाति, धर्म और शारीरिक क्षमता को न्याय का अधिकार बनाया, तो वहीं लेनिन, माओ, मुसोलिनी आदि ने विचारधारा के नाम पर रक्तंजित न्याय किया। न्यायाधिकार जब एक व्यक्ति से परे जाकर भीड़ को प्राप्त हो जाता है तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है। भीड़ द्वारा दिया जाने वाला न्याय कभी-कभी न केवल व्यक्ति विशेष को अपितु पूरे समुदाय के अस्तित्व को संकट में डाल देता है।

### □ क्या है लिंगिंग?

लिंगिंग शब्द का अर्थ होता है- 'किसी को दोषी करार देकर उसे बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए मृत्युदण्ड देना'। लिंगिंग शब्द लिंग कानून (Lynch Law) से आया है। इसे 1780 ई. के आस-पास संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत के निवासी विलियम लिंग (William Lynch) के कुकृत्यों के बाद गढ़ा गया। विलियम लिंग द्वारा खुद के बनाए न्यायाधिकरण,

जिसका वह स्वघोषित न्यायाधीश भी था, के माध्यम से बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए अनेक आरोपियों को उनका पक्ष रखने का अवसर दिए बिना मौत की सजा सुनाई गई। इस न्यायाधिकरण के सर्वाधिक शिकार अफ्रीकी मूल के व्यक्ति हुए, जिन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया गया। यद्यपि प्रारंभ में यह अमेरिका तक ही सीमित था, परंतु समय के साथ इस कुप्रथा का विस्तार अन्य देशों में भी होता गया।

### □ भारत में मॉब लिंगिंग

भारत जैसा सहिष्णु देश, जिसकी विशेषता ही रही है कि सबको अपनाया जाए, भी भीड़ हिंसा के दाग से खुद को बचा नहीं पाया। आधुनिक भारत में देखा जाए, तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय अनेक अवसरों पर भीड़ ने अनियंत्रित होकर हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम दिया। असहयोग आंदोलन के समय में घटी चोरी-चौरा अग्निकांड की घटना तो जग जाहिर है। इसी तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भी भीड़ हिंसा की अनेक घटनाएं प्रकाश में आती हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारत में विभाजन के कारण आबादी स्थानांतरण के समय मुस्लिम समुदाय तो इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात सिख समुदाय भीड़ के निशाने पर रहे।

हाल-फिलहाल में भारत में मॉब लिंगिंग की अनेक घटनाएं प्रकाश में आईं, जिनमें किसी व्यक्ति को दोषी

करार देकर भीड़ द्वारा सजा-ए-मौत का फरमान सुनाया गया। किसी को बच्चा चोरी के आरोप में, तो किसी को व्यभिचार के आरोप में,

लिंगिंग शब्द 1780 के आस-पास विलियम लिंग के कुकृत्यों के बाद गढ़ा गया

भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा के पीछे संदर्भ समूह की अवधारणा



चोरी-चौरा की घटना फरवरी, 1922 में, असहयोग आंदोलन के दौरान



भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी भीड़ हिंसा की अनेक घटनाएं

आरेखीय चित्र : मॉब लिंगिंग : कानून व्यवस्था के समक्ष चुनौती



किसी को गो-वध के लिए, तो किसी को तांत्रिक क्रियाओं के लिए, किसी को धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का, तो किसी को जातीय भावनाओं को चोट पहुंचाने का दोषी करार दिया गया। भले ही सभी घटनाएं अलग-अलग क्षेत्रों में और अलग-अलग कारणों से घटी हों, लेकिन सभी घटनाओं में ये बातें समान रही हैं कि इनमें न तो किसी का दोष सिद्ध हुआ था, न ही किसी को अपनी बात रखने का अवसर मिला और न ही उन्हें सजा देने के लिए किसी न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया गया। ये सभी घटनाएं भीड़ द्वारा की गई मान्यताओं पर आधारित रहीं।

भारत में भीड़ द्वारा की गई हिंसा न तो कानूनी दृष्टि से मान्य है और न ही नैतिक दृष्टि से उचित। इसी कारण हाल की माँब लिंगिंग की घटनाओं से पूरे देश में चिंता का माहौल बना हुआ है। भीड़ द्वारा की जा रही हिंसा की घटनाओं तथा उस घटना की वीडियोग्राफी तथा उसका प्रचार कर श्रेय लेने की होड़ ने अनेक गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। भारत में माँब लिंगिंग के कारणों तथा प्रभाव पर आने से पूर्व सामूहिक हिंसा के सामाजिक-मनोवैज्ञानिक कारणों की पड़ताल भी आवश्यक है।

## □ सामूहिक हिंसा का सामाजिक - मनोविज्ञान

सामूहिक हिंसा एक सामाजिक-मनोवैज्ञानिक क्रिया-कलाप है। हिंसा के विस्तार, लक्ष्य तथा इसकी योजना बद्धता के आधार पर इसे तीन प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका एक प्रकार है- सामुदायिक हिंसा, जिसमें किसी जातीय समूह को निशाना बनाकर सामूहिक हिंसा की जाती है। बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों के विरुद्ध की गई हिंसा इसके अंतर्गत आती है। ऐसी हिंसाएं आमतौर पर नियोजित होती हैं तथा इनका विस्तार काफी अधिक होता है। इनसे पूरे समुदाय के विनाश का भी जोखिम बना रहता है। सामूहिक हिंसा का दूसरा प्रकार है- सामाजिक मान्यताओं को बचाने के लिए की जाने वाली हिंसा। इस प्रकार की हिंसा परंपरा को कानून से ऊपर मानने के कारण होती है, इसमें हिंसा के द्वारा डर का माहौल पैदा कर एक संदेश दिया जाता है। इस प्रकार की हिंसा में हिंसा को एक पवित्र कार्य माना जाता है तथा इसे धर्म की गलत व्याख्याओं के द्वारा समर्थन भी प्राप्त होता है। जैसे कि “वेदों का आदेश है कि गो हत्या करने वालों को मार डालना पाप नहीं

है (यद्यपि इसकी सत्यता संदिग्ध है)।” इस तरह की हिंसा भी नियोजित होती है। सामूहिक हिंसा का तीसरा प्रकार है- भीड़ हिंसा। सामान्यतः यह किसी तात्कालिक कारण से उत्पन्न आवेश का परिणाम होता है। आमतौर पर यह अनियोजित होता है और इसका विस्तार काफी सीमित क्षेत्रों तक होता है।

## □ माँब लिंगिंग के कारण

ऊपरी तौर से देखने से माँब लिंगिंग किसी ऐसी तात्कालिक घटना का परिणाम होता है, जिससे जन भावनाएं आहत हों। जन भावनाओं को ठेस पहुंचने की स्थिति में लोगों द्वारा सामूहिक प्रतिक्रिया (हिंसात्मक) की जाती है तथा समूह तथाकथित दोषी को शारीरिक दण्ड देता है। सामान्यतः भीड़ का उद्देश्य दोषी को केवल शारीरिक पीड़ा पहुंचाना होता है, परंतु इतनी अधिक हिंसा के बाद ज्यादातर मामलों में व्यक्ति काल के गाल में समा जाता है।

भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा के पीछे का तात्कालिक कारण केवल क्षणिक उन्माद को जन्म देता है, जबकि लोगों के मन में अनेक कारणों से उन्मादी पृष्ठभूमि पहले से ही बन चुकी होती है, जिस

कारण उनकी सहिष्णुता क्षीण हो चुकी होती है। भीड़ हिंसा के पीछे छिपे कारणों को मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक तथा आर्थिक चश्मों से देखने पर स्थिति और भी स्पष्ट होती है।

## ● मनोवैज्ञानिक कारण

भीड़ द्वारा की गई हिंसा के पीछे संदर्भ समूह (Reference Group) की अवधारणा कार्य करती है। संदर्भ समूह एक मनोवैज्ञानिक समूह होता है, जिसमें व्यक्ति सदस्य न होते हुए भी खुद को उससे जोड़ लेता है तथा अपने आप को उस समूह का सदस्य मानने लगता है। इसी मनोयोग के वशीभूत भीड़ के सदस्य जब भीड़ के किसी अन्य सदस्य (भले ही वो अनजान हो) के खिलाफ कोई उत्पीड़क कृत्य देखते हैं, तो वे उसे खुद पर उत्पीड़न मान बैठते हैं तथा प्रतिक्रिया करते

हैं और इसका परिणाम होता है- सामूहिक रूप से दोषी को दण्ड देने का क्रिया-कलाप। इसके अतिरिक्त अन्य कारणों (पारिवारिक, सामाजिक, नौकरी संबंधी आदि) से मानसिक तनाव से ग्रसित व्यक्ति भी ऐसे अवसरों पर अपनी खीझ निकालने लगते हैं। इससे कई बार हिंसा का स्वरूप और भी वीभत्स हो जाता है।



- अनियंत्रित सोशल मीडिया
- अंतरराष्ट्रीय छवि प्रभावित
- वोटों का ध्रुवीकरण
- निवेश कम



आरेखीय चित्र : माँब लिंगिंग : कानून व्यवस्था के समक्ष चुनौती

## ● कानूनी एवं राजनैतिक कारण

भारत में भीड़ हिंसा से निपटने हेतु किसी स्पष्ट कानून के अभाव में सामान्य अपराध कानूनों से ही भीड़ हिंसा के दोषियों को दण्डित किए जाने के कारण कई बार सामूहिक अपराध करने वाले कई लोग बच निकलते हैं। कई बार पुलिस भी अनावश्यक विवेचना से बचने हेतु इसे अज्ञात द्वारा किया गया अपराध करार देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेती है। कुछ मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप भी पुलिस के कदमों को रोकने का कारण बनते प्रतीत होते हैं।

इसके अतिरिक्त राजनीतिक विफलता भी भीड़ हिंसा की पृष्ठभूमि तैयार करती है। जब सरकार लोगों को अपराध पूर्व सुरक्षा तथा अपराध पश्चात न्याय दिलाने में असफल रहती है, तो लोगों का धीरे-धीरे कानून एवं न्याय व्यवस्था पर विश्वास कम होता जाता है। ऐसी स्थिति में लोगों द्वारा इस भावना के वशीभूत कि अपराधी (भीड़ द्वारा घोषित) कानूनी प्रक्रिया में बच निकलेगा, अपराधी को तुरंत दण्ड दिया जाता है।

कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा भी अपने संकीर्ण स्वार्थों के वशीभूत होकर वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कभी-कभी भीड़ को गुमराह करके हिंसात्मक कार्रवाइयां करवाई जाती हैं। इस स्थिति में लोगों को यह विश्वास दिलवाया जाता है कि अमुक गतिविधि जायज है तथा उन्हें उनके कृत्यों के लिए न केवल कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा, अपितु उन्हें भविष्य में राजनैतिक लाभ भी मिलेंगे। भीड़ हिंसा में नेतृत्व करने वाले का महिमामंडन तथा उसे समुदाय का हीरो बनाने की भावना ने भी भीड़ हिंसा की घटना में वृद्धि की पृष्ठभूमि बनायी है। इसके अतिरिक्त इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि संगठित अपराधी भी खुद को जांच से दूर रखने हेतु किसी की हत्या को भीड़ हत्या का जामा पहना दे।

## ● सामाजिक-सांस्कृतिक कारण

भीड़ हिंसा के पीछे अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक कारण भी उत्तरदायी हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों द्वारा अपनी आस्था एवं विश्वास को कानूनों से ऊपर माना जाता है। ऐसी स्थिति में उनकी आस्था एवं विश्वास को तोड़ने वालों को सजा देने को एक पवित्र कार्य माना जाता है। किसी समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह से इस भावना को और भी बल मिलता है। भारत में गो हत्या को लेकर की जा रही भीड़ हिंसा इसका एक उदाहरण है। इसके अतिरिक्त धर्म की गलत व्याख्या, सामान्य कृत्य को धार्मिक अपराध के रूप में दर्शाना आदि भी भीड़ हिंसा के प्रमुख कारण रहे हैं।

## ● आर्थिक कारण

मॉब लिंगिंग के लिए सबसे जरूरी है- मॉब अर्थात् भीड़। जब कोई देश पूर्ण रोजगार की स्थिति में होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्वों के निर्वहन में व्यस्त रहता है और भीड़ के हिंसात्मक स्वरूप का निर्माण ही नहीं हो पाता है। यह सामान्य धारणा है कि जितनी

अधिक बेरोजगारी होगी, उतनी ही बड़ी भीड़। इसके अतिरिक्त बेरोजगारी आर्थिक अभाव को जन्म देती है और आर्थिक अभाव अनेक तनावों को तनावों के हिंसात्मक होने की संभावना काफी अधिक होती है। बड़ी मात्रा में बेरोजगारी की स्थिति अराजक तत्वों के लिए एक आसान परिवेश का निर्माण करती है तथा वे इसे नकारात्मक भीड़ में रूपांतरित कर देते हैं।

## ● अनियंत्रित सोशल मीडिया

अनियंत्रित सोशल मीडिया ने तथ्यहीन तथा भड़काऊ सामग्रियों के तीव्र संप्रेषण को आसान बना दिया है। इससे स्थानीय एवं सामान्य-सी घटना को भी संवेदनशील स्वरूप में ढालकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जाता है। इसके दो दुष्प्रभाव होते हैं। इससे एक तो सामान्य-सी घटना को बृहद दंगे की पृष्ठभूमि बना दिया जाता है और दूसरे इन तथ्यहीन सामग्रियों से किसी समुदाय/जाति/वर्ग विशेष को देश के शत्रु के रूप में रेखांकित कर दिया जाता है। इसका समग्र परिणाम देश में नागरिक सैन्यीकरण के रूप में भी होता है तथा नागरिक देश के भीतरी शत्रुओं से मातृभूमि की रक्षा करने हेतु मनोवैज्ञानिक रूप से लामबंद होने लगते हैं। परिणामस्वरूप पहले से ही शत्रु मान बैठे किसी समुदाय/वर्ग/जाति के सदस्य को उसकी सामान्य गलती के लिए भी देशद्रोह करार देकर उसको सजा दी जाने लगती है।

## □ प्रभाव

भीड़ द्वारा सड़कों पर दिया जा रहा न्याय न केवल स्थानीय अपितु राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की नींव खोदने का कार्य कर रहा है। यह न केवल देश की कानून व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न करेगा, अपितु खुद न्याय प्रणाली को भी कटघरे में खड़ा कर देगा। यदि इसी तरह लोगों को सड़कों पर न्याय करने का अधिकार मिलता रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब लोग न्याय की समानांतर व्यवस्था बनाने लगेंगे और वर्तमान न्याय व्यवस्था का औचित्य जाता रहेगा।

भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा के व्यक्ति एवं समष्टि दोनों प्रभाव काफी कष्टकारी होते हैं। स्थानीय एवं तुच्छ से मुद्दे को लेकर की गई हिंसा बड़े दंगों में रूपांतरित हो जाती है। इससे कुछ लोगों के मूर्खतापूर्वक कृत्यों का दण्ड पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। जब स्थिति पारिवारिक स्तर पर देखी जाती है, तो वह और भी हृदयविदारक नजर आती है। हिंसा में मारे गए व्यक्ति के परिवार को काफी मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक दबाव झेलना पड़ता है। कई बार तो उनके सभी आर्थिक विकल्प ही समाप्त हो जाते हैं और उनके समक्ष आजीविका का प्रश्न खड़ा हो जाता है।

देश में हो रही भीड़ हिंसा से देश की अंतरराष्ट्रीय छवि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह देश के व्यापार एवं देश में आने वाले निवेश को भी दुष्प्रभावित कर सकता है। भीड़ हिंसा से देश का अंतरराष्ट्रीय कद भी घटता है, क्योंकि इससे देश में कानून व्यवस्था की विफलता का संदेश जाता है।

## □ नियंत्रण के उपाय

भीड़ हिंसा से निपटने का सर्वोत्तम उपाय है, उसे होने से ही रोक दिया जाए। भीड़ हिंसा से निपटने हेतु तीन स्तरीय रणनीति होनी चाहिए। प्रथम स्तर पर निवारक उपायों को अपनाया जाए, जिनसे ऐसी घटनाओं को होने ही न दिया जाए। दूसरे स्तर पर हिंसा के तुरंत बाद इस पर आवश्यक कार्रवाई कर इसके प्रभावों को शिथिल किया जाना चाहिए। तीसरे स्तर पर दोषियों की पहचान करके उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए। भीड़ हिंसा को रोकने के लिए सबसे पहले प्रशासनिक सूचना तंत्र को मजबूत बनाना होगा, जिससे कि ऐसी घटनाओं के होने की संभावना को ही दबा दिया जाए। इसके बाद घायल व्यक्ति को तुरंत इलाज दिलाया जाना अति आवश्यक है ताकि उसे बचाया जा सके। पुलिस को अफवाहों को रोकने की प्रणाली पर भी ध्यान देना होगा तथा उन व्यक्तियों की पहचान को सुनिश्चित करना होगा तथा उन्हें कानूनी प्रक्रिया के अधीन दण्डित करना होगा। भीड़ हिंसा के अपराधियों की परिभाषा को व्यापक करने की आवश्यकता है। इसमें प्रत्यक्ष हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल लोगों के साथ-साथ उन लोगों को जो इसमें सहयोग करते हैं तथा उन्हें भी जो इसे प्रोत्साहित करते हैं, को भी शामिल करना होगा। पुलिस को भी भीड़ हिंसा का नाम देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेने की मनोवृत्ति से बाहर आना होगा।

भीड़ हिंसा के खिलाफ सामाजिक-सांस्कृतिक नियंत्रण भी अपनाया होगा। लोगों तक धर्म की गलत व्याख्या को पहुंचने से रोकने हेतु स्थानीय संतों एवं स्थानीय नेतृत्व को भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व करना चाहिए तथा लोगों को जागरूक करना चाहिए। भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा की स्थिति में स्थानीय प्रशासन को बिना किसी भी राजनीतिक दबाव के काम करना चाहिए तथा दोषियों को दण्डित करना चाहिए।

## □ क्या अलग कानून ही एकमात्र समाधान है?

भीड़ द्वारा की जा रही हिंसाओं से निपटने हेतु स्पष्ट कानून के अभाव के आलोक में अनेक व्यक्तियों द्वारा एक बिल्कुल नए कानून की वकालत की जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की तर्ज पर इसे मानव सुरक्षा कानून (मासुका) नाम दिया जा रहा है। मासुका की मांग करने वालों का तर्क है कि यह भीड़ हत्या की रोकथाम हेतु यह भारतीय न्याय शास्त्र के शून्य को भर देगा। इसके अतिरिक्त मासुका का एक सकारात्मक प्रभाव इस रूप में भी पड़ेगा कि इससे लोगों तक एक सख्त संदेश जाएगा और लोग हिंसात्मक भीड़ की सदस्यता से बचेंगे।

परंतु कानूनविदों का एक वर्ग अलग कानून को अनावश्यक मानता है। उनका मानना है कि मौजूदा कानून ही इतने पर्याप्त हैं कि मॉब लिंग पर लगाम लगा सकते हैं। अपने कथन के समर्थन में वे अनेक देशों का भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जहां कम कानूनों के बावजूद नागरिक सुरक्षा की स्थिति उन देशों से काफी बेहतर है, जहां अनेक कानून हैं।

कानूनविद इस नए कानून के राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना को भी नकारते नहीं हैं। उनके अनुसार, इस नए कानून से सत्ताधारी दल विपक्ष की जायज मांगों हेतु शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर भी प्रतिबंध लगा देगा अथवा दण्डात्मक कार्रवाई कर सकता है। इससे लोकतंत्र का दर्शन जाता रहेगा। इससे सकारात्मक भीड़ (अच्छे परिवर्तन हेतु एकत्रित) एवं नकारात्मक भीड़ का विभेद ही समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जब कार्रवाई मौजूदा पुलिस को ही करनी है, तो चाहे कितने भी कानून क्यों न बना दिए जाए स्थिति ढाक के तीन पात वाली ही रहेगी। अतः आवश्यकता राजनीतिक इच्छाशक्ति और पुलिस की दक्षता बढ़ाने की है न कि नए कानून बना कर कर्तव्यों के इतिश्री कर लेने की।

### मॉब लिंग पर उच्चतम न्यायालय का दिशा-निर्देश

- ◆ 17 जुलाई, 2018 को भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने देश में भीड़ द्वारा की जा रही हिंसा से निपटने हेतु दिशा-निर्देश दिया।
- ◆ इसमें घटना को होने से पूर्व ही रोक देने (निवारक) संबंधी निर्देश, घटना की स्थिति में सहायता देने (उपचारात्मक) संबंधी निर्देश तथा लापरवाही हेतु दण्डात्मक निर्देश दिए गए हैं।

### निवारक उपाय (Preventive Measures)

- ◆ प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक (SP) रैंक के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाए, जो पुलिस उपाधीक्षक (DSP) रैंक के सहायक अधिकारी की सहायता से भीड़ हिंसा को रोकने का कार्य करे।
- ◆ नोडल अधिकारी इंटेलिजेंस अधिकारियों तथा थाना प्रभारियों के साथ नियमित बैठक (महीने में कम-से-कम एक) करेगा तथा भीड़ हिंसा के विरुद्ध आवश्यक कदम उठाएगा।
- ◆ सभी राज्य निर्णय के तीन सप्ताह के भीतर उन सभी जिलों/संभागों/ग्रामों की पहचान करेंगे, जहां पिछले पांच वर्षों में भीड़ हिंसा की घटना घटी हो।
- ◆ पुलिस महानिदेशक (DGP) अथवा गृह सचिव प्रत्येक तिमाही में कम-से-कम एक बार सभी नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा करेंगे।
- ◆ पुलिस अधिकारी CrPC की धारा 129 का प्रयोग करते हुए उस भीड़ को जिसमें हिंसा की प्रवृत्ति हो, को तुरंत तितर-बितर करेंगे।
- ◆ केंद्रीय गृह मंत्रालय सभी राज्यों के सहयोग से भीड़ हिंसा के कारणों की पहचान करे तथा विधि के शासन को सुनिश्चित कराए।
- ◆ सभी संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग को सुनिश्चित कराया जाए।
- ◆ केंद्र एवं राज्य सरकारें रेडियो, टेलीविजन सहित समस्त संचार माध्यमों से यह प्रसारित करवाए कि मॉब लिंग गंभीर अपराध है।

◆ केंद्र एवं राज्य सरकारें उन समस्त संदेशों, चलचित्र एवं अन्य सामग्रियों जिनसे घृणा तथा हिंसा फैल सकती है, को फैलने से रोके।

◆ ऐसे संदेशों को प्रसारित करने को भी IPC की धारा 153A के तहत FIR का आधार बनाया जा सकता है।

#### **उपचारात्मक उपाय (Remedial Measures)**

◆ भीड़ हिंसा अथवा लिंगिग की कोई भी घटना प्रकाश में आने के तुरंत बाद बिना किसी देर किए पुलिस द्वारा FIR दर्ज किया जाएगा।

◆ जिस थाने में FIR दर्ज किया जाएगा, के थाना प्रभारी का यह दायित्व होगा कि वे जिले के नोडल अधिकारी को सूचित करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि पीड़ित परिवार के किसी भी सदस्य को हानि न पहुंचे।

◆ नोडल अधिकारी व्यक्तिगत रूप से ऐसी घटनाओं की विवेचना की निगरानी करेंगे।

◆ इस निर्णय से एक महीने के भीतर CrPC की धारा 357A (पीड़ित मुआवजा योजना) के तहत राज्य सरकारें भीड़ हिंसा से पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की योजना तैयार करेंगी।

◆ पीड़ितों के मुआवजे का आकलन व्यापक दृष्टिकोण के साथ किया जाएगा, जिसमें शारीरिक क्षति के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक क्षति, रोजगार अवसरों की क्षति, शिक्षा की क्षति, उपचार तथा कानूनी प्रक्रिया पर क्षति आदि शामिल होगा। इसे पीड़ित को अंतरिम राहत के रूप में हिंसा से तीस दिनों के भीतर प्रदान कर दिया जाए।

◆ ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 6 माह के भीतर निपटाया जाए।

◆ ऐसे केसों के गवाहों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।

◆ पीड़ित अथवा उसका परिवार ऐसे मामलों में निःशुल्क विधिक सहायता पाने का भी पात्र है।

#### **दण्डात्मक उपाय (Punitive Measures)**

◆ उच्चतम न्यायालय ने अधिकारियों के दायित्व को भी निर्धारित करने हेतु निर्देश दिया है।

◆ यदि कोई पुलिस अधिकारी अथवा जिला प्रशासन का कोई अधिकारी मॉब लिंगिग के संदर्भ में उक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे जान-बूझकर लापरवाही माना जाएगा तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

◆ यदि कोई अधिकारी पूर्व सूचना होने के बावजूद भी भीड़ हिंसा की घटनाओं को रोकने हेतु आवश्यक कदम नहीं उठाता है अथवा जहां पर ऐसी घटना घट चुकी हो और अधिकारी अभियुक्त के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही नहीं करता है, के भी खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

#### **भीड़ हिंसा की रोकथाम हेतु गठित समिति**

◆ भीड़ हिंसा से निपटने से संबंधित उपाय सुझाने हेतु भारत सरकार द्वारा जुलाई, 2018 में केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई।

◆ न्याय विभाग, कानूनी मामले विभाग, विधायी विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव इस समिति के सदस्य हैं।

◆ समिति को चार सप्ताह में अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करना है।

◆ इस समिति की अनुशंसाओं पर विचार गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी मंत्रि समूह द्वारा किया जाएगा।

◆ इसमें विदेश मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, नौवहन, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री, कानून व न्याय मंत्री तथा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सदस्य होंगे।

#### **संस्थागत न्याय ही समाधान है**

न्याय का मौजूदा बहुस्तरीय स्वरूप लंबे अनुभवों के बाद आया है। मौजूदा प्रणाली में दण्ड-प्रक्रिया को वस्तुनिष्ठ (सभी के लिए एक समान) रखा गया है तथा न्याय पाने को बहुस्तरीय। इस व्यवस्था में आरोपी को अपना पक्ष रखने का भी पूरा अवसर दिया जाता है तथा न्याय में एक स्तर पर चूक को दूसरे स्तर पर सुधार का विकल्प भी मिलता है। भले ही न्यायिक प्रक्रिया में विलंब होता हो, परंतु इससे किसी को भी यह अधिकार नहीं मिल जाता है कि वह समानांतर प्रणाली बनाकर न्याय करने लगे। चाहे वह कोई संगठन हो या व्यक्तियों का असंगठित समूह। बहुमत को भी न्याय का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। भारत में भीड़ द्वारा की जा रही हिंसात्मक घटनाओं पर तुरंत लगाम लगाने की आवश्यकता है, नहीं तो ये देश में गलत परंपराओं को जन्म दे देंगी। शासन, प्रशासन तथा न्यायालय स्तर से सख्त संदेश दिया जाना चाहिए कि किसी का भी अपराध कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे दण्ड देने का अधिकार केवल और केवल न्यायालय को है। यदि भीड़ न्याय पर नियंत्रण नहीं लगाया जाता है, तो यह धीरे-धीरे भारत को एक संयुक्त एवं सौहार्द्रपूर्ण भारत से परस्पर विद्वेषों से भरे सामुदायिक समूहों वाले भारत में रूपांतरित कर देगा। इस संदर्भ में कवि कैलाश 'असोनिया' की चेतावनी काफी प्रासंगिक प्रतीत होती है।

न्याय के मंदिर से, क्या उठ रहा भरोसा है;

इस मंदिर का पुजारी, क्यों हुआ अब झूठा है;

यदि यही होता रहा तो, मानवता कहां बच पाएगी;

एक उन्मत्त भीड़ ही, न्याय का उपहास उड़ाएगी।

### अटल बिहारी वाजपेयी : निधन

#### □ वर्तमान परिप्रेक्ष्य

16 अगस्त, 2018 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 93 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, विशाल व्यक्तित्व वाले वाजपेयी जी को उनकी दूरगामी सोच, उनकी कविताओं, पोखरण परमाणु विस्फोट, कारगिल में भारत की विजय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का गौरव बढ़ाने के लिए याद किया जाता रहा है।

#### □ प्रारंभिक जीवन परिचय

➔ 25 दिसंबर, 1924 को ग्वालियर के एक निम्न मध्यमवर्गीय परिवार में जन्में वाजपेयी जी ने ग्वालियर के ही विक्टोरिया (अब लक्ष्मीबाई) कॉलेज और कानपुर के डीएवी कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी।

- ➔ उन्होंने राजनीति विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर किया तथा पत्रकारिता में अपना कैरियर शुरू किया।
- ➔ इस दौरान उन्होंने राष्ट्र धर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन का संपादन किया।
- ➔ ये युवावस्था से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे तथा आजीवन अविवाहित रहते हुए संपूर्ण जीवन देश को समर्पित कर दिया।

#### □ राजनीतिक यात्रा

➔ अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक यात्रा एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में होती है। उन्होंने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गए।  
➔ वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य बने। कालांतर में वर्ष 1968 से 1973 तक इसके अध्यक्ष भी रहे।

- ➔ वर्ष 1957 में वे बलरामपुर से लोक सभा चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे। अगले पांच दशकों के उनके संसदीय कैरियर की

यह शुरुआत थी।

- ➔ वर्ष 1977 में उन्हें मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री बनाया गया। इस दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 32वें अधिवेशन में हिंदी में भाषण दिया था। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय राजनेता थे।
- ➔ वर्ष 1980 में वे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे तथा वर्ष 1980 से 1986 तक इसके अध्यक्ष भी रहे।
- ➔ वे 1962 से 1967 और वर्ष 1986 में राज्य सभा के सदस्य भी रहे।
- ➔ 16 मई, 1996 को वो पहली बार प्रधानमंत्री बने, किंतु लोक सभा में बहुमत न सिद्ध कर पाने की वजह से 31 मई, 1996 को त्याग-पत्र देना पड़ा।

➔ वर्ष 1998 में सहयोगी पार्टियों के साथ गठबंधन कर वे पुनः प्रधानमंत्री बने, लेकिन AIADMK द्वारा समर्थन वापस लेने से उनकी सरकार गिर गई।  
➔ वर्ष 1999 में उनके नेतृत्व में गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ तथा एक बार फिर वे प्रधानमंत्री बने।

➔ इस प्रकार वर्ष 1996 में 13 दिन के लिए, वर्ष 1998-99 में 13 महीने के लिए तथा वर्ष 1999-2004 के दौरान पूरे पांच वर्ष के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे।

➔ प्रधानमंत्री के रूप में पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले वे पहले गैर-कांग्रेसी थे।

➔ वर्ष 2004 के लोक सभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

➔ वर्ष 2005 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी।

#### □ प्रमुख कार्य

अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में राजस्थान स्थित पोखरण में मई, 1998 में किया गया परमाणु परीक्षण प्रमुख स्थान रखता है।



वर्ष 1951 में जनसंघ के संस्थापक सदस्य बने



स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आरंभ की

1996 में 13 दिन, वर्ष 1998 में 13 महीने के लिए, तथा वर्ष 1999 में पूरे 5 वर्ष के लिए भारत के प्रधानमंत्री



मई, 1998 में पोखरण विस्फोट प्रसिद्ध काव्य संग्रह : मेरी इक्यावन कविताएं



16 अगस्त, 2018 को मृत्यु

आरेखीय चित्र : अटल बिहारी वाजपेयी का निधन

- ❖ विश्व के अनेक देशों द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद उन्होंने अपनी कूटनीतिक क्षमता से विश्व जनमत को अपने पक्ष में किया तथा भारत को एक जिम्मेदार परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया।
- ➔ कारगिल युद्ध तथा युद्ध में मिली विजय उनके कार्यकाल की प्रमुख घटना रही।
- ❖ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के माध्यम से उन्होंने पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया।
- ❖ वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई, जिसका परिणाम आज सबके सामने है।
- ❖ वर्ष 1999 में उन्होंने पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार की पहल की तथा सदा-ए-सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस यात्रा की शुरुआत की।

### ❑ एक कवि के रूप में

अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिज्ञ के साथ-साथ कवि भी थे। उनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह 'मेरी इक्यावन कविताएं' है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में 'संसद में तीन दशक', 'राजनीति की रपटीली राहें', 'सेक्युलरवाद' आदि हैं।

जीवन परिचय	
जन्म	: 25 दिसंबर, 1924, ग्वालियर (मध्यप्रदेश)
पिता	: कृष्ण बिहारी वाजपेयी
माता	: कृष्णा देवी
पुत्री	: नमिता (गोद ली हुई)
सम्मान/पुरस्कार	: पद्मविभूषण 1992 लोकमान्य तिलक अवॉर्ड 1994 सर्वश्रेष्ठ सांसद 1994 पं. गोविंद बल्लभ पंत अवॉर्ड 1994 भारत रत्न 2015
मृत्यु	: 16 अगस्त, 2018
संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीयों द्वारा हिंदी में भाषण	
❖ वर्ष 1977 में सर्वप्रथम तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी।	
❖ वर्ष 1988 में तत्कालीन विदेश मंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव।	
❖ वर्ष 2012 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेन्द्र यादव।	
❖ वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।	
❖ वर्ष 2016 एवं 2017 में विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज।	

सं. कालीशंकर 'शारदेय'

## भारत स्मार्ट शहर अध्येतावृत्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रम

### ❑ वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➔ 9 जुलाई, 2018 को आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने 'अमृत' (AMRUT : Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) और स्मार्ट सिटीज मिशन (Smart Cities Mission) के तहत कुछ नई पहलों का शुभारंभ किया।

➔ ये नई पहले हैं:-

- ❖ 'भारत स्मार्ट शहर अध्येतावृत्ति' (ISCF : India Smart Cities Fellowship) कार्यक्रम,
- ❖ 'भारत स्मार्ट शहर प्रशिक्षण (ISCI : India Smart Cities Internship) कार्यक्रम,
- ❖ 'स्मार्ट शहर डिजिटल भुगतान पुरस्कार, 2018' (SCDPA : Smart Cities Digital Payments Awards, 2018),
- ❖ 'नवप्रवर्तन, एकीकरण और स्थायित्व हेतु शहरों में निवेश (CITIIS : Cities Investment to Innovate, Integrate and Sustain) और
- ❖ क्षेत्र आधारित अवसंरचना मामलों के शीघ्र समाधान हेतु

प्रारोगिक आधार पर 25 शहरों में स्थानीय क्षेत्र योजना (LAP)/ कस्बा नियोजन योजना (TPS)।

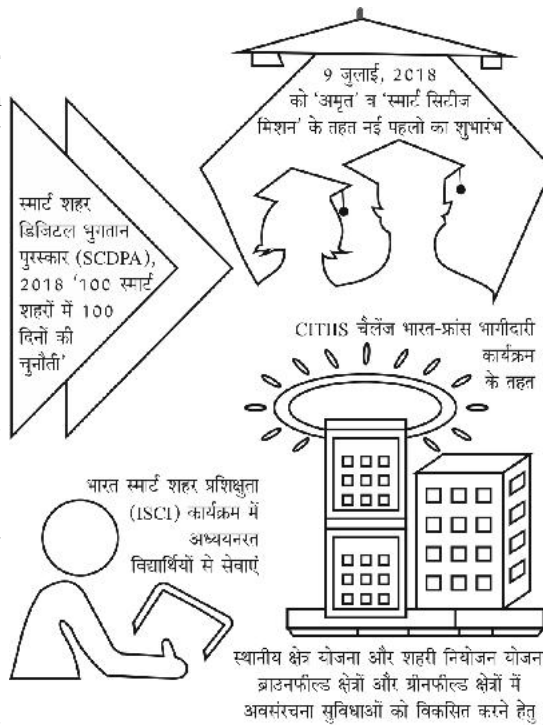
### ❑ भारत स्मार्ट शहर अध्येतावृत्ति (ISCF) कार्यक्रम

➔ भारत स्मार्ट शहर अध्येतावृत्ति कार्यक्रम का निर्माण विशेष रूप से स्मार्ट शहर और सामान्य रूप से शहरी नवीकरण क्षेत्र में इच्छुक युवाओं को मूल्यवान अनुभव प्रदान करने के लिए किया गया है।

❖ इस कार्यक्रम के तहत आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा शहरी नियोजन, शहरी डिजाइन, इंजीनियरिंग, सूचना तथा प्रौद्योगिकी, शहरी गतिशीलता, वित्त, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों के क्षेत्र में 'स्मार्ट शहर अध्येता' (Smart Cities Fellows) के रूप में 30 युवा स्नातकों/अधिस्नातकों (Post Graduates) तथा पीएचडी उपाधि धारकों (PhDs) को नियुक्त किया जाएगा।

❖ नियुक्ति की अवधि एक वर्ष होगी, जिसे बढ़ाकर तीन वर्ष किया जा सकेगा।

❖ चयनित स्मार्ट शहर अध्येताओं को 60000 रुपये की समेकित राशि प्रतिमाह प्रति अध्येता प्रदान की जाएगी।



आरेखीय चित्र : भारत स्मार्ट शहर अध्येतावृत्ति एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

➔ ये अध्येता आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय में स्मार्ट शहर, मिशन निदेशक कार्यालय और/अथवा चयनित स्मार्ट शहरों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEOs) को विश्लेषण, अनुसंधान, प्रलेखन, स्वतंत्र आकलन आदि क्षेत्रों में आवश्यक समर्थन प्रदान करेंगे।

#### □ भारत स्मार्ट शहर प्रशिक्षुता (ISCI) कार्यक्रम

➔ इस कार्यक्रम के तहत आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों/शहरों में स्मार्ट शहर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता के लिए पूर्व स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि हेतु अध्ययनरत विद्यार्थियों की सेवाएं 'प्रशिक्षु' (Intern) के रूप में ली जाएगी।

➔ प्रशिक्षुता 6 से 12 सप्ताह की अवधि के लिए अवैतनिक आधार पर होगी।

- कार्यक्रम के सफल समापन पर प्रशिक्षुओं को अनुभव प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- प्रशिक्षुओं को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकास के अनेक क्षेत्रों में आवश्यक जानकारीयां प्रदान की जाएगी, जिनमें शहरी नियोजन, शहरी डिजाइन, इंजीनियरिंग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, शहरी गतिशीलता, वित्त, सामाजिक क्षेत्र और पर्यावरणीय मुद्दे शामिल हैं।
- ये प्रशिक्षु स्मार्ट सिटी मिशन के भाग होंगे और उनकी मुख्य भूमिका कार्यान्वयन/रिपोर्टिंग/आकलन एवं निगरानी/ज्ञान प्रबंधन/हितधारक सहभागिता/मीडिया तक पहुंच आदि में होगी।
- प्रशिक्षुओं का चयन मिशन निदेशक (स्मार्ट सिटी मिशन) द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

#### □ स्मार्ट शहर डिजिटल भुगतान पुरस्कार (SCDPA), 2018

➔ स्मार्ट शहर डिजिटल भुगतान पुरस्कार, 2018 '100 स्मार्ट शहरों में 100 दिनों की चुनौती' (100 Days Challenge in 100 Smart Cities) आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य भारत के शहरी क्षेत्र के निवासियों के जीवन को आसान बनाना है।

➔ इन पुरस्कारों का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और अपने-अपने शहरों में अभिनव भुगतान पहलों को कार्यान्वित करने के लिए स्मार्ट शहरों को प्रेरित और पुरस्कृत करना है।

- यह कार्यक्रम न केवल डिजिटल भुगतान में अग्रणी शहरों को पुरस्कृत करेगा, बल्कि अन्य शहरों को भी अपने यहां डिजिटल भुगतान ढांचे को अपनाने, डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल लेन-देन के लिए नागरिकों को अनेक विकल्प देने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

➔ आकलन के उद्देश्य से स्मार्ट शहरों को उनकी जनसंख्या के आधार पर चार विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा।

- ये श्रेणियां हैं— प्रथम श्रेणी- 5 लाख से कम जनसंख्या, द्वितीय श्रेणी-5-10 लाख जनसंख्या, तृतीय श्रेणी-1-4 मिलियन जनसंख्या और चतुर्थ श्रेणी-4 मिलियन से अधिक जनसंख्या।
- प्रत्येक श्रेणी में तीन पुरस्कार दिए जाएंगे। इस प्रकार इस कार्यक्रम के तहत कुल 12 पुरस्कार दिए जाएंगे।

○ ये पुरस्कार हैं— सर्वोत्तम डिजिटल भुगतान अनुकूलक, सर्वोत्तम डिजिटल भुगतान अन्वेषक और डिजिटल भुगतान पर केंद्रित सर्वाधिक प्रगतिशील स्मार्ट शहर।

#### □ नवप्रवर्तन, एकीकरण और स्थायित्व हेतु शहरों में निवेश (CITIIS) चैलेंज

➔ 25 जून, 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन के शुभारंभ के दौरान 100 स्मार्ट शहरों के चयन के लिए एक प्रतिस्पर्धी चुनौती प्रक्रिया का उपयोग किया गया था।

➔ अब चुनौती प्रक्रिया को नीति आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है।

➔ भारत-फ्रांस भागीदारी कार्यक्रम के तहत न्यूनतम 15 परियोजनाओं का अखिल भारतीय चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा।

- इस कार्यक्रम की अवधि तीन वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक) होगी।

➔ भारत-फ्रांस भागीदारी के तहत परियोजनाओं के चयन के लिए चुनौती प्रक्रिया का संचालन 'राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान' द्वारा किया जाएगा।

#### □ स्थानीय क्षेत्र योजना (LAP) और कस्बा नियोजन योजना (TPS)

➔ स्थानीय क्षेत्र योजना और कस्बा नियोजन योजना को 'अमृत' (AMRUT) मिशन के तहत तैयार किया गया है, जिससे क्रमशः ब्राउनफील्ड क्षेत्रों (Brownfield Areas) और ग्रीनफील्ड क्षेत्रों (Greenfield Areas) में अवसंरचना सुविधाओं को विकसित करने के लिए समुचित नियोजन सुनिश्चित किया जा सके।

- उल्लेखनीय है कि ब्राउनफील्ड क्षेत्र शहर के वे हिस्से हैं जो पहले ही विकसित हो चुके हैं, किंतु मौजूदा अवसंरचना सुविधाओं पर पड़ रहे दबाव को सहन करने में सक्षम नहीं हैं।
- ग्रीनफील्ड क्षेत्र शहर की परिधि के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र हैं, जहां बेतरतीब वृद्धि और विकास की आशंका रहती है।
- इन योजनाओं का कार्यान्वयन प्रायोगिक आधार पर 25 चयनित शहरों में किया जाएगा।
- यह योजना चयनित शहरों को स्थानीय क्षेत्र आधारित योजनाएं और कस्बा नियोजन योजनाएं बनाने के लिए सक्षम करेगी, जिसके लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता उपलब्ध होगी।

#### □ निष्कर्ष

भारत सरकार द्वारा प्रारंभ स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य नागरिकों को मूलभूत अवसंरचना एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन उपलब्ध कराने हेतु शहरों को प्रोत्साहित करना है। अमृत मिशन के तहत सरकार द्वारा शहरों में मूलभूत सेवाओं (जैसे-जलापूर्ति, सीवेज, शहरी यातायात) को उपलब्ध कराया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत मिशन के तहत सद्यः प्रारंभ चारों कार्यक्रमों से शहरों में अवसंरचना सुविधाओं एवं सेवाओं को उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

सं. नीरज ओझा

# खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, वर्ष 2018-19

## □ वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➔ आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 4 जुलाई, 2018 को स्वीकृत वर्ष 2018-19 के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ऐतिहासिक है, क्योंकि यह केंद्रीय बजट 2018-19 में घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन लागत के मुकाबले कम-से-कम 150 प्रतिशत रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत के वादे को पूरा करता है।

➔ यह वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने हेतु कृषि नीति में बदलाव को इंगित करता है, जिसके तहत किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

## □ प्रमुख घोषणाएं

➔ वर्ष 2017-18 के मुकाबले वर्ष 2018-19 के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि (52.47%) रागी के मूल्य में की गई है।

- ☉ जबकि सभी खरीफ फसलों में से सर्वाधिक मूल्य वृद्धि (1827 रुपये) राम तिल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई है।



आरेखीय चित्र : खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, 2018-19

## खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (रुपये प्रति कुंतल)

फसलें	वर्ष 2017-18 के लिए एमएसपी (रुपये में)	वर्ष 2018-19 के लिए एमएसपी (रुपये में)	वृद्धि		लागत* के मुकाबले प्रतिफल (Return) (प्रतिशत में)
			शुद्ध (रुपये में)	प्रतिशत	
धान (सामान्य)	1550	1750	200	12.90	50.09
धान (ब्रेड-ए)	1590	1770	180	11.32	51.80
ज्वार (हाइब्रिड)	1700	2430	730	42.94	50.09
ज्वार (मालदांडी)	1725	2450	725	42.3	51.33
बाजरा	1425	1950	525	36.84	96.97
रागी	1900	2897	997	52.47	50.01
मक्का	1425	1700	275	19.30	50.31
अरहर (तूर)	5450	5675	225	4.13	65.36
मूंग	5575	6975	1400	25.11	50.00
उड़द	5400	5600	200	3.70	62.89
मूंगफली	4450	4890	440	9.89	50.00
सूरजमुखी	4100	5388	1288	31.42	50.01
सोयाबीन	3050	3399	349	11.44	50.01
तिल	5300	6249	949	17.91	50.01
नाइजर सीड (राम तिल)	4050	5877	1827	45.11	50.01
कपास (मध्यम रेशा)	4020	5150	1130	28.11	50.01
कपास (लंबा रेशा)	4320	5450	1130	26.16	58.75

\*लागत में सभी लागत जैसे- मजदूरी, पशुश्रम/मशीन श्रम, भूमि का पट्टा/किराया, बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई लागत, अवमूल्यन एवं विविध कृषि खर्च तथा परिवार के सदस्यों के श्रम की लागत शामिल हैं।



➔ वर्ष 2018-19 के लिए घोषित एमएसपी में लागत के मुकाबले सर्वाधिक प्रतिफल (लागत का 196.97प्रतिशत) बाजरे में प्राप्त होगा।  
➔ दलहन में अरहर (तूर) के एमएसपी (MSP) में 225 रुपये की वृद्धि की गई है, जिससे लागत के मुकाबले उसके प्रतिफल (Return) में 65.36 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

- ➔ इसी प्रकार उड़द के लिए उसकी लागत के मुकाबले रिटर्न में 62.89 प्रतिशत की वृद्धि के लिए उसकी एमएसपी में 200 रुपये प्रति कुंतल की वृद्धि की गई है।
- ➔ उल्लेखनीय है कि दलहन की खेती को बढ़ावा दिए जाने से भारत में पोषण असुरक्षा से निपटने, मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने तथा किसानों की आय में वृद्धि हेतु मदद मिलेगी।
- ➔ वर्ष 2018-19 की खरीफ फसलों हेतु घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य में तिलहनी फसलों के एमएसपी में काफी वृद्धि की गई है। इस वृद्धि से तिलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तथा इन फसलों हेतु निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
- ➔ ध्यातव्य है कि तिलहन उत्पादन में वृद्धि होने से भारत सरकार को अपना आयात व्यय घटाने में भी मदद मिलेगी।

➔ उल्लेखनीय है कि भारत अपने सकल आयात व्यय का एक बड़ा हिस्सा (वर्ष 2016-17 में 2.8%) खाद्य तेलों के आयात पर व्यय करता है।

### □ किसानों को लाभ

- ➔ न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कृषि की लाभदेयता में वृद्धि करेगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
- ➔ वर्ष 2018-19 हेतु घोषित खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दलहन एवं तिलहन उत्पादों को प्रोत्साहित करने वाला प्रतीत होता है।
  - ➔ इससे एक ओर भारत में पोषण स्तर में सुधार होगा तो दूसरी ओर दलहन एवं तिलहन उत्पादों हेतु भारत की आयात पर निर्भरता में कमी आएगी।
- ➔ भारतीय किसानों की कृषि आय में वृद्धि से जहां एक ओर भारतीय कृषि का विविधीकरण होगा, वहीं कृषि अधिक धारणीय एवं पर्यावरण के अनुकूल होगी।
- ➔ कृषि की लाभदेयता में वृद्धि कृषि क्षेत्र में निवेश एवं नवप्रवर्तन को भी बढ़ाएगी।

सं. शिवशंकर कुमार तिवारी

## उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों की घोषणा

### □ वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➔ 9 जुलाई, 2018 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 6 शैक्षणिक संस्थानों को 'उत्कृष्ट संस्थान' (Institution of Eminence) घोषित किया।

### □ उद्देश्य

➔ इस घोषणा के फलस्वरूप चयनित संस्थानों को पूर्ण स्वायत्तता की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सकेगी तथा वे अधिक तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे।

- ➔ साथ ही इस कदम से इन संस्थानों को गुणवत्ता में सुधार के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे वे शिक्षा के क्षेत्र में विश्वस्तरीय संस्थान बन सकेंगे।

### □ संस्थानों का विवरण

➔ मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी सूची में 3 सार्वजनिक क्षेत्र के और 3 निजी संस्थान शामिल हैं।

#### ➔ सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान हैं—

- (1) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु (कर्नाटक)

(2) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे (महाराष्ट्र)

(3) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली

#### ➔ निजी क्षेत्र के संस्थान हैं—

- (1) जियो इंस्टीट्यूट (रिलायंस फाउंडेशन), पुणे (महाराष्ट्र) (ग्रीनफील्ड श्रेणी के अंतर्गत)
- (2) बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, पिलानी (राजस्थान)
- (3) मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, मणिपाल (कर्नाटक)

### □ चयनित संस्थानों हेतु प्रावधान

➔ उत्कृष्ट संस्थान के रूप में चयनित प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान को 5 वर्षों की अवधि में 1000 करोड़ रु. तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

➔ इन संस्थानों में 30 प्रतिशत विदेशी छात्रों का दाखिला संभव हो सकेगा।

➔ इन संस्थानों में 25 प्रतिशत तक विदेशी शिक्षक भर्ती किए जा सकेंगे।

➔ ये संस्थान अपने कुल कार्यक्रमों में से 20 प्रतिशत ऑनलाइन पाठ्यक्रम के



एन. गोपालस्वामी की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन

5 वर्षों की अवधि में 1000 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता



आरेखीय चित्र : उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों की घोषणा

रूप में संचालित कर सकेंगे।

➔ इन संस्थानों को बिना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की स्वीकृति के विश्व रैंकिंग में शीर्ष 500 संस्थानों के साथ अकादमिक सहयोग स्थापित करने का अधिकार होगा।

### □ पृष्ठभूमि

➔ हाल ही में केंद्र सरकार ने 20 संस्थानों (10 सार्वजनिक क्षेत्र से तथा 10 निजी क्षेत्र से) की स्थापना/उन्नयन हेतु विनियामक प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु एक योजना को मंजूरी प्रदान की थी।

- ➔ विश्वस्तरीय शिक्षण तथा अनुसंधान संस्थानों के रूप में स्थापित/अपग्रेड होने वाले इन संस्थानों को 'उत्कृष्टता संस्थान' (Institutions of Eminence) के रूप में जाना जाएगा।
- ➔ इस योजना के अंतर्गत उत्कृष्टता संस्थान के रूप में चयन हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 114 आवेदन प्राप्त हुए।

- ➔ उत्कृष्टता संस्थानों के चयन हेतु एन. गोपालस्वामी की अध्यक्षता में एक सशक्त विशेषज्ञ समिति (EEC) का गठन किया गया।
- ➔ समिति ने अपनी रिपोर्ट में केवल 6 संस्थानों (3 सार्वजनिक क्षेत्र से तथा 3 निजी क्षेत्र से) के ही उत्कृष्टता संस्थान के रूप में चयन हेतु सिफारिश की।

### □ निष्कर्ष

- ➔ ऐसी उम्मीद है कि चयनित संस्थान अगले 10 वर्षों में विश्व रैंकिंग में शीर्ष 500 संस्थानों में शामिल हो सकेंगे।
- ➔ साथ ही उत्तरोत्तर ये संस्थान शीर्ष 100 संस्थानों में भी स्थान बनाने में सक्षम हो सकेंगे।
- ➔ उल्लेखनीय है कि भारत के लगभग 800 विश्वविद्यालयों में से एक भी विश्वविद्यालय विश्व रैंकिंग में शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में शामिल नहीं है।

सं. सौरभ मेहरोत्रा

## वैश्विक दासता सूचकांक, 2018

### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➔ 19 जुलाई, 2018 को 'वॉक फ्री फाउंडेशन' (Walk Free Foundation) नामक संगठन द्वारा 'वैश्विक दासता सूचकांक, 2018' (Global Slavery Index, 2018) जारी किया गया।

### उद्देश्य

➔ वैश्विक दासता सूचकांक के अंतर्गत विश्व के विभिन्न देशों में आधुनिक दासता (Modern Slavery) के प्रसार का मापन किया जाता है, साथ ही इस मुद्दे से निपटने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों का विश्लेषण भी प्रस्तुत किया जाता है।

➔ वर्ष 2018 के वैश्विक दासता सूचकांक में विश्व के 167 देशों को आधुनिक दासता के बंधन में जकड़े लोगों की संख्या के आधार पर रैंक प्रदान की गई है।

### क्या है आधुनिक दासता?

➔ वॉक फ्री फाउंडेशन के अनुसार, आधुनिक दासता एक व्यापक पद है तथा इसकी परिभाषा के अंतर्गत बलात श्रम, मानव तस्करी, जबरन विवाह के फलस्वरूप दासता जैसे मुद्दों को शामिल किया जा सकता है।

➔ वास्तव में आधुनिक दासता शब्द शोषण की ऐसी स्थितियों को

संदर्भित करता है, जिसमें कोई व्यक्ति धमकी, हिंसा तथा जबरदस्ती आदि कारणों से शोषण से न तो उबर पाता है न ही इसका विरोध कर पाता है।



उज्वला योजना तस्करी की शिकार महिलाओं के पुर्नवास हेतु



वैश्विक दासता के बंधन में जकड़े लोगों की कुल संख्या के संदर्भ में भारत शीर्ष स्थान पर

आधुनिक दासता के सर्वाधिक मामले उत्तर कोरिया में

सूचकांक में भारत 53वें स्थान पर

आरेखीय चित्र : वैश्विक दासता सूचकांक, 2018

➔ रिपोर्ट के अनुसार, विगत वर्षों में आधुनिक दासता के मामले वस्त्र निर्माण, खनन, कृषि आदि उद्योगों में दृष्टिगत हुए हैं।

### रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

➔ वैश्विक दासता सूचकांक, 2018 के अनुसार, वर्ष 2016 में विश्व में अनुमानित 40.3 मिलियन लोग आधुनिक दासता के बंधन में जकड़े हुए थे, इनमें से लगभग 71 प्रतिशत महिलाएं थीं।

➔ रिपोर्ट के अनुसार, आधुनिक दासता के सर्वाधिक मामले उत्तर कोरिया में दर्ज किए गए हैं, यहां प्रति 10 में से एक व्यक्ति आधुनिक दासता का शिकार है।

➔ वैश्विक स्तर पर प्रति 1000 व्यक्तियों पर 5.4 लोग आधुनिक दासता के शिकार हैं।

➔ क्षेत्रीय दृष्टि से, आधुनिक दासता के मामलों की संख्या के संदर्भ में अफ्रीका महाद्वीप शीर्ष पर है।

➔ यहां प्रति 1000 व्यक्तियों पर 7.6 लोग आधुनिक दासता के शिकार हैं।

- ⦿ वर्ष 2016 में एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में आधुनिक दासता का जीवन जी रहे लोगों की अनुमानित संख्या 24.9 मिलियन है।
- ⦿ यहां प्रति हजार पर 6.1 व्यक्ति आधुनिक दासता के शिकार हैं।

### रैंकिंग

- ➔ वैश्विक दासता सूचकांक, 2018 में 167 देशों की सूची में उत्तर कोरिया शीर्ष स्थान पर है।
- ➔ यहां प्रति 1000 जनसंख्या पर 104.6 लोग आधुनिक दासता का जीवन जी रहे हैं।
- ⦿ सूचकांक में जापान अंतिम (167 वें) स्थान पर है, यहां प्रति 1000 जनसंख्या पर मात्र 0.3 व्यक्ति ही आधुनिक दासता के शिकार हैं।

वैश्विक दासता सूचकांक, 2018 : शीर्ष 5 देश		
रैंक	देश	आधुनिक दासता के अनुमानित मामले (प्रति 1000 जनसंख्या)
1.	उत्तर कोरिया	104.6
2.	इरीट्रिया	93.0
3.	बुरुंडी	40.0
4.	मध्य अफ्रीकी गणराज्य	22.3
5.	अफगानिस्तान	22.2

### □ भारत की स्थिति

- ➔ वैश्विक दासता सूचकांक, 2018 में 167 देशों की सूची में भारत 53वें स्थान पर है।
- ➔ यहां प्रति 1000 जनसंख्या पर आधुनिक दासता का जीवन जी रहे लोगों की संख्या 6.1 है।
- ⦿ वर्ष 2018 के सूचकांक के अनुसार, वर्ष 2016 में भारत में लगभग 80 लाख लोग आधुनिक दासता का जीवन जी रहे थे, जो कि विश्व में सर्वाधिक हैं।
- ⦿ उल्लेखनीय है कि दो वर्ष पूर्व भारत में आधुनिक दासता के शिकार लोगों की संख्या 1.83 करोड़ थी।
- ⦿ विश्व में आधुनिक दासता के बंधन में जकड़े लोगों की कुल संख्या के संदर्भ में शीर्ष 10 देश क्रमशः हैं- भारत, चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, नाइजीरिया, ईरान, इंडोनेशिया, कांगो, रूस तथा फिलीपींस।

### □ भारत : आधुनिक दासता के उन्मूलन हेतु प्रयास

- ➔ भारतीय दंड संहिता के तहत भारत द्वारा आधुनिक दासता के अधिकतर रूपों जैसे - मानव तस्करी, दासता, बलात् श्रम तथा बच्चों के यौन शोषण को अपराध घोषित किया गया है।
- ➔ हालांकि भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत, केवल अपहरण की स्थिति में ही जबरन विवाह (Forced Marriage) को अपराध घोषित किया गया है।
- ➔ व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक,

2018 को 18 जुलाई, 2018 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

- ⦿ यह विधेयक 26 जुलाई, 2018 को लोक सभा द्वारा पारित कर दिया गया।
- ⦿ इस विधेयक के तहत मानव तस्करी के मामलों की जांच और विधेयक के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए एक 'राष्ट्रीय तस्करी-रोधी ब्यूरो' (National Anti-Trafficking Bureau) की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- ➔ भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई उज्ज्वला योजना विशेष रूप से तस्करी की शिकार महिलाओं के पुनर्वास के लिए है।
- ⦿ जबकि इसी मंत्रालय की 'स्वाधार योजना' घरेलू हिंसा से पीड़ित, बेघर तथा संकटग्रस्त महिलाओं को सहायता सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु लक्षित है।
- ⦿ आधुनिक दासता से निपटने हेतु कई कानूनों एवं योजनाओं के अस्तित्व में होने के बावजूद भारत सरकार की नीति प्रतिबद्धताओं एवं कार्यान्वयन में कुछ अंतराल (Gap) दृष्टिगत हुए हैं, जिन्हें दूर कर भारत वैश्विक दासता सूचकांक में जापान एवं कनाडा जैसे कम आधुनिक दासता के मामलों वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो सकता है।

सं. सौरभ मेहरोत्रा

# विश्व बैंक : जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट

## □ पृष्ठभूमि

➔ जलवायु परिवर्तन की विश्वव्यापी समस्या दिनों-दिन गंभीर रूप धारण करती जा रही है। इसके कारण मानव जीवन स्तर में बदलाव की भयावह तस्वीर प्रकट होने लगी है। इसकी प्रवृत्ति में लगातार बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। भारत की बात की जाए, तो जहां एक ओर भारत की मानसून प्रणाली अव्यवस्थित होने से निरंतर बाढ़ एवं सूखा की प्रवृत्ति में तीव्रता देखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय कृषि व्यवस्था पर संकट उत्पन्न होने से देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष भी गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।

## □ वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➔ 28 जून, 2018 को विश्व बैंक द्वारा जारी 'दक्षिण एशिया के हॉटस्पॉट : तापमान एवं वर्षण में परिवर्तन का जीवन स्तर पर प्रभाव' (South Asia's Hotspots : Impacts of Temperature & Precipitation Changes on Living Standards) नामक रिपोर्ट जारी की गई।

➔ इस रिपोर्ट में दक्षिण एशिया तथा भारत पर जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों को प्रदर्शित किया गया है।

## □ रिपोर्ट

➔ विश्व बैंक द्वारा जारी यह रिपोर्ट स्थानिक जलवायु और घरेलू डेटा विश्लेषण का उपयोग करके सुभेद्य (Vulnerable) राज्यों और जिलों की पहचान करती है।

➔ रिपोर्ट द्वारा हॉटस्पॉट को उस स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां औसत तापमान और वर्षण (Precipitation) में परिवर्तन मानव जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

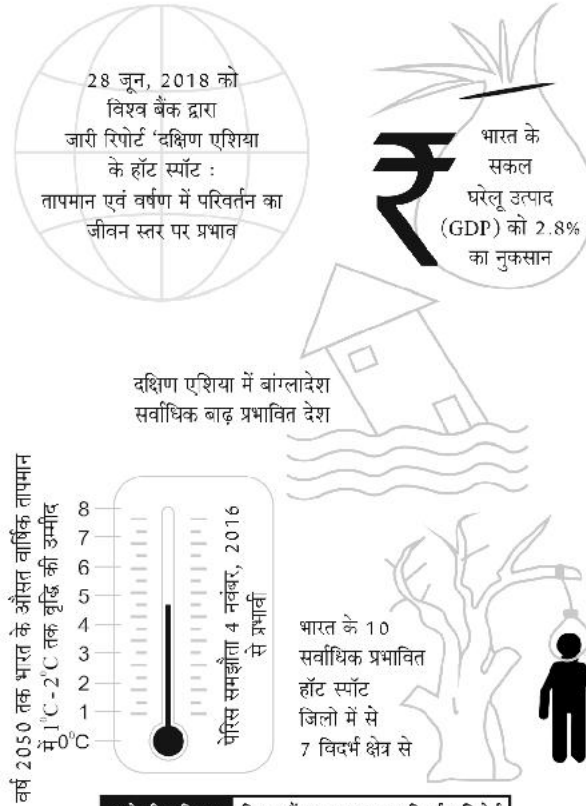
➔ ये हॉटस्पॉट न केवल अपने आस-पास के क्षेत्रों की तुलना में उच्च तापमान के क्षेत्र हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्थानीय आबादी की सामाजिक-आर्थिक क्षमता को भी प्रदर्शित करते हैं।

## □ रिपोर्ट में भारत

➔ विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ते तापमान और मानसूनी वर्षा के बदलते स्वरूप के कारण भारत के सकल घरेलू

उत्पाद (GDP) को 2.8 प्रतिशत का नुकसान हो सकता है।

- ➔ रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2050 तक भारत की लगभग आधी जनसंख्या के जीवन स्तर में गिरावट आने की संभावना है।
- ➔ वर्ष 2015 के पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते द्वारा अनुशंसित निवारक उपायों को अपनाने के बावजूद वर्ष 2050 तक भारत के औसत वार्षिक तापमान में 1.00 से 2 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि की उम्मीद है।
- ➔ यदि पेरिस समझौते द्वारा अनुशंसित उपायों को नहीं अपनाया जाता है, तो भारत के औसत तापमान में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना है।
- ➔ रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान समय में भारत में लगभग 600 मिलियन लोग ऐसे स्थानों पर निवास कर रहे हैं, जो वर्ष 2050 तक व्यापारिक-सामान्य परिदृश्य के तहत मध्यम (Moderate) अथवा गंभीर (Severe) हॉटस्पॉट बन सकते हैं।
- ➔ औसत तापमान और वर्षण में परिवर्तन के संदर्भ में भारत के मध्य, उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित राज्य सर्वाधिक सुभेद्य हैं।



आरेखीय चित्र : विश्व बैंक : जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट

➔ रिपोर्ट के विश्लेषण के अनुसार, वर्ष 2050 तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, शीर्ष दो जलवायु हॉटस्पॉट के रूप में उभर सकते हैं।

➔ इनके बाद क्रमशः राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का स्थान है।

➔ भारत के शीर्ष 10 सर्वाधिक प्रभावित हॉटस्पॉट जिलों में से 7 जिलों के महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से संबंधित होने की संभावना व्यक्त की गई है।

## □ रिपोर्ट में दक्षिण एशिया

➔ विश्व बैंक के दक्षिण एशिया क्षेत्र में मुख्य अर्थशास्त्री एवं लेखक मुथुकुमार मणि के अनुसार, इन मौसमी परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति खपत का स्तर कम हो जाएगा, जो दक्षिण एशिया में गरीबी और असमानता बढ़ाने के साथ दक्षिण एशिया को विश्व के सर्वाधिक गरीब क्षेत्रों में शामिल करा सकता है।

➔ यह रिपोर्ट दक्षिण एशिया के सभी देशों पर जलवायु परिवर्तन के संभावित

खतरों के प्रति आगाह करती है।

☉ दक्षिण एशिया में बांग्लादेश सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है।

## ☐ सुझाव

➔ विश्व बैंक की यह रिपोर्ट, जलवायु परिवर्तन हेतु स्थानीय लचीलापन (Resilience) बनाने के लिए निवेश और रणनीतियों को प्राथमिकता देने का विकल्प प्रदान करती है।

☉ यह रिपोर्ट, भारत में नकारात्मक आर्थिक प्रभाव को दूर करने के लिए शैक्षिक प्राप्ति को बढ़ाने, जल तनाव (Water stress) को कम करने तथा गैर-कृषि क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों में सुधार का सुझाव देती है।

## ☐ निष्कर्ष

➔ विकास, वास्तव में सबसे अच्छी अनुकूल रणनीति है, क्योंकि यह

जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते खतरे का सामना करने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे, बाजारोन्मुखी सुधारों, वर्द्धित मानव क्षमताओं और एक मजबूत संस्थागत क्षमता से जुड़ी हुई है। संयुक्त राज्य संघ के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी बाधा के रूप में है। 20 जून, 2018 को जारी संयुक्त राज्य संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में विश्व में लगभग 38 मिलियन लोग अधिक कुपोषित हैं। इसके लिए जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से जिम्मेदार है। हाल ही में भारत के नीति आयोग द्वारा जारी समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार, वर्ष 2030 तक भारत में जल की मांग दोगुनी हो जाएगी। अतः जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है।

सं. कालीशंकर 'शारदेय'

## इरीट्रिया-इथियोपिया सीमा समझौता

### ☐ वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➔ 8-9 जुलाई, 2018 को द्विपक्षीय इरीट्रिया-इथियोपिया शिखर सम्मेलन का आयोजन अस्मारा (Asmara), इरीट्रिया में किया गया।

☉ इस सम्मेलन में इरीट्रिया के राष्ट्रपति इसायस अफवर्की (Isaias Afwerki) और इथियोपियाई प्रधानमंत्री अबी अहमद (Abiy Ahmed) ने आधिकारिक रूप से भाग लिया।

### ☐ उद्देश्य

➔ यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच लंबित विवादों को सुलझाने से संबंधित है।

➔ सम्मेलन उपरांत जारी संयुक्त घोषणा-पत्र द्वारा आपसी सहमति के महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख किया गया।

➔ संयुक्त घोषणा-पत्र 'इरीट्रिया एवं इथियोपिया के मध्य शांति एवं मित्रता' शीर्षक से जारी किया गया।

### ☐ संयुक्त घोषणा-पत्र के मुख्य बिंदु

➔ लगभग दो दशक से बंद राजनयिक दूतावास को पुनः खोलने पर सहमति बनी है।

➔ युद्ध की स्थिति को समाप्त करने पर सहमति बनी है।

➔ राजनयिक संबंधों, परिवहन, व्यापार, उद्योग, पर्यटन आदि को बढ़ाने पर सहमति बनी है।

➔ दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र के सीमा समझौते पर सहमति जताई है। अभी तक इथियोपिया इस सीमा समझौते को मानने से इंकार कर रहा था जो विवाद की मुख्य जड़ थी।

➔ संयुक्त रूप से क्षेत्रीय शांति, विकास एवं सहयोग को बढ़ावा देने

पर सहमति बनी है।

### ☐ दोनों देशों के बीच संघर्ष का इतिहास

➔ इरीट्रिया एक समय इथियोपिया का ही एक अंग था, लेकिन कुछ कारणों से वहां के स्थानीय लोग अलग देश की मांग करने लगे।

➔ वर्ष 1993 में लगभग तीन दशकों के संघर्ष उपरांत इरीट्रिया को इथियोपिया से आजादी प्राप्त हुई।

➔ कुछ सीमा विवादों के कारण दोनों देशों में तनाव की स्थिति बनी रही, धीरे-धीरे इस तनाव में वृद्धि होती गई।

☉ अंततः वर्ष 1998 में इरीट्रिया ने इथियोपिया पर आक्रमण कर दिया।

☉ इस युद्ध में लगभग 80 से 90 हजार लोग मारे गए।

➔ वर्ष 2000 में दोनों देशों के बीच अल्जीयर्स समझौते (Algiers Agreement) पर हस्ताक्षर किया गया लेकिन 2 वर्ष पश्चात इथियोपिया ने इस समझौते को मानने से मना कर दिया।

➔ इस प्रकार दोनों देशों के मध्य लगभग 2 दशकों से 'युद्ध' की स्थिति बनी हुई थी।

### ☐ समझौते का महत्व

➔ इस सहमति का इथियोपिया और इरीट्रिया सहित हॉर्न ऑफ अफ्रीका (अफ्रीका का पूर्वी क्षेत्र) के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

➔ यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है क्योंकि स्वेज नहर, लाल सागर, अदन की खाड़ी इसी क्षेत्र में अवस्थित है। अतः इस क्षेत्र में

शांति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी।



आरेखीय चित्र : इरीट्रिया इथियोपिया सीमा समझौता

➔ दोनों देशों ने सीमा विवाद के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के समझौते को मान्यता प्रदान की है। इस प्रकार यह समझौता, संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता को बढ़ाता है।

#### □ अन्य तथ्य

➔ इरीट्रिया, लाल सागर के पास स्थित एक तटीय देश है इसकी

राजधानी अस्मारा है तथा इसकी सीमा तीन देशों सूडान, इथियोपिया और जिबूती को स्पर्श करती है।

➔ इथियोपिया एक स्थल आबद्ध देश है इसकी राजधानी अदिस अबाबा है और इसकी सीमा कुल 6 देशों इरीट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, दक्षिण सूडान और सूडान को स्पर्श करती है।

सं. सचिन कुमार वर्मा

## यू.एन. : दक्षिण सूडान को हथियार आपूर्ति पर प्रतिबंध

#### □ पृष्ठभूमि

➔ वर्ष 2011 में सूडान से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से ही स्थलबद्ध देश दक्षिण सूडान में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जो बाद में गृह युद्ध में परिवर्तित हो गई।

➔ दक्षिण सूडान में सरकार एवं विपक्षी बलों के मध्य गृह युद्ध वर्ष 2013 से ही जारी है।

➔ राष्ट्रपति सल्वा कीर के नेतृत्व में डिका बहुसंख्यक समुदाय तथा पूर्व उपराष्ट्रपति रीक माचर से संबद्ध नुएर (Nuer) अल्पसंख्यक इस गृह युद्ध में आमने-सामने हैं।

➔ उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति सल्वा कीर डिका नृजातीय समूह से हैं, जो देश की आबादी का 15 प्रतिशत है।

➔ जबकि पूर्व उपराष्ट्रपति रीक माचर नुएर नृजातीय समूह से हैं, जो देश की आबादी का 10 प्रतिशत है।

➔ आंतरिक विवादों के चलते सरकार तथा विपक्षी ताकतों के मध्य संघर्ष से अत्यधिक मानव पीड़ाएं उत्पन्न हुई; यथा- जीवन की हानि, संघर्ष-प्रेरित खाद्य असुरक्षा, अकाल का खतरा, 4 मिलियन से अधिक लोगों का विस्थापन, संपत्ति की हानि इत्यादि ने दक्षिण सूडान के लोगों को अत्यधिक दरिद्रता एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में डाल दिया है।

#### □ संकल्प 2428 (2018)

➔ 13 जुलाई, 2018 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुमत से संकल्प 2428 (2018) पारित करते हुए निर्णय किया कि सभी सदस्य राष्ट्रों

द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दक्षिण सूडान को हथियारों की आपूर्ति, बिक्री या हस्तांतरण 31 मई, 2019 तक प्रतिबंधित रहेगा।

➔ इस संकल्प के अनुसार, सदस्य राष्ट्र अपने क्षेत्र के माध्यम से या अपने नागरिकों के माध्यम से या अपने पोतों के इस्तेमाल से हथियारों के प्रवाह को रोकने के लिए तत्काल प्रबंध करेंगे।

➔ दक्षिण सूडान को हथियार आपूर्ति पर प्रतिबंध के संबंध में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित इस संकल्प के पक्ष में 9 मत पड़े, जबकि विरोध में एक भी मत नहीं डाला गया।

➔ आइवरी कोस्ट, फ्रांस, नीदरलैंड्स, कुवैत, पेरू, पोलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम तथा यूएसए ने इस संकल्प के पक्ष में मतदान किया।

#### □ प्रभाव

➔ इस संकल्प के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र को अपेक्षा है कि दक्षिण सूडान में बढ़ती नरसंहार की घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित होगा।

➔ ऐसी उम्मीद है कि दक्षिण सूडान में समावेशी तथा सतत शांति को प्राप्त करने की दिशा में उपरोक्त प्रतिबंध मील का पत्थर साबित होगा।

#### □ दक्षिण सूडान की पृष्ठभूमि

➔ दक्षिण सूडान अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है तथा यह प्राकृतिक तेल के लिहाज से संपन्न देश है।

➔ वर्ष 2011 में दक्षिण सूडान के लोगों ने सूडान से अलग होने के लिए बड़े पैमाने पर मतदान किया था।

➔ वर्ष 2011 से पहले सूडान क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश था, परंतु बंटवारे के बाद वर्तमान

में अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है।

सं. राजन शुक्ल



दक्षिणी सूडान के क्षेत्र में हथियारों की आपूर्ति, बिक्री या हस्तांतरण 31 मई, 2019 तक प्रतिबंधित



UNITED NATIONS

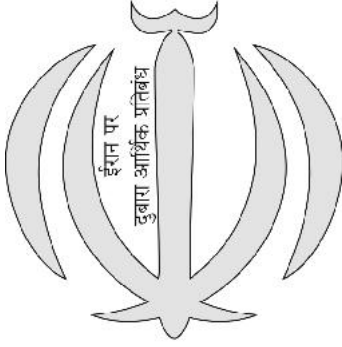
13 जुलाई, 2018 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रिजोल्यूशन 2428 (2018) पारित

आरेखीय चित्र : दक्षिण सूडान को हथियार आपूर्ति पर प्रतिबंध

## अमेरिका द्वारा ईरान पर पुनः प्रतिबंध

### □ पृष्ठभूमि

- ➔ अमेरिका और ईरान के संबंध वर्ष 1979 की ईरानियन क्रांति के बाद बिगड़ गए। प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका द्वारा ईरान पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए।
- ➔ अमेरिका और ईरान के बिगड़े संबंधों की एक बड़ी वजह ईरान द्वारा परमाणु बम बनाने की संभावना है। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियारों का निर्माण करे।



6 अगस्त, 2018 को USA JCPOA से पीछे हटा,



आरेखीय चित्र : अमेरिका द्वारा ईरान पर पुनः प्रतिबंध

- ➔ मध्य-पूर्व के क्षेत्र में अमेरिका के अपने हितों के संदर्भ में ईरान के साथ उसके संबंध बनते-बिगड़ते रहे हैं।
- ➔ गौरतलब है कि अमेरिका ने ईरान, इराक और उत्तरी कोरिया को 'शैतानियत की धुरी' (Axis of evil) वाले देशों की संज्ञा दी है।

### □ संयुक्त समग्र कार्ययोजना समझौता (जेसीपीओए)

- ➔ जुलाई, 2015 में बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी तथा यूरोपीय संघ के साथ मिलकर ईरान ने वियना में परमाणु समझौता किया था।
- ➔ इस समझौते का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए संचालित होगा।
- ➔ इस समझौते को P5+1 समझौता भी कहते हैं, क्योंकि इस समझौते में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांचों स्थायी सदस्यों के साथ ही जर्मनी भी शामिल है।

### □ वर्तमान परिदृश्य

- ➔ 6 अगस्त, 2018 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त समग्र कार्ययोजना समझौते (जेसीपीओए) से पीछे हटते हुए ईरान पर दुबारा आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की।
- ➔ गौरतलब है कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प शुरू से ही इस समझौते के मुखर आलोचक रहे हैं।
- ➔ इसी पृष्ठभूमि में वर्ष 2015 में किए गए समझौते से 8 मई, 2018 को अमेरिका ने स्वयं को अलग कर लिया था।

### □ प्रतिबंध पर समझौते में शामिल देशों का मत

- ➔ अमेरिका के इस निर्णय का विरोध समझौते में शामिल उसके यूरोपीय सहयोगियों यथा-ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के साथ ही चीन और रूस भी कर रहे हैं।
- ➔ जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने इस समझौते से पीछे हटने के अमेरिकी निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि यह समझौता तोड़कर अमेरिका ने मध्य-पूर्व की स्थिति को और बिगाड़ दिया है।
- ➔ मर्केल के अनुसार, यह समझौता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पारदर्शी बनाने के साथ ही उसे नियंत्रित रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
- ➔ चीन ने समग्र कार्ययोजना समझौते (जेसीपीओए) को बचाने और उसे क्रियान्वित करने के लिए सभी पक्षों से बातचीत जारी रखने की अपील की।
- ➔ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मध्य-पूर्व क्षेत्र में स्थिरता की बहाली हेतु समग्र कार्ययोजना समझौते को बनाए रखने पर जोर दिया।

जुलाई, 2015 में विएना में संयुक्त समग्र कार्ययोजना समझौता (JCPOA) या P5+1 समझौता



आरेखीय चित्र : अमेरिका द्वारा ईरान पर पुनः प्रतिबंध

## □ प्रतिबंध का भारत पर असर

➔ ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों का भारत के तेल आयात पर गंभीर असर पड़ने का अंदेश है। भारत और ईरान के बीच पारंपरिक रूप से बेहतर व्यापारिक संबंध रहे हैं। भारत ईरान से काफी मात्रा में तेल आयात करने के साथ ही उसकी तेल परियोजनाओं में सहयोग भी दे रहा है। इन्हीं नजदीकी संबंधों की वजह से ईरान ने भारत को चाबहार बंदरगाह में साझेदारी का मौका दिया है, इसलिए भारत भी समग्र कार्ययोजना समझौते को बनाए रखने का पक्षधर है।

☉ ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगने की स्थिति में भारत में ऊर्जा

संकट बढ़ने के साथ ही प्रस्तावित 'उत्तर-दक्षिण गलियारा परियोजना' के भी संकट में पड़ने की आशंका है।

## □ निष्कर्ष

संयुक्त समग्र कार्ययोजना समझौते से अलग होने के निर्णय से मध्य-पूर्व क्षेत्र में तनाव बढ़ने के साथ ही ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। इसके साथ ईरान अपने परमाणु हथियारों के विकास का कार्यक्रम पुनः प्रारंभ कर सकता है, जिससे अंततः वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों की दौड़ पुनः प्रारंभ हो सकती है।

सं. धीरेंद्र त्रिपाठी

# डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2018

## □ डीएनए

➔ डीएनए (DNA: Deoxyribonucleic Acid) सभी जीव रूपों के अनुदेश समुच्चय (Set of instructions) या रूपरेखा (blueprint) की तरह है।

☉ यह किसी जीवधारी की कोशिका के विभिन्न अंशों के निर्माण के लिए कार्यप्रणालियों के विस्तृत समुच्चय को कोड करता है।

➔ प्रत्येक मानव का डीएनए अंश माता-पिता, दोनों के डीएनए के आधे-आधे से मिलकर बनता है।

➔ व्यक्तियों की डीएनए रूपरेखा एक-दूसरे से भिन्न होती है।

☉ यह भिन्नता ही है जो प्रत्येक व्यक्ति को अनन्य और भिन्न (समान जुड़वां के अतिरिक्त) बनाती है।

## □ डीएनए प्रोफाइलिंग

➔ मानव शरीर को प्रभावित करने वाले (जैसे-हत्या, दुष्कर्म, मानव तस्करी या गंभीर चोट) और संपत्ति की हानि (जैसे-चोरी, संधमारी एवं डकैती) से संबंधित अपराधों के समाधान में फोरेंसिक डीएनए प्रोफाइलिंग का विशेष महत्व है।

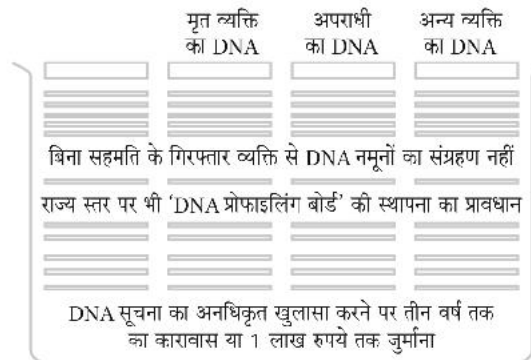
➔ वर्ष 2016 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, देश में ऐसे अपराधों की कुल संख्या प्रतिवर्ष 3 लाख से अधिक है।

☉ इनमें से बहुत कम मामलों के समाधान के लिए ही वर्तमान में डीएनए परीक्षण का सहारा लिया जाता है।

कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले DNA द्वारा ही आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में

4 जुलाई, 2018 को डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2018 को स्वीकृति

उद्देश्य : देश की न्यायिक प्रणाली को समर्थन देने व सुदृढ़ बनाने के लिए



आरेखीय चित्र :

डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2018

## □ वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➔ 4 जुलाई, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2018' [DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill, 2018] को स्वीकृति प्रदान की।

☉ 9 अगस्त, 2018 को यह विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

## □ उद्देश्य

➔ उक्त विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य देश की न्यायिक प्रणाली को समर्थन देने एवं सुदृढ़ बनाने के लिए डीएनए आधारित फोरेंसिक प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग को विस्तारित करना है।

## □ प्रमुख प्रावधान

➔ विधेयक में पीड़ितों, अपराधियों, संदिग्धों, विचाराधीन कैदियों, गुमशुदा व्यक्तियों और अज्ञात मृत व्यक्तियों सहित कुछ निश्चित श्रेणी के व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने के लिए डीएनए प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं अनुप्रयोग के विनियमन का प्रावधान किया गया है।

➔ विधेयक में 'डीएनए विनियामक बोर्ड' की स्थापना का प्रावधान है, जिसमें आणविक जीव विज्ञान, मानव आनुवांशिकी, जनसंख्या जीव विज्ञान,

जैवनैतिकता (Bioethics), सामाजिक विज्ञान, विधि और आपराधिक न्याय के विशेषज्ञ शामिल होंगे।



- ☉ बोर्ड द्वारा डीएनए प्रयोगशालाओं का प्रमाणन एवं प्रत्यायन, डीएनए डाटा बैंकों की स्थापना तथा उनकी निगरानी और डीएनए सूचनाओं के संग्रहण, भंडारण, आदान-प्रदान एवं निरसन से संबंधित प्रक्रियाओं तथा दिशा-निर्देशों का निर्माण किया जाएगा।
- ➔ विधेयक में 'राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक' की स्थापना का प्रावधान है, जो अपराधियों, संदिग्धों, गुमशुदा व्यक्तियों, अज्ञात मृत व्यक्तियों से डीएनए डाटा संग्रहीत करेगा।
- ☉ साथ ही यह हत्या, यौन हमला, व्यभिचार जैसे आपराधिक मामलों में डीएनए डाटा को संग्रहीत एवं प्रोफाइल करेगा।
- ➔ विधेयक के अनुसार, किसी भी डीएनए प्रयोगशाला एवं डाटा बैंक में निहित डीएनए प्रोफाइल, नमूना और अभिलेख सहित डीएनए डाटा का उपयोग केवल व्यक्ति की पहचान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से किया जाएगा।
- ☉ डीएनए डाटा को अभियोजन या बचाव और नागरिक मामलों से संबंधित जांच में सुविधा के लिए साक्ष्य की स्वीकार्यता के नियमों के अनुसार, आपराधिक मामलों में व्यक्तियों की पहचान की सुविधा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- ➔ विधेयक के अनुसार, संदिग्धों और अपराधियों की सूची के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की डीएनए सूचना अन्य सूची में संग्रहीत नहीं की जा सकती।
- ☉ ऐसे मामलों में केवल केस संदर्भ संख्या संग्रहीत की जाएगी।
- ☉ यदि कोई व्यक्ति अपराधी, संदिग्ध या विचाराधीन कैदी नहीं है, तो उसकी डीएनए सूचना का मिलान अपराधियों या

संदिग्धों की सूची से नहीं किया जा सकता है।

- ➔ विधेयक में अनधिकृत व्यक्तियों या अनधिकृत उद्देश्यों के लिए डीएनए सूचना का खुलासा करने हेतु तीन वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

### ☐ विगत प्रयास

- ➔ सरकार द्वारा सर्वप्रथम वर्ष 2007 में 'डीएनए प्रोफाइलिंग विधेयक' का मसौदा तैयार किया गया था।
- ➔ वर्ष 2012, 2015 और 2016 में भी 'मानव डीएनए प्रोफाइलिंग विधेयक' का मसौदा तैयार किया गया था।
- ➔ जुलाई, 2017 में विधि आयोग ने 'डीएनए आधारित प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं विनियमन) विधेयक, 2017' का मसौदा सरकार को सौंपा था।
- ➔ 'डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2018' कुछ मामूली परिवर्तनों को छोड़कर काफी हद तक विधि आयोग के प्रस्ताव पर आधारित है।

### ☐ निष्कर्ष

अपराधों के समाधान एवं गुमशुदा व्यक्तियों की पहचान के लिए डीएनए आधारित प्रौद्योगिकी की उपयोगिता विश्व भर में स्वीकृत है। इस दृष्टि से 'डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2018' एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल न्याय प्रणाली में शीघ्रता तथा अपराध सिद्धि दर में बढ़ोतरी होगी, बल्कि गुमशुदा व्यक्तियों, अज्ञात शवों और आपदा के शिकार व्यक्तियों के पहचान में मदद मिलेगी।

सं. नीरज ओझा

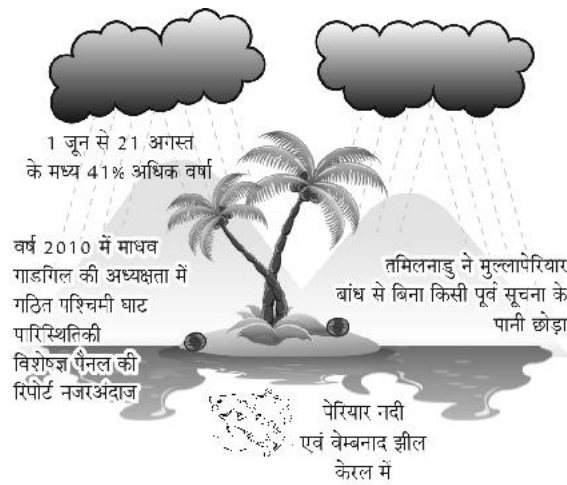
## केरल में बाढ़

### ☐ भूमिका

- ➔ भारत में प्रत्येक वर्ष मानसून के आगमन के साथ किसी न किसी राज्य में बाढ़ का आना लगभग तय होता है। सामान्यतः बाढ़ से उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र के राज्य अधिक प्रभावित होते रहे हैं। परंतु इस बार भारत के दक्षिण-पश्चिम भाग में अवस्थित तटीय राज्य केरल बाढ़ग्रस्त रहा।

### ☐ वर्तमान संदर्भ

- ➔ 'ईश्वर का अपना देश' (God's Own Country) कहा जाने वाला केरल जुलाई-अगस्त, 2018 में बाढ़ से प्रभावित रहा। यद्यपि अब बाढ़ का प्रकोप कम हो गया लेकिन इसने अपने चरम अवस्था में संपूर्ण केरल (कासरगोड़ को छोड़कर शेष 13 जिलों) को प्रभावित किया।



आरेखीय चित्र : केरल में बाढ़

- ☉ बाढ़ से केरल में लगभग 483 लोगों की मृत्यु हुई, हजारों बेघर हुए एवं करोड़ों की संपत्ति नष्ट हुई।

- ☉ बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि केरल में वर्ष 1924 में आई '99 की महान बाढ़' (मलयालम कैलेंडर के अनुसार 1099 ई.) से इसकी तुलना की गई।

### ☐ केरल में बाढ़ के कारण

- ➔ सामान्यतः बाढ़ तब आती है जब नदी, झील, तालाब या किसी जलाशय का जल तट से ऊपर होकर अस्थायी रूप से बहने लगता है। यह अधिक

वर्षा अथवा उपयुक्त जल निकास की व्यवस्था के अभाव के कारण होता है। यद्यपि केरल की बाढ़ के पीछे भी मुख्य रूप से यही कारण उत्तरदायी है तथापि इसके मानव जनित अन्य कारण भी हैं।

## ● मानसूनी वर्षा की अधिकता

➔ केरल का मौसम देश के अन्य राज्यों की तुलना में अलग है। मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के अनुसार, केरल में लगभग 286 दिन वर्षा होती है एवं वार्षिक औसतन 300 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है।

☞ परंतु इस वर्ष 1 जून से 21 अगस्त तक सामान्य से 41 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई। इससे केरल में प्रवाहित होने वाली कुल 44 नदियों में अतिशय वर्षा जल की उपलब्धता ने बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर दी।

## ● पश्चिमी घाट का अंधाधुंध दोहन

➔ केरल की वर्तमान बाढ़ के पीछे पश्चिमी घाट में संसाधनों का अविवेकपूर्ण, अवैध एवं अनियंत्रित दोहन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। ➔ पश्चिमी घाट एक 'पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र' है। इस क्षेत्र में हुए अवैध खनन एवं निर्माण कार्य तथा वन विनाश के कारण भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हुई।

☞ भूस्खलन के कारण वर्षा जल का मार्ग अवरुद्ध हो गया एवं बाढ़ की स्थिति बनी। ऐसी स्थिति केरल के पलक्कड़, कन्नूर, इडुक्की, कोझिकोड, वायनाड और मल्लपुरम जिले में अधिक थी, जो पश्चिमी घाट में अवस्थित हैं।

☞ गौरतलब है कि वर्ष 2010 में माधव गाडगिल की अध्यक्षता में गठित 'पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल' (Western Ghat Ecology Expert Panel) की रिपोर्ट में पश्चिमी घाट को संवेदनशील बताते हुए सभी अवैध खनन, निर्माण कार्य एवं वनों के विनाश को रोकने हेतु अनेक सुझाव दिए गए थे।

☞ परंतु केरल सहित अन्य राज्य सरकारों ने इन सुझावों को नजरअंदाज कर दिया, जिसका परिणाम वर्तमान बाढ़ रूपी विपदा के रूप में हमारे सामने है।

## ● बाढ़ में बांधों की भूमिका

➔ केरल सरकार के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में कुल 53 बांध एवं बड़े जलाशय हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 44,289 वर्ग किमी. है। अत्यधिक वर्षा के कारण इडुक्की एवं अन्य बांधों और जलाशयों में संचित जल को बिना किसी पूर्व सूचना के छोड़ना पड़ा, जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई।

➔ साथ ही केरल में बाढ़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में केरल सरकार ने बाढ़ के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा बिना किसी

पूर्व सूचना के 'मुल्लापेरियार बांध' से पानी छोड़े जाने को उत्तरदायी ठहराया है। इस प्रकार बांध संचालन में समन्वय की कमी ने भी बाढ़ की स्थिति को भयावह बनाया।

## □ प्राकृतिक आपदा

➔ केंद्र सरकार ने केरल की बाढ़ को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। वस्तुतः जब किसी आपदा को दुर्लभ या गंभीर प्रकृति का घोषित किया जाता है, तो राज्य सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर मदद दी जाती है।

➔ किसी भी अधिसूचित आपदा के दौरान बचाव और राहत खर्च को पूरा करने के लिए वित्तीय तंत्र, 'राज्य आपदा राहत कोष' और 'राष्ट्रीय आपदा राहत कोष' द्वारा संचालित होता है।

☞ केरल में भी एक आपदा राहत कोष बनाया गया है। इस राशि में 75 प्रतिशत हिस्सा केंद्र का 25 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार का होगा।

## □ ऑपरेशन मदद एवं अन्य बचाव कार्य

➔ 9-24 अगस्त, 2018 के मध्य कोच्चि स्थित नौसेना के दक्षिणी कमांड द्वारा केरल में बाढ़ पीड़ितों की सहायता, बचाव एवं राहत कार्य के लिए ऑपरेशन मदद संचालित किया गया था।

➔ केंद्र सरकार द्वारा केरल में सहायता के लिए चलाए गए बचाव कार्य में 40 हेलीकॉप्टर, 31 विमान, 182 बचाव दल, रक्षा बलों के 18 चिकित्सा दल, एनडीआरएफ (NDRF) की 58 टीमों, सीएपीएफ (CAPF) की 7 कंपनियों के साथ 500 से अधिक नौकाओं और

आवश्यक बचाव उपकरणों की मदद ली गई।

☞ इन सभी के द्वारा बाढ़ से घिरे इलाकों से सफलतापूर्वक 60,000 लोगों को निकालकर उन्हें राहत शिविरों तक पहुंचाया गया।

## □ निष्कर्ष

➔ केरल के वर्तमान बाढ़ त्रासदी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्या कारण है कि देश बाढ़ से निपटने में सक्षम नहीं हो पा रहा है? यह सही है कि बाढ़ को रोक पाना संभव नहीं है, लेकिन बाढ़ से पूर्व बाढ़ के उचित प्रबंधन की तैयारी कर, जनसमुदाय को जागरूक कर, सतत

विकास की संकल्पना पर आधारित विकास कार्यों को बढ़ावा देकर एवं बाढ़ चेतावनी प्रणाली को विकसित कर इसके प्रभाव को सीमित किया जा सकता है।



आरेखीय चित्र : केरल में बाढ़

सं. ललितंदर कुमार

## ट्रम्प-पुतिन शिखर वार्ता

### □ पृष्ठभूमि

➔ पिछले एक दशक में अमेरिका और रूस के संबंधों में तनातनी ज्यादा और नजदीकी कम ही रही है। सैन्य क्षमता की दृष्टि से सर्वाधिक शक्तिशाली दोनों देशों के मध्य ज्यादातर महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर मतभेद रहे हैं।

- ☉ दोनों देशों के मध्य हालिया मतभेद के मुख्य मुद्दे वर्ष 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस का हस्तक्षेप, यूक्रेन के क्रीमिया प्रांत पर रूस द्वारा अवैध कब्जा, सीरिया को लेकर दोनों पक्षों में तकरार तथा रूस द्वारा ईरानी शासन को समर्थन आदि रहे हैं।

### □ वर्तमान परिदृश्य

➔ 16 जुलाई, 2018 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मध्य फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में स्थित राष्ट्रपति भवन में अनौपचारिक वार्ता हुई।

- ☉ गौरतलब है कि फिनलैंड ने इसके पहले भी दो अहम मौकों पर अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों की वार्ताओं को अपने यहां संपन्न कराया था।

### □ वार्ता के उद्देश्य

➔ हेलसिंकी में संपन्न वार्ता का उद्देश्य अमेरिका व रूस के संबंधों में आए तनाव को कम कर, बेहतर संबंधों का निर्माण करना है।

### □ वार्ता में शामिल मुद्दे

➔ वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस मुलाकात के दौरान वह रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ सभी अहम मुद्दों जैसे व्यापार, सैन्य क्षमता, मिसाइल कार्यक्रमों और चीन पर गहन वार्ता करेंगे। इसके अतिरिक्त परमाणु हथियारों में कटौती भी वार्ता का हिस्सा होगी।

### ● चीन, वार्ता का एक अहम मुद्दा

➔ 21वीं सदी में चीन का शक्तिशाली आर्थिक एवं सैन्य उभार एक बड़ी घटना है। वर्तमान एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिकी प्रभुत्व को चीन ने कड़ी चुनौती पेश की है।

- ☉ विगत वर्षों में चीन और रूस की बढ़ती मित्रता ने अमेरिका को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर किया है।

- ☉ इसी संदर्भ में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रूस के साथ अपने संबंधों को सुधार कर चीनी प्रभुत्व को संतुलित करना चाहते हैं।

### □ रूस के अपने हित

➔ अमेरिका और यूरोपीय देशों ने पहले से ही रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं।

- ☉ वर्तमान में रूस सैन्य क्षमता की दृष्टि से दूसरा सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति जर्जर है।

- ☉ रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस वार्ता के माध्यम से रूसी संस्थाओं और कंपनियों पर लगे प्रतिबंधों को हटवाकर देश के आर्थिक हालात बेहतर करना चाहते हैं।

### □ विवादास्पद मुद्दों से दूरी

➔ दोनों देशों ने आपसी संबंधों को कमजोर करने वाले विवादास्पद मुद्दों से दूरी बनाए रखी।

- ☉ गौरतलब है कि दोनों पक्षों के मध्य सीरिया, उत्तरी कोरिया और यूक्रेन के मुद्दों पर मतभेद व हितों को लेकर टकराव की स्थिति है।

- ☉ हालांकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने वर्ष 2016 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप से इंकार किया।

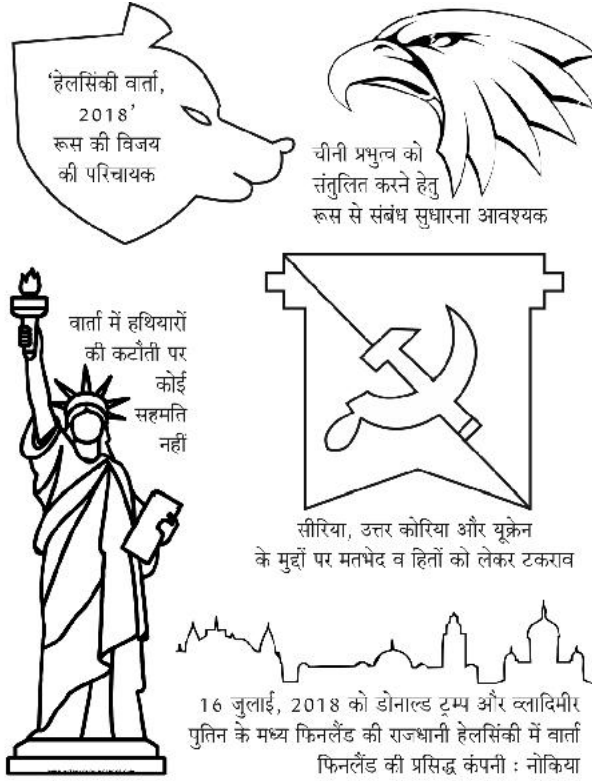
### □ संभावित परिणाम

➔ वैश्विक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि इस वार्ता का असर दुनिया के कई क्षेत्रों पर पड़ेगा। दोनों देशों में तनाव कम होगा और हथियारों की दौड़ में कमी आएगी।

➔ सीरिया में समझौते की स्थिति में हजारों निर्दोष नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा होगी।

- ☉ इसके अतिरिक्त उत्तर कोरिया, यूक्रेन, ईरान सहित अनेक अहम

मुद्दों पर दोनों शक्तिशाली देशों के मध्य वार्ता का मार्ग प्रशस्त होगा।



आरेखीय चित्र : ट्रम्प - पुतिन शिखर वार्ता

## □ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

➔ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने फिनलैंड के राष्ट्रपति शाउली निनिस्टो को इस अनौपचारिक वार्ता को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए धन्यवाद दिया।

- ☉ गौरतलब है कि यूरोपीय संघ के कई देशों एवं अमेरिका के नाटो (NATO) सहयोगियों ने रूस के साथ अमेरिका की इस वार्ता की मेजबानी से इंकार कर दिया था।
- ☉ इस अनौपचारिक वार्ता को 'हेलसिंकी वार्ता, 2018' के नाम से भी जाना जाता है।
- ☉ हेलसिंकी वार्ता में किसी औपचारिक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं हुआ। साथ ही इस अनौपचारिक वार्ता का

अमेरिका के विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया।

- ☉ राजनीतिक विशेषज्ञ हेलसिंकी वार्ता को अमेरिकी हितों के खिलाफ और रूस की विजय के रूप में देख रहे हैं।
- ☉ इस वार्ता में हथियारों की कटौती पर कोई सहमति नहीं बनी, जबकि अमेरिका और रूस के मध्य हथियारों की कटौती को लेकर हुई नई स्टार्ट (सामरिक शस्त्रों में कमी) संधि वर्ष 2021 में समाप्त होने जा रही है।
- ➔ गौरतलब है कि अमेरिकी और यूरोपीय देशों ने क्रीमिया पर अवैध कब्जा जमाने के कारण रूस को वर्ष 2014 में विकसित देशों के समूह जी-8 से अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया था।

सं. धीरेन्द्र त्रिपाठी

## मंगल ग्रह पर जलीय झील की खोज

### □ पृष्ठभूमि

➔ प्रकृति और जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए अब मनुष्य पृथ्वी से करोड़ों मील दूर मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है। 'जहां चाह वहां राह' की सूक्ति को चरितार्थ करते हुए मनुष्य ने मंगल ग्रह पर पानी को खोजने का अविश्वसनीय कारनामा संभवतः(?) कर दिखाया है।

### □ वर्तमान संदर्भ

➔ वर्ष 2011 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) द्वारा भेजे गए क्यूरियोसिटी रोवर से प्राप्त सूचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया था कि मंगल की सतह पर बहता हुआ जल होने की संभावना है।

- ☉ इसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए अमेरिकी जर्नल (Journal) 'साइंस' में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर पहली बार विशाल भूमिगत झील खोजने का दावा किया है।

➔ मंगल के हिमखंड के नीचे अवस्थित यह झील लगभग 20 किलोमीटर चौड़ी है।

☉ यह मंगल ग्रह पर पाया गया सबसे बड़ा जलीय भाग है।

➔ वैज्ञानिकों ने यह जानकारी वर्ष 2003 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी

द्वारा भेजे गए मंगल मिशन 'मार्स एक्सप्रेस आर्बिटर' पर लगे मार्सिस (MARSIS) उपकरण से प्राप्त की है।

➔ इटली के वैज्ञानिकों के एक दल ने मार्सिस के जिन आंकड़ों का अध्ययन कर मंगल ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की बर्फ के नीचे पानी की झील होने का पता लगाया है, वे आंकड़े मई, 2012 से दिसंबर, 2012 के मध्य हुए निरीक्षणों के हैं।

☉ इस अवधि में मार्सिस मंगल ग्रह के दक्षिणी ध्रुव वाले हिस्से, जिसे प्लानम ऑस्ट्रले (Planum Australe) कहा गया है, से कई बार उड़ता हुआ गुजरा था।

☉ इटली के वैज्ञानिक रोबर्टो ओरोसेई और उनके दल को इन निरीक्षणों के 29 ऐसे नमूने मिले, जो प्लानम ऑस्ट्रले के ऊपर

से उड़ान के दौरान मिले पिछले सभी नमूनों से अलग थे।

☉ वैज्ञानिकों के अनुसार, इस झील का पानी पीने योग्य नहीं है।

पानी दक्षिणी ध्रुव पर बर्फीली सतह के 1 किमी. नीचे द्रव अवस्था में

मंगल ग्रह पर पहली बार विशाल भूमिगत झील खोजने का दावा

मार्स एडवांस्ड रडार फॉर सरफेस एंड लोनोस्फेयर साउंडिंग - MARSIS



मार्सिस : मार्स एक्सप्रेस आर्बिटर पर मौजूद एक उपकरण



वर्ष 2003 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मार्स एक्सप्रेस आर्बिटर भेजा

आरेखीय चित्र : मंगलग्रह पर जलीय झील की खोज

तथा पानी बर्फीली सतह से लगभग 1 किलोमीटर नीचे होने के बावजूद मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम जैसे खनिज पदार्थों की मौजूदगी के कारण द्रव अवस्था में बना हुआ है।

### □ क्या है मारसिस ?

➔ 'मारस एडवांस्ड रडार फॉर सब-सरफेस एंड आयनोस्फियर साउंडिंग' (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding-MARSIS) मारस एक्सप्रेस ऑर्बिटर पर मौजूद एक ऐसा उपकरण है, जो रडार तरंगों के माध्यम से मंगल ग्रह की ऊपरी सतह के नीचे, तरल या बर्फ रूपी पानी का पता लगाने के लिए निर्मित है।

➔ मारसिस से उत्पन्न रेडियो तरंगों मंगल ग्रह की ऊपरी सतह भेद कर नीचे की अलग-अलग परतों से टकराकर परावर्तित होती हैं, जिससे उन परतों की संरचना का पता चलता है। मारसिस ने जुलाई, 2005 से काम करना शुरू किया था।

पृथ्वी एवं मंगल : एक तुलनात्मक अध्ययन		
	पृथ्वी	मंगल
सूर्य से औसत दूरी	93 मिलियन मील	142 मिलियन मील
व्यास	7926 मील	4,220 मील
अक्ष पर झुकाव	23.5 डिग्री	25 डिग्री
वर्ष की अवधि	365.25 दिन	687 पृथ्वी दिवस
दिन की अवधि	23 घंटा 56 मिनट	24 घंटा 37 मिनट
तापमान	औसत 57°F	औसत- 81°F
वातावरण	नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन आदि	अधिकांशतः कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ जलवाष्प
उपग्रहों की संख्या	1 (चंद्रमा)	2 (फोबोस, डिमोस)
स्रोत-नासा		

### □ निष्कर्ष

➔ मंगल पर हुई खोज से पूर्णतया यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि मंगल पर जीवन है या नहीं? परंतु इतना तो अवश्य ही कहा जा सकता है कि मंगल ग्रह पर पानी की उपस्थिति है। इससे मंगल पर अतीत और भविष्य में जीवन की संभावनाओं की तलाश को बल मिलेगा। हालांकि इस संबंध में किसी उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभी और अधिक गहन अध्ययन की आवश्यकता है।

मंगल ग्रह के लिए सफल अभियानों की सूची			
क्रम	वर्ष	नाम	देश
1.	1964	मैरीनर 4	USA
2.	1969	मैरीनर 6	USA
3.	1969	मैरीनर 7	USA
4.	1971	मारस 3	USSR

5.	1971	मैरीनर 9	USA
6.	1973	मारस 5	USSR
7.	1975	वाइकिंग 1	USA
8.	1975	वाइकिंग 2	USA
9.	1996	मारस ग्लोबल सर्वेयर	USA
10.	1996	मारस पाथफाइंडर	USA
11.	2001	मारस ओडिशी	USA
12.	2003	मारस एक्सप्रेस ऑर्बिटर	ESA
13.	2003	मारस एक्सप्लोरेशन रोवर स्पिरिट	USA
14.	2003	मारस एक्सप्लोरेशन रोवर ऑपच्युनिटी	USA
15.	2005	मारस रिक्वोनाइसेंस ऑर्बिटर	USA
16.	2007	फिनिक्स मारस लैंडर	USA
17.	2011	मारस साइंस लेबोरेटरी	USA
18.	2013	मारस एटमोसफियर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशन (मावेन)	USA
19.	2013	मारस ऑर्बिटर मिशन	India
20.	2016	एक्सो मारस ऑर्बिटर	ESA
21.	2018	मारस इनसाइट लैंडर	USA

सं. ललित कुमार

## उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2018

### □ वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➔ उत्तर प्रदेश में रक्षा एवं एयरोस्पेस उद्योग को प्रोत्साहित करने तथा प्रदेश में बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन हेतु उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा 3 जुलाई, 2018 को उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2018 को स्वीकृति प्रदान की गई।

➔ यह नीति अधिसूचित होने की तिथि (16 जुलाई, 2018) से आगामी पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगी तथा राज्य में रक्षा एवं एयरोस्पेस क्षेत्र के विकास हेतु रणनीतिक दिशा-निर्देश प्रदान करेगी।

➔ उत्तर प्रदेश में रक्षा एवं एयरोस्पेस विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रेरित यह नीति प्रदेश में फरवरी, 2018 में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश निवेशक शिखर सम्मेलन में घोषित उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के विकास हेतु समर्पित है।

➔ उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2018-19 के बजट में भारत में दो रक्षा औद्योगिक गलियारों (Defence Industrial Corridors) के विकास की घोषणा की गई थी।

- ☞ इनमें से एक गलियारे का विकास उत्तर प्रदेश में तथा दूसरे का विकास तमिलनाडु में किया जाना है।

### □ लक्ष्य

1. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में आगामी पांच वर्षों में 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना।

2. इस क्षेत्र में 2.5 लाख रोजगार का सृजन करना।

### □ उद्देश्य

(i) उत्तर प्रदेश को रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र हेतु एक सर्वोत्तम गंतव्य के रूप में स्थापित करना।

(ii) प्रदेश में रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण हेतु निजी औद्योगिक पार्कों के विकास को प्रोत्साहित करना।

(iii) रक्षा गलियारे के समानांतर रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना को प्रोत्साहित करना।

(iv) रक्षा क्षेत्र में निर्यात-मुख्य विनिर्माण आधार का विकास करना।

(v) इस क्षेत्र में सहायक उद्योगों को प्रोत्साहित करते हुए सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों का विकास करना।

(vi) रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ावा देते हुए रक्षा गलियारे में आगामी पांच वर्षों में कम-से-कम दो विश्वस्तरीय परीक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं का विकास करना।

(vii) रक्षा एवं एयरोस्पेस उद्योग के अनुरूप कौशल विकास को बढ़ावा देना।

### □ नीति के प्रमुख प्रावधान

➔ यह नीति रक्षा तथा एयरोस्पेस से संबंधित उद्यमों (सार्वजनिक एवं निजी दोनों) को प्रदेश में निवेश करने हेतु आकर्षित करने के लिए अनेक प्रोत्साहनों का प्रावधान करती है।

- ☞ नीति के तहत रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र की कंपनियों को निवेश की मात्रा तथा उनके स्वरूप के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है।

☞ 1000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाली इकाइयों को मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई की संज्ञा दी गई है।

☞ बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल क्षेत्र में 200 करोड़ रुपये से अधिक (अथवा न्यूनतम 1000 प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन), मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में 300 करोड़ रुपये से अधिक (अथवा न्यूनतम 1500 प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन) तथा गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जिलों में 400 करोड़ रुपये से अधिक निवेश (अथवा न्यूनतम 2000 प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन) करने वाली कंपनियों को एंकर रक्षा एवं एयरोस्पेस इकाइयों की संज्ञा दी गई है।

☞ इसके अतिरिक्त ऐसी इकाइयों जो एंकर इकाइयों के क्लस्टर में ही स्थित हों तथा अपने अंतिम उत्पाद का न्यूनतम 40 प्रतिशत एंकर इकाई को

3 जुलाई, 2018 को नीति को स्वीकृति  
नीति 5 वर्ष तक प्रभावी



निर्यात-मुख्य विनिर्माण  
आधार का विकास

आगामी 5 वर्षों की अवधि में  
50 हजार करोड़ का निवेश  
आकर्षित करने का लक्ष्य



निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन

आरेखीय चित्र :

उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2018

आपूर्ति करती हों, को वेंडर (Vendor) रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों की संज्ञा दी गई है।

- ➔ नीति के तहत मेगा एंकर एवं एंकर इकाइयों को रक्षा गलियारे में भूमि की खरीद पर भूमि की प्रचलित सर्किल दर अथवा क्रय मूल्य में से जो भी कम होगा, के 25 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- ➔ रक्षा गलियारे के अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास अथवा परीक्षण सुविधा की स्थापना हेतु लिए गए ऋण पर प्रतिवर्ष 50 प्रतिशत की दर से 5 वर्षों हेतु (प्रति इकाई अधिकतम 2 करोड़ रुपये) ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- ➔ प्रदेश सरकार द्वारा इस क्षेत्र में स्थापित इकाइयों के पेटेंट को सहूलियत देने हेतु घरेलू पेटेंट पंजीकरण शुल्क के 100 प्रतिशत तथा अंतरराष्ट्रीय पेटेंट पंजीकरण शुल्क के 50 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- ➔ नीति के तहत बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल क्षेत्र में स्थापित इकाई को 100 प्रतिशत, मध्यांचल एवं पश्चिमांचल क्षेत्र में स्थापित इकाई को 75 प्रतिशत तथा गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद में स्थापित इकाई को स्टैप शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

➔ इसके अतिरिक्त नीति में बाजार के विकास (मेलों/ प्रदर्शनियों के माध्यम से) क्षमता निर्माण (कौशल प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक समझौतों के द्वारा) तथा व्यवसाय में सुगमता (सिंगल विंडो क्लियरेंस, विद्युत आपूर्ति, औद्योगिक सुरक्षा प्रक्रियाओं की सरलता आदि द्वारा) से संबंधित अनेक प्रावधान है।

➔ यह नीति निजी क्षेत्र के उद्यमों को भी प्रोत्साहित करने हेतु अनेक प्रावधान करती है।

## □ प्रस्तावित रक्षा

### औद्योगिक गलियारा

- ➔ उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित रक्षा औद्योगिक गलियारा उत्तर प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों यथा- अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर तथा लखनऊ से होकर गुजरेंगा।
- ➔ इस गलियारे के विकास हेतु उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक

विकास प्राधिकरण (UPEIDA) नोडल एजेंसी होगी।

- ➔ यूपीडा (UPEIDA) इस हेतु बुंदेलखंड क्षेत्र में 3 हजार हेक्टेयर भूमि को चिह्नित कर उसको खरीदेगा।
- ➔ इसके तहत डिफेंस पार्क (कानपुर, झांसी व लखनऊ), एयरोस्पेस पार्क (लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ व गौतमबुद्ध नगर), परीक्षण सुविधाओं का विकास, ज़ोन/वायुयान/हेलीकॉप्टर आदि का निर्माण एवं एसेंबलिंग इकाइयों आदि की स्थापना हेतु निवेश आकर्षित किए जाएंगे।
- ➔ इसके अतिरिक्त पुलिस एवं सेना के आधुनिकीकरण हेतु उपकरण/कलपुर्जे से संबंधित इकाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित इकाइयां (आगरा, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद व नोएडा) तथा सैन्य वस्त्रों से संबंधित इकाइयों (कानपुर एवं आगरा) की भी स्थापना हेतु निवेश आकर्षित किया जाएगा।

## □ लाभ

➔ भारत जो रक्षा उत्पादों की दृष्टि से काफी हद तक अन्य देशों से आयात पर निर्भर है, की निर्भरता में कमी आएगी तथा आगे चलकर

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा।

➔ भारत स्वयं को रक्षा उत्पादों के निर्यातक के रूप में स्थापित करने को इच्छुक है। यह रक्षा गलियारा भारत को रक्षा उत्पादों का निर्यातक बनने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

➔ इससे उत्तर प्रदेश जो भारत की कुल जनसंख्या के 16.5 प्रतिशत का प्रतिनिधत्व करता है, को अनेक लाभ होंगे।

➔ रक्षा गलियारे में बुंदेलखंड क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता प्राप्त है। इससे बुंदेलखंड का आर्थिक विकास



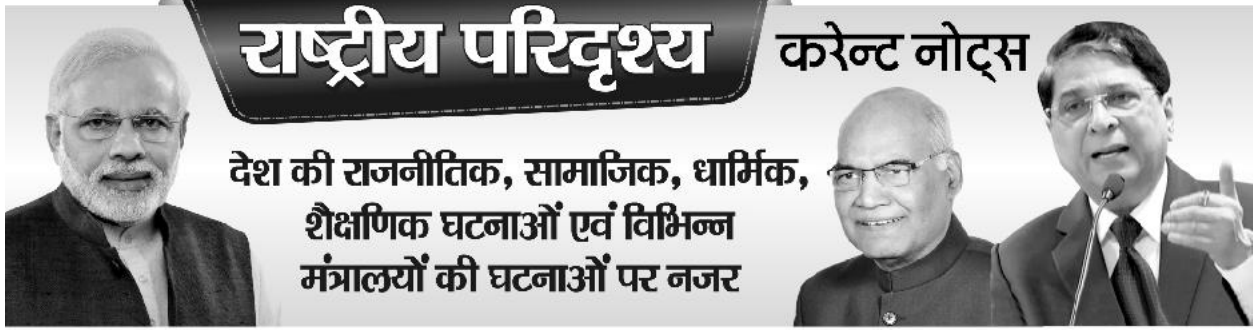
आरेखीय चित्र :

उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2018

होगा तथा यह क्षेत्र देश की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा।

➔ रक्षा गलियारे में बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन होगा। इससे प्रदेश के लोगों को रोजगार हेतु प्रवसन में कमी आएगी।

सं. विकास कुमार शुक्ल



## भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018

### वर्तमान परिदृश्य

➔ 5 अगस्त, 2018 को राष्ट्रपति ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 को स्वीकृति प्रदान कर दी। इससे यह विधेयक अब अधिनियम बन गया।

- ➔ 25 जुलाई, 2018 को राज्य सभा द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 को पारित कर दिया गया। इससे पूर्व 19 जुलाई, 2018 को इसे लोक सभा द्वारा पारित कर दिया गया था।

### प्रमुख प्रावधान

➔ भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये अथवा अधिक की राशि के अपराध/अपराधों को शामिल किया गया है।

### प्रक्रिया

➔ किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए विशेष न्यायालय के समक्ष आवेदन करना होगा।

- ➔ भगोड़ा आर्थिक अपराधी होने के आरोपित व्यक्ति को विशेष न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा।
- ➔ नोटिस जारी होने के कम-से-कम 6 सप्ताह में व्यक्ति से निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होने की अपेक्षा होगी।

➔ विशेष न्यायालय के आदेश से अभियुक्त व्यक्ति के स्वामित्वाधीन संपत्ति, उसकी बेनामी संपत्ति तथा अपराध के आगम व संपत्ति, जैसा आवेदन में वर्णित हो, को कुर्क किया जा सकेगा।

➔ न्यायालय द्वारा जिस व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जाएगा, उसकी संपत्ति को जब्त कर उसे केंद्र सरकार में निहित किया जा सकता है।

➔ ऐसे अपराधी की बेनामी संपत्ति सहित भारत और विदेशों में अन्य संपत्ति को जब्त किया जा सकता है।

➔ भगोड़े आर्थिक अपराधी को किसी सिविल दावे को दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

### भगोड़ा आर्थिक अपराधी

➔ भगोड़ा आर्थिक अपराधी को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके खिलाफ किसी अपराध (100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की रकम का) के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है तथा जो मुकदमे से बचने के लिए देश छोड़ दिया हो या मुकदमे का सामना करने के लिए देश लौटने से मना कर रहा हो।



## पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, 2018

### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➔ 21 जुलाई, 2018 को सार्वजनिक मामलों के केंद्र (Public Affairs Centre) द्वारा सार्वजनिक मामलों के सूचकांक, 2018 (PAI: Public Affairs Index, 2018) को जारी किया गया।

### पृष्ठभूमि

➔ सार्वजनिक मामलों के सूचकांक (पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स) को सार्वजनिक मामलों के केंद्र द्वारा विकसित किया गया है।

- ➔ इसको विकसित करने का उद्देश्य भारत में शासन की गुणवत्ता में सुधार लाना है।

➔ यह सूचकांक वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है।

### पीआई रिपोर्ट, 2018

➔ इस रिपोर्ट में 10 व्यापक विषयों (Themes), 30 फोकस विषयों और 100 संकेतकों को समाहित किया गया है।

➔ इसके अतिरिक्त, भारत में बच्चों पर एक विशेष अध्ययन शामिल किया गया है, जिसमें हमारे भविष्य के नागरिकों के साथ व्यवहार के बारे में विभिन्न मुद्दों की चर्चा की गई है।





➔ इस रिपोर्ट में राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर बड़े और छोटे राज्यों में विभाजित किया गया है।

- ➔ 2 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्य, बड़े राज्य की श्रेणी में रखे गए हैं, जबकि 2 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्य छोटे राज्य की श्रेणी में हैं।

### सूचकांक, 2018

➔ सार्वजनिक मामलों के सूचकांक, 2018 के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है अर्थात् वह सर्वश्रेष्ठ प्रशासित भारतीय राज्य है।

- ➔ इसके बाद क्रमशः तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात का स्थान है।

➔ उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 से ही केरल शीर्ष स्थान पर बना हुआ है।

➔ छोटे राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है।

➔ आर्थिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में गुजरात शीर्ष पर है। वहीं वित्तीय प्रबंधन में तेलंगाना पहले स्थान पर है।

➔ पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में कर्नाटक पहले स्थान पर, वहीं पर्यावरण के क्षेत्र में भी कर्नाटक पहले स्थान पर है।

- ➔ न्याय की पहुंच के क्षेत्र में मिजोरम, अपराध कानून तथा

आदेश के क्षेत्र में नगालैंड, महिलाएं एवं बच्चों के संदर्भ में मिजोरम शीर्ष पर है।

- ➔ सामाजिक सुरक्षा में ओडिशा, मानव विकास को सहयोग में सिक्किम तथा आवश्यक आधारभूत संरचना के क्षेत्र में गोवा शीर्ष स्थान पर है।

➔ बच्चों के अनुकूल राज्यों में क्रमशः केरल, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम प्रथम तीन स्थानों पर हैं।

सार्वजनिक मामलों के सूचकांक, 2018 (समग्र)			
उच्चतम स्थान		निम्नतम स्थान	
राज्य	रैंक	राज्य	रैंक
केरल	1	बिहार	30
तमिलनाडु	2	मेघालय	29
तेलंगाना	3	झारखंड	28
हिमाचल प्रदेश	4	मणिपुर	27
कर्नाटक	5	मध्य प्रदेश	26
गुजरात	6	उत्तर प्रदेश	25
महाराष्ट्र	7	ओडिशा	24
पंजाब	8	नगालैंड	23
आंध्र प्रदेश	9	दिल्ली	22
गोवा	10	जम्मू एवं कश्मीर	21

## विदर्भ, मराठवाड़ा : सिंचाई परियोजना विशेष पैकेज

### पृष्ठभूमि

➔ वर्ष 2012 से 2016 के मध्य महाराष्ट्र ने जलीय एवं कृषीय सूखे का सामना किया है। सूखे की स्थिति विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में सबसे अधिक भयावह होने के कारण इन क्षेत्रों में किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की दर सर्वाधिक रही है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के कई अन्य क्षेत्रों में भी सूखे के हालात हैं। राज्य में कई सिंचाई परियोजनाएं वित्तपोषण के अभाव के चलते अधर में लटकी हुई हैं।

### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➔ 18 जुलाई, 2018 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने मराठवाड़ा, विदर्भ तथा शेष महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में केंद्र प्रायोजित 91 सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मंजूरी दी।

- ➔ इनमें से 83 लघु सिंचाई परियोजनाएं, जबकि 8 बृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं।

### संबंधित तथ्य

➔ इस विशेष पैकेज से मराठवाड़ा, विदर्भ तथा शेष महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 3.77 लाख हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन में मदद मिलेगी।

➔ विशेष पैकेज के तहत शामिल परियोजनाएं, महाराष्ट्र की 8.501

हेक्टेयर अधिकतम क्षमता वाली 26 बृहद/मध्यम परियोजनाओं के अतिरिक्त हैं।



- ➔ इन 26 परियोजनाओं का वित्तपोषण प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (PMKSY-AIBP) के अंतर्गत किया जा रहा है।

- ➔ इनको दिसंबर, 2019 तक पूर्ण किए जाने की योजना है।
- ➔ परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी राज्य के साथ-साथ केंद्रीय जल आयोग द्वारा की जानी है।
- ➔ योजना के क्रियान्वयन से 341 लाख अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा।

### वित्तीय संभावनाएं

➔ 1 अप्रैल, 2018 को इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 13651.61 करोड़ रुपये है।

- ➔ इसमें केंद्र का योगदान 3831.41 करोड़ रुपये है। शेष राशि महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।
- ➔ महाराष्ट्र सरकार को यह राशि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से कर्ज के रूप में प्राप्त होगी।

## विपो कॉपीराइट, प्रदर्शन व फोनोग्राम संधि, 1996

### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➔ 4 जुलाई, 2018 को केंद्र सरकार द्वारा 'WIPO कॉपीराइट संधि, 1996' तथा 'WIPO प्रदर्शन तथा फोनोग्राम संधि, 1996' को स्वीकार किए जाने के 'औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग' (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।

- ☉ यह स्वीकृति 12 मई, 2016 को केंद्र सरकार द्वारा अंगीकृत 'राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति' में वर्णित उद्देश्य के तहत एक कदम है।

### इन संधियों से भारत को लाभ

- ➔ अंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट प्रणाली के माध्यम से रचनात्मक अधिकार धारकों को उनके श्रम का मूल्य प्राप्त होगा।
- ➔ रचनात्मक कार्यों के उत्पादन और उनके वितरण में किए जाने वाले निवेश पर लाभ प्राप्त होगा।
- ➔ घरेलू कॉपीराइट धारकों को अंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट की सुरक्षा सुविधा मिलेगी।
- ➔ दूसरे देशों में प्रतिस्पर्धा में समान अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि भारत विदेशी कॉपीराइट को मान्यता देता है।
- ➔ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रचनात्मक उत्पादों के निर्माण और वितरण में किए जाने वाले निवेश पर लाभ प्राप्त होगा और इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा।

➔ व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और जीवंत रचनात्मक अर्थव्यवस्था तथा एक सांस्कृतिक परिदृश्य का विकास होगा।

### पृष्ठभूमि

➔ विपो कॉपीराइट संधि 6 मार्च, 2002 को लागू हुई थी।

- ☉ इस संधि को अब तक 96 पक्षों ने अपनाया है।
- ☉ बर्न कन्वेंशन (साहित्यिक और कलात्मक रचनाओं की सुरक्षा के लिए) के तहत यह एक विशेष समझौता है।
- ☉ इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी कॉपीराइट सुरक्षा पर आधारित प्रावधान शामिल हैं।
- ➔ विपो प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि (WPPT) 20 मई, 2002 को लागू हुई थी और इसके 96 सदस्य हैं।
  - ☉ डब्ल्यूपीपीटी (WPPT) दो प्रकार के लाभार्थियों के अधिकारों, विशेष रूप से डिजिटल वातावरण में, से संबंधित है- 1. कलाकार (अभिनेता, गायक, संगीतकार आदि), 2. फोनोग्राम के उत्पादक (ध्वनि रिकॉर्ड)।
- ➔ दोनों ही संधियां रचनाकारों को तकनीकी सुविधाओं का उपयोग करते हुए रचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए फ्रेमवर्क उपलब्ध कराती हैं।



## 'खुशी' (हैप्पीनेस) पाठ्यक्रम

### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

- ➔ जुलाई, 2018 में दिल्ली सरकार ने अपने स्कूली छात्रों (नर्सरी से आठवीं कक्षा तक) के लिए 'खुशी (Happiness) पाठ्यक्रम' का शुभारंभ किया।
- ➔ खुशी पाठ्यक्रम बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा की उपस्थिति में लांच किया गया।

### उद्देश्य

➔ स्कूली छात्रों के शारीरिक विकास के साथ-साथ उनके मानसिक विकास का भी मार्ग प्रशस्त करना, जिससे उनके मन के क्रोध, घृणा, दंभ व ईर्ष्या जैसी नकारात्मक और सामाजिक विघटनकारी भावनाओं को दूर किया जा सके।

### पाठ्यक्रम का विवरण

- ➔ खुशी पाठ्यक्रम 6 महीने की अवधि में दिल्ली सरकार के 40 शिक्षकों, शिक्षाविदों और स्वयंसेवकों के एक संयुक्त समूह ने मिलकर तैयार किया है।
- ➔ इस पाठ्यक्रम में दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में नर्सरी से लेकर आठवीं तक के सभी छात्र-छात्राओं के लिए 45 मिनट का एक 'हैप्पीनेस' पीरियड होगा, जिसके तहत ध्यान, कहानियां, प्रश्नोत्तर सत्र तथा मानसिक अभ्यास को शामिल किया जाना है।

- ➔ प्रत्येक कक्षा का प्रारंभ एवं अंत 5 मिनट के ध्यान (Meditation) से होगा।
- ➔ इस पाठ्यक्रम में 10 लाख छात्र और करीब 50 हजार शिक्षकों के शामिल होने की उम्मीद है।



- ☉ पाठ्यक्रम के तहत, बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन 'खुशी सूचकांक' का उपयोग करके किया जाएगा।
- ➔ दिल्ली सरकार की इस पहल से 8-10 लाख छात्रों के लाभान्वित होने का अनुमान है।

### अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- ➔ उल्लेखनीय है कि जुलाई, 2016 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के नागरिकों में खुशहाली के प्रसार तथा मनोवैज्ञानिकों की सहायता से लोगों को सदैव खुश रहने हेतु परामर्श उपलब्ध कराने के लिए आनंद विभाग (Happiness Department) की स्थापना की घोषणा की थी।
- ☉ मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है, जिसने आनंद विभाग की स्थापना की है।

## भूटान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा

### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➔ 5-7 जुलाई, 2018 के मध्य भूटान के प्रधानमंत्री डाशो शेरींग तोबगे (Dasho Tshering Tobgay) ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की।

### पृष्ठभूमि

➔ वर्ष 1949 में दोनों देशों के मध्य हस्ताक्षरित मैत्री और सहयोग संधि ही भारत-भूटान द्विपक्षीय संबंधों की बुनियाद के रूप में है।

☉ इस संधि को फरवरी, 2007 में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक की भारत यात्रा के दौरान नवीकृत किया गया। इसके तहत भूटान अपनी विदेश नीति का स्वतंत्र निर्धारक बन गया है।

➔ भारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंध थिंपू में भारत के रेजीडेंट प्रतिनिधि की नियुक्ति के साथ वर्ष 1968 में स्थापित हुए थे।

### महत्वपूर्ण तथ्य

➔ भारत और भूटान वर्ष 2018 में अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं।

➔ सद्यः यात्रा के दौरान

भूटान के प्रधानमंत्री ने भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की।

➔ 6 जुलाई, 2018 को उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की।

➔ ध्यातव्य है कि महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति रखने के कारण भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के पश्चात अपने पहले विदेशी दौरे के लिए भूटान को चुना था।



## उत्तर प्रदेश : वन महोत्सव, 2018

### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➔ 1-31 जुलाई, 2018 के मध्य उत्तर प्रदेश में 'वन महोत्सव', 2018' आयोजित किया गया।

➔ 6 जुलाई, 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी जिले के महादेवा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में 'वन महोत्सव, 2018' का शुभारंभ किया।

### उद्देश्य

➔ इसका उद्देश्य प्रदेश में पौधों का व्यापक रूप से रोपण करना और सभी विभागों द्वारा समन्वित रूप से पर्यावरण संरक्षण के अभियान के लक्ष्य को पूरा करना है।

➔ महोत्सव के उद्देश्यों में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा एक वृक्ष लगाने का संकल्प लेना शामिल था।

### महोत्सव का विवरण

➔ महोत्सव के दौरान यूकेलिप्टस के अतिरिक्त औषधीय गुण और धार्मिक महत्ता वाले वृक्ष यथा-पीपल, पाकड़, नीम और बरगद आदि लगाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

☉ ज्ञातव्य है कि पीपल का वृक्ष पर्यावरण के लिए सर्वाधिक उपयोगी है।

➔ 9 करोड़ पौधों को

लगाने के लक्ष्य के तहत स्कूल, कॉलेजों और कार्यालयों के आस-पास की भूमि पर वृक्षारोपण किया गया।

➔ वन महोत्सव के अवसर पर 3 लाख 66 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए।

➔ इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने प्रकृति और जीव-जंतुओं के साथ समन्वय पर जोर दिया और सभी को वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया।

☉ उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में तत्कालीन सरकार ने 24 घंटे में 5 करोड़ पौधे लगाकर अपना नाम 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' में दर्ज कराया था।



## प्रवासियों और स्वदेश वापसी करने वाले लोगों हेतु बृहत योजना

### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➔ 4 जुलाई, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 'प्रवासियों और स्वदेश वापसी करने वाले लोगों के राहत एवं पुनर्वास' (Relief and Rehabilitation of Migrants and Repatriates) की गृह मंत्रालय की मौजूदा 8 योजनाओं को

मार्च, 2020 तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की गई।

### वित्तीय प्रावधान

➔ इन योजनाओं हेतु वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए 3183 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।



➔ योजनांतर्गत वर्षवार वित्तीय आवंटन वर्ष 2017-18 में 911 करोड़ रुपये, वर्ष 2018-19 में 1372 करोड़ रुपये और वर्ष 2019-2020 में 900 करोड़ रुपये होगा।

### योजना से लाभ

➔ उक्त योजनाओं के माध्यम से शरणार्थियों, विस्थापित लोगों, आतंकवादी/सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवाद की हिंसा से पीड़ित नागरिकों और भारतीय क्षेत्र में सीमा पार गोलीबारी एवं खान/आईईडी (MINE/IED) विस्फोट तथा विभिन्न घटनाओं के दंगा पीड़ितों आदि को राहत एवं पुनर्वास प्रदान किया जाएगा।

### योजनाओं का विवरण

➔ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जारी रखने की स्वीकृति प्राप्त 8 योजनाओं का वर्तमान में कार्यान्वयन किया जा रहा है और अनुमोदित मानदंड के अनुसार प्रत्येक योजना के लाभों को लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाया जाएगा।

### ये 8 योजनाएं हैं-

(i) पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर (PoJK) एवं छांब (Chhamb) से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए एकमुश्त केंद्रीय सहायता।

- (ii) भूमि सीमा समझौते के तहत भारत और बांग्लादेश के मध्य बस्तियों (Enclaves) के हस्तांतरण के पश्चात बांग्लादेशी बस्तियों एवं कूच बिहार जिले में अवसंरचना का उन्नयन तथा पुनर्वास पैकेज।
- (iii) तमिलनाडु और ओडिशा में शिविरों में रह रहे श्रीलंकाई शरणार्थियों को राहत सहायता।
- (iv) तिब्बती बस्तियों के प्रशासनिक और सामाजिक कल्याण व्यय हेतु पांच वर्ष के लिए 'केंद्रीय तिब्बती राहत समिति' (CTRC) को अनुदान सहायता।
- (v) त्रिपुरा के राहत शिविरों में रह रहे ब्रु (BRU) जनजाति के रख-रखाव के लिए त्रिपुरा सरकार को अनुदान सहायता।
- (vi) त्रिपुरा के ब्रु/रियांग (BRU/REANG) परिवारों का मिजोरम में पुनर्वास।
- (vii) वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के आश्रितों को 5 लाख रुपये का वृद्धित राहत अनुदान।
- (viii) आतंकवादी/सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवाद की हिंसा और भारतीय क्षेत्र में सीमा पार गोलीबारी तथा खान/आईईडी विस्फोट से पीड़ितों के परिवार/पीड़ित नागरिकों की सहायता के लिए केंद्रीय योजना।

## दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

### वर्तमान परिदृश्य

➔ 8-11 जुलाई, 2018 के मध्य दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जाइ-इन ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की।

➔ वर्ष 2017 में कार्यभार ग्रहण करने के बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा थी।

➔ राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी किम जुंग-सूक तथा प्रतिनिधिमंडल भी था।

### उद्देश्य

➔ दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की यात्रा का उद्देश्य शीर्ष भारतीय नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर साझा हितों से जुड़े विषयों पर चर्चा करना तथा दक्षिण कोरिया और भारत के रिश्तों को एक नया आयाम देना है।

### यात्रा का विवरण

➔ 9 जुलाई, 2018 को दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने भारत के उपराष्ट्रपति वैकैया नायडू और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ वार्ता की।

➔ दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने भारत-कोरिया व्यवसाय मंच के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

➔ 9 जुलाई, 2018 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने मेट्रो द्वारा 'मंडी हाउस' से नोएडा के 'बॉटैनिकल

गार्डन' मेट्रो स्टेशन तक की यात्रा टोकन खरीदकर आम जनता के साथ की।

➔ 9 जुलाई, 2018 को नोएडा, उत्तर प्रदेश में विश्व

की सबसे बड़ी मोबाइल उत्पादन फैक्ट्री का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से किया।

➔ 35 एकड़ क्षेत्र में फैली इस फैक्ट्री में सैमसंग ने लगभग 4915 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

➔ 10 जुलाई, 2018 को हैदराबाद हाउस में भारतीय प्रधानमंत्री और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के बीच आधिकारिक वार्ता हुई।

➔ दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति अपनी पत्नी किम जुंग-सूक के साथ राजघाट भी गए, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता 'महात्मा गांधी' को श्रद्धांजलि अर्पित की।

➔ दोनों देशों के बीच वर्ष 2017 में 20 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय कारोबार को वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 50 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है।

### दोनों देशों के मध्य समझौता-ज्ञापन / समझौते

➔ उन्नत व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) के प्रारंभिक हार्वैस्ट पैकेज पर संयुक्त वक्तव्य।

➔ व्यापारिक सुधार पर समझौता-ज्ञापन।



- ➔ भविष्य रणनीति समूह पर समझौता-ज्ञापन।
- ➔ 2018-2022 की अवधि के लिए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम।
- ➔ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (C.S.I.R.) और नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (N.S.T.) के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन।
- ➔ रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड आर्गनाइजेशन (R.D.S.O.) और कोरिया रेलरोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (K.R.R.I.) के बीच सहयोग पर समझौता-ज्ञापन।

- ➔ जैव-प्रौद्योगिकी और जैव-अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन।
- ➔ आई.सी.टी. और दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन।
- ➔ भारत और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन।
- ➔ गुजरात सरकार और कोरिया व्यापार संवर्धन एजेंसी (KOTRA) के बीच समझौता-ज्ञापन।
- ➔ रानी सुरिरत्ना स्मृति परियोजना के संबंध में समझौता-ज्ञापन।

## स्वास्थ्य मंत्रालय-इग्नू सहयोग समझौता

### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

- ➔ 25 जून, 2018 को स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

### समझौते का उद्देश्य

- ➔ इस समझौते का उद्देश्य 'आयुष्मान भारत : राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' के अंतर्गत स्थापित होने वाले 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों हेतु वर्ष 2025 तक 14 लाख प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों को तैयार करना है।

- ➔ इसके लिए इग्नू के विद्यमान प्लेटफार्म से स्वास्थ्य संबंधी 10 पाठ्यक्रमों को संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

### संबंधित तथ्य

- ➔ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में कुशल, प्रशिक्षित पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 2025 तक 14 लाख युवाओं को

प्रशिक्षित किया जाएगा।

- ➔ यह समझौता-ज्ञापन 'स्किल्स फॉर लाइफ, सेव ए लाइफ' पहल के मौजूदा ढांचे के तहत है, जिसके



अंतर्गत जून, 2017 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 10 अल्पकालिक पाठ्यक्रम औपचारिक रूप से जारी किए गए थे।

- ➔ समझौते के तहत इग्नू (IGNOU) में एक समर्पित प्रकोष्ठ (cell) की स्थापना की जाएगी, जो स्वास्थ्य क्षेत्र के पाठ्यक्रमों के विकास, क्रियान्वयन व कौशल आधारित कार्यक्रमों को प्रमाणित करने का कार्य करेगा।

- ➔ गौरतलब है कि देशभर में 200 से अधिक प्रशिक्षक एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित 35 प्रशिक्षण संस्थान, इस तरह के पाठ्यक्रमों का संचालन पहले से ही कर रहे हैं।

## बेनामी लेन-देन मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018

### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

- ➔ हाल ही में आयकर विभाग द्वारा 'बेनामी लेन-देन मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018' (Benami Transactions Informants Reward Scheme, 2018) की शुरुआत की गई है।

### उद्देश्य

- ➔ इस योजना का उद्देश्य काले धन का पता लगाने और कर अपवंचन में कमी लाने के आयकर विभाग के प्रयासों में लोगों की भागीदारी बढ़ाना है।

### लक्ष्य

- ➔ इस पुरस्कार योजना का लक्ष्य लोगों को बेनामी लेन-देन और परिसंपत्तियों के साथ-साथ छिपे निवेशकों एवं लाभकारी मालिकों द्वारा ऐसी संपत्तियों से अर्जित आय के संबंध में सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करना है।

### विशेषताएं

- ➔ बेनामी लेन-देन मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018 की शुरुआत 'बेनामी परिसंपत्ति लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988' यथा-संशोधित बेनामी लेन-देन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के तहत कार्रवाई योग्य बेनामी परिसंपत्ति की सूचना देने वाले मुखबिरों के लिए की गई है।
- ➔ योजना के तहत बेनामी परिसंपत्ति की विशिष्ट सूचना देने के लिए कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपये तक का पुरस्कार प्राप्त कर सकता है।
- ➔ विदेशी भी इस तरह के पुरस्कार के लिए पात्र होंगे।
- ➔ मुखबिर की पहचान, उसके द्वारा दी गई सूचना अथवा उसे दिए गए पुरस्कार का खुलासा किसी व्यक्ति/प्राधिकरण के समक्ष नहीं किया जाएगा।





### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

- ➔ 31 जुलाई, 2018 को प्रथम 'भारत-नेपाल थिंक टैंक सम्मेलन' का आयोजन काठमांडू, नेपाल में किया गया।
- ➔ इस सम्मेलन का मुख्य विषय था - "भारत-नेपाल संबंधों को प्रोत्साहन : विचार-मंच की भूमिका" (Promoting Nepal-India Relation : The Role of Think Tank)।

### उद्देश्य

- ➔ सम्मेलन का उद्देश्य दोनों देशों के विचार मंचों के बीच आपसी सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान में वृद्धि करना है।

### सम्मेलन : ज्ञान बिंदु

- ➔ इस सम्मेलन का आयोजन 'एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स' (AIDIA) और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी (NMML) की संयुक्त मेजबानी में किया गया।
- ➔ सम्मेलन का उद्घाटन नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (CPN) के सह-अध्यक्ष पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' द्वारा किया गया।

☞ भाजपा महासचिव राम माधव सम्मेलन के मुख्य वक्ता थे।

- ➔ सम्मेलन में नीति-निर्माता, सरकार के प्रतिनिधि, राजनयिक, उद्यमी,

शिक्षाविद, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता आदि लोगों ने भाग लिया।

- ➔ इस सम्मेलन को प्रति वर्ष दोनों देशों में बारी-बारी से आयोजित किए जाने की योजना है।

### सम्मेलन का महत्व

- ➔ यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि मधेसी आंदोलन और नेपाल में सत्ता परिवर्तन के कारण दोनों देशों के संबंध निम्न स्तर पर पहुंच गए थे।
- ➔ भारत और नेपाल में रोटी-बेटी का रिश्ता है। अतः इस प्रकार के सम्मेलन सामाजिक व सांस्कृतिक संबंधों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगे।

### अन्य तथ्य

- ➔ नेपाल, भारत के साथ लगभग 1850 किमी. लंबी सीमा साझा करता है।
- ☞ इसकी सीमा भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों को स्पर्श करती है।



## दिल्ली संवाद का 10वां संस्करण

### पृष्ठभूमि

- ➔ दिल्ली संवाद भारत और आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन) देशों के मध्य राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक भागीदारी पर चर्चा करने के लिए एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है।

☞ राजनय की शब्दावली में इसे ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी की संज्ञा दी जाती है।

### आयोजनकर्ता

- ➔ दिल्ली संवाद (Delhi Dialogue) का आयोजन दिल्ली स्थित स्वायत्त नीति अनुसंधान संस्था-आर.आई.एस. (RIS – Research

and Information System for Developing Countries) की साझेदारी में विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया।

### 10वां संस्करण

- ➔ दिल्ली संवाद के 10वें संस्करण का आयोजन 19-20 जुलाई, 2018 के मध्य नई दिल्ली में किया गया।
- ➔ इस आयोजन में भारत और आसियान सदस्य राष्ट्रों के राजनीतिज्ञ, नीति-निर्माता, वरिष्ठ अधिकारी, राजनयिक, व्यापारिक नेतृत्वकर्ता एवं अन्य विचारकों ने प्रतिभाग किया।



➔ दिल्ली संवाद के 10वें संस्करण की थीम 'भारत-आसियान समुद्री सहयोग को सुदृढ़ बनाना' (Strengthening India-ASEAN Maritime Co-operation) है।

#### चर्चा के विषय

- ➔ दिल्ली संवाद के 10वें संस्करण में निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई-
  - ⊙ एक्ट ईस्ट में उत्तर-पूर्व की भूमिका : आसियान के साथ संयोजकता बनाना।
  - ⊙ सामाजिक-सांस्कृतिक संबंध को सुदृढ़ करना।
  - ⊙ भारत-आसियान साझेदारी और उभरते वैश्विक परिवेश।
  - ⊙ लघु एवं मध्यम उद्यम और क्षेत्रीय विकास।

⊙ ई-वाणिज्य और डिजिटल संयोजकता।

⊙ पर्यटन सहयोग और स्मार्ट शहरों का निर्माण।

➔ भारत और आसियान देश समुद्री साझेदार होने के साथ ही पड़ोसी भी हैं।

⊙ दोनों पक्षों ने वार्ता के दौरान महासागरों और जलमार्गों की सुरक्षा व स्थायित्व सुनिश्चित करने हेतु सहमति दी।

➔ एक्ट ईस्ट पॉलिसी की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उत्तर-पूर्व राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी दिल्ली संवाद के 10वें संस्करण में प्रतिभाग किया।

## वैश्विक दिव्यांगता शिखर सम्मेलन, 2018

#### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➔ 24 जुलाई, 2018 को पहले वैश्विक दिव्यांगता शिखर सम्मेलन (Global Disability Summit) का आयोजन लंदन (यू.के.) में किया गया।

#### आयोजक

➔ सम्मेलन का आयोजन यू.के. सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगता गठबंधन (International Disability Alliance) और केन्या सरकार की सह-मेजबानी में किया गया।

#### उद्देश्य

- ➔ सम्मेलन का उद्देश्य दिव्यांगजनों के कल्याण के प्रति विभिन्न देशों के नेताओं की प्रतिबद्धता को बढ़ाना था।
- ➔ साथ ही दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार हेतु नवाचार तथा प्रौद्योगिकी द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका पर प्रकाश डालना था।

#### अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

➔ सम्मेलन में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

➔ सम्मेलन का आयोजन क्वीन एलिजाबेथ ओलंपिक पार्क, लंदन में किया गया।

➔ ध्यातव्य है कि ओलंपिक पार्क, लंदन में वर्ष 2012 के पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया गया था।

#### भारत तथा विश्व में दिव्यांगता

- ➔ विश्व में अनुमानित एक बिलियन लोग दिव्यांगता के शिकार हैं, जिनमें से 800 मिलियन लोग विकासशील देशों में रहते हैं।
- ➔ वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में दिव्यांगजनों की संख्या 26.8 मिलियन है, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है।



## विश्व शहर शिखर सम्मेलन, 2018

#### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➔ 8-12 जुलाई, 2018 के मध्य द्विवार्षिक 'विश्व शहर शिखर सम्मेलन, 2018' (World Cities Summit, 2018) का आयोजन सैंड्स एक्सपो एंड कन्वेंशन सेंटर, मैरिना बे सैंड्स, (Sands Expo & Convention Center, Marina Bay Sands) सिंगापुर में किया गया।

➔ इस सम्मेलन के साथ ही सिंगापुर इंटरनेशनल वाटर वीक (SIWW) और क्लीन एनवायरो समिट सिंगापुर (CESS : Clean Enviro Summit Singapore) का भी आयोजन किया गया।

#### मुख्य विषय

➔ वर्ष 2018 के विश्व शहर शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय (Theme) 'निवासयोग्य और टिकाऊ शहर : नवाचार एवं सहयोग के माध्यम से भविष्य को अपनाना' (Liveable & Sustainable Cities : Embracing the Future Through Innovation and Collaboration) था।

#### सम्मेलन का विवरण

➔ छठवें विश्व शहर शिखर सम्मेलन, 2018 में 128 शहरों के लगभग 130 मेयर और सिटी लीडर (Mayors and City Leaders) शामिल हुए।



☛ सम्मेलन में शामिल 128 शहरों में से 67 शहरों ने पहली बार इसमें भागीदारी की।

- ➔ सम्मेलन के दौरान सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में शहरों और हितधारकों के मध्य सहयोग हेतु 16 समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए।
- ➔ सम्मेलन में 110 देशों एवं क्षेत्रों के 24000 से अधिक सरकारी अधिकारी, शहरी विशेषज्ञ, शिक्षाविद आदि शामिल हुए।

#### अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- ➔ द्विवार्षिक विश्व शहर शिखर सम्मेलन निवासयोग्य एवं टिकाऊ

शहर चुनौतियों का समाधान करने, एकीकृत शहरी समाधान साझा करने और नई साझेदारी बनाने हेतु सरकारी नेताओं (Government Leaders) और उद्योग विशेषज्ञों का एक व्यापक मंच है।

- ➔ 7वें विश्व शहर शिखर सम्मेलन, 2020 का आयोजन 5-9 जुलाई, 2020 के मध्य सिंगापुर में किया जाएगा।
- ➔ 10-12 जुलाई, 2019 के मध्य 'विश्व शहर शिखर सम्मेलन मेयर मंच, 2019' का आयोजन मेडेलिन, कोलंबिया में किया जाएगा।

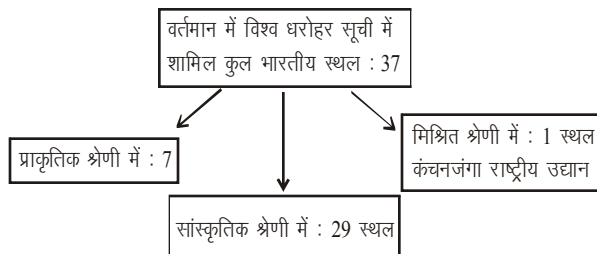
## विश्व धरोहर समिति की 42वीं बैठक

### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

- ➔ यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति (World Heritage Committee) की 42वीं वार्षिक बैठक 24 जून से 4 जुलाई, 2018 के मध्य मनामा (बहरीन) में संपन्न हुई।
- ➔ इस बैठक के दौरान समिति द्वारा संपूर्ण विश्व के कुल 19 नए स्थलों की यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया।
- ➔ इन नए स्थलों को शामिल किए जाने के उपरांत अब विश्व के 167 देशों में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 1092 हो गई है।

### विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नवीन भारतीय स्थल

- ➔ 30 जून, 2018 को दक्षिणी मुंबई स्थित विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको इमारतों के भव्य समूहों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है।
- ➔ एलिफेंटा गुफाओं और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन के बाद विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको इमारतें मुंबई का तीसरा स्थल है, जिसे यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है।
- ➔ ज्ञातव्य है कि विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको इमारतों के समूह को सांस्कृतिक स्थल (Cultural Sites) के रूप में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है।
- ➔ विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इमारतों का समूह 19वीं सदी के विक्टोरियन गोथिक भवनों तथा 20वीं सदी के आरंभ की आर्ट डेको शैली की वास्तुशिल्प का मिला-जुला रूप है।
- ➔ उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 41वीं बैठक पोलैंड में वर्ष 2017 में हुई थी, जिसमें अहमदाबाद शहर को सांस्कृतिक श्रेणी में भारत के पहले वैश्विक धरोहर शहर के रूप में मान्यता दी गई थी।



### विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रमुख विदेशी स्थल

- ➔ विश्व धरोहर समिति की 42वीं बैठक के दौरान भारत के अतिरिक्त जिन विदेशी स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, उनमें प्रमुख हैं-
  - नौम्बर्ग कैथेड्रल (जर्मनी)
  - कलहाट (Qalhat) का प्राचीन शहर (ओमान)
  - नागासाकी क्षेत्र में छिपे हुए ईसाई स्थल (जापान)
  - इवरीआ (Ivrea), 20वीं सदी का औद्योगिक नगर (इटली)
  - मदीना अजहारा का खलीफत शहर (स्पेन)

### संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थल

- ➔ विश्व धरोहर समिति की 42वीं बैठक में बेलीज बैरियर रीफ रिजर्व सिस्टम को 'विश्व की संकटग्रस्त धरोहरों की सूची' (List of World Heritage in Danger) से बाहर कर दिया गया।
  - ☛ उल्लेखनीय है कि मैंग्रोव एवं समुद्री पारिस्थितिकी के विनाश के चलते इस स्थल को वर्ष 2009 में विश्व की संकटग्रस्त धरोहरों की सूची में शामिल किया गया था।
- ➔ तुर्काना झील राष्ट्रीय उद्यान (केन्या) को विश्व की संकटग्रस्त धरोहरों की सूची में शामिल किया गया है।
- ➔ विश्व की संकटग्रस्त धरोहरों की सूची में भारत का कोई भी स्थल शामिल नहीं है।



## म्यांमार अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल

### चर्चा में क्यों?

➔ जुलाई, 2018 में म्यांमार 'अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन' (ISA) में 68वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ।

☞ दिल्ली डायलाग के पार्श्व में आयोजित द्विपक्षीय बैठक के दौरान म्यांमार के अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्री क्याव तिन ने ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके अपनी सहमति व्यक्त की।

### अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन

➔ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की परिकल्पना सौर संसाधन समृद्ध देशों के एक गठबंधन के रूप में की गई थी, जिससे इन देशों की विशिष्ट ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

➔ पेरिस में 30 नवंबर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को लांच किया था।

### ISA का विवरण

➔ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कर्क तथा मकर रेखा के मध्य आंशिक या पूर्ण रूप से अवस्थित सौर संसाधन संपन्न देशों का एक अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन है।

➔ इसका मुख्यालय

गुरुग्राम (हरियाणा) में है।

➔ संयुक्त राष्ट्र के ऐसे

सदस्य देश, जो कर्क एवं

मकर रेखा के मध्य स्थित

नहीं हैं, वे अंतरराष्ट्रीय

सौर गठबंधन में 'साझेदार देशों' (Partner Countries) के रूप में

शामिल हो सकते हैं।

➔ संयुक्त राष्ट्र (UN) अपने विभिन्न अंगों एवं निकायों सहित अंतरराष्ट्रीय

सौर गठबंधन में 'रणनीतिक भागीदार' (Strategic Partner) के रूप

में शामिल हो सकता है।

### अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

➔ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन 11 मार्च, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

➔ भारत सरकार ने देश में वर्ष 2022 तक 175 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा के रूप में, 60 गीगावॉट पवन ऊर्जा, 1 गीगावॉट जैव-ऊर्जा तथा 5 गीगावॉट लघु जल-विद्युत ऊर्जा के रूप में स्थापित की जाएगी।



## भारत : एआईबीडी का नया अध्यक्ष

### एआईबीडी

➔ एआईबीडी, एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का संक्षिप्त रूप है।

➔ एआईबीडी एक क्षेत्रीय अंतरसरकारी संगठन है, जिसका गठन वर्ष 1977 में यूनेस्को (UNESCO) के तत्वावधान में हुआ था।

☞ इसका सचिवालय कुआलालंपुर (मलेशिया) में स्थित है।

➔ गौरतलब है कि एआईबीडी, नीति एवं संसाधन विकास के माध्यम से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परिवेश की प्राप्ति हेतु अधिकृत है।

➔ वर्तमान में एआईबीडी के 26 पूर्णकालिक सदस्य (देश) हैं, जिनका प्रतिनिधित्व 34 संगठनों द्वारा किया जाता है।

☞ साथ ही एआईबीडी के 67 एफिलिएट सदस्य (संगठन) भी हैं।

### वर्तमान परिदृश्य

➔ 3 अगस्त, 2018 को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एआईबीडी

की 44वीं वार्षिक बैठक में भारत को 2 वर्ष के लिए AIBD की आम सभा का नया अध्यक्ष चुना गया।

➔ श्रीलंका को इसका उपाध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया है।

➔ भारत ने अध्यक्ष पद पर ईरान का स्थान ग्रहण किया, जिसका कार्यकाल इसी वर्ष समाप्त हुआ है।

➔ गौरतलब है कि एआईबीडी की 44वीं वार्षिक बैठक एवं 17वीं आम सभा (General Conference) का आयोजन 2-4 अगस्त, 2018 के मध्य कोलंबो (श्रीलंका) में हुआ।

### अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

➔ सम्मेलन के दौरान एआईबीडी वित्त व्यवस्था को पारदर्शी बनाने, बदलते मीडिया परिदृश्य में प्रशिक्षण मॉड्यूल (Training Modules)



में परिवर्तन करना, सामरिक योजना टीम को थिंक टैंक के रूप में बदलना जैसे सुधारों पर चर्चा हुई।

➔ एआईबीडी के नौ सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के चुनाव में ईरान, मालदीव और नेपाल नए सदस्यों के रूप में चुने गए, जबकि कम्बोडिया और पाकिस्तान पुनः सदस्य चुने गए।

➔ कार्यकारी बोर्ड के चार अन्य सदस्य भूटान, चीन, कोरिया और फिलीपींस हैं।

➔ गौरतलब है कि एआईबीडी के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य संस्थान के वार्षिक प्रदर्शन, प्रशासन और भविष्य की नीतियों के निर्माण के लिए वार्षिक बैठक करते हैं।

## भारत-अमेरिका : '2+2 वार्ता'

### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➔ भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के मध्य 6 जुलाई, 2018 को प्रस्तावित '2+2 वार्ता' को अमेरिका द्वारा स्थगित कर दिया गया।

- ➔ तत्पश्चात यह वार्ता 6 सितंबर, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित हुई।



### क्या है '2+2 वार्ता'?

➔ '2+2 वार्ता' की रूपरेखा जून, 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन डी.सी. यात्रा के दौरान बनी थी।

➔ गौरतलब है कि '2+2 वार्ता' में भारत की विदेश मंत्री एवं रक्षा मंत्री तथा अमेरिका के राज्य सचिव एवं रक्षा सचिव ने भाग लिया।

### वार्ता का उद्देश्य

➔ '2+2 वार्ता' का उद्देश्य भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय मुद्दों को हल करना है।

### वार्ता को स्थगित करने की पृष्ठभूमि

➔ '2+2 वार्ता' को स्थगित करने का कोई विशेष कारण अमेरिका की ओर से नहीं बताया गया, परंतु जानकारों का मानना था कि भारत एवं अमेरिका के मध्य वर्तमान में अनेक मुद्दों पर उभरे मतभेद, इस वार्ता के स्थगन का बहुत बड़ा कारण रहा।

➔ इस वार्ता को स्थगित करने की पृष्ठभूमि में भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा शुल्क को लेकर मतभेद उत्पन्न होना एवं भारत का ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका से अलग राय रखना है।

विज्ञापन



## तृतीय द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19

### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

- ➔ 1 अगस्त, 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली 'मौद्रिक नीति समिति' (MPC) द्वारा तृतीय द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19 (Third Bi-Monthly Monetary Policy Statement, 2018-19) जारी किया गया।
- ➔ मौद्रिक नीति समिति की इस 12वीं बैठक में नीतिगत दरों में बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया गया।
- ➔ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमुख दरों में वृद्धि के निर्णय से कर्ज के महंगे होने की संभावना बढ़ गई है।

### मुख्य निर्णय

- ➔ मौद्रिक नीति समिति द्वारा 'चलनिधि समायोजन सुविधा' (LAF) के अंतर्गत रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 6.50 प्रतिशत कर दिया गया, जबकि पूर्व की मौद्रिक नीति में यह 6.25 प्रतिशत थी।
- ➔ परिणामस्वरूप चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत रिवर्स रेपो दर भी 0.25 प्रतिशत बढ़कर 6.25 प्रतिशत, जबकि 'सीमांत स्थायी सुविधा' (MSF) और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर समायोजित हो गयी।
  - ➔ पूर्व में ये तीनों दरें क्रमशः 6 प्रतिशत, 6.50 प्रतिशत तथा 6.50 प्रतिशत के स्तर पर थीं।
- ➔ आरक्षित अनुपातों सीआरआर (CRR) तथा एसएलआर (SLR) में कोई परिवर्तन न करते हुए इसे वर्तमान स्तर (4% एवं 19.5%) पर ही बनाए रखा गया है।

### विश्लेषण

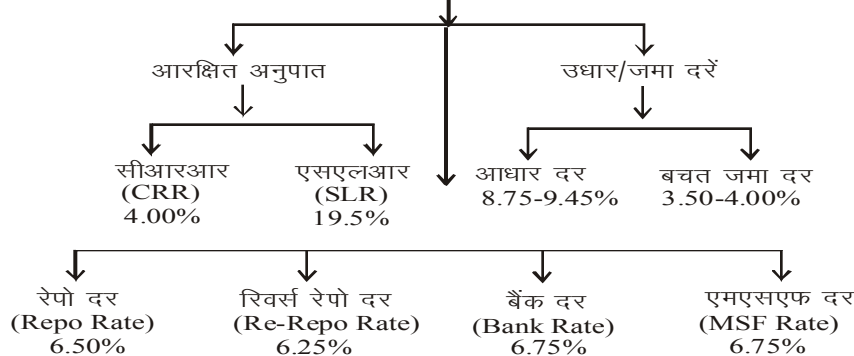
- ➔ रेपो दर में वृद्धि से उद्योग जगत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

- ➔ भविष्य में महंगाई बढ़ने की आशंका के आलोक में नीतिगत दरों में और भी वृद्धि की संभावना है।
- ➔ रिजर्व बैंक का अनुमान है कि वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही में महंगाई (CPI) की दर 4.7 प्रतिशत रह सकती है।



- ➔ आरबीआई ने इसके 8 कारण बताए हैं-
  1. कच्चे तेल की कीमतों में अनिश्चितता
  2. वैश्विक वित्तीय बाजार की अस्थिरता
  3. घरेलू महंगाई में वृद्धि
  4. राज्यों में आवासीय भत्ता बढ़ने के आसार
  5. मानसून का असमान क्षेत्रीय वितरण
  6. फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि
  7. औद्योगिक उत्पादन आगतों (Inputs) में वृद्धि तथा
  8. केंद्र और राज्यों के राजकोषीय घाटे
- ➔ छः सदस्यीय समिति के पांच सदस्यों डॉ. चेतन घाटे, डॉ. पामी दुआ, डॉ. माइकल देवब्रत पात्रा, डॉ. विरल वी. आचार्य तथा डॉ. उर्जित पटेल ने रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि का समर्थन किया, जबकि डॉ. रविंद्र एच. ढोलकिया ने निर्णय के खिलाफ मतदान किया।

### मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी नीतिगत दरें (1 अगस्त, 2018 को जारी)



## भारत में बैंक ऑफ चाइना की शाखा

### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

- ➔ जुलाई, 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा चीन के चार सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में से एक, बैंक ऑफ चाइना को भारत में अपनी बैंक शाखा खोलने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई।
- ➔ बैंक ऑफ चाइना ने इसके लिए आवेदन जुलाई, 2016 में किया था, परंतु डोकलाम गतिरोध के चलते अंतिम सहमति नहीं बन पाई थी।

### पृष्ठभूमि

- ➔ 9-10 जून, 2018 के मध्य चीन के किंगदाओ शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भारत एवं चीन के मध्य आर्थिक-व्यापारिक सहयोग पर सहमति बनी थी।

- ⊖ बैंक ऑफ चाइना की भारत में शाखा स्थापना को RBI की अनुमति इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है।

### बैंक ऑफ चाइना

- ➔ बैंक ऑफ चाइना वर्तमान में विश्व के 51 देशों में संचालित है।
- ⊖ यह बैंकों की निगरानी की 'बेसल समिति' द्वारा 'वैश्विक

व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक' (Global Systemically Important Bank) के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।



- ➔ बैंक ऑफ चाइना की शाखा खुलने के साथ ही भारत में संचालित विदेशी बैंकों की संख्या बढ़कर 46 हो जाएगी।

### अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- ➔ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (ICBC) वर्ष 2011 से भारत में संचालित है, इसकी शाखा मुंबई में है।
- ➔ वर्तमान में भारत के कुल 6 बैंकों को चीन में अपनी शाखाएं स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है।
- ⊖ ये बैंक हैं- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, एक्सिस बैंक तथा आईसीआईसीआई बैंक।

## फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची

### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

- ➔ जुलाई, 2018 में प्रतिष्ठित अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा 500 विश्व विख्यात कंपनियों की सूची 'ग्लोबल 500' जारी की गई है।

- ⊖ पत्रिका के अनुसार, वर्ष 2017 में विश्व की इन 500 सबसे बड़ी कंपनियों ने कुल 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर राजस्व तथा 1.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर लाभ प्राप्त किया है।

- ➔ विश्व के 33 देशों में स्थित इन 500 कंपनियों द्वारा विश्वभर में 67.7 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है।

### ग्लोबल 500 सूची

- ➔ वर्ष 2018 की इस सूची में विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में अमेरिकी रिटेल कंपनी 'वॉलमार्ट' को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है।

- ⊖ इसके पश्चात चीन की ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी 'स्टेट ग्रिड' दूसरे, 'सिनोपेक ग्रुप' (Sinopec Group) तीसरे तथा 'चाइना नेशनल पेट्रोलियम' चौथे स्थान पर है।

- ⊖ नीदरलैंड्स की कंपनी रायल डच शेल पांचवें स्थान पर है।

- ➔ वर्ष 2018 की 'फॉर्च्यून ग्लोबल 500' सूची में भारत की 7 कंपनियां शामिल हैं।

- ⊖ इस सूची में 65916 मिलियन अमेरिकी डॉलर राजस्व के साथ 'इंडियन ऑयल' 137वें स्थान पर काबिज है।

- ⊖ इसके पश्चात रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 148वें स्थान पर, ऑयल एंड नेचुरल गैस 197वें स्थान पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 216वें स्थान पर तथा टाटा मोटर्स 232वें स्थान पर है।

**FORTUNE**  
**500**  
2018

- ⊖ इनके अलावा सूची में भारत पेट्रोलियम (314वां स्थान) तथा राजेश एक्सपोर्ट (405वां स्थान) भी शामिल हैं।

- ➔ उल्लेखनीय है कि इस वर्ष शीर्ष 200 में भारत की तीन कंपनियां शामिल हैं, जबकि वर्ष 2017 की सूची में मात्र एक कंपनी 'इंडियन ऑयल' ही शामिल थी।

- ⊖ हिंदुस्तान पेट्रोलियम वर्ष 2017 की सूची में 384वें स्थान पर थी, परंतु इस वर्ष की सूची से वह बाहर है।

फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची, 2018 में शामिल शीर्ष पांच कंपनियां		
रैंक	कंपनी	राजस्व (\$ मिलियन)
1	वॉलमार्ट	500,343
2	स्टेट ग्रिड	348,903
3	सिनोपेक ग्रुप	326,953
4	चाइना नेशनल पेट्रोलियम	326,008
5	रॉयल डच शेल	311,870

फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची, 2018 में शामिल भारतीय कंपनियां		
भारत में रैंक	कंपनी	विश्व में रैंक
1	इंडियन ऑयल	137
2	रिलायंस इंडस्ट्रीज	148
3	ऑयल एंड नेचुरल गैस	197
4	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	216
5	टाटा मोटर्स	232
6	भारत पेट्रोलियम	314
7	राजेश एक्सपोर्ट	405

## फॉर्च्यून की 40 अंडर 40 सूची, 2018

### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➔ जुलाई, 2018 में 'फॉर्च्यून पत्रिका' द्वारा सर्वाधिक प्रभावशाली युवाओं की वार्षिक सूची '40 अंडर 40', 2018 (40 Under 40, 2018) जारी की गई।

- ➔ इस सूची में 40 वर्ष से कम आयु के उन युवाओं को जगह दी गई है, जिन्होंने अपने कार्य से अन्य लोगों को प्रोत्साहित किया है।

### 40 अंडर 40 सूची

➔ वर्ष 2018 की सूची में इंस्टाग्राम के सह-संस्थापक एवं सीईओ (CEO) केविन सिस्ट्रॉम तथा फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर हैं।

➔ लिफ्ट कंपनी (Lyft Company) के सह-संस्थापक 'लोगान ग्रीन' और 'जॉन जिमेर' को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

➔ तीसरे एवं चौथे स्थान पर क्रमशः चीनी कंपनी मितुआन-दियानपिंग के सह-संस्थापक एवं सीईओ वेंग जिंग (WangXing) तथा जनरल मोटर्स (GM) की मुख्य वित्त अधिकारी दिव्या सूर्यदेवरा हैं।

➔ पांचवें स्थान पर एअरबीएनबी (Airbnb) के सह-संस्थापक एवं सीईओ ब्रायन चेस्की हैं।

### सूची में भारत

➔ वर्ष 2018 की '40 अंडर 40' (40 Under 40) सूची में भारत/

भारतीय मूल के 4 व्यक्तियों ने स्थान बनाया है, जिसमें से तीन महिलाएं हैं।

- ➔ इनमें चौथे स्थान पर दिव्या सूर्यदेवरा, 14वें स्थान पर अंजलि

सूद (वीडियो शेयरिंग वेबसाइट विमियो की सीईओ), 24वें स्थान पर बैजू भट्ट (वित्तीय सेवाएं प्रदाता कंपनी राबिनहुड के सह-संस्थापक) तथा 32वें स्थान पर अनु दुग्गल (फीमेल फाउंडर्स फंड की संस्थापक) हैं।



### '40 अंडर 40', 2018 सूची में शीर्ष 5

रैंक	व्यक्ति	कंपनी
1	केविन सिस्ट्रॉम	इंस्टाग्राम (Instagram)
1	मार्क जुकरबर्ग	फेसबुक (Facebook)
2	लोगान ग्रीन और जॉन जिमेर	लिफ्ट (Lyft)
3	वेंग जिंग	मितुआन-दियानपिंग (Meituan-Dianping)
4	दिव्या सूर्यदेवरा	जनरल मोटर्स (General Motors)
5	ब्रायन चेस्की	एअरबीएनबी (Airbnb)

## द सॉफ्ट पॉवर 30, 2018

### पृष्ठभूमि

➔ 'सॉफ्ट पॉवर' शब्द की अवधारणा सबसे पहले वर्ष 1990 में हॉवर्ड विश्वविद्यालय के जोसेफ नये (Joseph Nye) ने अपनी पुस्तक 'Bound to lead: The Changing Nature of American Power' में दी थी।

➔ सॉफ्ट पॉवर शब्द का उपयोग उस क्षमता के लिए किया जाता है, जिससे दूसरों को बिना ताकत या धमकी का प्रयोग किए ही अपनी बातों को मानने के लिए तैयार किया जा सके।

- ➔ पारंपरिक रूप से 'हार्ड पॉवर' (Hard Power) जहां राज्य के सैन्य और आर्थिक संसाधनों पर निर्भर होती है, वहीं सॉफ्ट पॉवर (Soft Power) के तहत अपने को आकर्षक बनाकर किसी अन्य की सहमति प्राप्त की जाती है।

- ➔ सॉफ्ट पॉवर के तीन स्तंभ हैं- राजनीतिक मूल्य, संस्कृति तथा विदेश नीति।

### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➔ जुलाई, 2018 में यूनाइटेड किंगडम स्थित सामरिक सूचना सलाहकारी संस्था पोर्टलैंड एवं दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सार्वजनिक कूटनीति केंद्र (USC: Center on Public Diplomacy) द्वारा संयुक्त रूप

से 'द सॉफ्ट पॉवर 30' रिपोर्ट के वर्ष 2018 का संस्करण (चौथा संस्करण) प्रकाशित किया गया।

➔ यह सूचकांक 6 श्रेणियों यथा-सरकार (Government), संस्कृति (Culture), शिक्षा (Education), वैश्विक अनुबंध (Engagement), उद्यम (Enterprise) तथा डिजिटल (Digital) के आधार पर तैयार किया गया है।



## देशों की स्थिति

➔ 30 देशों की इस सूची में 80.55 स्कोर के साथ यूनाइटेड किंगडम शीर्ष पर है।

☉ इसके पश्चात दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः फ्रांस (स्कोर: 80.14) और जर्मनी (स्कोर 78.87) हैं।

☉ चौथे एवं पांचवें स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका (स्कोर 77.80) तथा जापान (स्कोर 76.22) हैं।

➔ इस सूचकांक में अंतिम स्थान (30वें) पर अर्जेंटीना है, जिसका प्राप्तांक 48.89 है।

सॉफ्ट पॉवर 30 रैंकिंग, 2018 में शीर्ष 5 देश		
रैंक	देश	प्राप्तांक
1	यूनाइटेड किंगडम	80.55
2	फ्रांस	80.14
3	जर्मनी	78.87
4	संयुक्त राज्य अमेरिका	77.80
5	जापान	76.22

➔ इस वर्ष की रिपोर्ट में विगत वर्ष की तुलना में जहां यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी तथा जापान की रैंकिंग में सुधार हुआ है, वहीं फ्रांस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है।

➔ यद्यपि 30 देशों की इस सूची में भारत शामिल नहीं है, तथापि इस रिपोर्ट में अलग से दी गई 10 एशियाई देशों की सूची में भारत को सॉफ्ट पॉवर के मामले में आठवां स्थान प्राप्त हुआ है।

☉ भारत का प्राप्तांक 40.64 है।

सॉफ्ट पॉवर 30, 2018 के 10 एशियाई देशों में शीर्ष 5 देश			
देश	प्राप्तांक	10 एशियाई देशों में रैंक	30 देशों में रैंक
जापान	76.22	1	5
दक्षिण कोरिया	62.75	2	20
सिंगापुर	62.44	3	21
चीन	51.85	4	27
ताइवान	47.25	5	—
भारत	40.64	8	—

## भारतीय राज्यों की कारोबार सुगमता रैंकिंग

### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➔ 10 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा भारतीय राज्यों की कारोबार सुगमता रैंकिंग जारी की गई।

➔ राज्यों को यह रैंकिंग उनके कारोबार सुगमता वाले क्षेत्रों (श्रम, पर्यावरणीय मंजूरी, एकल खिड़की प्रणाली, निर्माण मंजूरी, संविदा अनुपालन, संपत्ति के पंजीकरण एवं निरीक्षण आदि) में किए गए सुधार के आधार पर दी गई है।

➔ राज्यों की रैंकिंग औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से भारत के सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कारोबार सुधार कार्ययोजना (BRAP), 2017 के तहत किए गए वार्षिक सुधार सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों पर आधारित है।

### राज्यों की स्थिति

➔ भारतीय राज्यों में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है।

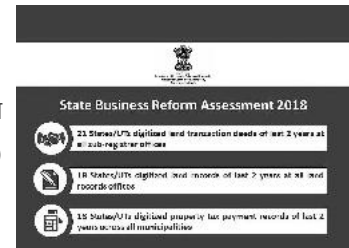
☉ इसके पश्चात तेलंगाना, हरियाणा तथा झारखंड क्रमशः दूसरे, तीसरे एवं चौथे सर्वाधिक सुधार वाले राज्य हैं।

➔ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे कम सुधार वाले तीन राज्य मेघालय, लक्षद्वीप तथा अरुणाचल प्रदेश हैं। इन्हें संयुक्त रूप से 34वें

रैंक प्रदान की गई है।

➔ कारोबार सुगमता रैंकिंग, 2018 में उत्तर प्रदेश को 12वां स्थान (स्कोर : 92.89%) प्राप्त हुआ है।

➔ कारोबार सुगमता रैंकिंग, 2018 में दिल्ली को 23वां स्थान (स्कोर : 31.69%) प्राप्त हुआ।



कारोबार सुगमता में शीर्ष पांच एवं अंतिम पांच राज्य		
रैंक	राज्य	प्राप्तांक (प्रतिशत में)
1.	आंध्र प्रदेश	98.30
2.	तेलंगाना	98.28
3.	हरियाणा	98.06
4.	झारखंड	98.05
5.	गुजरात	97.99

अंतिम पांच राज्य / केंद्रशासित प्रदेश		
34	मेघालय	0.00
34	लक्षद्वीप	0.00
34	अरुणाचल प्रदेश	0.00
33	सिक्किम	0.14
32	मणिपुर	0.27

## वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2018

### पृष्ठभूमि

➔ 'वैश्विक नवाचार सूचकांक' (GII: Global Innovation Index) का प्रकाशन वर्ष 2007 से ही प्रतिवर्ष 'विश्व बौद्धिक संपदा संगठन' (WIPO : World Intellectual Property Organization), INSEAD (The Business School for the World) तथा कॉर्नेल विश्वविद्यालय (न्यूयॉर्क) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।

➔ 'भारतीय उद्योग परिसंघ' (CII) इस सूचकांक के प्रकाशन में 'ज्ञान-भागीदार (Knowledgepartner) के रूप में शामिल है।

### वैश्विक नवाचार सूचकांक

➔ 10 जुलाई, 2018 को न्यूयॉर्क में 'वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2018' जारी किया गया।

➔ यह इस सूचकांक का 11वां वार्षिक संस्करण है।

➔ वर्ष 2018 के 'वैश्विक नवाचार सूचकांक' का केंद्रीय विषय है- 'नवप्रवर्तन के साथ दुनिया को स्फूर्तिवान करना' (Energizing the World with Innovation)।

➔ यह सूचकांक 126 देशों को उनकी अर्थव्यवस्थाओं में नवाचार प्रदर्शन (80 संकेतकों पर आधारित) के आधार पर सूचीबद्ध करता है।

➔ उल्लेखनीय है कि ये 126 देश विश्व की 90.8 प्रतिशत जनसंख्या तथा 96.3 प्रतिशत जीडीपी (GDP) का प्रतिनिधित्व करते हैं।

➔ वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2018 में शीर्ष 5 देश हैं- (1) स्विट्जरलैंड, (2) नीदरलैंड्स, (3) स्वीडन, (4) यूनाइटेड किंगडम और (5) सिंगापुर।

➔ चीन (17वां स्थान) शीर्ष

20 नवाचारी देशों में शामिल एकमात्र उच्च मध्यम आय (Upper-Middle Income) वाली अर्थव्यवस्था है।

➔ वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2018 में अंतिम तीन स्थानों पर क्रमशः यमन (126वीं रैंक), टोगो (125वीं रैंक) तथा बुर्कीना फासो (124वीं रैंक) रहे।

### सूचकांक में भारत

➔ वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2018 में भारत को 57वां स्थान प्राप्त हुआ, जो वर्ष 2017 (60वीं रैंक) की तुलना में सुधार को प्रदर्शित करता है।

➔ 'निम्न-मध्यम आय' वर्ग में भारत नवाचार की दृष्टि से 5वें स्थान पर है।

➔ वैश्विक नवाचार की दृष्टि से ब्रिक्स देशों में भारत की स्थिति चीन तथा रूस (46वीं रैंक) के बाद तीसरी है।

➔ दक्षिण अफ्रीका (58वीं रैंक) तथा ब्राजील (64वीं रैंक) की स्थिति भारत से निम्न है।



विज्ञापन

वैश्विक नवाचार सूचकांक में देशों की स्थिति					
शीर्ष 5 देश			निम्न पांच देश		
रैंक	देश	प्राप्तांक	रैंक	देश	प्राप्तांक
1	स्विट्जरलैंड	68.40	126	यमन	15.04
2	नीदरलैंड्स	63.32	125	टोगो	18.91
3	स्वीडन	63.08	124	बुर्कीना फासो	18.95
4	यूनाइटेड किंगडम	60.13	123	आइवरी कोस्ट	19.96
5	सिंगापुर	59.83	122	नाइजर	20.57

## भारत का विदेशी ऋण (मार्चात, 2018)

### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➔ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 29 जून, 2018 को भारत के विदेशी ऋण के मार्चात, 2018 के आंकड़े जारी किए गए।

➔ मार्च, 2018 के अंत में भारत के विदेशी ऋण में मार्चात, 2017 की तुलना में 12.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

☉ इस वृद्धि के मुख्य कारण वाणिज्यिक उधारों, अल्पावधिक ऋण तथा अनिवासी भारतीयों (NRI) की जमाराशि में वृद्धि रहे।

### विदेशी ऋण की स्थिति

➔ मार्चात, 2018 में भारत का विदेशी ऋण 529.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो मार्चात, 2017 की तुलना में 58.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि प्रदर्शित करता है।

➔ भारत के बाह्य ऋण में वाणिज्यिक उधार 38.2 प्रतिशत हिस्से के साथ विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक है।

☉ इसके पश्चात भारतीय अनिवासियों की जमाओं (23.8%) तथा अल्पावधिक व्यापार क्रेडिट (19%) की हिस्सेदारी है।

➔ मार्चात, 2018 में दीर्घावधिक ऋण (एक वर्ष से ऊपर की मूल परिपक्वता के साथ) 427.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो मार्चात, 2017 की तुलना में 44.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक है।

☉ मार्चात, 2018 में कुल विदेशी ऋण में दीर्घावधिक ऋण (मूल परिपक्वता) की हिस्सेदारी 80.7 प्रतिशत थी, जो मार्चात, 2017 के 81.3 प्रतिशत की तुलना से कम है।

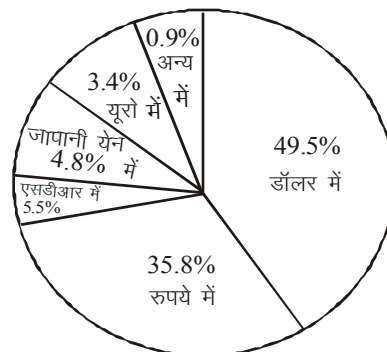
➔ कुल बाह्य ऋण में अल्पावधिक ऋण (एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता के साथ) की हिस्सेदारी मार्चात, 2017 के 18.7 प्रतिशत से बढ़कर मार्चात, 2018 में 19.3 प्रतिशत हो गई।

➔ मार्चात, 2018 में भारत के विदेशी ऋण में सबसे अधिक (49.5%) ऋण अमेरिकी डॉलर में लिए गए हैं।

☉ इसके पश्चात भारतीय रुपये (35.8%), एसडीआर (5.5%), जापानी येन (4.8%) तथा यूरो (3.4%) में लिए गए ऋणों का स्थान है।



भारत का विदेशी ऋण



भारत के विदेशी ऋण की संरचना (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)		
घटक	मार्चात, 2018 अनु.	कुल ऋण में हिस्सेदारी (%)
1. बहुपक्षीय ऋण	57.3	10.8
2. द्विपक्षीय ऋण	25.3	4.8
3. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)	5.8	1.1
4. व्यापार ऋण (Trade credit)	9.4	1.8
5. वाणिज्यिक उधार	202.3	38.2
6. एनआरआई जमाराशियां	126.2	23.8
7. रुपया ऋण	1.2	0.2
8. अल्पावधिक ऋण	102.2	19.3
<b>कुल विदेशी ऋण</b>	<b>529.7</b>	<b>100</b>

नोट- अनु. = अनुमानित



# वैज्ञानिक परिदृश्य

करेन्ट नोट्स



रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा  
एवं पर्यावरणीय विज्ञान संबंधी  
अद्यतन घटनाक्रम की प्रस्तुति



## मेराह पुतिह उपग्रह

### वर्तमान संदर्भ

➔ 7 अगस्त, 2018 को स्पेसएक्स (SpaceX) ने फॉल्कन-9 (Falcon 9) रॉकेट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित केप कैनवैरल 'एयर फोर्स स्टेशन' से इंडोनेशियाई भू-स्थिर (Geo Stationary) संचार उपग्रह 'मेराह पुतिह' का सफल प्रक्षेपण किया।

### मेराह पुतिह

➔ मेराह पुतिह का तात्पर्य इंडोनेशिया के राष्ट्रध्वज में मौजूद लाल और सफेद रंग से है।

➔ मेराह पुतिह (Merah Putih) या टेलकॉम-4 (Telkom-4) नाम का यह उपग्रह इंडोनेशिया की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी 'टेलकॉम इंडोनेशिया' के लिए छोड़ा गया है।

➔ इस उपग्रह का निर्माण कैलिफोर्निया में स्थित एसएसएल (SSL) कंपनी द्वारा किया गया है।

➔ 5800 किलोग्राम वजनी यह उपग्रह इंडोनेशिया के साथ-साथ भारत तथा दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य क्षेत्रों में भी दूर-संचार सेवा प्रदान कर सकता है।

➔ इस उपग्रह की सेवा अवधि 15 वर्ष अनुमानित है।

### फॉल्कन 9 ब्लॉक 5 संस्करण

➔ मेराह पुतिह उपग्रह प्रक्षेपण की सर्वाधिक प्रमुख बात यह थी कि इस उपग्रह प्रक्षेपण में स्पेसएक्स द्वारा फॉल्कन-9 रॉकेट के नवीनतम संस्करण ब्लॉक-5 के प्रथम चरण के बूस्टर का प्रथम बार पुनर्प्रयोग किया गया।

⊕ इससे पूर्व ब्लॉक-5 बूस्टर का प्रयोग 11 मई, 2018 को बांग्लादेश के प्रथम संचार उपग्रह 'बंगबंधु-1' का प्रक्षेपण करने हेतु किया गया था।

➔ सफल प्रक्षेपण के पश्चात यह बूस्टर मानवरहित पोत (Drone Ship) 'ऑफ कोर्स आई स्टिल लव यू' (Of Course I Still Love You) पर सुरक्षित रूप से उतरा।



➔ उल्लेखनीय है कि 'ब्लॉक-5' बूस्टर का विकास नासा (NASA) की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा प्रथम चरण के बूस्टर में बिना अधिक सुधार किए इसका त्वरित एवं लगातार पुनर्प्रयोग करने हेतु किया गया है।

### अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

➔ स्पेसएक्स (SpaceX) एक निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विनिर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा की अमेरिकी कंपनी है।

⊕ इसकी स्थापना वर्ष 2002 में 'एलन मस्क' द्वारा की गई थी तथा इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया के हॉथार्न (Hawthorne) में है।

➔ फॉल्कन-9 एक द्विचरणीय रॉकेट है, जिसके पहले चरण में 9 मर्लिन (Merlin) इंजन लगे होते हैं तथा जिसमें किसी एक इंजन के बंद होने के बाद भी अन्य इंजन मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं।

⊕ फॉल्कन-9 पुनर्उड़ान भरने में सक्षम प्रथम कक्षीय (Orbital) श्रेणी का रॉकेट है।

## सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल प्रक्षेपण

### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➔ 2 अगस्त, 2018 को भारत की सुपरसोनिक एएडी इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

⊕ इस परीक्षण हेतु इंटरसेप्टर मिसाइल को ओडिशा के बालासोर स्थित डॉ. अब्दुल कलाम द्वीप के एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) के लांच पैड-4 से कनस्टर (Canister) लांचर द्वारा दागा गया।

➔ इस परीक्षण में इंटरसेप्टर मिसाइल हवा में स्थित अपने लक्ष्यों पर निशाना साधने में पूर्णतः सफल रही।

### परीक्षण का विवरण

➔ रक्षा सूत्रों के अनुसार, यह परीक्षण उड़ान के दौरान इंटरसेप्टर मिसाइल



के विभिन्न मानकों के सत्यापन के लिए किया गया, जो पूर्णतः सफल रहा।

- ➔ यह अत्याधुनिक मिसाइल दुश्मन की निम्न ऊंचाइयों वाली मिसाइलों को बीच में ही रोककर मार गिराने में सक्षम है।
- ➔ इंटरसेप्टर मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ ही भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है।
- ➔ रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन (डीआरडीओ) का कहना है कि इस मिसाइल के परीक्षण ने सभी मानकों को पूरा कर लिया है।

### विशेषताएं

- ➔ 7.50 मीटर लंबी, एकल चरणीय, ठोस रॉकेट प्रणोदन युक्त यह निर्देशित मिसाइल हाइटेक कंप्यूटर और इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्टिवेटर वाली प्रणाली से लैस है।

➔ इस अत्याधुनिक मिसाइल का अपना खुद का मोबाइल लांचर है और यह दुश्मन मिसाइल को निशाना बनाने के लिए सुरक्षित डेटालिंक, आधुनिक रडार व अन्य तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी विशिष्टताओं से युक्त है।

### विगत परीक्षण

- ➔ ध्यातव्य है कि उपर्युक्त परीक्षण से पूर्व 28 दिसंबर, 2017 को भारत ने स्वदेश में विकसित एडवांस्ड एयर डिफेंस (AAD) सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का ओडिशा स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से ही सफल परीक्षण किया था।
- ➔ इस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण 6 दिसंबर, 2007 को संपन्न हुआ था।

## स्वदेशी परमाणु घड़ी

### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➔ हाल ही में 'भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन' (ISRO) ने एक परमाणु घड़ी का विकास किया है, जिसका उपयोग स्वदेशी नैविगेशन उपग्रहों में किया जाएगा।

- ➔ वर्तमान में यह घड़ी परीक्षण के दौर में है।
- ➔ सभी परीक्षणों के सफलतापूर्वक संपन्न होने के पश्चात इस स्वदेशी परमाणु घड़ी को एक प्रायोगिक नैविगेशन उपग्रह में संलग्न कर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, ताकि अंतरिक्ष में भी इसकी परिशुद्धता एवं स्थायित्व का परीक्षण किया जा सके।

### स्वदेशी घड़ी की आवश्यकता

➔ उल्लेखनीय है कि परमाणु घड़ियों का उपयोग नैविगेशन उपग्रहों में पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु की सही स्थिति के मापन हेतु किया जाता है।

➔ मूलतः 7 उपग्रहों वाली भारत की क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली 'नाविक' (NAVIC) में शामिल प्रत्येक उपग्रह में तीन परमाणु घड़ियां संलग्न हैं।

- ➔ नाविक प्रणाली में प्रयुक्त परमाणु घड़ियां स्विट्जरलैंड के मेसर्स स्पेक्ट्रा टाइम (M/s Spectra Time) द्वारा निर्मित हैं।
- ➔ नाविक प्रणाली के प्रथम उपग्रह IRNSS-1A में संलग्न इन घड़ियों में वर्ष 2016 में कुछ खराबी आ गई थी।
- ➔ इसके पश्चात इस प्रणाली के कुछ अन्य उपग्रहों में संलग्न घड़ियों में भी खराबी के मामले प्रकाश में आए।

➔ अगर भविष्य में भी इसी प्रकार विदेशी परमाणु घड़ियों में खराबी आती रही, तो भारत की स्वदेशी नौवहन उपग्रह



प्रणाली के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो सकता है।

➔ इसी चिंता के मद्देनजर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्वदेशी परमाणु घड़ियों के निर्माण का निर्णय लिया।

### अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

➔ स्वदेशी परमाणु घड़ी का विकास इसरो के अहमदाबाद स्थित 'अंतरिक्ष उपयोग केंद्र' (SAC : Space Applications Centre) द्वारा किया गया है।

➔ IRNSS-1A में संलग्न परमाणु घड़ियों में खराबी आ जाने के कारण इस उपग्रह के स्थानापन्न के रूप में इसरो ने अप्रैल, 2018 में IRNSS-II को प्रक्षेपित किया था।

➔ IRNSS-1A का उपयोग अब केवल आपदा चेतावनी, मछुआरों को संभावित मत्स्य-ग्रहण (Fishing) क्षेत्रों की सूचना प्रेषित करने जैसी संदेशन सेवाएं (Messaging Services) प्रदान करने हेतु ही किया जा सकेगा।

## S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली

### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➔ हाल ही में भारत और रूस के मध्य 'S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों' (S-400 Triumph Air Defence Missile Systems) की खरीद हेतु मूल्य संबंधी वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

➔ लगभग 40,000 करोड़ रुपये मूल्य के इस समझौते को अंतिम रूप अक्टूबर, 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मध्य प्रस्तावित वार्षिक शिखर बैठक के दौरान दिए जाने की संभावना है।

➔ इस समझौते के तहत रूस, भारतीय वायु सेना हेतु पांच S-400 ट्रायम्फ लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति करेगा।

### विशेषताएं

➔ वास्तव में S-400 ट्रायम्फ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जो यूएवी, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों इत्यादि को निशाना बना सकती है।

➔ S-400 मिसाइल की अधिकतम रफ्तार 4800 मीटर/सेकंड तक है।

➔ यह मिसाइल लगभग 10000 फीट की ऊंचाई तक दुश्मन के हथियारों आदि को ध्वस्त कर सकती है। इसकी तैनाती में केवल 5-10 मिनट तक का समय लगता है।

➔ यह वायु रक्षा प्रणाली लगभग 400 किमी. के क्षेत्र में दुश्मनों की बैलिस्टिक मिसाइलों, विमानों और ड्रोन सहित जमीनी लक्ष्यों को भी नष्ट करने में सक्षम है।

➔ S-400 प्रणाली S-300 मिसाइल प्रणाली का उन्नत संस्करण है।

➔ S-400 मिसाइल प्रणाली को भारतीय वायु सेना द्वारा संचालित किया जाएगा।

### भारत के संदर्भ में महत्व

➔ भारत को विशेष तौर पर लगभग 4000 किमी. लंबी भारत-चीन सीमा पर अपनी वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली की अत्यधिक आवश्यकता थी, जो इस समझौते से संभव हो सकेगी।

➔ इस समझौते से भारत को एक ऐसा रक्षा कवच मिल जाएगा जो किसी भी मिसाइल हमले को



असफल कर सकता है।

➔ इस प्रणाली से भारत पर होने वाले किसी परमाणु हमले का भी जवाब दिया जा सकेगा।

➔ इस प्रणाली से पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में उड़ रहे विमानों को भी ट्रैक करना संभव हो सकेगा।

### अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

➔ नाटो सेना द्वारा इस मिसाइल प्रणाली को SA-21 ग्राउलर नाम दिया गया है।

➔ अलमाज-एन्टे द्वारा विकसित यह मिसाइल प्रणाली रूस में वर्ष 2007 से सेवा में है।

➔ ज्ञातव्य है कि चीन वर्ष 2014 में रूस के साथ अंतरसरकारी समझौते के माध्यम से इस मिसाइल प्रणाली का प्रथम विदेशी खरीददार बना था।

## विकास इंजन का सफल परीक्षण

### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➔ 15 जुलाई, 2018 को 'भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन' (ISRO) द्वारा 'विकास' इंजन के 'उच्च ठेल' (High Thrust) प्रदान करने वाले संस्करण का जमीनी परीक्षण (Ground Test) सफलतापूर्वक संपन्न किया गया।

⊕ यह परीक्षण महेंद्रगिरि (तमिलनाडु) स्थित इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स (IPRC : ISRO Propulsion Complex) में किया गया, जो 195 सेकंड की अवधि का रहा।

### विकास इंजन

➔ विकास इंजन तरल ईंधन संचालित रॉकेट इंजन है।

⊕ इसका विकास 1970 के दशक में इसरो के 'द्रव नोदन प्रणाली केंद्र' (LPSC) द्वारा किया गया था।

⊕ विकास नाम भारत के प्रख्यात वैज्ञानिक विक्रम अंबालाल साराभाई (VIKRAM AMBALALSARABHAI) के नाम से प्रेरित परिवर्णी शब्द (Acronym) है।

⊕ इस इंजन का प्रयोग PSLV प्रक्षेपण यान के द्वितीय चरण में तथा GSLV के द्वितीय एवं चार स्ट्रैपऑन चरण में किया जाता है।

⊕ इसके अतिरिक्त जीएसएलवी मार्क -III रॉकेट के L110 चरण में दो विकास इंजनों का प्रयोग किया जाता है।

➔ विकास इंजन में यूडीएमएच (UDMH : Unsymmetrical Dimethylhydrazine) का प्रयोग ईंधन के रूप में, जबकि नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड (N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>) का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है।



### लाभ

➔ विकास इंजन के उच्च ठेल प्रदान करने वाले संस्करण से PSLV, GSLV तथा GSLV मार्क -III प्रक्षेपण यानों की नीतभार वहन क्षमता में सुधार अपेक्षित है।

### अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

➔ उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में जीएसएलवी मार्क -III की द्वितीय विकासआत्मक उड़ान के तहत जीसैट-29 संचार उपग्रह का प्रक्षेपण प्रस्तावित है तथा इस मिशन में उच्च ठेल प्रदान करने वाले विकास इंजन का प्रयोग किया जाएगा।

⊕ हालांकि भविष्य में इसरो की जीएसएलवी मार्क-III में विकास इंजन के स्थान पर अर्द्ध-क्रायोजेनिक इंजन (Semi-cryogenic Engine) के प्रयोग की योजना है।

## चालक दल बचाव प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण

### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➔ 5 जुलाई, 2018 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा 'चालक दल बचाव प्रणाली' (Crew Escape System) की योग्यता जांच श्रृंखला का पहला परीक्षण किया गया।

### उद्देश्य

➔ किसी मानव अंतरिक्ष मिशन के प्रक्षेपण के दौरान कोई हादसा होने की स्थिति में या मिशन की समाप्ति पर अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित करना विश्व की प्रायः सभी अंतरिक्ष एजेंसियों की प्राथमिकताओं में शामिल होता है।

- ☉ इसरो का उद्देश्य भी प्रक्षेपण के दौरान अंतरिक्ष यान में कोई खराबी आने पर पैराशूट इत्यादि के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर सुरक्षित उतारने की प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करना है।
- ☉ सद्यः परीक्षण इस तकनीक में दक्षता प्राप्त करने की दिशा में ही एक प्रयास था।

### परीक्षण का विवरण

➔ लगभग 5 घंटे की उलटी गिनती के पश्चात आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 12.6 टन वजनी एक कृत्रिम क्रू मॉड्यूल (वह कक्ष जिसमें किसी मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री सवार होते हैं) को चालक दल बचाव प्रणाली के साथ प्रक्षेपित किया गया।

- ☉ क्रू मॉड्यूल लगभग 2.7 किमी. की ऊंचाई तक गया, तत्पश्चात पैराशूट के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में उतार लिया गया।



- ☉ क्रू मॉड्यूल प्रक्षेपण केंद्र से 2.9 किमी. की दूरी पर समुद्र में लैंड हुआ।
- ☉ तीन नौकाओं की सहायता से क्रू मॉड्यूल को पुनर्प्राप्त (Recover) किया गया।
- ☉ इस परीक्षण की कुल अवधि 259 सेकंड रही।

### चालक दल बचाव प्रणाली

➔ चालक दल बचाव प्रणाली एक आपातकालीन बचाव युक्ति है, जिसे प्रक्षेपण के दौरान कोई हादसा होने की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों समेत क्रू मॉड्यूल को तुरंत बाहर निकाल कर प्रक्षेपण यान से दूर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है।

- ☉ यह प्रणाली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान की दृष्टि से प्रासंगिक एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी है।

## एसईएस-12 उपग्रह

### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➔ 4 जून, 2018 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केप कैनवेरेल से स्पेस-एक्स के फॉल्कन-9 रॉकेट द्वारा संचार उपग्रह एसईएस-12 (SES-12) का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

### SES-12

➔ SES-12 संचार क्षेत्र में संलग्न लक्जमबर्ग की कंपनी SES द्वारा संचालित उपग्रह है।

- ☉ पूर्णतः विद्युत चालित इस उपग्रह का निर्माण एयरबस (Airbus) द्वारा किया गया है।
- ☉ 5400 किग्रा. वजनी इस उपग्रह की विद्युत क्षमता 19 किलोवॉट है।
- ☉ यह उपग्रह भू-स्थिर कक्षा में SES-8 उपग्रह के साथ 95° पूर्व की कक्षीय स्थिति से संचालित होगा।

### विशेषताएं

- ➔ SES-12, SES कंपनी द्वारा अब तक प्रक्षेपित सबसे बड़े भू-स्थिर उपग्रहों में से एक है।
- ➔ SES-12 कुल 76 सक्रिय ट्रांसपोंडरों तथा 8 एंटीना के साथ Ku तथा Ka बैंड में संचालित होगा।

### लाभ

➔ SES-12 टेलिफोन कंपनियों, मोबाइल नेटवर्क संचालकों तथा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अधिक विश्वसनीय सेल्युलर तथा द्रुत गति की ब्रॉडबैंड सेवाओं की आपूर्ति करने में सक्षम बनाएगा।

- ☉ साथ ही यह उपग्रह मध्य-पूर्व तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में DTH प्रसारण, VSAT तथा HTS (High Throughput Satellite) डाटा कनेक्टिविटी सेवाएं आदि प्रदान करने की SES कंपनी की क्षमताओं में वृद्धि करेगा।



➔ SES-8 एवं SES-12 द्वारा प्रदत्त संचार सेवाओं से 18 मिलियन घरों के टेलिविजन दर्शक लाभान्वित होंगे।

- ☉ इन दोनों उपग्रहों के संचालन से DTH संचालक HD (High Definition) तथा अल्ट्रा HD प्रसारण प्राप्त करने की दर्शकों की दिन-प्रतिदिन बढ़ती मांग को पूरा करने में समर्थ हो सकेंगे।

### भारतीय संदर्भ में

➔ अभी तक SES कंपनी के पांच उपग्रहों यथा- NSS-12, SES-8, NSS-6, SES-7 तथा SES-9 की सेवाएं भारत को प्राप्त हो रही हैं।

- ☉ SES-12 उपग्रह, NSS-6 के स्थान पर भारत में संचार सेवाएं मुहैया कराने हेतु SES कंपनी के उपग्रहों के नेटवर्क में शामिल होगा।

## चीन द्वारा पाकिस्तान के उपग्रहों का प्रक्षेपण

### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

- ➔ 9 जुलाई, 2018 को चीन द्वारा जिउकुआन (Jiuquan) उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र (उत्तर-पश्चिम चीन में स्थित) से पाकिस्तान के दो उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया।
  - ➔ लांग मार्च-2सी (Long March-2C) रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित ये दोनों उपग्रह हैं- पीआरएसएस-1 (PRSS-1) और पाकटेस-1ए (PakTES-1A)।
- ### PRSS-1
- ➔ 1200 किग्रा. वजनी PRSS-1 (Pakistan Remote Sensing Satellite-1) का निर्माण पाकिस्तान की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी सुपारको (SUPARCO : Pakistan Space & Upper Atmosphere Research Commission) के लिए चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी (चीन) द्वारा किया गया है।
  - ➔ पीआरएसएस-1 किसी विदेशी खरीददार के लिए 'चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी (CAST : China Academy of Space Technology) द्वारा बनाया गया 17वां उपग्रह है।
  - ➔ पीआरएसएस-1 उपग्रह का उपयोग भूमि एवं संसाधन सर्वेक्षण, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, कृषि अनुसंधान, शहरी निर्माण आदि हेतु सुदूर संवेदन जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
  - ➔ इस उपग्रह का जीवनकाल 7 वर्ष है और इसमें दो पैक्रोमेटिक/मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरे लगे हैं, जिनका विभेदन 1 मीटर और आच्छादन 60 किमी. तक है।

### PakTES-1A

- ➔ 285 किग्रा. वजनी पाकटेस-1ए (PakTES-1A : Pakistan Technology Evaluation Satellite-1A) को सुपारको के इंजीनियरों द्वारा ही डिजाइन एवं निर्मित किया गया है।



- ➔ इस उपग्रह का जीवनकाल तीन वर्ष है तथा यह 610 किमी. की ऊंचाई पर स्थित कक्षा से संचालित होगा।

### अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- ➔ सद्यः प्रक्षेपण लांग मार्च रॉकेट श्रृंखला का 279वां मिशन था।
  - साथ ही यह वर्ष 1999 में मोटोरोला के इरीडियम (IRIDIUM) उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के पश्चात लांग मार्च-2सी की पहली अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक उड़ान भी थी।
- ➔ लांग मार्च-2सी रॉकेट का उपयोग मुख्यतया निम्न पृथ्वी (Low Earth) अथवा सूर्य-समकालिक (Sun-Synchronous) कक्षाओं में उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए किया जाता है।
- ➔ उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व अगस्त, 2011 में चीन द्वारा पाकिस्तान के संचार उपग्रह पाकसैट-1आर (PakSAT-1R) का प्रक्षेपण किया गया था।

## विश्व का पहला मानवीय फोरेंसिक केंद्र

### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

- ➔ 20 जून, 2018 को गुजरात के गांधीनगर स्थित 'गुजरात फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय' में विश्व के पहले अंतरराष्ट्रीय मानवीय फोरेंसिक केंद्र (International Centre for Humanitarian Forensics) का उद्घाटन किया गया।
- ➔ यह केंद्र गुजरात फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और भारत, भूटान, नेपाल एवं मालदीव के लिए रेडक्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति (ICRC) के क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडल के संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया है।

### उद्देश्य

- ➔ अंतरराष्ट्रीय मानवीय फोरेंसिक केंद्र (ICHF) मौजूदा विश्वविद्यालय प्रणाली के अंतर्गत मानवीय फोरेंसिक कार्यवाही को संस्थागत रूप प्रदान करने का पहला स्पष्ट प्रयास है।
- ➔ यह केंद्र मानवतावादी सेवाओं के उत्कृष्ट फोरेंसिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
- ➔ आपदाओं के दौरान यह केंद्र मृतकों के प्रबंधन के लिए कार्य करने के साथ ही उनकी पहचान में भी सहायक भूमिका निभाएगा।

### लाभ

- ➔ यह केंद्र विभिन्न अकादमिक एवं व्यावसायिक कार्यक्रमों, प्रशिक्षण, अनुसंधान आदि का संचालन तो करेगा ही, साथ ही मानवतावादी

- फोरेंसिक के क्षेत्र में विभिन्न संबद्ध एजेंसियों एवं प्राधिकरणों के साथ अभियानों में सहयोग हेतु तकनीकी विशेषज्ञता भी प्रदान करेगा।
- ➔ यह वैश्विक उच्च गुणवत्ता और टिकाऊ क्षमता निर्माण, अनुसंधान और नवाचार परियोजनाओं के लिए एशिया में उत्कृष्टता का केंद्र बन सकता है, जो मानवीय फोरेंसिक उद्देश्यों के लिए परिचालन प्रतिक्रियाओं को सहयोग प्रदान करेगा।

### निष्कर्ष

- ➔ देश-विदेश में प्राकृतिक व मानवजनित आपदाएं समय-समय पर निरंतर आती रहती हैं, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है, ऐसे समय पर मानवतावादी फोरेंसिक का महत्व काफी बढ़ जाता है।
  - युद्ध, आपदा एवं विस्थापन के दौरान मृत लोगों के अवशेषों की खोज एवं पहचान मानवतावादी कार्यों के अंतर्गत शामिल है और फोरेंसिक विज्ञान इन मानवतावादी कार्यों के लिए आवश्यक उपकरण एवं विशेषज्ञता उपलब्ध कराता है।



## कॉर्पेट : भारत-बांग्लादेश नौसैन्य समन्वित गश्त

### वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➔ 27 जून, 2018 को चटगांव, बांग्लादेश में भारतीय नौसेनाध्यक्ष एडमिरल सुनील लनबा ने भारतीय नौसेना एवं बांग्लादेश की नौसेना के



मध्य 'समन्वित गश्त' (Coordinated Patrol : CORPAT) का उद्घाटन किया।

- ☉ उल्लेखनीय है कि दोनों देशों की नौसेनाओं के मध्य आयोजित किए जाने वाले वार्षिक गश्ती अभ्यास का यह प्रथम संस्करण था।

### अभ्यास का विवरण

➔ भारतीय नौसेना की ओर से युद्धपोत आईएनएस सतपुड़ा तथा आईएनएस कदमत ने इस गश्ती अभ्यास में प्रतिभाग किया।

- ☉ जबकि बांग्लादेश की नौसेना का प्रतिनिधित्व युद्धपोत 'अबु बक्र' तथा 'धलेश्वरी' द्वारा किया गया।
- ☉ इस नौसैन्य समन्वित गश्त का समापन 3 जुलाई, 2018 को विशाखापत्तनम में हुआ।

### पृष्ठभूमि

➔ उल्लेखनीय है कि अप्रैल, 2017 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य रक्षा सहयोग की रूपरेखा से संबंधित एक समझौता-ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित हुआ था।

- ☉ दोनों देशों की नौसेनाओं के मध्य सद्यः संपन्न, कॉर्पेट गश्ती अभ्यास को इसी समझौता-ज्ञापन के प्रतिफल के रूप में देखा जा सकता है।

### अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

➔ उल्लेखनीय है कि भारतीय नौसेना नियमित रूप से इंडोनेशिया, म्यांमार तथा थाईलैंड की नौसेनाओं के साथ कॉर्पेट नाम से ही समन्वित गश्ती अभ्यास का संचालन करती है।

- ☉ ज्ञातव्य है कि भारत एवं इंडोनेशिया के मध्य आयोजित होने वाला कॉर्पेट अभ्यास का 31वां संस्करण जून, 2018 में इंडोनेशिया में संपन्न हुआ था।

विज्ञापन

# संक्षिप्तियां कनेन्ट नोदस

चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, संघ/संगठन, योजना/परियोजना, ऑपरेशन/अभियान, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार, शब्द संक्षेप तथा और भी बहुत कुछ...



## चर्चित व्यक्ति

### □ बी.के. मिश्रा

➔ प्रख्यात न्यूरोसर्जन; डॉ. बी.सी. रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चयनित। (31 अगस्त, 2018)



➔ उन्हें वर्ष का प्रख्यात चिकित्सक (Eminent Medical Person of the Year) चुना गया है।

➔ उन्हें यह पुरस्कार 1 जुलाई, 2019 को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाएगा।

### □ कोफी अन्नान

➔ संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव एवं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का निधन। (18 अगस्त, 2018)



➔ वह लगातार दो कार्यकाल वर्ष 1997 से 2006 तक के लिए संयुक्त राष्ट्र के 7वें महासचिव रहे।

➔ कोफी अन्नान अफ्रीकी मूल के पहले (अश्वेत) संयुक्त राष्ट्र महासचिव थे।

➔ वर्ष 2012 में उन्होंने सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र और अरब लीग के विशेष दूत के रूप में कार्य किया।

➔ उनकी जीवनी 'इंटरनरेशनल्स : ए लाइफ इन वॉर एंड पीस' है।

### □ सोमनाथ चटर्जी

➔ लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष का निधन। (13 अगस्त, 2018)



➔ वह जून, 2004 से मई, 2009 तक लोक सभा के अध्यक्ष रहे।

### □ वी.एस. नायपॉल

➔ भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक एवं साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन। (11 अगस्त, 2018)



➔ उन्हें वर्ष 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

➔ वर्ष 1971 में 'इन ए फ्री स्टेट' कृति के लिए उन्हें प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था।

➔ उनकी प्रमुख कृतियों में- 'ए बेंड इन द रिकर', 'द मिमिक मेन', 'ए वे इन द वर्ल्ड', 'द इनिम्मा ऑफ अराइवल', 'हाफ ए लाइफ', 'ऐन एरिया ऑफ डार्कनेस', 'इंडिया : वाउंडेड सिविलाइजेशन', 'इंडिया : ए मिलियन म्यूटिनीज नाऊ' तथा 'गुरिल्लाज' आदि शामिल हैं।

### □ न्यायमूर्ति गीता मित्तल

➔ दिल्ली उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश; जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। (11 अगस्त, 2018)



➔ इसके साथ ही वह जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनीं।

### □ रेखा शर्मा

➔ राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष नियुक्त। (9 अगस्त, 2018)



➔ सितंबर, 2017 में ललिथा कुमारमंगलम के पद छोड़ने के बाद से वह आयोग के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थीं।

### □ उच्चतम न्यायालय के तीन नए न्यायाधीश

➔ न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति के.एम.



जोसेफ ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया। (7 अगस्त, 2018)

➔ भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) दीपक मिश्रा ने न्यायाधीशों को शपथ दिलायी।

➔ इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 25 (कुल स्वीकृत संख्या 31) हो गई।

### □ एम. करुणानिधि

➔ डीएमके प्रमुख एवं तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन। (7 अगस्त, 2018)



➔ वह राज्य के प्रमुख द्रविड़ राजनीतिक दल द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) के 10 बार अध्यक्ष चुने गए थे।

➔ वे पांच बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे थे।

## ❑ राजीव कुमार

➔ उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रमुख सचिव; यूपी रेरा (UP RERA) के अध्यक्ष नियुक्त। (4 अगस्त, 2018)



- ➔ राजीव कुमार के अतिरिक्त पूर्व आईएएस अधिकारी कल्पना मिश्रा, बलविंदर कुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी भानु प्रताप सिंह यूपी रेरा के सदस्य नियुक्त हुए।
- ➔ ज्ञातव्य है कि यूपी रेरा प्रदेश की रियल एस्टेट कंपनियों की एक नियामक संस्था है।

## ❑ अजय दाता

➔ एक्सजेन प्लस (XGen Plus) के संस्थापक और सीईओ; सीसीएनएसओ (ccNSO:Country Code Names Supporting Organisation) परिषद के सदस्य नियुक्त। (3 अगस्त, 2018)



- ➔ आईसीएनएन (ICANN) ढांचे के अंतर्गत सीसीटीएलडी (ccTLD) : Country Code Top Level Domains) के संबंध में वैश्विक मुद्दों के लिए सीसीएनएसओ एक नीति विकास निकाय है।
- ➔ वह इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं।

## ❑ विमला बाथम

➔ नोएडा की पूर्व विधायक; उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'उ.प्र. राज्य महिला आयोग' की नई अध्यक्ष नामित। (2 अगस्त, 2018)



- ➔ इस पद पर उन्होंने जरीना उस्मानी का स्थान लिया।

## ❑ अनीता कुमार

➔ भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार; 'व्हाइट हाउस कॉर्रेस्पॉन्डेन्ट्स एसोसिएशन' (WHCA) बोर्ड की सदस्य नियुक्त। (अगस्त, 2018)



- ➔ WHCA, व्हाइट हाउस और अमेरिकी राष्ट्रपति संबंधी समाचारों को कवर करने वाला पत्रकारों का एक संघ है।
- ➔ वह इस बोर्ड में शामिल होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी हैं।

## ❑ सैयदा ताहिरा सफदर

➔ पाकिस्तान के बलूचिस्तान उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नामित। (23 जुलाई, 2018)



- ➔ पाकिस्तान में पहली बार किसी महिला को इस पद पर नियुक्त किया जा रहा है।

## ❑ गोपालदास नीरज

➔ प्रसिद्ध गीतकार व कवि का निधन। (19 जुलाई 2018)



- ➔ उनका जन्म 4 जनवरी, 1925 को इटावा जिले के पुरावली गांव में हुआ था।
- ➔ उनकी कुछ प्रमुख कृतियां- 'दर्द दिया है', 'प्राणगीत', 'आसावरी', 'गीत जो गाए नहीं', 'बादर बरस गयो', 'नीरज की पाती' तथा 'कारवां गुजर गया' आदि हैं।

## ❑ न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल

➔ उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश; केंद्र सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (NGI) के नए अध्यक्ष नियुक्त। (6 जुलाई, 2018)



- ➔ कार्यकाल- 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें जो भी पहले हो।

## ❑ न्यायमूर्ति एल. नरसिम्हा रेड्डी

➔ पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश; 'केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण' (CAT) के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण। (3 जुलाई, 2018)



- ➔ इसके साथ ही उन्हें हैदराबाद विश्वविद्यालय का कुलपति भी नियुक्त किया गया।

## ❑ कमांडर अभिलाष टॉमी

➔ भारतीय नौसेना के कमांडर; फ्रांस के लेस सैब्लस डी'ओलोन हार्बर (Les Sables d'Olonne



- harbour) से आरंभ समुद्री यात्रा 'गोल्डेन ग्लोब रेस, 2018' में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। (1 जुलाई, 2018)
- ➔ वह प्रतिष्ठित गोल्डेन ग्लोब रेस में आमंत्रित एकमात्र एशियाई नाविक हैं।

## ❑ सत्यरूप सिद्धांत

➔ प्रसिद्ध भारतीय पर्वतारोही; विश्व के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत 'ओजोस डेल सलाडो' (Ojos Del Salado) पर चढ़ने वाले दूसरे भारतीय पर्वतारोही बने। (जुलाई, 2018)



- ➔ यह अर्जेंटीना-चिली सीमा पर एंडीज पर्वत शृंखला में स्थित तथा 6893 मीटर ऊंचा एक सक्रिय ज्वालामुखी है।
- ➔ मल्ली मस्तान बाबू इस पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय पर्वतारोही थे।
- ➔ सत्यरूप सिद्धांत अंटार्कटिका के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत 'सिडले' पर चढ़ने वाले पहले भारतीय भी हैं।

## ❑ पॉल पोलमैन

➔ यूनीलीवर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO); विश्व के सबसे बड़े ब्यापारिक संगठन 'इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स' (ICC) के अध्यक्ष निर्वाचिता। (21 जून, 2018)



- ➔ इस पद पर इन्होंने भारती इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल का स्थान लिया।
- ➔ इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा।



## अन्य चर्चित व्यक्ति

- **आर.के. धवन**— वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन। (6 अगस्त, 2018)
- **आदित्य विक्रम**— भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी; केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के सदस्य नियुक्त। (6 अगस्त, 2018)
- **प्रमोद चंद्र मोदी**— भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी; केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के सदस्य नियुक्त। (6 अगस्त, 2018)
- **एस. गोपाकुमार**— केंद्र सरकार द्वारा 'यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.' के निदेशक एवं महाप्रबंधक नियुक्त। (7 अगस्त, 2018)
- **न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन**— पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश; दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। (4 अगस्त, 2018)
- **न्यायमूर्ति विजया के. तहीलरमानी**— बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश; मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। (4 अगस्त, 2018)
- **न्यायमूर्ति ऋषीकेश रॉय**— केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। (4 अगस्त, 2018)
- **न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस**— कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश; झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। (4 अगस्त, 2018)
- **न्यायमूर्ति एम.आर. शाह**— गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश; पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। (4 अगस्त, 2018)
- **न्यायमूर्ति कल्पेश सत्येन्द्र झावेरी**— राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश; ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। (4 अगस्त, 2018)
- **के.एस. देशपांडे**— प्रसिद्ध लाइब्रेरी वैज्ञानिक का निधन। (4 अगस्त, 2018)
- **न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा**— जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त। (3 अगस्त, 2018)
- **एमर्सन नंगावा**— जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित। (2 अगस्त, 2018)
- **विशेष गुप्ता**— उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'उ.प्र. बाल अधिकार संरक्षण आयोग' के नए अध्यक्ष नामित। (2 अगस्त, 2018)
- **भीष्म नारायण सिंह**— असम और तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता का निधन। (1 अगस्त, 2018)।
- **इवान डुक्यु**— कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण। (अगस्त, 2018)
- **सरदार इकबाल सिंह**— उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंजाबी अकादमी के उपाध्यक्ष नामित। (18 जुलाई, 2018)
- **डॉ. टी.सी.ए. राघवन**— उपराष्ट्रपति वैकैया नायडू द्वारा 'विश्व मामलों की भारतीय परिषद' (ICWA) के महानिदेशक नियुक्त। (12 जुलाई, 2018)
- **न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी**— छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण। (7 जुलाई, 2018)
- **पी.के. श्रीवास्तव**— आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) के नए महानिदेशक एवं अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण। (1 जुलाई, 2018)
- **गिरीश चंद्र चतुर्वेदी**— भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी; आईसीआईसीआई बैंक के अंशकालिक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त। (1 जुलाई, 2018)
- **विश्वास पटेल**— इंफिबीम एवेन्यू के निदेशक; भारतीय भुगतान परिषद (PCI) के अध्यक्ष नियुक्त। (2 जुलाई, 2018)
- **अनूप चंद्र पांडे**— भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी; उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव के रूप में पदभार ग्रहण। (30 जून, 2018)
- **अनंत बरुआ**— केंद्र सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त। (27 जून, 2018)
- **अरविंद सक्सेना**— संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के सदस्य; आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त। (20 जून, 2018)
- **संदीप बख्शी**— आईसीआईसीआई बैंक लि. के पूर्णकालिक निदेशक एवं मुख्य संचालन अधिकारी (COO) नियुक्त। (18 जून, 2018)
- **दिव्या सूर्यदेवरा**— भारतीय मूल की अमेरिकी महिला; अमेरिकी वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स (GM) की मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त। (13 जून, 2018)
- **शरद कुमार**— राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के पूर्व अध्यक्ष; केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त। (10 जून, 2018)
- **न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी**— पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण। (जून, 2018)
- **एस. रमेश**— केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के नए अध्यक्ष नियुक्त। (जून, 2018)
- **बी.वी.आर. सुब्रमण्यम**— भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी; जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रमुख सचिव के रूप में पदभार ग्रहण। (जून, 2018)
- **रीता भादुड़ी**— प्रसिद्ध फिल्म एवं टेलीविजन अभिनेत्री का निधन। (17 जुलाई, 2018)
- **प्रो.एन.एन. विग**— प्रसिद्ध मनोचिकित्सक का निधन। (13 जुलाई, 2018)
- **एम.एम. जैकब**— वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं मेघालय के पूर्व राज्यपाल का निधन। (8 जुलाई, 2018)
- **कबूतर देवी**— उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोकगायिका का निधन। (7 जुलाई, 2018)
- **मेजर जनरल जोस एलाडियो अलकैन**— उरुग्वे के मेजर जनरल, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा भारत-पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह (UN Military Observer Group in India and Pakistan : UN MOGIP) के प्रमुख (मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक) नियुक्त। (जुलाई, 2018)
- **कल्कि कोएलिन**— प्रसिद्ध अभिनेत्री; भारत में फ्रांस के राजदूत अलेक्जेंडर जीगलर द्वारा फ्रांस के 'नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स' सम्मान से सम्मानित। (22 जून, 2018)

## चर्चित स्थल

### □ नया रायपुर

➔ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नया रायपुर का नामकरण 'अटल नगर' किए जाने का निर्णय (21 अगस्त, 2018)



- ➔ राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर विश्वविद्यालय और मड़वा ताप बिजली परियोजना का नामकरण भी अटल जी के नाम पर करने का निर्णय लिया गया।
- ➔ प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विकास यात्रा के दूसरे चरण को अटल विकास यात्रा के नाम से संचालित किया जाएगा।

### □ पंचकुला

➔ 5 राज्यों (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड) और केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ द्वारा नशीली दवाओं के खतरे से निपटने हेतु पंचकुला में एक केंद्रीकृत सचिवालय की स्थापना का निर्णय (20 अगस्त, 2018)



- ➔ यह निर्णय चंडीगढ़ में आयोजित 'ड्रग खतरा, चुनौतियों और रणनीतियों' विषय पर हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित मुख्यमंत्रियों के क्षेत्रीय सम्मेलन में लिया गया।

### □ चिरवा घाट क्षेत्र

➔ राजस्थान के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया द्वारा उदयपुर के निकट चिरवा घाट क्षेत्र में नगर वन उद्यान 'फूलों की घाटी' का लोकार्पण। (3 अगस्त, 2018)



- ➔ यह नया पर्यटन स्थल उदयपुर शहर से 9 किमी. की दूरी पर अम्बेरी वन क्षेत्र में 80 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तारित है।

### □ जीनोम घाटी

➔ तेलंगाना के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के.टी. रामाराव द्वारा 60 करोड़ रुपये के निवेश से जीनोम घाटी, हैदराबाद में एक बायोटेक और फार्मा सुविधा बी-हब (B-Hub) की स्थापना किए जाने की घोषणा। (31 जुलाई, 2018)



- ➔ इस अत्याधुनिक हब में बायोफार्मा आधारित अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) के लिए विनिर्माण की सुविधा होगी।
- ➔ यह भारत का पहला बायोफार्मा-हब होगा।

### □ नई दिल्ली

➔ नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 'भाषांतर' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में ई-अक्षरायन सॉफ्टवेयर लांचा (30 जुलाई, 2018)



- ➔ यह सॉफ्टवेयर भारतीय भाषाओं के स्कैन किए हुए दस्तावेजों (Documents) को पूरी तरह से संपादन योग्य टेक्स्ट प्रारूप में रूपांतरित करता है।

### □ मोहाली

➔ केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा मोहाली (पंजाब) में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (NSTI) के स्थायी परिसर का शिलान्यासा (28 जुलाई, 2018)



- ➔ यह पंजाब के लिए पहला एनएसटीआई (NSTI) संस्थान और भारत में अपनी तरह का पहला संस्थान है, जो विशिष्ट रूप से महिलाओं के लिए है।

➔ इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (PMKK) भी लांच किया, जो दिव्यांगजनों को भी प्रवेश देगा।

### □ केंद्रपाड़ा

➔ ओडिशा सरकार द्वारा केंद्रपाड़ा जिले में महानदी पर राज्य के पहले नदी बंदरगाह की स्थापना का निर्णय। (28 जुलाई, 2018)



- ➔ इस बंदरगाह की स्थापना केंद्रपाड़ा जिले के महाकालपाड़ा ब्लॉक के अंतर्गत अखादासली गांव में की जाएगी।
- ➔ यह बंदरगाह 'बिल्ड-ओन-ऑपरेट-शेयर-ट्रांसफर' (BOOST) आधार पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड पर विकसित किया जाएगा।

### □ प्रताप वन

➔ राजस्थान के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया द्वारा उदयपुर जिले में नए ईको टूरिज्म डेस्टिनेशन 'प्रताप वन' का शिलान्यासा (27 जुलाई, 2018)



- ➔ यह उदयपुर शहर में वन विभाग द्वारा नगर निगम के वित्तीय सहयोग से 30 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा।

### □ विजयवाड़ा

➔ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में अमरावती अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर की आधारशिला रखी। (24 जुलाई, 2018)

- ➔ आंध्र प्रदेश के खेल प्राधिकरण (SAAP) का मुख्यालय इस परिसर में स्थापित किया जाएगा।

## □ अंबाला छावनी

➔ हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल परिसर में राजकीय कैंसर केयर सेंटर की आधारशिला रखी गई। (24 जुलाई, 2018)



## □ मावडियांगडियांग

➔ केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीपद येसो नाइक द्वारा मेघालय की राजधानी शिलांग के मावडियांगडियांग में पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान (NEIAH) के निर्माण कार्यों के दूसरे चरण की आधारशिला रखी गई। (23 जुलाई, 2018)



## □ गाजीपुर

➔ रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा द्वारा गाजीपुर (उ.प्र.) में क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान (RRTI) का उद्घाटन। (22 जुलाई, 2018)

☛ उद्देश्य-उत्तर-पूर्वी रेलवे के कर्मचारियों की विशेषज्ञताओं एवं क्षमताओं को और बेहतर बनाना।

## □ हरियाणा-ब्राजील उत्कृष्टता केंद्र

➔ हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के मवेशियों की नस्ल में सुधार लाने के उद्देश्य से राजकीय पशुधन फर्म, हिसार में हरियाणा-ब्राजील उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय। (22 जुलाई, 2018)



☛ इस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड और एबीसीजेड उबेराबा, ब्राजील के मध्य हुए त्रिपक्षीय समझौते के तहत की जाएगी।

## □ सलेमपुर

➔ आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा देवरिया जिले के सलेमपुर में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी। (18 जुलाई, 2018)



☛ नए मेडिकल कॉलेज की निर्माण लागत राशि 250 करोड़ रुपये होगी।

## □ दरभंगा

➔ विश्व की सबसे सस्ती स्वच्छ पेयजल परियोजना 'सुलभ जल' का दरभंगा (बिहार) में शुभारंभ। (14 जुलाई, 2018)

☛ यह परियोजना सुलभ इंटरनेशनल द्वारा शुरू की गई है।  
☛ परियोजनांतर्गत लोग 50 पैसे प्रति लीटर की दर से पेयजल प्राप्त कर सकेंगे।

## □ ओडिशा

➔ ओडिशा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय हेरिटेज कैबिनेट के गठन संबंधी अधिसूचना जारी। (12 जुलाई, 2018)



☛ उद्देश्य-राज्य में प्राचीन स्मारकों, मंदिरों, पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा करना और राज्य में संस्कृति, भाषा और साहित्य को संरक्षित करने हेतु उचित कदम उठाना।

## □ एएसआई का नया मुख्यालय

➔ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली स्थित तिलक मार्ग पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के नए मुख्यालय 'धरोहर भवन' का उद्घाटन। (12 जुलाई, 2018)



☛ संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ई. में हुई थी।  
☛ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे, वर्तमान महानिदेशक उषा शर्मा हैं।

## □ पुर्तगाल

➔ पुर्तगाल की संसद द्वारा देश में 16 वर्ष और उससे अधिक के वयस्क नागरिकों को बिना सत्यापित मेडिकल रिपोर्ट के अपना लिंग और नाम परिवर्तन करने से संबंधित कानून को मंजूरी। (12 जुलाई, 2018)



☛ इस प्रकार के कानून को मंजूरी प्रदान करने वाला पुर्तगाल छटां यूरोपियन देश है।  
☛ इससे पूर्व डेनमार्क, माल्टा, स्वीडन, आयरलैंड और नॉर्वे द्वारा इस प्रकार के कानून को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है।

## □ भारत-कोरिया प्रौद्योगिकी विनिमय केंद्र

➔ केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम (एमएसएमई) उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरिराज सिंह और कोरिया गणराज्य के लघु व मध्यम उद्यम एवं स्टार्ट-अप मंत्री होंग जोंग-हाक द्वारा भारत-कोरिया प्रौद्योगिकी विनिमय केंद्र का नई दिल्ली में उद्घाटन। (10 जुलाई, 2018)



## □ भरोहिया

➔ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोरखपुर जिले में स्थित 'भरोहिया' को विकास खंड बनाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी। (10 जुलाई, 2018)

## □ गौतमबुद्ध नगर (नोएडा)

➔ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जाइ-इन द्वारा गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित नई मोबाइल फोन निर्माण इकाई का उद्घाटन। (9 जुलाई, 2018)



## □ देहरादून

➔ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेद सिंह रावत द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी भवन, आई.टी.पार्क, देहरादून में ड्रोन अनुप्रयोग अनुसंधान केंद्र और साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन। (9 जुलाई, 2018)



- यह भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र है।
- इस केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान (एनटीआरओ) के सहयोग से की गई है।

## □ पश्चिम बंगाल

➔ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा मंत्रियों और नौकरशाहों के लिए 'एक व्यक्ति एक कार' नीति की घोषणा। (5 जुलाई, 2018)

## □ हैदराबाद

➔ नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास। (5 जुलाई, 2018)



- भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा इसकी स्थापना हेतु 12 वर्षों की अवधि के लिए 1200 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

## □ भोपाल

➔ मध्य प्रदेश के जनसंपर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में स्थापित मीडिया इन्क्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन। (4 जुलाई, 2018)



- इस सेंटर की स्थापना नीति आयोग के सहयोग से की गई है।
- यह देश का पहला मीडिया इन्क्यूबेशन सेंटर है।

➔ इस सेंटर का संचालन संवाद भारती संस्था के माध्यम से किया जाएगा।

## □ मेहली

➔ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा शिमला के निकट मेहली में इन्क्यूबेशन सेंटर ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पॉक्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) की आधारशिला रखी गई। (2 जुलाई, 2018)



## □ झारखंड

➔ झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास द्वारा राज्य में देश का पहला 'खादी मॉल' बनाए जाने की घोषणा। (2 जुलाई, 2018)

○ यह मॉल रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (एचईसी) परिसर की भूमि पर निर्मित किया जाएगा।



## □ कोरबा

➔ केंद्र सरकार द्वारा कोरबा (छत्तीसगढ़) में केंद्रीय प्लास्टिक एवं इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी संस्थान (सीपेट) की स्थापना को मंजूरी। (जुलाई, 2018)

○ छत्तीसगढ़ में रायपुर के बाद कोरबा दूसरा शहर है, जहां सीपेट की स्थापना की जाएगी।



## □ मालदीव

➔ मालदीव में विश्व की पहली अंतःज्वारीय (Intertidal) आर्ट गैलरी (कोरालारियम) को खोला गया। (जुलाई, 2018)

○ यह मूंगा और अन्य समुद्री प्रजातियों का आश्रय स्थल होगा।



## □ विशाखापत्तनम

➔ यूनेस्को प्रतिनिधिमंडल और आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास बोर्ड के मध्य 'गेमिंग डिजिटल लर्निंग हब' की स्थापना हेतु समझौता। (जुलाई, 2018)

○ संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) विशाखापत्तनम में गेमिंग के लिए डिजाइन विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा।



## □ रिस्पना पुल का नाम परिवर्तित

➔ देहरादून जिले में देहरादून-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-72 (नई संख्या-7) पर स्थित रिस्पना पुल का नाम परिवर्तित। (जुलाई, 2018)

○ इस पुल का नाम परिवर्तित कर स्वामी दयानंद सरस्वती पुल रखा गया है।

## □ रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन

→ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर सोनभद्र रेलवे स्टेशन कर दिया गया। (जुलाई, 2018)



## □ गुरुग्राम

→ हरियाणा सरकार द्वारा 1000 एकड़ क्षेत्र में गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी की स्थापना की जाएगी। (जुलाई, 2018)

→ यह ग्लोबल सिटी जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा वित्तपोषित है।

## □ बंगलुरु

→ भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक अंतर विश्वविद्यालय योग केंद्र की स्थापना को मंजूरी। (21 जून, 2018)

→ इस केंद्र की स्थापना स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु में की जाएगी।



## □ न्यूयॉर्क

→ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यो-वन प्राकृतिक उषाचार केंद्र (Yo1 Nature Cure Center) का उद्घाटन। (21 जून, 2018)

→ इस केंद्र की स्थापना न्यूयॉर्क, अमेरिका में की गई है।



## □ जम्मू-कश्मीर

→ जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू करने की घोषणा तत्कालीन राज्यपाल एन.एन. वोहरा द्वारा की गई। (19 जून, 2018)

→ उल्लेखनीय है कि जून, 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली भाजपा-पीडीपी गठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लिया था।

## पुरस्कार/सम्मान

### □ 24वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, 2018

→ पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपालकृष्ण गांधी को। (20 अगस्त, 2018)



### □ शलाका सम्मान, 2017-18

→ दिल्ली सरकार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान, प्रसिद्ध गीतकार एवं पटकथा लेखक जावेद अख्तर को। (1 अगस्त, 2018)



### □ फील्ड्स मेडल पुरस्कार, 2018

→ गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समतुल्य इस पुरस्कार के

विजेता हैं-

(i) भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई गणितज्ञ अक्षय वेंकटेश।

(ii) केंब्रिज विश्वविद्यालय में ईरानी-कुर्द मूल के प्रोफेसर कौचर बिरकर।

(iii) जर्मन गणितज्ञ पीटर स्कॉलेज।



(iv) इतालवी गणितज्ञ एलेसियो फिगैली। (1 अगस्त, 2018)

→ गौरतलब है कि अक्षय वेंकटेश यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं।

→ इससे पूर्व यह पुरस्कार वर्ष 2014 में मंजुल भार्गव को प्राप्त हुआ था।

→ यह पुरस्कार इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन (IMU) की अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस में प्रति चार वर्षों में 40 वर्ष से कम उम्र के उदीयमान गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है।

### □ रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 2018

→ एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से विख्यात रेमन मैग्सेसे पुरस्कारों की घोषणा। (26 जुलाई, 2018)

→ इस वर्ष यह पुरस्कार 6 व्यक्तियों को दिए जाने का निर्णय लिया गया, जो इस प्रकार हैं-

(i) यूक छांग (कंबोडिया)

(ii) मारिया डी लोर्डस मार्टिस क्रूज (पूर्व तिमोर)

(iii) हावर्ड-डी (फिलीपींस)

(iv) भरत वाटवानी (भारत)

(v) वो थी होआंग येन (वियतनाम)

(vi) सोनम वांगचुक (भारत)



### □ संगीत कलानिधि पुरस्कार, 2018

→ प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका अरुणा साइराम को। (15 जुलाई, 2018)



### □ स्टेशन परिसरों के सौंदर्यीकरण के लिए पुरस्कार, 2018

→ केंद्रीय रेल तथा कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने स्टेशन परिसरों के सौंदर्यीकरण के लिए पुरस्कार प्रदान किए। (12 जुलाई, 2018)

→ मध्य रेलवे के बलहारशाह तथा चन्द्रपुर रेलवे स्टेशन को पहला पुरस्कार मिला।



### □ गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार, 2018

→ प्रसिद्ध कनाडाई कवि एवं उपन्यासकार माइकल ओन्डात्से के उपन्यास 'द इंग्लिश पेशेंट' (The English Patient) को। (8 जुलाई, 2018)



- ☞ 'द इंग्लिश पेशेंट' को विगत पांच दशकों में मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाला सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित किया गया।
- ☞ इस उपन्यास को वर्ष 1992 में बैरी अन्सवर्थ के 'सैक्रेड हंगर' के साथ मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
- ➔ उल्लेखनीय है कि यह विशेष पुरस्कार मैन बुकर पुरस्कार के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गठित किया गया था।

## ☐ फुकुओका पुरस्कार, 2018

(i) ग्रैंड पुरस्कार- जिया झांग्के (चीन)



(ii) अकादमी पुरस्कार- सुएहियो अकिरा (जापान)

(iii) कला एवं संस्कृति पुरस्कार- तीजन बाई (भारत)

## ☐ पेन पिंटर पुरस्कार, 2018

➔ नाइजीरिया की लेखिका चिमांमंदा न्गोजी अडीची (Chimamanda Ngozi Adichie) को।



## ☐ टेंपलटन पुरस्कार, 2018

➔ जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह द्वितीय को। (27 जून, 2018)



## ☐ जेनेसिस प्राइज, 2018

➔ इस्राइली-अमेरिकी अभिनेत्री नताली पोर्टमैन को।



## ☐ स्टॉकहोम वाटर प्राइज, 2018

➔ ब्रूस रिटमैन (अमेरिका) एवं मार्क वान लोसड्रेक्ट (नीदरलैंड्स) को।



## ☐ योग प्रोत्साहन और विकास में असाधारण योगदान हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार, 2018

➔ नासिक के विश्वास मांडलिक (व्यक्तिगत-राष्ट्रीय श्रेणी में) तथा योग संस्थान, मुंबई (संगठन-राष्ट्रीय श्रेणी में) को। (20 जून, 2018)

## ☐ ATP/WTA प्लेयर ऑफ द ईयर, 2017

➔ पुरुष वर्ग में स्पेन के राफेल नडाल और महिला वर्ग में गाबिने मुगुरुजा को।



## ☐ IAAF वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, 2017

➔ पुरुष वर्ग में कतर के मुताज ईसा बारिशम तथा महिला वर्ग में बेल्जियम की नफिसतोउ थियम को।



## ☐ एआईएफएफ वार्षिक पुरस्कार, 2017

➔ अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) की वार्षिक बैठक में वर्ष 2017 के वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की गई। (22 जुलाई, 2018)



वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर- सुनील छेत्री  
वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर- कमला देवी  
सर्वश्रेष्ठ रेफरी- सी.आर. श्रीकृष्णा

## योजना/परियोजना

### ☐ सौर सिंचाई योजना

➔ हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में सौर सिंचाई योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय। (9 अगस्त, 2018)



- ☞ इस योजना हेतु 224 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
- ☞ योजनांतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को राज्य सरकार व्यक्तिगत रूप से 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- ☞ मध्यम और बड़े किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान (उपदान) प्रदान किया जाएगा।

➔ लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसानों, किसान विकास संघ, कृषक विकास संघ और किसानों की पंजीकृत संस्था इत्यादि को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता राज्य सरकार प्रदान करेगी।

### ☐ बहाव सिंचाई योजना

➔ हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बहाव सिंचाई योजना को शुरू किए जाने हेतु मंजूरी। (9 अगस्त, 2018)



- ☞ राज्य सरकार द्वारा इस योजना की घोषणा राज्य बजट में की गई थी।
- ☞ इस योजना हेतु आवंटित राशि 174.50 करोड़ रुपये है।
- ➔ यह योजना कृषि विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।
- ☞ योजनांतर्गत 7152.30 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा।

### ☐ राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम

➔ हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 'राज्य कृषि यंत्रीकरण' कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय। (9 अगस्त, 2018)



- ☞ यह कार्यक्रम किसानों को खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया।
- ☞ इस कार्यक्रम हेतु आवंटित राशि 20 करोड़ रुपये है।

## □ विद्यार्थी वन मित्र योजना

➔ हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में 'विद्यार्थी वन मित्र योजना' शुरू करने का निर्णय (9 अगस्त, 2018)



☉ यह योजना विद्यार्थियों को वनों के महत्व तथा पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका के विषय में शिक्षित और जागरूक करने के लिए शुरू की गई है।

## □ तत्पर बाइसिकल शेयर

➔ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा नया रायपुर में 'तत्पर बाइसिकल शेयर' योजना का शुभारंभ (9 अगस्त, 2018)



☉ इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित स्कूली बच्चों को पब्लिक साइकिल शेयरिंग कार्ड वितरित कर इस योजना की शुरुआत की।  
 ☉ यह योजना पर्यावरण हितैषी होने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद और आर्थिक रूप से लाभकारी है।  
 ☉ इस सेवा के अंतर्गत नागरिकों को न्यूनतम दर पर साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी।  
 ☉ ये साइकिलें जीपीएस तकनीक से युक्त हैं, जिनकी कंट्रोल रूम से सतत निगरानी की जाएगी।

## □ निर्यात मित्र मोबाइल ऐप

➔ केंद्रीय बाणिज्य और उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा निर्यात मित्र मोबाइल ऐप लांच (8 अगस्त, 2018)



☉ भारतीय निर्यात महासंघ (FIEO) द्वारा विकसित यह ऐप एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म वाले सभी मोबाइल फोन पर उपलब्ध है।  
 ☉ इसके जरिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सभी नियमों और व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।  
 ➔ इसमें आयात-निर्यात से जुड़ी नीतियां, जीएसटी की दरें, निर्यात के लिए मिलने वाली रियायतें, शुल्क तथा बाजारों तक पहुंचने के लिए आवश्यक बातें शामिल हैं।

☉ इसमें 87 देशों का डाटा शामिल किया गया है।  
 ☉ इसमें टैरिफ से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध हैं।

## □ सौर ऊर्जा लैम्प योजना

➔ उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह द्वारा लखनऊ जिले

के सरोजिनी नगर विकास खंड स्थित बेती गांव में सौर ऊर्जा लैम्प योजना का शुभारंभ (1 अगस्त, 2018)



☉ उत्तर प्रदेश में सौर लैम्प निर्माण हेतु पहली कंपनी की स्थापना सोनभद्र में की जाएगी।

## □ पोर्टल 'फोकल' का शुभारंभ

➔ भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) द्वारा कार्गो मालिकों एवं लॉजिस्टिक्स संचालकों को जोड़ने हेतु एक पोर्टल 'फोकल' (FOCAL: Forum of Cargo Owners and Logistics Operators) का शुभारंभ (31 जुलाई, 2018)



☉ यह पोर्टल जहाजरानी ऑपरेटरों और कार्गो मालिकों के बीच सीधे संपर्क का जरिया बनेगा।

## □ उद्यानिकी प्रोत्साहन योजना

➔ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में प्याज और लहसुन की फसल हेतु उद्यानिकी प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय (30 जुलाई, 2018)



☉ योजनांतर्गत प्याज और लहसुन के लिए क्रमशः 400 रुपये और 800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

## □ 'मोबाइल तिहार' का शुभारंभ

➔ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह द्वारा रायपुर में प्रदेशव्यापी 'मोबाइल तिहार' (मोबाइल महोत्सव) और मोबाइल ऐप 'गोट' का शुभारंभ (30 जुलाई, 2018)



☉ संचार क्रांति योजना के अंतर्गत सरकार राज्य में 50 लाख लोगों को निःशुल्क स्मार्ट फोन का वितरण करेगी।

➔ ध्यातव्य है कि 26 जुलाई, 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी 'संचार क्रांति योजना' का शुभारंभ किया गया था।

## □ मेघालय मिल्क (दूध) मिशन

➔ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह द्वारा मेघालय मिल्क (दूध) मिशन के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के माध्यम से 215 करोड़ रुपये की राशि की परियोजना शुरू किए जाने की घोषणा (29 जुलाई, 2018)



☉ परियोजनांतर्गत 2000 डेयरी फार्म इकाइयां स्थापित की जाएंगी।  
 ➔ **उद्देश्य**-प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता तथा मांग-आपूर्ति के अंतर को कम करना जो अभी प्रति व्यक्ति दूध की खपत के संदर्भ में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा की गई सिफारिश से काफी कम है।

### ☐ मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोत्तरी सौर योजना

➔ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोत्तरी सौर योजना का शुभारंभ (25 जुलाई, 2018)

☉ **उद्देश्य**- राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की आय में तीन से पांच गुना की वृद्धि करना।

### ☐ रुकुरा मध्यम सिंचाई परियोजना

➔ ओडिशा के मुख्यमंत्री ने सुंदरगढ़ जिले में रुकुरा मध्यम सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया। (25 जुलाई, 2018)



☉ सुंदरगढ़ जिले में सूखे की समस्या से निपटने हेतु लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से इस परियोजना की शुरुआत की गई, जिससे लगभग 5750 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जा सकेगी।

☉ यह परियोजना ब्रह्मणी तथा वैतरणी बेसिन क्षेत्र में रुकुरा नदी पर बनायी गई है।

### ☐ दुग्गर जलविद्युत परियोजना

➔ हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चंबा जिले में चिनाब नदी पर निर्मित दुग्गर जलविद्युत परियोजना (449 मेगावॉट) को बीओओटी (Build Own Operate and Transfer) आधार पर एनएचपीसी लिमिटेड को आवंटित करने का निर्णय। (24 जुलाई, 2018)



☉ एनएचपीसी लिमिटेड को इस परियोजना का आवंटन 70 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है।

### ☐ मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना

➔ हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों को राहत प्रदान करने हेतु 'मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना' के कार्यान्वयन को मंजूरी। (24 जुलाई, 2018)

☉ योजनांतर्गत 3 या इससे अधिक किसानों के समूह को 85 प्रतिशत अनुदान तथा जंगली जानवरों से फसल के बचाव हेतु खेतों में सौर फेन्सिंग (बाड़) लगाने हेतु किसानों को 80 प्रतिशत उपदान (Gratuity) प्रदान किया जाएगा।



### ☐ मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस जीर्णोद्धार योजना

➔ हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में किसानों के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस जीर्णोद्धार योजना के कार्यान्वयन हेतु मंजूरी। (24 जुलाई, 2018)

☉ इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को पॉली हाउसों की क्षतिग्रस्त पॉली सीटों को बदलने हेतु वर्तमान के 50 प्रतिशत अनुदान के स्थान पर 70 प्रतिशत अनुदान प्रदान करेगी।



### ☐ मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना, 2018

➔ हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 18-40 आयु वर्ग के स्थानीय युवाओं को आजीविका प्रदान करने हेतु 'मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना', 2018 को शुरु करने हेतु मंजूरी। (24 जुलाई, 2018)



☉ **उद्देश्य**-प्रदेश में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना और स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करना।  
 ☉ योजनांतर्गत अधिकतम 30 लाख रुपये का निवेश करने पर पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को क्रमशः 25 प्रतिशत और 30 प्रतिशत उपदान (Gratuity) प्रदान किया जाएगा।

### ☐ छात्र-पुलिस कैडेट कार्यक्रम

➔ केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन हेतु छात्र पुलिस कैडेट कार्यक्रम का गुरुग्राम (हरियाणा) में शुभारंभ। (21 जुलाई, 2018)



☉ यह कार्यक्रम बुजुर्गों के प्रति सम्मान, अनुशासन, सामाजिक जिम्मेदारी एवं पुलिस-छात्र परस्पर संपर्कों के माध्यम से छात्रों में मूल्यों को समावेशित कर उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने में मददगार होगा।

☉ यह कार्यक्रम व्यापक रूप से दो विषयों को कवर करता है-(i) अपराध की रोकथाम एवं नियंत्रण (ii) मूल्य एवं नैतिकता।

### ☐ इस्पात सीपीएसई कर्मचारी पेंशन योजना

➔ केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंदर सिंह द्वारा नई दिल्ली में इस्पात सीपीएसई कर्मचारी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा। (17 जुलाई, 2018)



☉ यह योजना कार्यकारियों के संदर्भ में 1 जनवरी, 2007 से और गैर-कार्यकारियों के संदर्भ में 1 जनवरी, 2012 से या कंपनी द्वारा लिए गए फैसले के तहत बाद की किसी तिथि से प्रभावी होगी।

### ☐ विशाखापत्तनम में बंदरगाह परियोजनाओं का उद्घाटन

➔ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा विशाखापत्तनम में 5 बंदरगाह परियोजनाओं का उद्घाटन। (13 जुलाई, 2018)



☉ इन परियोजनाओं की लागत राशि 1062 करोड़ रुपये है।



- इसके अलावा श्री गडकरी ने 679 करोड़ रुपये लागत राशि की दो बंदरगाह कनेक्टिविटी परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया।

## □ टेक्नोलॉजी चैलेंज

➔ आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने हेतु टेक्नोलॉजी चैलेंज (Technology Challenge : Identifying Solutions for Cleaning of Sewerage Systems and Septic Tanks) का शुभारंभ (11 जुलाई, 2018)

- उद्देश्य-सेप्टिक टैंक और मेनहोल इत्यादि में मानव प्रवेश की आवश्यकता को समाप्त करना।

➔ यह चैलेंज 2 अक्टूबर, 2018 को आयोजित किए जाने वाले महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन का एक हिस्सा होगा।

## □ जयपुर में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास

➔ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य में 13 शहरी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं (लागत राशि



2100 करोड़ रुपये) का शिलान्यास। (7 जुलाई, 2018)

- इन परियोजनाओं में अजमेर के लिए एलीवेटेड सड़क परियोजना, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, हनुमानगढ़, सीकर, माउंट आबू हेतु जलापूर्ति और सीवरेंज परियोजनाएं तथा बूंदी, बीकानेर और अजमेर जिलों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत विभिन्न परियोजनाएं इत्यादि शामिल हैं।

## □ ई-मार्केटिंग प्रणाली 'किमिस'

➔ खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना द्वारा ई-मार्केटिंग प्रणाली 'खादी संस्थान प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली' (किमिस)



का नई दिल्ली में शुभारंभ। (3 जुलाई, 2018)

- खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की खरीद और बिक्री हेतु देश में कहीं से भी इस प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है।

## □ मोबाइल ऐप 'सिविजिल'

➔ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ.पी. रावत, चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और अशोक लवसा द्वारा



संयुक्त रूप से मोबाइल ऐप 'सिविजिल' (cVIGIL) लांच। (3 जुलाई, 2018)

- इस ऐप के माध्यम से नागरिक चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित किसी मामले की रिपोर्ट

निर्वाचन आयोग को कर सकते हैं।

- रिपोर्ट करने की अनुमति निर्वाचन घोषणा की तिथि से प्रभावी होकर मतदान के एक दिन बाद तक रहेगी।
- इस ऐप का उपयोग चार राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों में सामान्य रूप से और अगले लोकसभा चुनाव के दौरान व्यावहारिक रूप से किया जाएगा।

## □ प्रोजेक्ट जिंदगी

➔ गुरुग्राम (हरियाणा) के सरकारी स्कूलों में प्रोजेक्ट जिंदगी का शुभारंभ। (2 जुलाई, 2018)



- उद्देश्य - मनोवैज्ञानिकों के माध्यम से बच्चों को तनावमुक्त वातावरण देना व उनकी अधिगम अक्षमता दूर करना।

- इस पायलट प्रोजेक्ट में 6-18 वर्ष के बच्चों को शामिल करते हुए जिला प्रशासन गुरुग्राम द्वारा जिले के 15 विद्यालयों में इसे संचालित किया जाएगा।

## □ सरल बिजली बिल योजना

➔ मध्य प्रदेश में सरल बिजली बिल योजना और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना लागू। (1 जुलाई, 2018)



- यह योजना मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना, 2018 में पंजीकृत श्रमिकों को बिजली बिल में राहत प्रदान करने हेतु शुरू की गई है।
- सरल बिजली बिल योजनांतर्गत उपभोक्ताओं (पंजीकृत श्रमिकों) को प्रतिमाह बिजली बिल मात्र 200 रुपये देना होगा, शेष राशि की पूर्ति सरकार द्वारा सब्सिडी देकर की जाएगी।
- मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों एवं बीपीएल उपभोक्ताओं की जून, 2018 तक बकाया बिजली बिल की पूरी राशि (बकाया एवं सरचार्ज भी शामिल) माफ की जाएगी।

## □ ओक तसर विकास परियोजना

➔ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किसान भवन, देहरादून में ओक तसर विकास परियोजना (टी.एस.पी.) का शुभारंभ। (22 जून, 2018)



- यह परियोजना केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से केंद्र प्रायोजित योजनांतर्गत क्रियान्वित है।
- हिमाचल प्रदेश सरकार की तरह उत्तराखंड सरकार भी राज्य में रेशम कीड़ों के पालन हेतु किसानों को धनराशि उपलब्ध कराएगी।

## □ रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना

➔ मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ला द्वारा रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना (750 मेगावॉट) की इकाई-1 (Unit-1) में विद्युत उत्पादन (5 मेगावॉट) का औपचारिक शुभारंभ (21 जून, 2018)



☞ उत्पादित 5 मेगावॉट विद्युत मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को प्रदान की जा रही है।

➔ यूनिट-2 जयपुर सोलर पॉवर प्राइवेट लिमिटेड और यूनिट-3 एरिसन क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

☞ इस सौर परियोजना से उत्पादित 76 प्रतिशत विद्युत राज्य सरकार खरीदेगी और 24 प्रतिशत बिजली की दिल्ली मेट्रो को बिक्री की जाएगी।

## □ नर्मदा-पार्वती लिंक परियोजना

➔ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सीहोर जिले के आष्टा में महत्वाकांक्षी नर्मदा-पार्वती लिंक परियोजना का शिलान्यास (17 जुलाई, 2018)



☞ परियोजनांतर्गत पहले और दूसरे चरण में इंदिरा सागर जलाशय से लगभग 295 मीटर की ऊंचाई तक पानी लिफ्ट कर किसानों के खेतों तक पाइप लाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।

☞ इससे सीहोर जिले की आष्टा, जावर तथा इछावर तहसील के 187 गांवों की लगभग 2.50 लाख एकड़ भूमि सिंचित होगी।

## □ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ, 2018 रथ

➔ छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ, 2018 रथ' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। (18 जुलाई, 2018)



☞ उद्देश्य-किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के महत्व के विषय में जानकारी प्रदान करना एवं खरीफ फसलों का बीमा कराने हेतु प्रोत्साहित करना।

☞ इस कंपनी को प्रदेश के 6 जिलों (कांकेर, गरियाबंद, सूरजपुर, रायगढ़, दंतेवाड़ा और बिलासपुर) में योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

## □ बाणसागर नहर परियोजना

➔ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चनईपुर गांव मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) में बाणसागर नहर परियोजना राष्ट्र को समर्पित। (15 जुलाई, 2018)



☞ इस परियोजना की लागत राशि 3420 करोड़ रुपये है।

☞ इस परियोजना से मिर्जापुर, इलाहाबाद और आस-पास के क्षेत्रों में 1.50 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।

## □ पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे

➔ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मंदुरी में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास। (14 जुलाई, 2018)



☞ इस एक्सप्रेस-वे की लंबाई लगभग 353 किमी. है।

☞ 6 लेन वाले (एक्सपेन्डेबल 8 लेन) प्रवेश नियंत्रित पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण ग्राम चांद सराय (लखनऊ) से ग्राम-हैदरिया (गाजीपुर) तक किया जाएगा।

☞ इस एक्सप्रेस-वे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा कराया जाएगा।

## □ 'एक किसान, एक ट्रांसफार्मर' योजना

➔ महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा राज्य में 15 अगस्त, 2018 से किसानों के लिए 'एक किसान, एक ट्रांसफार्मर' योजना शुरू करने की घोषणा। (10 जुलाई, 2018)

## □ मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना

➔ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को मंजूरी। (9 जुलाई, 2018)



☞ योजनांतर्गत दिल्ली सरकार प्रतिवर्ष 77 हजार वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु) को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराएगी।

☞ तीर्थयात्रा हेतु तय पांच रूट हैं-मथुरा-वृंदावन, हरिद्वार-ऋषिकेश-नीलकंठ, पुष्कर-अजमेर, अमृतसर-बाघा-आनंदपुर साहिब और वैष्णो देवी-जम्मू।

## □ मुंडका-सिटी पार्क (बहादुरगढ़) मेट्रो लाइन

➔ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुंडका-सिटी पार्क (बहादुरगढ़) मेट्रो लाइन का उद्घाटन। (24 जून, 2018)



☞ गुरुग्राम एवं फरीदाबाद के बाद बहादुरगढ़ दिल्ली मेट्रो से जुड़ने वाला हरियाणा का तीसरा स्थल है।

☞ पूर्णतया एलिवेटेड 11.18 किमी. लंबा यह कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो के ग्रीन लाइन (कुल-29.64 किमी.) का हिस्सा है।

## □ मोहनपुरा परियोजना

➔ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में सिंचाई के दृष्टिगत मोहनपुरा परियोजना का लोकार्पण। (23 जून, 2018)



☞ इस परियोजना से राजगढ़ जिले के आस-

पास के 700 से अधिक गांव सीधे लाभान्वित होंगे, लगभग 1.34 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, साथ ही 400 से अधिक गांवों को पेयजल उपलब्ध होगा।

## □ 'वाणिज्य कर आपके द्वार' योजना

➔ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जी.एस.टी. दिवस के अवसर पर राज्य में जनसंपर्क की एक महत्वाकांक्षी योजना 'वाणिज्य कर आपके द्वार' की शुरुआत। (1 जुलाई, 2018)

## □ गट्टू लिफ्ट सिंचाई परियोजना

➔ तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने जोगुलम्बा गडवाल जिले में पेंचिकला गांव में गट्टू लिफ्ट सिंचाई परियोजना की आधारशिला रखी। (29 जून, 2018)



## □ शाइकांगचु लघु जलविद्युत परियोजना

➔ अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा तवांग जिले के गोंगखार गांव में स्थापित शाइकांगचु लघु जलविद्युत परियोजना (6 मेगावॉट) का उद्घाटन। (26 जून, 2018)

## ऑपरेशन/अभियान

### □ हॉर्न नॉट ओके जागरूकता अभियान

➔ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा 'हॉर्न नॉट ओके' जागरूकता अभियान और मोबाइल ऐप 'शोर नहीं' का शुभारंभ। (3 अगस्त, 2018)



- ➔ प्रथम चरण में यह अभियान दो शहरों शिमला और मनाली में शुरू किया गया है।
- ➔ अभियान के दौरान वाहन-चालकों को अनावश्यक हॉर्न का प्रयोग न करने हेतु प्रेरित किया जाएगा।

### □ ग्रीन महानदी मिशन

➔ ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा ग्रीन महानदी मिशन (वृक्षारोपण) का शुभारंभ। (24 जुलाई, 2018)

- ➔ इस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने बौद्ध और सुबरनपुर जिले की यात्रा के दौरान महानदी के तट पर पौधरोपण कर किया।
- ➔ अभियान के दौरान महानदी और इसकी सहायक नदियों (इब और तेल नदी) के किनारे 2 करोड़ पौधे रोपित किए जाएंगे।

### □ बृहद स्वच्छता अभियान

➔ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2018 और बृहद स्वच्छता अभियान का शुभारंभ। (23 जुलाई, 2018)



- ➔ बृहद स्वच्छता अभियान सभी जिलों के प्रत्येक ग्राम में 25 जुलाई से 25 अगस्त, 2018 तक आयोजित किया गया।
- ➔ यह अभियान स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, 2018 की तैयारी हेतु शुरू किया गया।

### □ रिस्पना से ऋषिपर्णा अभियान

➔ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा रिस्पना से ऋषिपर्णा अभियान का शुभारंभ। (22 जुलाई, 2018)



- ➔ इस अभियान की शुरुआत केरवाण गांव से हुई।
- ➔ अभियान के तहत 2.50 लाख पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य है।

### □ मीजल्स-रूबेला टीकाकरण अभियान

➔ गुजरात सरकार द्वारा मीजल्स-रूबेला टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। (16 जुलाई, 2018)



- ➔ 5 सप्ताह तक संचालित इस अभियान के अंतर्गत पूरे राज्य में 9 माह से 15 वर्ष तक की आयु वर्ग के 1.6 करोड़ बच्चों का टीकाकरण किया गया।
- ➔ इस अभियान हेतु केंद्र सरकार ने गुजरात सरकार को 300 करोड़ रुपये की अनुदान राशि प्रदान की।

### □ सघन डायरिया नियंत्रण अभियान

➔ हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में संचालित सघन डायरिया नियंत्रण अभियान संपन्न। (15-30 जुलाई, 2018)



- ➔ हरियाणा में इस अभियान के दौरान 5 वर्ष से कम आयु के 26.5 लाख बच्चों को ओआरएस (ORS) और चिक के पैकेट वितरित किए गए।
- ➔ इस अभियान का उद्देश्य डायरिया से होने वाली मौतों को शून्य (Zero) तक लाना है।

### □ शिशु संरक्षण अभियान

➔ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्यों में 'शिशु संरक्षण माह' (गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के लिए) आयोजित। (19 जून से 20 जुलाई, 2018 तक)

### □ विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह

➔ उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा 38 जनपदों में दस्तक अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत 'विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह' संचालित। (2-31 जुलाई, 2018)



- ➔ यह अभियान जापानी इंसेफेलाइटिस/एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (जेई/ईईएस) पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु शुरू किया गया है।

## आयोग/समिति

### □ राजीव ढोलकिया समिति

➔ केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय लेखा तथा सकल घरेलू उत्पादन (GDP) गणना के लिए आधार वर्ष को संशोधित करने की योजनाओं की पृष्ठभूमि में राज्यों और जिलों के स्तर पर आर्थिक आंकड़ों की गणना के लिए मानदंडों को अपग्रेड करने हेतु समिति का गठन। (जुलाई, 2018)



➔ आईआईएम, अहमदाबाद के सेवानिवृत्त प्रोफेसर रवींद्र ढोलकिया समिति के अध्यक्ष बनाए गए।

### □ एनसीसी और एनएसएस के बीच तालमेल कायम करने हेतु समिति

➔ केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) और राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के बीच तालमेल कायम करने हेतु एक समिति गठित करने का निर्णय लिया। (17 जुलाई, 2018)



➔ पूर्व स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव अनिल स्वरूप समिति के अध्यक्ष होंगे।

### □ ताजमहल के आस-पास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने हेतु समिति

➔ केंद्र सरकार ने ताजमहल के आस-पास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के लिए एक समिति का गठन किया। (16 जुलाई, 2018)

➔ केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन सचिव सी.के. मिश्रा समिति के अध्यक्ष होंगे।



➔ इसके अलावा समिति में नीरी (NEERI), आईआईटी (IIT) और कई अन्य संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हैं।

### □ कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दंड प्रावधानों की समीक्षा करने हेतु समिति

➔ केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दंड प्रावधानों की समीक्षा करने हेतु एक दस सदस्यीय समिति गठित की। (15 जुलाई, 2018)



➔ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव इंजेती श्रीनिवास समिति के अध्यक्ष होंगे।

### □ मेट्रो रेल प्रणाली में मानकीकरण और स्वदेशीकरण हेतु समिति

➔ केंद्र सरकार ने मेट्रो रेल में मानकीकरण और स्वदेशीकरण हेतु डॉ. ई. श्रीधरन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। (26 जून, 2018)



## सम्मेलन/समारोह

### □ अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, 2018

➔ कुरुक्षेत्र, हरियाणा में आयोजन प्रस्तावित। (7-23 दिसंबर, 2018)

- ➔ इस महोत्सव में हरियाणा सरकार द्वारा गुजरात राज्य को भागीदार राज्य के रूप में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया गया है।
- ➔ वर्ष 2017 में इस महोत्सव में भागीदार राज्य उत्तर प्रदेश था।



### □ एडवेंचर नेक्स्ट, 2018

➔ भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित होगा। (3-5 दिसंबर, 2018)

- ➔ इसका आयोजन एडवेंचर ट्रैवेल की अंतरराष्ट्रीय संस्था, एडवेंचर ट्रैवेल ट्रेड एसोसिएशन (ATTA) द्वारा किया जाएगा।
- ➔ इसका आयोजन एशिया में पहली बार किया जा रहा है।
- ➔ मुख्य विषय-"Pulse of Tomorrow"।



### □ थोक बाजार विश्व संघ का 33वां सम्मेलन

➔ गुरुग्राम, हरियाणा में आयोजन प्रस्तावित। (10-12 अक्टूबर, 2018)

- ➔ इसका आयोजन हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
- ➔ यह सम्मेलन भारत में पहली बार और एशिया में दूसरी बार आयोजित होगा।
- ➔ एशिया में पहली बार थोक बाजार विश्व संघ (WUWM) का 30वां सम्मेलन वर्ष 2015 में चीन में आयोजित किया गया था।



### □ मूव : ग्लोबल मोबिलिटी शिखर सम्मेलन, 2018

➔ नीति आयोग द्वारा भारत का पहला ग्लोबल मोबिलिटी शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली में आयोजित। (7-8 सितंबर, 2018)



### □ 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 2018

➔ मॉरीशस में संपन्न। (18-20 अगस्त, 2018)

➔ मुख्य विषय-"हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति"।



### □ 24वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फिलॉसफी, 2018

➔ पैकिंग यूनिवर्सिटी, बीजिंग (चीन) में संपन्न। (13-20 अगस्त, 2018)

➔ मुख्य विषय (Theme) - 'मानव होने के लिए'



सीखना' (Learning to be Human)

➔ इसका आयोजन 'इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिलॉसफिकल सोसाइटीज' और 'पेकिंग यूनिवर्सिटी' द्वारा किया गया।

### □ प्रथम सार्क एग्री कोऑपरेटिव बिजनेस फोरम, 2018

➔ पार्क विलेज, काठमांडू (नेपाल) में संपन्ना (28-30 अगस्त, 2018)

➔ मुख्य विषय (The me)-

“दक्षिण एशिया में सतत विकास लक्ष्य 1 और 2 को प्राप्त करने में परिवार किसान सहकारी समितियों का संयोजन एवं सुदृढ़ीकरण” (Organizing and Strengthening Family Farmers Cooperatives to Attain SDGs 1 and 2 in South Asia)

### □ स्मार्ट रेलवे कॉन्क्लेव, 2018

➔ नई दिल्ली में आयोजित। (28 अगस्त, 2018)

➔ यह कार्यक्रम फिक्की (FICCI) द्वारा आयोजित किया गया।

➔ इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तकनीकी नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करना था।

### □ उत्तर प्रदेश ट्रेवल मार्ट (चतुर्थ संस्करण), 2018

➔ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में आयोजित। (27-28 अगस्त, 2018)

➔ इसका आयोजन राज्य सरकार और फिक्की (FICCI) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

### □ कृषि एवं मनरेगा अभिसरण कार्यशाला

➔ कृषि एवं मनरेगा अभिसरण कार्यशाला लखनऊ में आयोजित। (9 अगस्त, 2018)

➔ यह कार्यशाला बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में आयोजित हुई।

➔ इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया।

➔ उद्देश्य- कृषकों की आय दोगुना करने पर विचार-विमर्श करना।

### □ एक जनपद-एक उत्पाद (ओडीओपी) सम्मेलन

➔ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में आयोजित। (10 अगस्त, 2018)

➔ सम्मेलन के दौरान राज्य सरकार एवं अमेजन, जीई हेल्थकेयर, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, एनएससी, बीएससी के प्रतिनिधियों के मध्य विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

➔ सम्मेलन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों समेत अनेक उद्यमियों ने भागीदारी की।

### □ मेडटेक इनोवेशन समिट, 2018

➔ रायपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित। (31 जुलाई, 2018)

➔ इसका आयोजन स्वास्थ्य विभाग,

छत्तीसगढ़ सरकार और स्टेनफोर्ड बायोडिजाइन इन इंडिया फाउंडर्स फोरम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

➔ इस अवसर पर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 'हेल्थ टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट' शीर्षक से प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन किया।

### □ ऑर्किड उत्सव

➔ सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, उदयपुर (राजस्थान) में संपन्ना। (27-29 जुलाई, 2018)

➔ वन विभाग द्वारा आयोजित प्रदेश में इस प्रकार का

यह पहला उत्सव था, जिसमें दक्षिण राजस्थान के ऑर्किड की विभिन्न प्रजातियों को प्रदर्शित किया गया।

### □ राजस्थान डिजिफेस्ट, 2018

➔ पांचवां संस्करण, बीकानेर में संपन्ना। (25-27 जुलाई, 2018)

➔ उद्देश्य-राज्य में तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना।

➔ इसमें रोबोट 'बुधिया' को प्रदर्शित किया गया, जो भामाशाह योजना से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने के साथ ही इस योजना से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करने में भी समक्ष है।

### □ इनोवेशन समिट

➔ हरिद्वार, उत्तराखंड में संपन्ना। (22-23 जुलाई, 2018)

➔ इसका आयोजन हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण और टेक्नोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया।

➔ उद्देश्य-हरिद्वार में प्रस्तावित महाकुंभ को भव्य रूप से आयोजित किए जाने के संदर्भ में विचार-विमर्श करना।



## □ जयपुर योग महोत्सव, 2018

➔ जयपुर, राजस्थान में संपन्न। (21-23 जुलाई, 2018)

- ☉ इसका आयोजन अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा केंद्रीय आयुष मंत्रालय के केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से किया गया।



## □ उद्यमी महासम्मेलन, 2018

➔ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में आयोजित। (10 जुलाई, 2018)

- ☉ इसका आयोजन भारतीय उद्योग संघ द्वारा उत्तर प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विभाग के सहयोग से किया गया।



## □ 8वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक, 2018

➔ डरबन, दक्षिण अफ्रीका में संपन्न। (20 जुलाई, 2018)

- ☉ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।



## □ आयुष राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों का सम्मेलन, 2018

➔ आयुष मंत्रालय के अधीन 'अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान' (AIIA) द्वारा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित। (17-18 जुलाई, 2018)

- ☉ उद्देश्य-आयुष संस्थानों की स्थिति को आईआईटी और आईआईएम के समकक्ष बनाना।
- ☉ सम्मेलन के दौरान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के बीच समझौता-पत्र पर भी हस्ताक्षर हुए।



## □ चौथा ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन, 2018

➔ बेला-बेला, लिम्पोपो, दक्षिण अफ्रीका में संपन्न। (16-18 जुलाई, 2018)

- ☉ मुख्य विषय-"Radical Economic Transformation -Making the New Development Bank Work for the Youth".



## □ ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की छठवीं बैठक, 2018

➔ केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित। (9-10 जुलाई, 2018)

- ☉ मुख्य विषय-"Deepening BRICS Education Partnerships and Exchanges".



## □ 27वां मैंगो मेला

➔ पिंजौर, हरियाणा में संपन्न। (7-8 जुलाई, 2018)

- ☉ इसका आयोजन हरियाणा पर्यटन और बागवानी विभाग, हरियाणा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
- ☉ इसमें आयोजित प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के उस्मान जबकि तफजील अहमद को क्रमशः पहला एवं दूसरा स्थान जबकि उत्तराखंड के निर्मल तोमर को सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ।



➔ आम उत्पादक संस्थानों की श्रेणी में उत्तराखंड राजकीय बाग, काशीपुर पहले स्थान पर और उत्तर प्रदेश का सहारनपुर राजकीय कंपनी बाग दूसरे स्थान पर रहा।

## □ गैर-लौह खनिजों और धातुओं पर 22वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, 2018

➔ रांची, झारखंड में संपन्न। (6-7 जुलाई, 2018)

- ☉ मुख्य विषय-"Harnessing Non-ferrous Mineral Reserves for The Growth of Non-ferrous Metal Production in India".

## □ आपदा जोखिम में कमी पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, 2018

☉ उलानबटोर, मंगोलिया में आयोजित। (3-6 जुलाई, 2018)

- ☉ मुख्य विषय- "आपदा जोखिम की रोकथाम : सतत विकास की सुरक्षा" (Preventing Disaster Risk : Protecting Sustainable Development)।



## □ वन महोत्सव, 2018

➔ उत्तर प्रदेश में आयोजित। (1-31 जुलाई, 2018)

- ☉ इस महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महादेवा (बाराबंकी) में वृक्षारोपण कर किया।
- ☉ यह महोत्सव पूरे प्रदेश में संचालित किया गया।



## □ उद्यम संगम, 2018

➔ केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित (27 जून, 2018)

☞ इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया।

☞ इस अवसर पर उन्होंने 'सोलर चरखा मिशन' का शुभारंभ किया।

☞ इसके अलावा राष्ट्रपति ने एमएसएमई मंत्रालय का 'संपर्क' पोर्टल भी लांच किया।



## □ सातवीं ओपेक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, 2018

➔ वियना (ऑस्ट्रिया) में आयोजित (20-21 जून, 2018)

☞ मुख्य विषय- 'पेट्रोलियम-एक सतत भविष्य के लिए सहयोग' (Petroleum-Cooperation for a Sustainable Future)

## □ राष्ट्रीय योग ओलंपियाड, 2018

➔ नई दिल्ली में आयोजित (18-20 जून, 2018)



## □ नीति आयोग के शासी परिषद की चौथी बैठक

➔ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के शासी परिषद की चौथी बैठक संपन्न। (17 जून, 2018)



☞ इसका उद्देश्य विकास कार्यों की समीक्षा करना था।

## □ इबसा के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक, 2018

➔ प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में संपन्न (4 जून, 2018)

☞ विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।



## □ 23वां यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव, 2018

➔ महोत्सव का शुभारंभ सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में (18 जून, 2018)

☞ फिल्म महोत्सव के दौरान 18 जून से 31 अगस्त, 2018 तक नई दिल्ली, चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर, पुडुचेरी, कोलकाता, जयपुर, पुणे, विशाखापत्तनम, त्रिशुर, हैदराबाद तथा गोवा में फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।



➔ इस फिल्म महोत्सव की उद्घाटन फिल्म स्लोवाकिया की 'लिटिल हार्बर' (Little Harbour) रही।

## संधि/समझौता

### □ विश्व बैंक एवं बांग्लादेश के बीच वित्तीय समझौता

➔ विश्व बैंक ने बांग्लादेश में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार हेतु आर्थिक समझौते किए।



☞ विश्व बैंक बांग्लादेश में माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु 'ट्रांसफॉर्मिंग सेकंडरी एजुकेशन फॉर रिजल्ट' (टीएसईआर) कार्यक्रम चलाएगा, जिसके लिए 510 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रावधान किया गया है। (13 अगस्त, 2018)

☞ प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु 715 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहयोग से 'क्वालिटी लर्निंग फॉर ऑल' कार्यक्रम चलाया जाएगा। (28 जून, 2018)

### □ एनएचएआई और एसबीआई में समझौता

➔ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के मध्य दीर्घकालिक असुरक्षित ऋण हेतु समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर। (3 अगस्त, 2018)



☞ इस समझौते के तहत भारतीय स्टेट बैंक एनएचएआई को 10 वर्षों की अवधि हेतु 25,000 करोड़ रुपये राशि का असुरक्षित ऋण प्रदान करेगा।

☞ मंजूर की गई कुल राशि का वितरण 31 मार्च, 2019 के पहले एनएचएआई को कर दिया जाएगा।

☞ इस ऋण की पुनर्भुगतान स्थगन अवधि 3 वर्ष है।

➔ यह किसी संस्थान द्वारा एकबारगी एनएचएआई हेतु मंजूर की गई सर्वाधिक ऋण राशि तथा एसबीआई द्वारा एकबारगी किसी निकाय को मंजूर की गई सर्वाधिक दीर्घकालिक असुरक्षित ऋण राशि भी है।

### □ स्वास्थ्य मंत्रालय एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मध्य समझौता

➔ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी' (NHA) तथा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 'समान सेवा केंद्र' (CSC) के मध्य समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर। (31 जुलाई, 2018)



☞ इस समझौते से 2.5 लाख पंचायतों में तीन लाख 'समान सेवा केंद्र' (सीएससी) के माध्यम से स्वास्थ्य योजना 'आयुष्मान भारत' के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी, जिससे 50 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।

## ❑ इन्वेस्ट इंडिया और बिजनेस फ्रांस में समझौता

➔ इन्वेस्ट इंडिया और बिजनेस फ्रांस के मध्य भारत और फ्रांस में स्टार्ट-अप एवं निवेश में सुविधा हेतु समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर। (25 जुलाई, 2018)



- ❶ उद्देश्य-प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाना और आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान प्रदाता कंपनियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

## ❑ नीति आयोग और ल्यूपिन फाउंडेशन में समझौता

➔ नीति आयोग और ल्यूपिन

फाउंडेशन के मध्य सरकार द्वारा चिह्नित आकांक्षी जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, वित्तीय समावेश, कौशल विकास, कृषि, जल संसाधन तथा पिछड़े जिलों के बुनियादी ढांचे के संकेतकों में सुधार हेतु सहयोग के लिए समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर। (23 जुलाई, 2018)



- ❶ समझौता-ज्ञापन के अंतर्गत प्रथम चरण में तीन राज्यों के तीन जिलों (डोलपुर (राजस्थान), नंदुरबार (महाराष्ट्र) और विदिशा (मध्य प्रदेश) में आर्थिक विकास, तकनीकी व्यवहार्यता और नैतिक नेतृत्व को विकसित करने हेतु ये दोनों संस्थान मिलकर काम करेंगे।

## ❑ एनएचए और पश्चिम बंगाल सरकार में समझौता

➔ पश्चिम बंगाल सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (National Health Agency) के बीच केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन को बढ़ावा देने हेतु राज्य में स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने हेतु समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर (20 जुलाई, 2018)

- ❶ उद्देश्य-इस योजनांतर्गत 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रतिवर्ष प्रदान किया जाना है।

## ❑ सीएसआईआर-एनपीएल और एचपीसीएल में समझौता

➔ सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (CSIR-National Physical Laboratory) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के बीच भारतीय निर्देशक द्रव्य के व्यावसायिक नाम के अंतर्गत पेट्रोलियम प्रमाणित संदर्भ सामग्री के स्वदेशी विकास हेतु समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर। (19 जुलाई, 2018)



## ❑ भारत-क्यूबा समझौता

➔ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और क्यूबा के मध्य पारंपरिक औषधि एवं होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग हेतु किए गए समझौता-ज्ञापन को



पूर्वव्यापी मंजूरी। (18 जुलाई, 2018)

- ❶ यह समझौता-ज्ञापन 22 जून, 2018 को हस्ताक्षरित हुआ था।

## ❑ ब्रिक्स देशों के मध्य क्षेत्रीय विमानन साझेदारी हेतु समझौता

➔ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा क्षेत्रीय विमानन साझेदारी सहयोग पर ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी। (18 जुलाई, 2018)

- ❶ ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।

## ❑ भारत-इंडोनेशिया समझौता

➔ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत के केंद्रीय औषधीय मानक नियंत्रण संगठन और इंडोनेशिया के नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग एंड फूड कंट्रोल के मध्य औषधीय उत्पाद, औषधीय पदार्थ, जैव वैज्ञानिक उत्पाद और सौंदर्य प्रसाधन विनियमन के क्षेत्र में सहयोग हेतु किए गए समझौता-ज्ञापन को पूर्वव्यापी मंजूरी। (18 जुलाई, 2018)



- ❶ इस समझौता-ज्ञापन पर 25 मई, 2018 को जकार्ता (इंडोनेशिया) में हस्ताक्षर किया गया था।

## ❑ ICAI और CPA, आयरलैंड के मध्य समझौता

➔ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आईसीएआई (ICAI) और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्डेड पब्लिक अकाउंटेंट्स (CPA), आयरलैंड के मध्य हाल ही में किए गए पारस्परिक मान्यता समझौते को मंजूरी। (18 जुलाई, 2018)

- ❶ इस समझौते से लेखांकन ज्ञान के उन्नयन, पेशेवर एवं बौद्धिक विकास, संबंधित सदस्यों के हितों को बेहतर बनाने तथा भारत और आयरलैंड में लेखा पेशा के विकास में सकारात्मक योगदान के लिए पारस्परिक सहयोग ढांचे को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

## ❑ आईसीएआई और बीआईबीएफ में समझौता

➔ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय सनदी लेखा संस्थान (ICAI : Institute of Chartered Accountants of India) और बहरीन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (BIBF), बहरीन के मध्य समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी। (18 जुलाई, 2018)

- ❶ इस समझौता-ज्ञापन के अंतर्गत दोनों संस्थान बहरीन में लेखा वित्त तथा लेखा परीक्षण आधारित ज्ञान को मजबूत बनाने हेतु मिलकर काम करेंगे।

## ❑ बीईएल और स्वीडिश फर्म 'साब' में समझौता

➔ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) एवं स्वीडिश एयरोस्पेस और रक्षा फर्म 'साब' (Saab) के बीच एल-बैंड 3 डी एयर-निगरानी रडार रॉल-03 (RAWL-03) के संयुक्त रूप





से विपणन हेतु समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर (16 जुलाई, 2018)

- ☉ यह एयर-निगरानी रडार दोनों कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- ☉ नवीनतम सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीक से युक्त यह रडार हवा और सतह के लक्ष्यों की प्रारंभिक पहचान और ट्रैकिंग में सहायक होगा।

## □ भारत-यूके के मध्य समझौता

➔ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और यूके के मध्य कानून एवं न्याय के क्षेत्र में सहयोग और एक संयुक्त परामर्श समिति का गठन करने हेतु समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी। (4 जुलाई, 2018)

➔ भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य कानून एवं न्याय के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग तथा एक परामर्श समिति गठित करने हेतु समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर। (जुलाई, 2018)

## □ 'ब्रू' समुदाय के प्रत्यावर्तन हेतु समझौता

➔ भारत सरकार, मिजोरम और त्रिपुरा की सरकार और 'मिजोरम ब्रू (Bru) डिस्प्लेस्ड पीपुल्स फोरम' (MBDPF) के मध्य मिजोरम से विस्थापित (वर्ष 1997 से) ब्रू (Bru) समुदाय के प्रत्यावर्तन हेतु समझौते पर हस्ताक्षर। (3 जुलाई, 2018)

☉ समझौते के तहत वर्तमान में त्रिपुरा में अस्थायी शिविरों में निवासरत परिवारों में से 5,407 परिवार 30 सितंबर, 2018 से पूर्व मिजोरम वापस आ जाएंगे।

➔ विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) रीना मित्रा की अध्यक्षता में एक समिति इस समझौते के कार्यान्वयन का समन्वय करेगी।

## □ भेल-नैनो कंपनी लिमिटेड में समझौता

➔ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) और दक्षिण कोरिया की नैनो कंपनी लिमिटेड के मध्य कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में उत्सर्जन नियंत्रण के लिए एससीआर उत्प्रेरकों की डिजाइन एवं निर्माण संबंधी प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता किया गया। (28 जून, 2018)

- ☉ यह समझौता भेल को उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों (De-Nox अनुप्रयोगों) के उपयोग को बढ़ाने में सक्षम करेगा।
- ☉ भेल मेक इन इंडिया पहल के तहत इस प्रकार की प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षमताओं का उपयोग करने वाली पहली भारतीय कंपनी होगी।

## □ भारत-सिंगापुर में समझौता

➔ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और सिंगापुर के मध्य शहरी नियोजन और विकास के क्षेत्र में सहयोग हेतु 31 मई, 2018 को हस्ताक्षरित



समझौता-ज्ञापन को पूर्वव्यापी मंजूरी। (27 जून, 2018)

- ☉ समझौता-ज्ञापन के अंतर्गत नियोजन के क्षेत्र में क्षमता सृजन कार्यक्रम, शहरी नियोजन, जल और अपशिष्ट; जल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कुशल परिवहन प्रणाली और सार्वजनिक वित्तपोषण (सार्वजनिक निजी भागीदारी) पर फोकस किया जाएगा।

## □ भारत-बहरीन में समझौता

➔ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और बहरीन के मध्य स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हेतु मंजूरी। (27 जून, 2018)

- ☉ समझौता-ज्ञापन के तहत शामिल सहयोग के विवरणों को व्यापक बनाने तथा समझौता-ज्ञापन के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु एक संयुक्त कार्यसमूह का गठन किया जाएगा।

## □ भारत-जर्मनी में समझौता

➔ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और जर्मनी के बीच नागर विमानन क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हेतु मंजूरी। (27 जून, 2018)

## □ मुथूट फिनकोर्प लिमिटेड और एनएसडीसी में समझौता

➔ मुथूट फिनकोर्प लिमिटेड और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2 (पीएमकेवीवाई-2) कार्यक्रम के तहत 10,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु साझेदारी की घोषणा। (17 जून, 2018)

- ☉ इस योजना के तहत मुथूट फिनकोर्प आगामी तीन वर्षों में 10,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार हेतु तैयार करेगा।

## □ मेघालय करेगा आयुष्मान भारत का कार्यान्वयन

➔ मेघालय के स्वास्थ्य मंत्री ए.एल. हेक और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा के बीच आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन को कार्यान्वित करने के संबंध में नई दिल्ली में आयोजित स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में एक समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। (14 जून, 2018)

- ☉ इस समझौते के बाद मेघालय सरकार, मेघालय राज्य बीमा योजना का विलय आयुष्मान भारत योजना में करेगी।
- ☉ गौरतलब है कि मेघालय स्वास्थ्य बीमा योजना में 2,80,000 रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है, जबकि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।

## □ भारत-पेरू समझौता

➔ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और पेरू के बीच नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हुए समझौते को मंजूरी। (13 जून, 2018)



- यह समझौता मई, 2018 में लीमा (पेरू) में हस्ताक्षरित हुआ था।
- उद्देश्य-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में पारस्परिक लाभ समानता पारस्परिकता के आधार पर तकनीकी द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने हेतु दोनों देशों के मध्य सहयोगात्मक संस्थागत संबंध स्थापित करना।

## ❑ ओडिशा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना हेतु समझौता

➔ ओडिशा सरकार के खेल एवं युवा सेवा विभाग और पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन फाउंडेशन के मध्य राज्य में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी की स्थापना हेतु समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर। (8 जून, 2018)



- प्रस्तावित बैडमिंटन अकादमी हेतु ओडिशा सरकार द्वारा सभी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

## संघ/संगठन

### ❑ वोडाफोन-आइडिया का विलय

➔ भारतीय दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर के विलय को मंजूरी प्रदान की। (26 जुलाई, 2018)



- नई कंपनी का प्रस्तावित नाम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड होगा।
- कुमार मंगलम बिड़ला नई इकाई के गैर-कार्यकारी चेयरमैन और बालेश शर्मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे।

### ❑ भारत को मिला सामरिक व्यापार प्राधिकरण- 1 का दर्जा

➔ संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान और दक्षिण कोरिया के बाद भारत को सामरिक व्यापार प्राधिकरण-1 (STA-1) सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है। (जुलाई, 2018)



- भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एसटीए-1 सूची में शामिल होने वाला 37वां देश है।
- साथ ही भारत यह दर्जा पाने वाला दक्षिण एशिया का पहला और एशिया का तीसरा देश है।

### ❑ बजाज इलेक्ट्रिकल्स द्वारा निरलेप का अधिग्रहण

➔ बजाज इलेक्ट्रिकल्स कंपनी ने नॉन स्टिक कुकवेयर कंपनी निरलेप एप्लाइंसेज के सभी शेयरों को 42.50 करोड़ में खरीद लिया। (15 जून, 2018)

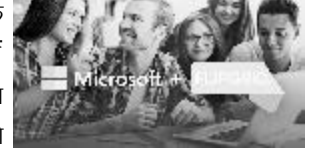


- अब निरलेप कंपनी बजाज इलेक्ट्रिकल्स की सहायक कंपनी बन गई है।

### ❑ माइक्रोसॉफ्ट ने फिलपग्रीड का अधिग्रहण किया

➔ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म फिलपग्रीड का अधिग्रहण कर लिया है। (18 जून, 2018)

- शिक्षकों के सशक्तीकरण के उद्देश्य से वर्ष 2015 में फिलपग्रीड सशुल्क सेवा शुरू की गई, जिसमें वीडियो लेक्चर के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है।



- इस अधिग्रहण के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने फिलपग्रीड की सेवा निःशुल्क करने का ऐलान किया है।

## विधि/न्याय

### ❑ राष्ट्रीय खेल-कूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2018

- ➔ राष्ट्रीय खेल-कूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2018 राज्य सभा में पारित। (9 अगस्त, 2018)
- यह विधेयक लोक सभा द्वारा 3 अगस्त, 2018 को पारित किया जा चुका है।
- इस विधेयक के तहत मणिपुर में 542 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।



- ➔ यह दूरस्थ कैंपस, क्षेत्रीय केंद्रों या कॉलेजों की स्थापना भारत या भारत के बाहर कर सकता है।

- विश्वविद्यालय को विश्वस्तरीय बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया के दो विश्वविद्यालयों, (कैनबरा विश्वविद्यालय और विक्टोरिया विश्वविद्यालय) की पाठ्यचर्या अनुसंधान सुविधाओं और प्रयोगशालाओं के विकास के लिए सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

- यह विश्वविद्यालय शारीरिक शिक्षा पर शोध कार्य, खेल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सशक्त बनाने का कार्य करेगा।

### ❑ अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2018

- ➔ अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2018 राज्य सभा में पारित। (9 अगस्त, 2018)



- लोक सभा में यह विधेयक 6 अगस्त, 2018 को पारित हुआ था।
- संशोधित विधेयक में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु किसी जांच अधिकारी की मंजूरी के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
- ➔ विधेयक में यह भी प्रावधान है कि आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराने के लिए प्रारंभिक जांच आवश्यक नहीं है।

### ❑ दांडिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2018

- ➔ दांडिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2018 राज्य सभा में पारित। (6 अगस्त, 2018)

- यह विधेयक लोक सभा में 30 जुलाई, 2018 को पारित किया जा चुका है।
- विधेयक के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता, 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पाक्सो अधिनियम), 2012 के कई प्रावधानों में संशोधन किया गया है।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 376 में संशोधन द्वारा बलात्संग के लिए न्यूनतम दंड 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है।
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173(IA) में संशोधन कर बच्चों से बलात्कार के अन्वेषण प्रक्रिया को पूर्ण करने की अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह कर दी गई है।
- धारा 376 में उपखंड (3) के तहत 16 वर्ष से कम आयु की महिला से बलात्कार की दशा में न्यूनतम 20 वर्ष का कठोर कारावास हो सकेगा (शेष प्राकृत जीवन) तथा अर्थदंड से दंडित किए जाने का उपबंध किया गया है।
- 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री (बालिका) से बलात्कार पर न्यूनतम 20 वर्ष का कठोर कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है, सामूहिक बलात्कार की दशा में आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है।



## ❑ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018

- भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018 राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत (26 जुलाई, 2018)
- लोक सभा द्वारा यह विधेयक 24 जुलाई, 2018 को और राज्य सभा द्वारा 19 जुलाई, 2018 को पारित कर दिया गया था।
- इस अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन किया गया है।
- इसमें किसी व्यक्ति द्वारा लोकसेवक को रिश्वत दिए जाने के अपराध के लिए न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने का उपबंध किया गया है।
- धन व संपत्ति आदि के समपहरण व कुर्की के लिए एक नया अध्याय IVA जोड़ा गया है।



- वर्ष 2018 के अधिनियम में आदतन (Habitual) अपराधियों के कारावास की न्यूनतम अवधि 5 वर्ष तथा अधिकतम अवधि 10 वर्ष किया जाना प्राविधानित है।

## ❑ व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018

- व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 लोक सभा में पारित। (26 जुलाई, 2018)
- इस विधेयक के अंतर्गत तस्करी के



- शिकार लोगों के निवारण, बचाव और पुनर्वास का प्रावधान है।
- विधेयक में तस्करी के मामलों की जांच एवं विभिन्न प्रावधानों को लागू करने हेतु राष्ट्रीय तस्करी रोधी ब्यूरो (National Anti Trafficking Bureau) की स्थापना का प्रावधान है।
- इस विधेयक के अंतर्गत राज्य सरकार राज्य नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगी।
- इसके अलावा इसमें जिला स्तर पर एंटी ट्रेफिकिंग यूनिट्स और राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर एंटी ट्रेफिकिंग राहत और पुनर्वास कमेटी (एटीसीज) के गठन का भी प्रावधान किया गया है।

## ❑ उत्तराखंड उच्च न्यायालय : जीव-जंतुओं को विधिक व्यक्ति का दर्जा

- उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा आकाशीय व जलीय जीवों सहित समस्त जीव समुदाय को, जो जीवित व्यक्तियों से संबंधित अधिकार, कर्तव्यों और देनदारियों के साथ एक विशिष्ट व्यक्तित्व रखते हैं, को विधिक इकाई घोषित किया गया। (4 जुलाई, 2018)
- यह निर्णय न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने सुनाया।



## ❑ मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018

- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 को मंजूरी। (19 जून, 2018)
- संशोधन के अंतर्गत नामांतरण, जीवनकाल (जीवित अवस्था में) में भूमि का बंटवारा, सीमांकन में निजी अधिकृत एजेंसियों की सहायता प्राप्त करने, डायवर्जन, सीमांकन, बंदोबस्त, बटाई व्यवस्था आदि के संबंध में प्रावधान किया गया है।



## वर्ष/दिवस

### ❑ अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस

- तिथि - 8 सितंबर, 2018
- मुख्य विषय - 'साक्षरता और कौशल विकास' (Literacy and Skills Development)



### ❑ परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस

- तिथि - 29 अगस्त, 2018
- इस दिवस का उद्देश्य परमाणु हथियारों से होने वाले नुकसान एवं उनके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता विकसित करना है।



## □ विश्व मानवतावादी दिवस

→ तिथि - 19 अगस्त, 2018

→ यह दिवस उन लोगों की स्मृतियों हेतु मनाया जाता है जिन्होंने मानवता की सेवा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए।



## □ विश्व के स्थानीय लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस

→ तिथि-9 अगस्त, 2018

→ मुख्य विषय- 'स्वदेशी लोगों के प्रवासन और आंदोलन' (Indigenous people's migration and movement)



## □ विश्व स्तनपान सप्ताह

→ तिथि-1-7 अगस्त, 2018

→ स्लोगन- 'स्तनपान : जीवन के लिए आधार' (Breastfeeding : Foundation of Life)



## □ राष्ट्रीय हथकरघा दिवस

→ तिथि- 7 अगस्त, 2018

→ उद्देश्य-हथकरघा उद्योग के महत्व एवं आमतौर पर देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना।



## □ अर्थ ओवरशूट डे

→ तिथि- 1 अगस्त, 2018

→ यह वह अनुमानित दिन है, जब मनुष्य उस वर्ष के लिए निर्धारित प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर चुका होता है।

→ इस सीमा के बाद उपभोग उस वर्ष में प्रकृति द्वारा मनुष्य पर ऋण होता है।

→ इसलिए इस दिवस को 'पारिस्थितिकी ऋण दिवस' भी कहा जाता है।

→ उद्देश्य- पृथ्वी के सीमित संसाधनों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा भावी पीढ़ियों के लिए उसे संरक्षित करना।



## □ अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस

→ तिथि-29 जुलाई, 2018

→ उद्देश्य- विश्व में बाघों के निवास के संरक्षण, विस्तार तथा उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना।



## □ विश्व हेपेटाइटिस दिवस

→ तिथि-28 जुलाई, 2018

→ मुख्य विषय-"Test. Treat. Hepatitis"।



## □ विश्व जनसंख्या दिवस

→ तिथि-11 जुलाई, 2018

→ मुख्य विषय- "परिवार नियोजन एक मानव अधिकार है" (Family Planning is a Human Right)



## □ अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस

→ तिथि- 7 जुलाई, 2018 (जुलाई का प्रथम शनिवार)

→ मुख्य विषय- "सतत उपभोग और उत्पादन" (Sustainable Consumption and Production)



→ स्लोगन-"सहयोग के माध्यम से सतत विकास" (Sustainable Societies Through Cooperation)

## पुस्तकें

- अनकही थी जो— ब्रह्मानन्द दुबे
- थनपंडी सिंघम — एम. करुणानिधि
- अभिमन्यु —रामपाडा चौधरी
- द धौनी टच : अनरैवेलिंग द इनिग्मा दैट इज महेंद्र सिंह धौनी — भरत सुंदरेसन
- द हाउस ऑफ इस्लाम : ए ग्लोबल हिस्ट्री— इद हुसैन
- सिंगल मदर— जे.के. वर्मा
- क्लाउड्स— चन्द्रहास चौधरी
- ऑल द नेम्स दे यूज्ड फॉर गाड —अंजलि सचदेवा
- गर्ल्स बर्न ब्राइटर —शोभा राव
- एक्रॉस द बेंच : इनसाइट इनटू द इंडियन मिलिटरी ज्यूडिशियल सिस्टम— ले. जनरल ज्ञान भूषण
- सिटीजन डेवेली : माई टाइम्स, माई लाइफ— शीला दीक्षित
- रमाल कंट्री— गेल फ्राए
- वारलाइट — माइकल ओन्दात्जे
- द वोमेन इन द विंडो— ए.जे. फिन
- द ग्रेट एलोन— क्रिस्टिन हन्नाह
- स्टिल मी — जोजो मोएस
- कोशिशों की उड़ान— पूजा अग्रवाल
- ऑल वी इवर वांटेड— एमिली गिफिन
- द ब्रोकेन गर्ल्स— सिमोने सेंट जेम्स
- आयरन गोल्ड— पियर्स ब्राउन
- लेजेंड्री— स्टेफनी गारबर
- कालिंग सेहमत-हरिंदर सिक्का
- डेविल्स एडवोकेट : द अनटोल्ड स्टोरी— करन थापर
- नवीन पटनायक— रुबेन बनर्जी
- सी प्रेयर— खालेद हुसैनी
- काशी : सीक्रेट ऑफ द ब्लैक टेम्पल — विनीत बाजपेई
- न्यूजमैन : ट्रेकिंग इंडिया इन द मोदी एरा— राजदीप सरदेसाई
- इंदिरा : इंडियाज मोस्ट पॉवर फुल प्राइममिनिस्टर— सागरिका घोष

- द व्यूटी ऑफ ऑल माई डेज : ए मेमॉयर— रस्किन बांड
- इफ यू लीव मी— क्रिस्टल हाना किम
- द ग्रेट बिलीवर्स — रेबेका मार्काई
- द बुक ऑफ एम— पेंग शेफर्ड
- ए रिवर ऑफ स्टार्स — वनेशा हुआ
- कुल्हड़ भर इश्क : काशीश्क — कौशलेन्द्र मिश्र
- वापसी इम्पॉसिबल — सुरभि सिंघल
- यदा यदा हि योगी — विजय त्रिवेदी
- सरगोशियां— ममता तिवारी
- रेड अलर्ट — प्रभात रंजन
- अंधेरे में बुद्ध — गगन गिल
- रस्ट एंड स्टारडस्ट — टी. ग्रीनवुड
- द गोल्डेन टॉवर— होली ब्लैक
- दास्तान-ए-दस्तकारी : लीजेंड्स ऑफ क्रॉफ्ट — मुजफ्फर अली

## विविध

### □ सऊदी अरब में रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म

➔ प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत फिल्म 'गोल्ड' सऊदी अरब में रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बनी। (30 अगस्त, 2018)



- इससे पूर्व रजनीकांत अभिनीत फिल्म 'काला' सऊदी अरब में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म (टॉलीवुड) थी।
- गौरतलब है कि कट्टरपंथियों के विरोध के चलते सऊदी अरब में सिनेमा पर विगत 35 वर्षों से प्रतिबंध लगा था।
- इस प्रतिबंध को 18 अप्रैल, 2018 को हटा दिया गया।
- हॉलीवुड फिल्म ब्लैक पैथर सऊदी अरब में प्रतिबंध हटने के बाद रिलीज हुई पहली फिल्म थी।

### □ स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, 2019

➔ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा विश्व के सबसे बड़े ओपन इनोवेशन मॉडल के तृतीय संस्करण 'स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, 2019' (SIH, 2019) का शुभारंभ। (29 अगस्त, 2018)



➔ एसआईएच, 2019 लोगों के जीवन में आने वाली कुछ गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए छात्रों को एक मंच मुहैया करवाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल है।

➔ यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एआईसीटीई, पर्सिस्टेंस सिस्टम्स, आई4सी और रामभाऊ मल्गी प्रबोधिनी की संयुक्त पहल है।

### □ विश्व के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची, 2018

➔ प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका 'फोर्ब्स' द्वारा जारी। (22 अगस्त, 2018)

### ○ सूची में शामिल शीर्ष 3 अभिनेता -

- अमेरिकी अभिनेता जॉर्ज क्लूनी (239 मिलियन अमेरिकी डॉलर) 
- अमेरिकी अभिनेता डूवेन जॉनसन (द रॉक) (124 मिलियन अमेरिकी डॉलर) 
- अमेरिकी अभिनेता एवं निर्माता रॉबर्ट जॉन डॉनी जूनियर (81 मिलियन अमेरिकी डॉलर) 

WORLD'S HIGHEST PAID ACTORS 2018

### ➔ सूची में शामिल भारतीय अभिनेता -

- अक्षय कुमार (7वें स्थान पर, 40.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर)
- सलमान खान (9वें स्थान पर, 38.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर)

### □ विश्व की उच्चतम भुगतान पाने वाले महिला एथलीटों की सूची, 2018

➔ प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका 'फोर्ब्स' द्वारा जारी। (21 अगस्त, 2018)

### ○ सूची में शामिल शीर्ष 3 महिला एथलीट

- प्रसिद्ध अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स (18.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर) 
- डेनमार्क की टेनिस खिलाड़ी कैरोलीन वॉज्जिआकी (13 मिलियन अमेरिकी डॉलर)
- अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी स्लोएन स्टीफेंस (11.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर)

➔ इस वर्ष की सूची में भारत की एक ही महिला खिलाड़ी पी.वी. सिंधु (बैडमिंटन) को स्थान प्राप्त हुआ है जो 8.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ सातवें स्थान पर रहीं।

### □ विश्व की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों की सूची, 2018

➔ प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका 'फोर्ब्स' द्वारा जारी। (16 अगस्त, 2018)

### ➔ सूची में शामिल शीर्ष 3 अभिनेत्रियां

- अमेरिकी अभिनेत्री, मॉडल एवं गायिका स्कार्लेट जोहॉनसन (40.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) 
- अमेरिकी अभिनेत्री एंजेलिना जॉली (28 मिलियन अमेरिकी डॉलर) 
- अमेरिकी अभिनेत्री जेनिफर एनिस्टन (19.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) 

WORLD'S HIGHEST PAID ACTRESSES 2018

➔ विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सूची में कोई भारतीय अभिनेत्री शामिल नहीं है।

### □ नीति आयोग और सीआईआई के बीच एसडीजी पर भागीदारी

➔ नीति आयोग, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और संयुक्त राष्ट्र द्वारा नई दिल्ली में सरकार और उद्योग जगत



साझेदारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। (8 अगस्त, 2018)

- ☉ सम्मेलन के दौरान नीति आयोग और भारतीय उद्योग परिसंघ ने सतत विकास लक्ष्यों पर तीन वर्षों के लिए एक साझेदारी का शुभारंभ किया।

➔ सम्मेलन में सीआईआई ने "Indian Solutions for the World to Achieve SDGs" रिपोर्ट पेश की, जिसमें एसडीजी और कारोबारी निहितार्थों के बारे में विस्तार से बताया गया है।

## □ बोलीदाता सूचना प्रबंधन प्रणाली

➔ केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग, जहाजरानी तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बोलीदाता सूचना प्रबंधन प्रणाली (BIMS) और भूमि राशि तथा लोक वित्त प्रणाली (PFMS) संपर्क पोर्टल का शुभारंभ। (6 अगस्त, 2018)



- ☉ उद्देश्य- निर्माण पूर्व गतिविधियों से संबंधित बोली प्रक्रिया और भूमि अधिग्रहण के कार्यों में तेजी लाना।
- ☉ बीआईएमएस (BIMS) का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से जुड़े अनुबंध और प्रक्रियाओं को बोलीदाताओं के लिए ज्यादा पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है।

➔ 'भूमि राशि पोर्टल' सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा मिलकर तैयार किया गया है।

- ☉ इस पोर्टल में देश के सभी 6.4 लाख गांवों की भूमि का राजस्व आंकड़ा दिया गया है।
- ☉ इससे भूमि परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आसान हो सकेगी।

➔ पीएफएमएस एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जिसे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय (CGA) द्वारा विकसित और क्रियान्वित किया गया है।

## □ नासा का पहला वाणिज्यिक यान

➔ भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स सहित नौ अंतरिक्ष यात्रियों को अमेरिकी एजेंसी नासा ने वाणिज्यिक (Commercial) रॉकेट और अंतरिक्ष यान के पहले मिशन के लिए चुना है। (3 अगस्त, 2018)



- ☉ यह मिशन वर्ष 2019 की शुरुआत में बोइंग सीएसटी-100 स्टारलाइनर एवं स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा जाएगा।
- ☉ नए अंतरिक्ष यान का निर्माण और संचालन बोइंग कंपनी और स्पेस एक्स ने किया है।

➔ इस मिशन में सुनीता विलियम्स के अलावा जोस कसाडा, रॉबर्ट बेहंकन, डगलस हर्ले, एरिक बोए, निकोल मैन, क्रिस्टोफर फर्ग्युसन, विक्टर ग्लोवर और माइकल हॉपकिंस नौ सदस्यीय दल के सदस्य होंगे।

## □ चीन द्वारा हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट का परीक्षण

➔ चीन द्वारा उत्तर-पश्चिम चीन में अत्याधुनिक हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट का सफल परीक्षण। (3 अगस्त, 2018)



- ☉ इस एयरक्रॉफ्ट का नाम जिंगकांग-2 (XINGKONG-2) अथवा स्टारी स्काई-2 (STARRY SKY-2) है।
- ☉ यह एयरक्राफ्ट चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन की भागीदारी में 'चाइना एकेडमी ऑफ एयरोस्पेस एयरो-डायनामिक्स' (CAA) द्वारा निर्मित किया गया है।

➔ उड़ान के दौरान एयरक्राफ्ट 5.5-6 मैक की गति से 30 किमी. ऊंचाई तक पहुंचा।

## □ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के संदर्भ में WHO की रिपोर्ट

➔ 2 अगस्त, 2018 को जारी WHO की रिपोर्ट

में अनुमान लगाया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के परिणामस्वरूप अक्टूबर, 2014 से अक्टूबर, 2019 के मध्य अतिसार एवं प्रोटीन के अभाव से जनित कुपोषण के चलते तीन लाख से ज्यादा मौतों की रोकथाम की जा सकेगी।



- ☉ SBM-G के तहत 19 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित किया गया है।
- ☉ जहां 7.9 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया, वहीं 421 जिले ODF घोषित किए गए।
- ☉ साथ ही देश में 4.9 लाख से अधिक गांव भी ODF घोषित किए गए।
- ☉ भारत का ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 2 अगस्त, 2018 तक 89.07 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

## □ गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन हेतु नीति-रूपरेखा को मंजूरी

➔ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शेल ऑयल/गैस और कोल बेड मीथेन (सीबीएम) जैसे गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन की खोज एवं दोहन हेतु नीति-रूपरेखा को मंजूरी। (1 अगस्त, 2018)

- ☉ इस नीति की मंजूरी के पश्चात् 'एकल हाइड्रोकार्बन संसाधन प्रकार' के स्थान पर 'समान लाइसेंसिंग नीति' लागू होगी, जो हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (HELP) और अन्वेषित लघु क्षेत्र (DSF) नीति में लागू है।

## □ 13 नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु मंजूरी

➔ आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 7 राज्यों में 13 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना हेतु मंजूरी। (1 अगस्त, 2018)



- ☉ मंजूरी प्रदत्त 13 नए केंद्रीय विद्यालयों में उत्तर प्रदेश में 5 केंद्रीय विद्यालयों (बांदा, मिर्जापुर, भदोही,

सीआईएसएफ सूरजपुर और बावली) की स्थापना की जाएगी।

- ☉ इसके अलावा मध्य प्रदेश में रतलाम जिले के एलोट में दूसरे जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना करने हेतु भी मंजूरी प्रदान की गई है।

## ☐ पहला स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर

➔ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के कंप्यूटर वैज्ञानिकों एवं छात्रों की एक टीम ने प्रोजेक्ट शक्ति के अंतर्गत 'RISECREEK' नाम के एक स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर को विकसित किया है। (अगस्त, 2018)



- ☉ यह माइक्रोप्रोसेसर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है एवं यह 350 मेगाहर्ट्ज पर कार्य करने वाले रक्षा एवं रणनीतिक उपकरणों की मांग के अनुरूप कार्य कर सकता है।

## ☐ रेलवे में कार्यरत खिलाड़ियों के लिए नई संवर्धन नीति

➔ केंद्रीय रेल एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल द्वारा रेलवे में कार्यरत खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु नई नीति को मंजूरी। (अगस्त, 2018)

- ☉ इस नई नीति के अनुसार, ओलंपिक खेलों से जुड़ी प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ी तथा उनके कोचों और पद्मश्री सहित अन्य खेल पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को भी अधिकारी श्रेणी में पदोन्नत किया जाएगा।

## ☐ मुख्य युद्धक टैंक इंजन का स्वदेशी निर्माण

➔ केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई स्थित इंजन फैक्ट्री अवाडी में मुख्य युद्धक टैंक टी-72 और टी-90 के लिए स्वदेश में विकसित इंजन को सेना को सौंपा। (29 जुलाई, 2018)



- ☉ इस फैक्ट्री में टी-72 अजेय टैंक के लिए वी 46-6 (V46-6) इंजन को और टी-90 भीष्म टैंक के लिए वी92एस2 (V92S2) इंजन को विकसित किया गया है।

## ☐ 70 रेलवे स्टेशनों के सुगम्यता परीक्षण की पहल

➔ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) और 'योजना तथा वास्तुकला विद्यालय' (School of Planning and Architecture), दिल्ली के मध्य सुगम्य बनाए गए 10 प्रतिशत स्टेशनों के सुगम्यता परीक्षण हेतु समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर। (27 जुलाई, 2018)

- ☉ समझौता-ज्ञापन के अंतर्गत 6 माह की अवधि के भीतर 25 राज्यों में 70 स्टेशनों का सुगम्यता परीक्षण किया जाएगा।

## ☐ छत्तीसगढ़ के मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण की पहली आधिकारिक रिपोर्ट

➔ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह

द्वारा छत्तीसगढ़ के मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण की पहली आधिकारिक रिपोर्ट का विमोचन। (24 जुलाई, 2018)



- ☉ यह रिपोर्ट भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा तैयार की गई है।

- ☉ राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2015-16 के अंतर्गत यह सर्वेक्षण राज्य के तीन जिलों (रायपुर, कबीरधाम और जांजगीर-चांपा) के 60 गांवों में किया गया।

- ☉ रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर राज्य में लगभग 20 लाख वयस्क किसी न किसी प्रकार के मानसिक विकार से ग्रस्त हैं।

## ☐ आईओसीएल यूपीएसओ-2 और एलिम्को में समझौता

➔ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

यूपीएसओ-2 (विपणन डिवीजन) और भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO-Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India) के मध्य कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व योजना के तहत दिव्यांगजनों की मदद हेतु समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर। (24 जुलाई, 2018)



- ☉ समझौता-ज्ञापन के अंतर्गत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीएसओ-2 (UPSO-2) एलिम्को को 1 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करेगा।

- ☉ समझौता-ज्ञापन के तहत एलिम्को दिव्यांगजनों को सहायता तथा सहायक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु आगरा (उ.प्र.) और आकांक्षी जिला-हरिद्वार (उत्तराखंड) में आकलन शिविर लगाएगा।

## ☐ सीमा हाटों पर भारत-बांग्लादेश संयुक्त समिति की पहली बैठक

➔ त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में संपन्न। (22-23 जुलाई, 2018)

- ☉ इस बैठक में सीमा हाटों के कामकाज की समीक्षा करने तथा उसमें सुधार हेतु सुझाव दिए गए।



- ☉ नए सीमा हाटों के लिए नए स्थान प्रस्तावित करने का प्रावधान करने के साथ ही सीमा हाटों के आस-पास के क्षेत्रों में निवासरत लोगों की आजीविका पर हाटों के सकारात्मक प्रभाव को दोनों पक्षों ने स्वीकार किया।

- ☉ इस समिति की आगामी बैठक बांग्लादेश में होगी।

## ☐ वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान की सर्वाधिक उन्नत प्रणाली

➔ केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी

विज्ञान, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा चांदनी चौक, दिल्ली में वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान की सर्वाधिक उन्नत प्रणाली (System of Air Quality and Weather Forecasting: SAFAR) का अनावरण। (21 जुलाई, 2018)



- ☉ यह प्रणाली स्वदेशी तरीके से भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे द्वारा विकसित एवं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा संचालित है।

## □ उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड

➔ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक स्वशासी निकाय के रूप में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड गठित। (19 जुलाई, 2018)

- इस बोर्ड के गठन का उद्देश्य मिट्टी संबंधित कार्य में कार्यरत कारीगरों एवं शिल्पियों के व्यवसाय में वृद्धि करना, इस परंपरागत उद्योग को नवाचार के माध्यम से संरक्षित एवं संवर्धित करना, सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करना, तकनीकी विकास को बढ़ावा देना और विपणन इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराना है।
- यह बोर्ड माटी कला एवं माटी शिल्पकला के विकास से संबंधित उद्योगों के लिए नीति तैयार करेगा।

## □ 100 रुपये के नए बैंकनोट

➔ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा महात्मा गांधी (नई) शृंखला में 100 रुपये के नए बैंकनोट जारी करने की घोषणा। (19 जुलाई, 2018)

- नए मूल्यवर्ग के बैंकनोट के पृष्ठभाग पर 'रानी की वाव' का चित्र है, जो देश की सांस्कृतिक विरासत का चित्रण करता है।
- बैंकनोट का आकार 66 मिमी. × 142 मिमी. होगा।

➔ नोट का आधार रंग लैवेंडर (हल्का बैंगनी रंग) है।

## □ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कैदियों को विशेष माफी

➔ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर कैदियों को विशेष माफी देने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी। (18 जुलाई, 2018)

- महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर विभिन्न श्रेणी में विशेष माफी प्राप्त कैदियों को तीन चरणों-पहले चरण में 2 अक्टूबर, 2018 (महात्मा गांधी की जयंती) को, दूसरे चरण में 10 अप्रैल, 2019 (चंपारण सत्याग्रह की वर्षगांठ) को और तीसरे चरण में 2 अक्टूबर, 2019 (महात्मा गांधी की जयंती) को रिहा किया जाएगा।
- मृत्युदंड की सजा प्राप्त अथवा ऐसे कैदी जिनकी मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया है, को माफी नहीं दी जाएगी।

## □ चीनी सीजन वर्ष 2018-19 हेतु मूल्य निर्धारण को मंजूरी

➔ आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा गन्ना किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए चीनी सीजन वर्ष 2018-19 हेतु चीनी मिलों

द्वारा देय उचित एवं लाभकारी मूल्य के निर्धारण को मंजूरी। (18 जुलाई, 2018)

- 10 प्रतिशत बुनियादी रिकवरी के आधार पर प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य 275 रुपये निर्धारित किया गया है।
- 10 प्रतिशत से अधिक की रिकवरी में प्रति 0.1 प्रतिशत बढ़ोतरी के संबंध में 2.75 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम प्रदान किया जाएगा।

➔ चीनी सीजन वर्ष 2018-19 हेतु उत्पादन लागत 155 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है।

## □ विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाली मशहूर हस्तियों की सूची, 2018

➔ प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले मशहूर हस्तियों (The World's 100 Highest Paid Celebrities) की सूची, 2018 जारी। (16 जुलाई, 2018)

- सूची में शीर्ष स्थान- प्रसिद्ध अमेरिकी मुक्केबाज फ्लायड मेवेदर (285 मिलियन अमेरिकी डॉलर)।
- सूची में शामिल मशहूर भारतीय हस्तियां (i) अक्षय कुमार (40.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 76वां स्थान)। (ii) सलमान खान (37.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 82वां स्थान)।



## □ भारत : डब्ल्यूसीओ के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष

➔ भारत जुलाई, 2018 से जून, 2020 तक की 2 वर्ष की अवधि के लिए विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष बना। (15 जुलाई, 2018)

○ WCO विश्वभर में 182 सीमा शुल्क प्रशासकों का प्रतिनिधित्व करता है।

## □ ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम लांच

➔ केंद्रीय रेल तथा कोयला मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 'ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम' (IR-BMS) लांच। (12 जुलाई, 2018)

○ यह वेब सक्षम आईटी ऐप्लीकेशन है जिसमें ब्रिज मास्टर डेटा, वर्क डेटा, भारतीय रेल के पुलों का निरीक्षण/निगरानी तथा रख-रखाव कार्य से संबंधित डेटा का एकत्रीकरण, विश्लेषण तथा प्रसार कार्य शामिल है।





## □ लोकतंत्र सेनानियों एवं उनके पात्र आश्रितों को प्रदत्त सम्मान राशि में वृद्धि

➔ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोकतंत्र सेनानियों एवं उनके पात्र आश्रितों को प्रतिमाह प्रदत्त की जाने वाली सम्मान राशि को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये किए जाने का निर्णय (10 जुलाई, 2018)

☞ यह वृद्धि 1 जुलाई, 2018 से प्रभावी हुई।

## □ ई-टिकटिंग का चयन करने वाला पहला केंद्रीय बल

➔ भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) तथा राष्ट्रीय सुरक्षा बल (एनएसजी) के मध्य समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर। (4 जुलाई, 2018)



☞ राष्ट्रीय सुरक्षा बल इस समझौता-ज्ञापन के माध्यम से ई-टिकटिंग प्रणाली का चयन करने वाला पहला केंद्रीय बल है।

## □ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प- 2427

➔ संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद (स्थायी एवं अस्थायी सदस्य) द्वारा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क (अमेरिका) में सशस्त्र संघर्ष के दौरान बच्चों के संरक्षण, अधिकार, कल्याण और सशक्तीकरण हेतु एक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से 'संकल्प-2427' को अपनाया गया। (9 जुलाई, 2018)



☞ यह संकल्प स्कूलों और अस्पतालों के खिलाफ हमलों तथा सशस्त्र संघर्ष के समय बच्चों के साथ किए गए अंतरराष्ट्रीय कानून के सभी उल्लंघन और सशस्त्र संघर्ष के सभी पक्षों द्वारा बच्चों की भर्ती, उपयोग और शोषण का विरोध करता है।  
☞ वर्ष 2017 में सशस्त्र संघर्ष में बाल अधिकारों के गंभीर उल्लंघनों के लगभग 21,000 से अधिक मामले संयुक्त राष्ट्र द्वारा सत्यापित किए गए।

## □ अगरतला हवाई अड्डे का नया नाम

➔ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा त्रिपुरा के अगरतला हवाई अड्डे का नाम बदलकर 'महाराजा वीर बिक्रम माणिक्य किशोर हवाई अड्डा, अगरतला' करने की मंजूरी दी गई। (4 जुलाई, 2018)

## □ 'सीएमएसएमएस' एवं खान प्रहरी ऐप

➔ केंद्रीय कोयला एवं रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 'कोयला खान निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली (CMSMS) और मोबाइल ऐप 'खान प्रहरी' लांचा (4 जुलाई, 2018)



☞ CMSMS का मुख्य उद्देश्य अनधिकृत

कोयला खनन गतिविधियों पर रिपोर्टिंग, निगरानी और उपयुक्त कार्यवाही करना है।

☞ यह एक वेब आधारित GIS एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से अनधिकृत खनन के लिए स्थलों (Sites) का पता लगाया जा सकता है।

## □ बैफल फायरिंग रेंज

➔ रक्षा मंत्रालय द्वारा मिलिट्री स्टेशनों/ छाबनियों/प्रशिक्षण संस्थानों में 17 नए बैफल फायरिंग रेंज (60 फायरिंग रेंज के अलावा) के निर्माण को स्वीकृति। (3 जुलाई, 2018)



☞ इन फायरिंग रेंजों की निर्माण लागत राशि 238 करोड़ रुपये (अनुमानित) होगी।

☞ प्रस्तावित बैफल फायरिंग रेंज से 300-500 मीटर तक फायरिंग की जा सकेगी।

## □ भारत-पाकिस्तान के मध्य सामान्य कैदियों की सूचियों का आदान-प्रदान

➔ भारत और पाकिस्तान के मध्य एक-दूसरे की जेलों में बंद सामान्य कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान-प्रदान किया गया। (1 जुलाई, 2018)

☞ भारत ने पाकिस्तान को 249 नागरिक कैदियों और 108 मछुआरों की सूची और पाकिस्तान ने भारत को 53 नागरिक कैदियों और 418 मछुआरों की सूची सौंपी।

☞ ज्ञातव्य है कि प्रतिवर्ष दोनों देशों के मध्य इस प्रकार की सूचियों का आदान-प्रदान 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाता है।

## □ भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा एक्सोप्लैनेट की खोज

➔ अभिजीत चक्रवर्ती के नेतृत्व में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा सूर्य जैसे तारे की कक्षा में एक एक्सोप्लैनेट (EPIC



211945201-b' या K2-236b) की खोज। (जुलाई, 2018)

☞ सुपर नेच्यून ग्रह के आकार जैसे इस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 27 गुना एवं त्रिज्या 6 गुना है।

## □ आयात निर्भरता को कम करने के तरीकों का सुझाव देने हेतु कार्यबल

➔ केंद्र सरकार द्वारा आयात निर्भरता को कम करने के तरीकों का

सुझाव देने हेतु कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कार्यबल का गठना (जुलाई, 2018)

## □ नीलगिरि तहर पर जलवायु परिवर्तन का खतरा

➔ जुलाई, 2018 में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा नीलगिरि तहर (वैज्ञानिक नाम-Nilgiritragus hylocrius) पर जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन जारी किया गया, जिसमें वर्ष 2030 तक इनके आवास में लगभग 60 प्रतिशत तक की कमी का अनुमान लगाया गया है।



☞ यह तमिलनाडु का राजकीय पशु है।

## □ राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट के लिए निधि

➔ आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट हेतु 1040 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान राशि को मंजूरी। (27 जून, 2018)



- ☞ इस राशि (निधि) का उपयोग 3 वर्षों की अवधि (वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20) तक किया जाएगा।
- ☞ वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 में प्रत्येक वर्ष के लिए 300 करोड़ रुपये की राशि राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट को प्रदान की जाएगी।

## □ ईसीजीसी में पूंजी निवेश हेतु मंजूरी

➔ आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (Export Credit Guarantee Corporation Limited) में 2000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश को मंजूरी। (27 जून, 2018)



- ☞ यह पूंजी निवेश तीन वित्त वर्षों (2017-18, 2018-19 तथा वर्ष 2019-20) के दौरान होगा।
- ☞ वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और वर्ष 2019-20 में क्रमशः 50 करोड़, 1450 करोड़ और 500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

## □ एम-पासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप

➔ छठवें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज ने 'एम-पासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप' लांच किया। (26 जून, 2018)

- ☞ इस ऐप में पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवेदन करने, भुगतान करने आदि की सुविधा है।
- ☞ इस ऐप के माध्यम से देश के किसी भी हिस्से से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया जा सकता है।



## □ राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी राष्ट्र को समर्पित

➔ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जाबड़ेकर ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पठन-पाठन दिवस के अवसर



पर भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। (19 जून, 2018)

- ☞ इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर द्वारा विकसित किया गया है।
- ☞ सूचना व संचार तकनीक के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तत्वावधान में भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक परियोजना है।
- ☞ यह भारत और विदेशों के शिक्षा संस्थानों से अध्ययन सामग्री, एकत्र करने का प्लेटफॉर्म है।
- ☞ यह एक डिजिटल पुस्तकालय है, जिसमें पाठ्य पुस्तक, आर्टिकल्स, वीडियो-आडियो पुस्तकें, व्याख्यान, उपन्यास तथा अन्य प्रकार की शिक्षण सामग्रियां शामिल हैं।

## □ आईसीएटी द्वारा प्रथम बीएस-VI इंजन प्रमाण-पत्र जारी

➔ अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र (ICAT) द्वारा मेसर्स वोल्वो आयशर कॉमर्शियल व्हीकल लि.



को भारी-भरकम इंजन हेतु प्रथम 'बीएस-VI' प्रमाण-पत्र जारी किया।

- ☞ इस इंजन का निर्माण एवं विकास वोल्वो आयशर द्वारा भारत में ही किया गया है।





## टेनिस

### □ वेस्टर्न एंड सर्दर ओपन, 2018

- ➔ सिनसिनाटी, अमेरिका में संपन्ना (13-19 अगस्त, 2018)
- ➔ इसे सिनसिनाटी मास्टर्स के नाम से भी जाना जाता है।

#### ➔ प्रतियोगिता परिणाम

##### ☉ पुरुष एकल

विजेता - नोवाक जोकोविक (सर्बिया)  
उपविजेता - रोजर फेडरर (स्विट्जरलैंड)



##### ☉ महिला एकल

विजेता - किकी बर्टेस (नीदरलैंड्स)  
उपविजेता - सिमोना हालेप (रोमानिया)

### □ हॉल ऑफ फेम टेनिस टूर्नामेंट, 2018

- ➔ न्यूपोर्ट, अमेरिका में संपन्ना (16-22 जुलाई, 2018)
- ➔ प्रतियोगिता परिणाम

##### ☉ पुरुष एकल

विजेता - स्टीव जॉनसन (अमेरिका)  
उपविजेता - रामकुमार रामनाथन (भारत)



##### ☉ पुरुष युगल

विजेता - जेनाथन इल्वि (इंग्लैंड) एवं अर्टेम सित्नाक (न्यूजीलैंड)  
उपविजेता - मार्सेलो अरेवालो (अल सल्वडोर) एवं मिगुएल एंगेल

रिएस - वारेला (मेक्सिको)

- ➔ रामकुमार पिछले सात वर्षों में ATP टूर के किसी टूर्नामेंट की एकल स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय बने।



☉ उनसे पूर्व वर्ष 2011 में सोमदेव देववर्मन जोहॉन्सबर्ग में SA टेनिस ओपन के फाइनल में पहुंचे थे, जिसमें वह केविन एंडरसन (द. अफ्रीका) से पराजित हो गए थे।

### □ स्विस ओपन, 2018

- ➔ गस्टैड, स्विट्जरलैंड में संपन्ना (23-29 जुलाई, 2018)
- ➔ प्रतियोगिता परिणाम

##### ☉ पुरुष एकल

विजेता - मत्तेओ बेर्रेटीनी (इटली)  
उपविजेता - रॉबर्टो बाउतिस्ता अगुत (स्पेन)



##### ☉ पुरुष युगल

विजेता - मत्तेओ बेर्रेटीनी एवं डैनियल ब्रासिआली (दोनों इटली)

उपविजेता - डेनिस मोलचानोव (यूक्रेन) एवं इगोर जेलेनाय (स्लोवाकिया)

### □ स्वीडिश ओपन, 2018

- ➔ बासटैड, स्वीडन में संपन्ना (15-22 जुलाई, 2018)

#### ➔ प्रतियोगिता परिणाम

##### ☉ पुरुष एकल

विजेता - फैबियो फोगनिनी (इटली)  
उपविजेता - रिचर्ड गैस्केट (फ्रांस)



##### ☉ पुरुष युगल

विजेता - जूतियो पेराल्स (चिली) एवं होरासिओ जेबातॉस (अर्जेंटीना)

उपविजेता - सिमोन बोलेली एवं फैबियो फोगनिनी (दोनों इटली)

### □ क्रोएशिया ओपन उमाग, 2018

- ➔ उमाग, क्रोएशिया में संपन्ना (15-22 जुलाई, 2018)

#### ➔ प्रतियोगिता परिणाम

##### ☉ पुरुष एकल

विजेता - मार्को सेस्हीनातो (इटली)  
उपविजेता - गुइडो पेल्ला (अर्जेंटीना)



##### ☉ पुरुष युगल

विजेता - रॉबिन हास एवं मैटवे मिडेलकूप (दोनों नीदरलैंड्स)

उपविजेता - रोमन जेबावी एवं जीरी वेसेली (दोनों चेक गणराज्य)

### □ BB&T अटलांटा ओपन, 2018

- ➔ अटलांटा, अमेरिका में संपन्ना (23-29 जुलाई, 2018)

#### ➔ प्रतियोगिता परिणाम

##### ☉ पुरुष एकल

विजेता - जॉन इश्नर (अमेरिका)  
उपविजेता - रेयान हैरीसन (अमेरिका)



##### ☉ पुरुष युगल

विजेता - निकोलस मोनरोए (अमेरिका) एवं जॉन-पैट्रिक स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)

उपविजेता - रेयान हैरीसन एवं राजीव राम (दोनों अमेरिका)

## ❑ रोजर्स कप, 2018

➔ कनाडा में संपन्न। (6-12 अगस्त, 2018)

➔ प्रतियोगिता परिणाम

☉ पुरुष एकल

विजेता - राफेल नडाल (स्पेन)

उपविजेता - स्टेफानोस सितसिपास (ग्रीस)

☉ महिला एकल

विजेता - सिमोना हालेप (रोमानिया)

उपविजेता - स्लोएन स्टीफेंस (अमेरिका)



## ❑ सिटी ओपन, 2018

➔ वाशिंगटन डी.सी., अमेरिका में संपन्न।

(30 जुलाई - 5 अगस्त, 2018)

➔ प्रतियोगिता परिणाम

☉ पुरुष एकल

विजेता - अलेक्जेंडर ज्वेरेव (जर्मनी)

उपविजेता - एलेक्स डी मिनौर (ऑस्ट्रेलिया)

☉ महिला एकल

विजेता - स्वेतलाना कुज्नेत्सोवा (रूस)

उपविजेता - डोना वेकिक (क्रोएशिया)



## क्रिकेट

## ❑ सीनियर महिला टी-20 चैलेंजर ट्रॉफी, 2018-19

➔ भारत की घरेलू टी-20 प्रतियोगिता 'सीनियर महिला टी-20 चैलेंजर ट्रॉफी, 2018-19' का प्रथम संस्करण KSCA क्रिकेट ग्राउंड, अलूर (बंगलुरु) में संपन्न। (14-21 अगस्त, 2018)

➔ प्रतियोगिता प्रारूप - डबल राउंड - रॉबिन और फाइनल्स

➔ प्रशासक - BCCI

➔ प्रतिभागी टीमों (3) - इंडिया ब्लू, इंडिया ग्रीन और इंडिया रेड।

➔ प्रतियोगिता परिणाम

☉ विजेता - इंडिया ब्लू (4 रनों से), पहला खिताब।

☉ उपविजेता - इंडिया रेड

➔ टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन - पूनम राउत (इंडिया रेड), 135 रन।

➔ टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट - अनुजा पाटिल (इंडिया ब्लू), 8 विकेट।



## ❑ ICC महिला विश्व टी-20 क्वालीफायर, 2018

➔ ICC महिला विश्व टी-20 टूर्नामेंट, 2018 के लिए क्वालीफिकेशन टूर्नामेंट नीदरलैंड्स की मेजबानी में संपन्न। (7-14 जुलाई, 2018)

➔ टूर्नामेंट की शीर्ष दो टीमों बांग्लादेश और आयरलैंड ने टी-20 विश्व कप के लिए अर्हता प्राप्त की।

➔ प्रतियोगिता परिणाम

☉ विजेता - बांग्लादेश (25 रनों से)

☉ उपविजेता - आयरलैंड

➔ 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' - क्लेयर शिलिंगटन (आयरलैंड)

➔ ICC महिला विश्व टी-20 टूर्नामेंट,

2018 का आयोजन 9-24 नवंबर, 2018 के मध्य वेस्टइंडीज में किया जाएगा।

☉ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली अन्य टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, द. अफ्रीका, श्रीलंका और मेजबान वेस्टइंडीज शामिल हैं।



## ❑ भारतीय टीम का इंग्लैंड दौरा, 2018

➔ भारतीय क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा। (3 जुलाई से 11 सितंबर, 2018)

➔ इस दौरान 3 टी-20, 3 एकदिवसीय तथा 5 टेस्ट मैचों की शृंखला खेली जाएगी।

### ● एकदिवसीय शृंखला

➔ 3 एकदिवसीय मैचों की शृंखला 12 से 17 जुलाई, 2018 के मध्य संपन्न हुई।

➔ इंग्लैंड ने एकदिवसीय शृंखला 2-1 से जीत ली।

➔ शृंखला में सर्वाधिक 216 रन बनाने वाले इंग्लैंड के जो रूट को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया।

➔ भारत के कुलदीप यादव ने शृंखला में सर्वाधिक 9 विकेट लिए।

➔ शृंखला के दूसरे मैच में भारत के

एम.एस. धौनी 10000 एकदिवसीय रनों का आंकड़ा पार करने वाले चौथे भारतीय एवं विश्व के 12वें क्रिकेटर बने।

☉ धौनी से पूर्व यह उपलब्धि प्राप्त करने वाले भारतीय क्रिकेटरों में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली शामिल हैं।

➔ साथ ही धौनी एकदिवसीय क्रिकेट में 10000 रन पूरे करने वाले विश्व के दूसरे विकेटकीपर बन गए।

☉ श्रीलंका के कुमार संगकारा ऐसे पहले विकेटकीपर हैं, जिन्होंने एकदिवसीय क्रिकेट में 10000 या उससे अधिक रन बनाए हैं।

☉ सचिन तेंदुलकर एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 18426 रन (463 मैचों में) बनाकर शीर्ष पर हैं।

➔ इसी मैच में धौनी एकदिवसीय क्रिकेट में 300 कैच पकड़ने वाले प्रथम भारतीय एवं विश्व के चौथे विकेटकीपर बने।

☉ उनसे पूर्व ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट (417), दक्षिण अफ्रीका के मार्क बाउचर (402) और श्रीलंका के कुमार संगकारा (383) यह कारनामा कर चुके हैं।



## ● टी-20 शृंखला

➔ 3 अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैचों की शृंखला संपन्ना (3-8 जुलाई, 2018)

➔ भारत ने यह शृंखला 2-1 से जीत ली।

➔ शृंखला में सर्वाधिक 137 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा को 'प्लेयर ऑफ सीरीज' चुना गया।

➔ शृंखला के तीसरे मैच में भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने शतक लगाया।

⊕ इसी के साथ रोहित शर्मा, न्यूजीलैंड के कोलिन मुनरो के बाद टी-20



अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीन शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे क्रिकेटर बन गए।

⊕ रोहित, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों (टेस्ट, एकदिवसीय तथा टी-20) में तीन या उससे अधिक शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने।

➔ शृंखला के दौरान रोहित टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय पुरुष क्रिकेटर (पहले - विराट कोहली) बने।

⊕ ज्ञातव्य है कि हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रनों का आंकड़ा पार करने वाली प्रथम भारतीय क्रिकेटर बनीं थीं।

➔ शृंखला का दूसरा मैच महेंद्र सिंह धौनी के कैरियर का 500 अंतरराष्ट्रीय मैच था।

➔ तीसरे टी-20 मैच में धौनी एक अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच में 5 कैच तथा समग्र रूप से 50 या उससे अधिक अंतरराष्ट्रीय टी-20 कैच पकड़ने वाले विश्व के पहले विकेटकीपर बन गए।

➔ शृंखला के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैचों में सबसे तेज (56वीं पारी में) 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। (3 जुलाई, 2018)



⊕ इससे पूर्व यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैक्कुलम के नाम दर्ज था, जिन्होंने अपनी 66वीं पारी में 2000 रनों का आंकड़ा पार किया था।

➔ शृंखला के पहले मैच में कुलदीप यादव टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच की एक पारी में 5 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बने।

⊕ इससे पूर्व भुवनेश्वर कुमार एवं युजवेंद्र चहल यह कारनामा कर चुके हैं।

## □ भारत 'A' ने जीती त्रिकोणीय शृंखला

➔ भारत 'A', इंग्लैंड 'A' और वेस्टइंडीज 'A' के मध्य त्रिकोणीय शृंखला लंदन में संपन्ना (22 जून - 2 जुलाई, 2018)

➔ प्रतियोगिता परिणाम

विजेता - भारत 'A' (5 विकेट से)

उपविजेता - इंग्लैंड 'A'

➔ इंग्लैंड 'A' द्वारा जीत के लिए दिए गए 265 रनों के लक्ष्य को

भारत 'A' ने 48.2 ओवर में 5 विकेट पर 267 रन बनाकर प्राप्त कर लिया।

➔ भारत 'A' टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर थे।

## □ भारतीय टीम का आयरलैंड दौरा

➔ भारत एवं आयरलैंड के मध्य 2 अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैचों की शृंखला डबलिन, आयरलैंड में संपन्ना (27-29 जून, 2018)

➔ भारत ने यह शृंखला 2-0 से जीत ली।

⊕ भारत के युजवेंद्र चहल को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया।

⊕ शृंखला में सर्वाधिक विकेट - कुलदीप यादव (भारत), कुल 7 विकेट।

⊕ शृंखला में सर्वाधिक रन - रोहित शर्मा (भारत), कुल 97 रन।

➔ शृंखला का पहला मैच भारत का 100वां अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच था, जिसे भारत ने 76 रनों से जीता। (27 जून, 2018)

➔ दूसरे टी-20 मैच में भारत ने आयरलैंड को 143 रनों से पराजित किया, जो रनों के मामलों में भारत की सबसे बड़ी तथा अंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट के इतिहास की संयुक्त रूप से दूसरी सबसे बड़ी जीत थी।

⊕ ध्यातव्य है कि अप्रैल, 2018 में खेले गए एक अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 143 रनों से ही पराजित किया था।

⊕ इस मामले में श्रीलंका की टीम शीर्ष पर है, जिसने सितंबर, 2007 में केन्या को 172 रनों से पराजित किया था।

➔ इस शृंखला हेतु भारत के कप्तान विराट कोहली तथा आयरलैंड के कप्तान गैरी विल्सन रहे।



## फुटबॉल

### □ फीफा U-20 महिला विश्व कप, 2018

➔ 9वां संस्करण फ्रांस के चार शहरों में आयोजित किया गया। (5-24 अगस्त, 2018)

➔ प्रतिभागी टीमों - 6 कंफेडरेशन्स की 16 टीमों।

➔ फाइनल स्थल - वानेस (Vannes), फ्रांस।

➔ प्रतियोगिता परिणाम

⊕ विजेता - जापान (3-1), पहला खिताब।

⊕ उपविजेता - स्पेन

⊕ तीसरा स्थान - इंग्लैंड

➔ प्रतियोगिता में प्रदत्त प्रमुख पुरस्कार

⊕ 'गोल्डेन बॉल' - फ्रैंसिसिया गुइजारो (स्पेन)

⊕ 'गोल्डेन बूट' - फ्रैंसिसिया गुइजारो (स्पेन)



- ☉ 'गोल्डेन ग्लव' - सैंडी मैसाइवर (इंग्लैंड)
- ☉ 'फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी' - जापान
- ➔ भारत की युवेना फर्नांडीज को फीफा U-20 महिला विश्व कप में सहायक रेफरी की भूमिका के लिए चुना गया था।
- ☉ युवेना इससे पूर्व जॉर्डन में 2016 में संपन्न U-17 महिला विश्व कप के दौरान मैच संचालन में भूमिका निभाने वाली प्रथम भारतीय महिला सहायक रेफरी बनी थीं।

## ☐ सैफ U-15 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप

- ➔ थिम्पू, भूटान में संपन्न। (9-18 अगस्त, 2018)
- ➔ प्रतिभागी टीमों (6) - बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका।
- ➔ प्रतियोगिता परिणाम
- ☉ विजेता - भारत (पहला खिताब), 1-0 से।
- ☉ उपविजेता - बांग्लादेश
- ➔ 'टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी' - नाओरेम प्रियंका देवी (भारत)
- ➔ 'फेयर प्ले अवॉर्ड' - बांग्लादेश



## हॉकी

### ☐ भारत-हांगकांग हॉकी मैच, 2018

- ➔ जकार्ता, इंडोनेशिया में 18वें एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपने दूसरे ग्रुप मुकाबले में हांगकांग को 26-0 से करारी शिकस्त दी। (22 अगस्त, 2018)
- ➔ यह अंतरराष्ट्रीय हॉकी में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है।
- ➔ इससे पूर्व भारत ने वर्ष 1932 के ओलंपिक खेलों में अमेरिका को 24-1 से पराजित किया था।
- ☉ इस मैच में भारत के रुपिंदर पाल सिंह ने सर्वाधिक 5 गोल किए।



### ☐ महिला हॉकी विश्व कप, 2018

- ➔ 14वां संस्करण लंदन (इंग्लैंड) में संपन्न। (21 जुलाई - 5 अगस्त, 2018)
- ➔ फाइनल मैच में नीदरलैंड्स (कप्तान- कार्लिन डिकर्से वेन डेन ह्यूबेल) ने आयरलैंड (कप्तान - कैथरीन मुलन) को 6-0 से पराजित कर यह विश्व कप जीत लिया।
- ➔ स्पेन को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ।
- ➔ वर्ष 2018 के इस संस्करण में विश्व की 16 टीमों ने भाग लिया था।
- ➔ इस टूर्नामेंट के दौरान कुल 36 मैच खेले गए, जिनमें कुल 126 गोल हुए।



- ➔ नीदरलैंड्स की किटी वैन मेल ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 8 गोल किए।
- ➔ विश्व कप में प्रदत्त प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार रहे-
- वाइटेलिटी बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट - लिडेविज वेल्टन (नीदरलैंड्स)
- बेस्ट गोलकीपर - आइशा मैकफेरन (आयरलैंड)
- बेस्ट जूनियर प्लेयर - लूसिना वॉन डेर हायडे (अर्जेंटीना)
- हीरो टॉप गोल स्कोरर - किटी वैन मेल (नीदरलैंड्स)
- ➔ उल्लेखनीय है कि नीदरलैंड्स ने रिकॉर्ड आठवीं बार महिला हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है।
- ➔ 2 अगस्त, 2018 को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत, आयरलैंड से पेनाल्टी शूटआउट में 3-1 से पराजित होकर विश्व कप प्रतियोगिता से बाहर हो गया था।



## बैडमिंटन

### ☐ योनेक्स/K & D ग्राफिक्स इंटरनेशनल सीरीज, 2018

- ➔ कैलिफोर्निया, अमेरिका में संपन्न। (7-11 अगस्त, 2018)
- ➔ प्रतियोगिता परिणाम
- ☉ पुरुष एकल
- विजेता - बी.आर. संकीर्थ (कनाडा)
- उपविजेता - फिलिप्स जैप (अमेरिका)
- ☉ महिला एकल
- विजेता - साया यामामोतो (जापान)
- उपविजेता - लौरेन लैम (अमेरिका)
- ☐ लागोस इंटरनेशनल, 2018

- ➔ लागोस, नाइजीरिया में संपन्न। (18-21 जुलाई, 2018)
- ➔ प्रतियोगिता परिणाम
- ☉ पुरुष एकल
- विजेता - मिशा जित्बरमैन (इंडोनेशिया)
- उपविजेता - रामदाम मिस्बन (मलेशिया)
- ☉ महिला एकल
- विजेता - सेनिया पोलिकारपोवा (इंडोनेशिया)
- उपविजेता - श्रीकृष्णा प्रिया (भारत)
- ☉ पुरुष युगल
- विजेता - मनु अत्री एवं बी. सुमित रेड्डी (दोनों भारत)
- उपविजेता - वैभव एवं प्रकाश राज (दोनों भारत)

- महिला युगल  
विजेता - रिया मुखर्जी एवं कुहु गर्ग (दोनों भारत)  
उपविजेता - करिश्मा वाडकर एवं वी. हरिका (दोनों भारत)

- मिश्रित युगल  
विजेता - मनु अत्री एवं के. मनीषा (दोनों भारत)  
उपविजेता - रोहन कपूर एवं कुहु गर्ग (दोनों भारत)

### ❑ वियतनाम ओपन, 2018

- वियतनाम में संपन्ना (7-12 अगस्त, 2018)

#### ➤ प्रतियोगिता परिणाम

- पुरुष एकल  
विजेता - शोसार हिरेन रुस्तावितो (इंडोनेशिया)  
उपविजेता - अजय जयराम (भारत)

- महिला एकल  
विजेता - यिओ जिया मिन (सिंगापुर)  
उपविजेता - हान युए (चीन)

### ❑ इंडिया जूनियर इंटरनेशनल, 2018

- पुणे, भारत में संपन्ना (9-12 अगस्त, 2018)

#### ➤ प्रतियोगिता परिणाम

- महिला एकल (U-19)  
स्वर्ण पदक - आर्कषि कश्यप (भारत)  
रजत पदक - मालविका बंसोड़ (भारत)  
कांस्य पदक - पूर्वा बर्वे (भारत) एवं कि जुआन ईऊन (मलेशिया)

- पुरुष युगल (U-19)  
कांस्य पदक - विष्णु वर्धन पंजाला एवं श्रीकृष्णा साई पोडिले (दोनों भारत)

### ❑ रशियन ओपन, 2018

- व्लादिवोस्टोक, रूस में संपन्ना (24-29 जुलाई, 2018)

#### ➤ प्रतियोगिता परिणाम

- पुरुष एकल  
विजेता - सौरभ वर्मा (भारत)  
उपविजेता - कोकी वातानाबे (जापान)

- महिला एकल  
विजेता - येन मेई हो (मलेशिया)  
उपविजेता - शियोरी एबिहारा (जापान)

- मिश्रित युगल स्पर्धा में रोहन कपूर तथा कुहु गर्ग (दोनों भारत) ने रजत पदक जीता।

### ❑ BWF विश्व चैंपियनशिप, 2018

- नानजिंग, चीन में संपन्ना (30 जुलाई - 5 अगस्त, 2018)

#### ➤ प्रतियोगिता परिणाम

- पुरुष एकल  
स्वर्ण पदक - केंटो मोमोता (जापान)  
रजत पदक - शी युकी (चीन)



- महिला एकल  
स्वर्ण पदक - कैरोलिना मारिन (स्पेन)  
रजत पदक - पी.वी. सिंधु (भारत)

- पुरुष युगल  
स्वर्ण पदक - ली जुनहुई एवं लियू यूवेन (दोनों चीन)  
रजत पदक - ताकेशी कामुरा एवं किगो सोनोडा (दोनों जापान)

- महिला युगल  
स्वर्ण पदक - मायू मात्सुमोतो एवं वकाना नागाहारा (दोनों जापान)  
रजत पदक - युकी फुकुशिमा एवं सयाका हिरोता (दोनों जापान)

### ❑ सिंगापुर ओपन, 2018

- सिंगापुर इंडोर स्टेडियम (सिंगापुर) में संपन्ना (17-22 जुलाई, 2018)

#### ➤ प्रतियोगिता परिणाम

- पुरुष एकल  
विजेता - चोउ तिएन चेन (चीनी ताइपे)  
उपविजेता - हसु जेन हाओ (चीनी ताइपे)

- महिला एकल  
विजेता - सयाका ताकाहाशी (जापान)  
उपविजेता - गाओ फेंगजी (चीन)

### ❑ इंडोनेशिया ओपन, 2018

- जकार्ता, इंडोनेशिया में संपन्ना (3-8 जुलाई, 2018)

#### ➤ प्रतियोगिता परिणाम

- पुरुष एकल  
विजेता - केंटो मोमोता (जापान)  
उपविजेता - विकटर एक्सेलसन (डेनमार्क)

- महिला एकल  
विजेता - ताई त्जु यिंग (चीनी ताइपे)  
उपविजेता - चेन युफेई (चीन)

### ❑ व्हाइट नाइट्स, 2018

- गात्विना, रूस में संपन्ना (4-8 जुलाई, 2018)

#### ➤ प्रतियोगिता परिणाम

- पुरुष एकल  
विजेता - पाब्लो अबियान (स्पेन)  
उपविजेता - अजय जयराम (भारत)

- महिला एकल  
विजेता - जॉय शुआन डेंग (हांगकांग)  
उपविजेता - जिया मिन ईओ (सिंगापुर)

### ❑ घाना इंटरनेशनल, 2018

- टेमा, घाना में संपन्ना (12-15 जुलाई, 2018)

#### ➤ प्रतियोगिता परिणाम

- पुरुष एकल  
विजेता - हरशील दानी (भारत)  
उपविजेता - सिद्धार्थ ठाकुर (भारत)





## ☉ महिला एकल

विजेता - सेनिया पोलीकारपोवा (इग्राइल)

उपविजेता - औरेली मैरी एलिसा (मॉरीशस)

## ☉ पुरुष युगल

विजेता - वसंथा कुमार हनुमैया एवं अशीथ सूर्या (दोनों भारत)

उपविजेता - वैभव एवं प्रकाश राज (दोनों भारत)

## ☉ महिला युगल

विजेता - हरिका वेलुदुरथी एवं करिश्मा वाडकर (दोनों भारत)

उपविजेता - ग्रेस अतिपाका एवं स्टेला बेनटम (दोनों घाना)

## ☉ मिश्रित युगल

विजेता - हरिका वेलुदुरथी एवं विग्नेश देवलेकर (दोनों भारत)

उपविजेता - करिश्मा वाडकर एवं उत्कर्ष अरोरा (दोनों भारत)

## ☐ थाईलैंड ओपन, 2018

➔ बैंकॉक, थाईलैंड में संपन्ना (10-15 जुलाई, 2018)

### ➔ प्रतियोगिता परिणाम

#### ☉ पुरुष एकल

विजेता - कांटा सुनेयामा (जापान)

उपविजेता - टॉमी सुगिआर्तो (इंडोनेशिया)

#### ☉ महिला एकल

विजेता - नोजोमी ओकुहारा (जापान)

उपविजेता - पी.वी. सिंधु (भारत)



## शतरंज

## ☐ अबु धाबी मास्टर्स, 2018

➔ संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में संपन्ना (6-16 अगस्त, 2018)

### ➔ प्रतियोगिता परिणाम

☉ विजेता - डैनिल दुबोव (रूस), संभावित 9 में 7.5 अंक प्राप्त किए।

➔ दुबोव के अतिरिक्त एंटोन कोरोबोव (यूक्रेन) एवं सालेह सालेम (यूएई) ने भी 7.5 अंक प्राप्त किए थे, परंतु बेहतर टाई-ब्रेक के आधार पर दुबोव ने जीत दर्ज की।



## ☐ राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप, 2018

➔ नई दिल्ली में संपन्ना (3 जुलाई, 2018)

### ➔ प्रतियोगिता परिणाम

☉ पुरुष वर्ग विजेता - पी.कार्तिकेयन (भारत)

☉ महिला वर्ग विजेता - तानिया सचदेव (भारत)

## ☐ द. अफ्रीका ओपन शतरंज चैंपियनशिप, 2018

➔ द. अफ्रीका में संपन्ना (7-14 जुलाई, 2018)

### ➔ प्रतियोगिता परिणाम

☉ विजेता - सहज ग्रोवर (भारत)



➔ ग्रोवर ने चैंपियनशिप में अजेय रहते हुए 11 चक्रों में 10 अंक अर्जित किए।

## बिलियर्ड्स/स्नूकर

## ☐ CCI क्लासिक आमंत्रण बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, 2018

➔ क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, मुंबई में संपन्ना (13-18 अगस्त, 2018)

### ➔ प्रतियोगिता परिणाम

☉ विजेता - सिद्धार्थ पारिख (रेलवे)

☉ उपविजेता - सौरव कोठारी (ONGC)



## ☐ ECC ऑल इंडिया ओपन 6 रेड स्नूकर टूर्नामेंट, 2018

➔ एल्फिंस्टोन क्रिकेट क्लब, मुंबई में संपन्ना (2-15 अगस्त, 2018)

### ➔ प्रतियोगिता परिणाम

☉ विजेता - लक्ष्मण रावत (बॉम्बे जिमखाना)

☉ उपविजेता - मोहम्मद हुसैन खान (रेलवे)



## गोल्फ

## ☐ विंडहैम चैंपियनशिप, 2018

➔ नॉर्थ कैरोलीना, अमेरिका में संपन्ना (19 अगस्त, 2018)

### ➔ प्रतियोगिता परिणाम

☉ विजेता - ब्रैंड्ट स्नेडेकर (अमेरिका)

## ☐ PGA चैंपियनशिप, 2018

➔ PGA टूर, 2018 सत्र की चौथी और अंतिम मेजर चैंपियनशिप मिसौरी, अमेरिका में संपन्ना (12 अगस्त, 2018)

### ➔ प्रतियोगिता परिणाम

☉ विजेता - ब्रुक्स कोएपका (अमेरिका)

## ☐ टेक सॉल्युशन मास्टर्स, 2018

➔ बंगलुरु (कर्नाटक गोल्फ एसोसिएशन) में संपन्ना (9-12 अगस्त, 2018)

### ➔ प्रतियोगिता परिणाम

☉ विजेता - विराज माडाप्पा (भारत)

➔ इस जीत के साथ 20 वर्षीय विराज एशियन टूर खिताब जीतने वाले सबसे युवा भारतीय गोल्फर बन गए हैं।



☉ इससे पूर्व यह रिकॉर्ड गगनजीत भुल्लर के नाम था, जिन्होंने 21 वर्ष की आयु में इंडोनेशिया आमंत्रण टूर्नामेंट जीता था।

## ❑ फिजी इंटरनेशनल, 2018

➔ फिजी में संपन्ना (2-5 अगस्त, 2018)

➔ प्रतियोगिता परिणाम

☉ विजेता - गगनजीत भुल्लर (भारत)

➔ यह गगनजीत के कैरियर का पहला यूरोपीय टूर खिताब है।



## ❑ WGC - ब्रिजस्टोन आमंत्रण, 2018

➔ PGA टूर, 2018 की चार वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप्स में से चौथी और अंतिम चैंपियनशिप ओहियो, अमेरिका में संपन्ना (5 अगस्त, 2018)

➔ प्रतियोगिता परिणाम

☉ विजेता - जस्टिन थॉमस (अमेरिका)

## ❑ RBC कनाडियन ओपन, 2018

➔ ऑंटारियो, कनाडा में संपन्ना (26-29 जुलाई, 2018)

➔ प्रतियोगिता परिणाम

☉ विजेता - जस्टिन जॉनसन (अमेरिका)

## ❑ द ओपन चैंपियनशिप, 2018

➔ PGA टूर, 2018 की चार मेजर चैंपियनशिप्स में से तीसरी 'द ओपन चैंपियनशिप (ब्रिटिश ओपन), 2018' स्कॉटलैंड में संपन्ना (22 जुलाई, 2018)

➔ प्रतियोगिता परिणाम

☉ विजेता - फ्रांसेस्को मोलिनारी (इटली)

## ❑ इंडोनेशिया ओपन, 2018

➔ जकार्ता में संपन्ना (15 जुलाई, 2018)

➔ प्रतियोगिता परिणाम

विजेता - जस्टिन हार्डिंग (द. अफ्रीका)

➔ हार्डिंग ने अपना पहला एशियाई टूर खिताब जीता।

## टेबल टेनिस

## ❑ इलेवन स्पोर्ट्स सेंट्रल जोन नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट, 2018

➔ इंदौर, मध्य प्रदेश में संपन्ना (12-17 जुलाई, 2018)

➔ PSPB के मानव ठक्कर ने लगातार दूसरी बार युवा एवं पुरुष वर्ग का खिताबी डबल पूरा किया।

➔ प्रतियोगिता परिणाम

☉ पुरुष वर्ग

एकल विजेता - मानव ठक्कर (PSPB)

उपविजेता - जीत चंद (हरियाणा)



☉ महिला वर्ग

एकल विजेता - पूजा सहस्रबुद्धे (PSPB)

उपविजेता - अर्चना कामथ (PSPB)

☉ युवा बालक वर्ग

एकल विजेता - मानव ठक्कर (PSPB)

उपविजेता - मानुष शाह (गुजरात)

☉ युवा बालिका वर्ग

एकल विजेता - सेलेनादीप्ती सेल्वाकुमार (तमिलनाडु)

उपविजेता - याशिनी शिवशंकर (तमिलनाडु)



## फॉर्मूला वन

## ❑ हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स

➔ हंगरी में संपन्ना (29 जुलाई, 2018)

➔ विजेता - लुईस हैमिल्टन (ब्रिटेन), टीम - मर्सिडीज (जर्मनी)

## ❑ जर्मन ग्रैंड प्रिक्स

➔ हॉकेनहेइम, जर्मनी में संपन्ना (22 जुलाई, 2018)

➔ विजेता - लुईस हैमिल्टन (ब्रिटेन), टीम - मर्सिडीज (जर्मनी)

## ❑ ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स

➔ नार्थम्पटनशायर, इंग्लैंड में संपन्ना (8 जुलाई, 2018)

➔ विजेता - सेबेस्टियन वेडेल (जर्मनी), टीम - फेरारी (इटली)

## ❑ ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स

➔ ऑस्ट्रिया में संपन्ना (1 जुलाई, 2018)

➔ विजेता - मैक्स वर्सटाप्पेन (नीदरलैंड्स), टीम - रेड बुल रेसिंग (ऑस्ट्रिया)

## खेल विविध

## ❑ यासर दोगु अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट, 2018

➔ इस्तांबुल, तुर्की में संपन्ना (27-29 जुलाई, 2018)

➔ भारत ने इस टूर्नामेंट में 10 पदक जीते, जिसमें से 7 पदक महिलाओं ने प्राप्त किए।

➔ पुरुष वर्ग में बजरंग पूनिया (70 किग्रा. भार वर्ग) और महिला वर्ग में पिकी (55 किग्रा. भार वर्ग) ने स्वर्ण पदक जीते।

## ❑ 36वां गोल्डेन ग्लव ऑफ वोच्चोदीना

➔ युवा मुक्केबाजी टूर्नामेंट, सर्बिया में संपन्ना (15 जुलाई, 2018)

➔ भारतीय मुक्केबाजों ने 7 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 17 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

➔ टूर्नामेंट में कजाखस्तान दूसरे स्थान (5 स्वर्ण) तथा रूस तीसरे स्थान (3 स्वर्ण) पर रहा।

➔ भारतीय 7 स्वर्ण पदक विजेता इस प्रकार रहे-

1. अमन (+91 किग्रा. भार वर्ग)
2. आकाश कुमार (56 किग्रा. भार वर्ग)
3. एस. बरुण सिंह (49 किग्रा. भार वर्ग)
4. विजयदीप (69 किग्रा. भार वर्ग)
5. नीतू (48 किग्रा. भार वर्ग)
6. दिव्या पवार (54 किग्रा. भार वर्ग)
7. ललिता (69 किग्रा. भार वर्ग)

□ बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल, 2022 : सात

नई स्पर्धाएं शामिल

➔ अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के कार्यकारी बोर्ड ने वर्ष 2022 में बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों हेतु सात नई स्पर्धाओं को शामिल करने का निर्णय लिया। (19 जुलाई, 2018)

➔ इनमें महिला मोनोबॉब, पुरुषों और महिलाओं की बिग एयर फ्री स्टाइल स्कीइंग, मिश्रित वर्ग में शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग, स्की जंपिंग, स्की एरियल्स और स्नोबोर्ड क्रॉस को शामिल किया गया है।

➔ इन स्पर्धाओं के जुड़ने से अब कुल 109 स्पर्धाएं (Events) शीतकालीन ओलंपिक में आयोजित होंगी।

□ टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर

➔ जापान ओलंपिक समिति द्वारा वर्ष 2020 में टोक्यो (जापान) में आयोजित होने वाले ओलंपिक तथा पैरालंपिक खेलों के शुभंकरों की घोषणा की गई। (22 जुलाई, 2018)

➔ टोक्यो में वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों का शुभंकर नीले चोक धारी मिराइतोवा (Miraitowa) को चुना गया।

☉ मिराइतोवा, जापानी भाषा के मिराइ (Mirai) तथा तोवा (Towa) शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्रमशः 'भविष्य' तथा 'अमरत्व' है।

☉ ज्ञातव्य है कि जापान ओलंपिक समिति द्वारा टोक्यो (जापान) में वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले पैरालंपिक खेलों का शुभंकर गुलाबी रंग वाले सोमाइटी (Someity) को चुना गया, जिसका नाम जापान के खास चेरी के पुष्प सोमाइयोशिनी (Someiyoshino) के नाम प्रेरित है।

➔ इन शुभंकरों को कैरेक्टर डिजाइनर 'रियो तानीगुची' ने डिजाइन किया है।

☉ उल्लेखनीय है कि हजारों शुभंकरों की प्रविष्टियों में से इन दोनों शुभंकरों का चुनाव प्राथमिक स्कूल के बच्चों द्वारा किया गया है।



□ दुबई कबड्डी मास्टर्स, 2018

➔ इस प्रतियोगिता का प्रथम संस्करण दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल और स्टार इंडिया नेटवर्क के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन द्वारा आयोजित किया गया। (22-30 जून, 2018)

➔ प्रतियोगिता परिणाम

विजेता - भारत (44-26 से)

उपविजेता - ईरान



चर्चित खेल व्यक्ति

□ झूलन गोस्वामी

➔ भारतीय महिला क्रिकेटर एवं तेज गेंदबाज।

➔ अंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। (23 अगस्त, 2018)

➔ झूलन ने 68 अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैचों में 56 विकेट प्राप्त किए हैं।

➔ इन्होंने अगस्त, 2006 में इंग्लैंड के विरुद्ध अपना पहला अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच खेला था।

☉ जून, 2018 में बांग्लादेश के विरुद्ध खेला गया टी-20 मैच इनका अंतिम टी-20 मैच रहा।

➔ झूलन, एकदिवसीय क्रिकेट में 200 विकेटों का आंकड़ा पार करने वाली विश्व की एकमात्र महिला क्रिकेटर हैं।

□ शार्दुल विहान

➔ भारतीय युवा निशानेबाज।

➔ एशियाई खेलों में भारत के लिए पदक जीतने वाले सबसे कम आयु के निशानेबाज बने। (23 अगस्त, 2018)

➔ 15 वर्षीय शार्दुल ने पुरुषों की डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता।

➔ शार्दुल ने फाइनल में कुल 73 का स्कोर किया और मात्र 1 अंक के मामूली अंतर से स्वर्ण पदक से चूक गए।

□ राही सरनोबत

➔ भारतीय महिला निशानेबाज।

➔ रोमांचक शूटऑफ जीतने के साथ ही एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनीं। (22 अगस्त, 2018)

➔ राही ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के शूट-ऑफ मुकाबले में थाईलैंड की नफासवान यांगपाइबून को पराजित किया।

□ विनेश फोगाट

➔ भारतीय महिला पहलवान।

➔ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला



पहलवान बनीं (20 अगस्त, 2018)

➔ 18वें एशियाई खेलों में विनेश ने 50 किग्रा. भार वर्ग में महिलाओं की फ्री स्टाइल स्पर्धा में जापानी



पहलवान इरी यूकी को 6-2 से पराजित कर स्वर्ण पदक हासिल किया।

➔ विनेश अपनी स्पर्धा में अजेय रहीं और उन्होंने अपने चारों मुकाबले जीते।

➔ इससे पूर्व विनेश ने वर्ष 2014 इंचियोन एशियन गेम्स में 48 किग्रा. भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था।

## ❑ बजरंग पूनिया

➔ भारतीय पहलवान।

➔ एशियाई खेल, 2018 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। (19 अगस्त, 2018)

➔ बजरंग ने फ्रीस्टाइल कुश्ती में पुरुषों के 65 किग्रा. भार वर्ग में जापान के पहलवान तकातानी दाईची को 11-8 से पराजित किया।



➔ बजरंग एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाले 9वें पहलवान बने।

➔ बजरंग ने अपना यह स्वर्ण पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किया।

## ❑ ऋषभ पंत

➔ 20 वर्षीय भारतीय विकेटकीपर एवं बल्लेबाज; भारत के 291वें टेस्ट क्रिकेटर बने (इंग्लैंड के विरुद्ध पदार्पण)। (18 अगस्त, 2018)

➔ अपने टेस्ट कैरियर की पदार्पण पारी में 5 या अधिक खिलाड़ियों को कैच आउट करने के मामले में अब ऋषभ पंत विश्व के तीसरे और भारत के पहले विकेटकीपर बन गए।



➔ पंत से पूर्व वर्ष 1966 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रायन ताबेर और वर्ष 1978 में ऑस्ट्रेलिया के ही जॉन मेकलीन ने यह कारनामा किया था।

➔ अपने पदार्पण टेस्ट मैच में पंत ने छक्का लगाकर टेस्ट कैरियर में रनों का खाता खोला था।

➔ इस मामले में वह दुनिया के 12वें और भारत के पहले खिलाड़ी हैं।

## ❑ अजित वाडेकर

➔ पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान।

➔ मुंबई में निधन। (15 अगस्त, 2018)

➔ वाडेकर ने वर्ष 1966 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध टेस्ट मैच से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था।



➔ इन्होंने वर्ष 1966 से 1974 के मध्य 37 टेस्ट एवं 2 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।

➔ इनकी कप्तानी में भारत ने वर्ष 1971 में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड में टेस्ट श्रृंखलाएं जीती थीं।

➔ भारत सरकार द्वारा वाडेकर को वर्ष 1967 में अर्जुन अवॉर्ड और 1972 में पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया था।

## ❑ एसो अल्बेन

➔ भारतीय जूनियर साइक्लिस्ट।

➔ स्विट्जरलैंड में संपन्न UCI जूनियर ट्रैक साइक्लिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बने।



(17 अगस्त, 2018)

➔ 17 वर्षीय अल्बेन ने केइरिन (Keirin) स्पर्धा में रजत पदक जीता।

## ❑ निहाल सरीन

➔ भारतीय शतरंज इंटरनेशनल मास्टर (IM)।

➔ भारत के 53वें ग्रैंडमास्टर बने। (14 अगस्त, 2018)



➔ निहाल ने अपना तीसरा और अंतिम

ग्रैंडमास्टर नॉर्म अबु धाबी मास्टर्स टूर्नामेंट में प्राप्त किया।

➔ 14 वर्षीय निहाल शतरंज इतिहास के 12वें सबसे युवा ग्रैंडमास्टर हैं।

## ❑ रमेश पोवार

➔ पूर्व भारतीय स्पिन गेंदबाज।

➔ BCCI द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त। (14 अगस्त, 2018)

➔ ज्ञातव्य है कि जुलाई, 2018 में पूर्व कोच



तुषार अरोटे के इस्तीफा देने के बाद से पोवार अंतरिम कोच के रूप में कार्य कर रहे थे।

## ❑ हकम सिंह भट्टल

➔ एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक

एवं ध्यानचंद अवॉर्ड विजेता एथलीट का निधन। (14 अगस्त, 2018)



➔ इन्होंने बैंकॉक एशियन गेम्स, 1978 में पुरुषों की 20 किमी. पैदल चाल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था।

➔ वर्ष 1979 टोक्यो में संपन्न एशियन ट्रैक एंड फील्ड मीटिंग में भी स्वर्ण पदक जीता था।

## ❑ प्रदीप चौधरी

➔ मोहन बागान फुटबॉल क्लब के पूर्व कप्तान।

➔ मोहन बागान क्लब द्वारा 'मोहन बागान रत्न, 2018' से सम्मानित। (29 जुलाई, 2018)

➔ मोहन बागान क्लब की स्थापना की वर्षगांठ के अवसर पर शिल्टन पॉल को 'वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी' तथा सुदीप चटर्जी को 'वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर' का पुरस्कार प्रदान किया गया।



➔ सौरव दास को 'वर्ष का सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर' चुना गया।  
➔ गत वर्ष फीफा अंडर-17 विश्व कप में भारतीय टीम के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले फुटबॉलर रहीम अली को 'विशेष पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

## □ सुनील छेत्री

➔ भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान।  
➔ अखिल भारतीय फुटबॉल संघ द्वारा वर्ष 2017 हेतु 'एआईएफएफ प्लेयर ऑफ द ईयर' चुना गया। (22 जुलाई, 2018)



## □ अभिनव बिंद्रा

➔ ओलंपिक चैंपियन भारतीय निशानेबाज।  
➔ अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) द्वारा वर्ष 2018 के लिए गठित 'एथलीट्स कमीशन' (Athletes' Commission) के सदस्य नियुक्त किए गए।

➔ ज्ञातव्य है कि बिंद्रा वर्ष 2016 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के बाद 'एथलीट्स कमीशन' में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं।

➔ बिंद्रा ने वर्ष 2008 में बीजिंग में आयोजित ओलंपिक खेलों में पुरुषों की 10 मी. एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, जो कि उस वर्ष ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा जीता गया एकमात्र स्वर्ण पदक था।



## □ मोहम्मद कैफ

➔ भारतीय क्रिकेटर।  
➔ क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा। (13 जुलाई, 2018)

➔ उल्लेखनीय है कि वर्ष 2002 में 13 जुलाई को ही क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान में खेले गए नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल मैच में कैफ ने इंग्लैंड के विरुद्ध ऐतिहासिक पारी खेलकर जीत दिलाई थी।

➔ कैफ ने 13 टेस्ट मैचों में 624 रन और 125 एकदिवसीय मैचों में 2753 रन बनाए।



## □ नीरज चोपड़ा

➔ भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी।  
➔ 18वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक बने। (18 अगस्त, 2018)

➔ 29 जुलाई, 2018 को फिनलैंड में आयोजित सावो खेलों में नीरज ने 85.69 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता।



## □ लक्ष्य सेन

➔ भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी।  
➔ एशियाई जूनियर चैंपियनशिप के पुरुष एकल मुकाबले में विश्व के नं. 1 खिलाड़ी कुनलाकुत विविदसरन (थाईलैंड) को हराकर स्वर्ण पदक जीता। (22 जुलाई, 2018)



➔ इस प्रतियोगिता के पुरुष एकल मुकाबले में स्वर्ण पदक जीतने वाले वह दूसरे भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं।  
➔ इससे पूर्व वर्ष 1965 में गौतम ठक्कर ने स्वर्ण पदक जीता था।  
➔ जबकि महिलाओं की श्रेणी में वर्ष 2012 में भारतीय शटलर पी.वी. सिंधु ने स्वर्ण पदक जीता था।

## □ बेंजामिन पवार्ड

➔ फ्रांसीसी फुटबॉलर।  
➔ 2018 फीफा वर्ल्ड कप 'गोल ऑफ द टूर्नामेंट' का पुरस्कार जीता। (25 जुलाई, 2018)



➔ बेंजामिन ने यह गोल प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना के विरुद्ध लुकास हर्नांडेज के क्रॉस पर 57वें मिनट में किया था।

## □ फखर जमां

➔ पाकिस्तानी क्रिकेटर।  
➔ अंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज (18 पारियों) 1000 रन पूरे करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने। (जिम्बाब्वे के विरुद्ध; 22 जुलाई, 2018)

➔ जिम्बाब्वे के विरुद्ध पांच मैचों की एकदिवसीय शृंखला के चौथे मैच में नाबाद दोहरा शतक (210 रन) बनाया। (20 जुलाई, 2018)



➔ फखर यह कारनामा करने वाले पहले पाकिस्तानी एवं विश्व के छठे बल्लेबाज बनें।

## □ साहिबजादा फरहान

➔ पाकिस्तानी क्रिकेटर।  
➔ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने पदार्पण मैच में बिना गेंद खेले आउट होने वाले विश्व के पांचवें क्रिकेटर बन गए। (8 जुलाई, 2018)



➔ ओपनर फरहान को ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया) ने वाइड बॉल पर विकेटकीपर एलेक्स कैरे के हाथों स्टंप कराया।

➔ इसी के साथ फरहान अपने पदार्पण मैच में वाइड बॉल पर स्टंप आउट होने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर भी बन गए।

➔ उल्लेखनीय है कि फरहान के अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी प्रारूप में अपनी प्रथम पारी में बिना कोई गेंद खेले आउट होने वाले चार क्रिकेटर हैं- एडो ब्रांडेस (जिम्बाबे), रेयान हर्ले (वेस्टइंडीज), एश्ले नाफके (ऑस्ट्रेलिया) तथा एलेक्स लाउडन (इंग्लैंड)।

➔ हालांकि ये सभी चारों खिलाड़ी रन आउट हुए थे।

➔ बिना कोई गेंद खेले आउट (0 off 0 Balls) होने की स्थिति को क्रिकेट में 'डायमंड डक' (Diamond duck) की संज्ञा दी जाती है।

## ❑ एरोन फिच

➔ टी-20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान।

➔ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने टी-20 क्रिकेट की ताजा रैंकिंग जारी की। (9 जुलाई, 2018)

➔ फिच ने टी-20 रैंकिंग में 900 रेटिंग अंक प्राप्त किए।

➔ फिच यह उपलब्धि प्राप्त करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज हैं।

➔ फिच ने जिम्बाबे के हरारे में अंतरराष्ट्रीय टी - 20 क्रिकेट मैच में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का नया रिकॉर्ड बनाया।

➔ फिच ने त्रिकोणीय श्रृंखला के एक मैच में जिम्बाबे के विरुद्ध 76 गेंदों पर 172 रन की पारी खेलकर यह उपलब्धि प्राप्त की। (3 जुलाई, 2018)

## ❑ योगेश कथुनिया

➔ भारतीय पैरा एथलीट।

➔ बर्लिन में पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में पुरुषों की चक्का फेंक स्पर्धा (F-36 श्रेणी) में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। (2 जुलाई, 2018)

➔ कथुनिया ने 45.18 मीटर की दूरी तक चक्का फेंका।

## ❑ श्रीकांत वाघ

➔ भारतीय तेज गेंदबाज।

➔ इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में एक पारी में पूरे 10 विकेट प्राप्त कर

चर्चा में रहे। (3 जुलाई, 2018)

➔ उन्होंने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की प्रीमियर डिवीजन लीग, नार्थ यार्कशायर एंड साउथ डरहम (NYSD) क्रिकेट लीग के एक मैच में यह उपलब्धि प्राप्त की।

## ❑ शोएब मलिक

➔ पाकिस्तानी क्रिकेटर।

➔ 100 अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच खेलने वाले विश्व के प्रथम पुरुष खिलाड़ी बने। (2 जुलाई, 2018)

➔ मलिक ने जिम्बाबे में त्रिकोणीय श्रृंखला के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध यह कीर्तिमान स्थापित किया।

➔ मलिक ने हमवतन शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 99 अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच खेले हैं।

## ❑ अंजू खोसला

➔ सबसे कठिन खेल आयोजनों में से एक आयरनमैन ट्रायथलॉन (Ironman Triathlon) कैरिथिया, ऑस्ट्रेलिया में संपन्न। (1 जुलाई, 2018)

➔ इसमें प्रतिभागी को बिना रुके 3.86 किमी. तैराकी, 180.25 किमी. साइकिलिंग और 42.2 किमी. की मैराथन दौड़ पूरी करनी होती है।

➔ दिल्ली निवासी 52 वर्षीय अंजू खोसला इस ट्रायथलॉन को पूरा करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बन गईं।

## ❑ जनार्दन सिंह गहलौत

➔ एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया (AKFI) के पूर्व अध्यक्ष।

➔ अगले चार वर्षों हेतु अंतरराष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन (IKF) के अध्यक्ष चुने गए। (29 जून, 2018)



## अन्य चर्चित खेल व्यक्ति

● **मिशेल जॉनसन** — ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज; क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की (19 अगस्त, 2018)। इन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच नवंबर, 2015 में खेला था।

● **मारियो गोमेज गार्सिया** — जर्मन फुटबॉलर; अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। (5 अगस्त, 2018)

● **दीपा करमाकर** — शीर्ष भारतीय जिम्नास्ट; मर्सिन (तुर्की) में FIG कलात्मक जिम्नास्टिक्स विश्व चैलेंज कप की वॉल्ट स्पर्धा में

स्वर्ण पदक जीता (8 जुलाई, 2018)। दीपा का यह विश्व चैलेंज कप में पहला पदक है।

● **दीपिका पल्लीकल** — भारतीय स्ववैश खिलाड़ी; राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (CGF) के एथलीट सलाहकार आयोग में एशिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। (8 जुलाई, 2018)

● **रजत शर्मा** — वरिष्ठ पत्रकार; दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) के अध्यक्ष चयनित। (2 जुलाई, 2018)

# यू.पी.पी.सी.एस.(मुख्य) परीक्षा, 2017

प्रथम प्रश्न-पत्र (18 जून, 2018 को संपन्न)

सीरीज - C

सम-सामयिक घटना चक्र द्वारा पाठकों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (मुख्य) परीक्षा, 2017 का प्रथम प्रश्न-पत्र व्याख्यात्मक उत्तरों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रत्येक प्रश्न के हल हेतु व्याख्या के लिए उत्तर के मूल स्रोत तक पहुंचने का प्रयास किया गया है। इन मूल स्रोतों अर्थात् उत्तर को प्रमाणित करने वाली व्याख्या हेतु प्रयुक्त अधिकांश पाठ्य सामग्री हमारे पास संरक्षित है। इन्हीं मूल स्रोतों के आधार पर हम इस हल प्रश्न-पत्र की अधिकतम शुद्धता का दावा करते हैं। यदि कहीं किसी प्रश्न के उत्तर हेतु हमारी व्याख्या से न संतुष्ट हो पा रहे हों, तो दूरभाष सं. 9335140296 पर मध्याह्न 12 बजे से सायं 8 बजे के मध्य हमसे संपर्क करें। हम आपको वस्तुस्थिति से अवगत करा देंगे।

1. नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को तथ्य (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है-

तथ्य (A) : गोण्डवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है।

कारण (R) : अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित हैं।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-

कूट :

- (a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।  
(b) (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।  
(c) (A) सही है, किंतु (R) गलत है।  
(d) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर-(b)

भारत में लगभग 90 प्रतिशत से अधिक कोयला गोण्डवाना शैल समूह से प्राप्त होता है। अधिकांशतः लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल तंत्र में पाए जाते हैं। अतः तथ्य एवं कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण, तथ्य की सही व्याख्या नहीं है।

2. 2015 में निम्नलिखित राज्यों में से किसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे अधिक प्रतिशतांश वनों के अंतर्गत था?

- (a) अरुणाचल प्रदेश (b) नगालैंड  
(c) मेघालय (d) मिजोरम

उत्तर-(d)

भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2015 के अनुसार, राज्यों के भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत वनों का सबसे अधिक प्रतिशतांश मिजोरम (88.93%) का था। विकल्प में दिए गए अन्य राज्यों का प्रतिशतांश इस प्रकार है- अरुणाचल प्रदेश - 80.30%, नगालैंड - 78.21% तथा मेघालय - 76.76%।

3. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-

सूची - I

(चारागाह/हिल स्टेशन)

- A. बन्नी चारागाह  
B. बग्याल चारागाह  
C. खज्जियार  
D. पहलगाम

सूची -II

(स्थिति/राज्य)

1. उत्तराखंड  
2. जम्मू एवं कश्मीर  
3. गुजरात  
4. हिमाचल प्रदेश

कूट :

	A	B	C	D
(a)	1	3	2	4
(b)	3	1	4	2
(c)	3	1	2	4
(d)	4	2	1	3

उत्तर-(b)

सही सुमेलन है-

सूची-I (चारागाह/हिल स्टेशन)	सूची-II (स्थिति/राज्य)
बन्नी चारागाह	गुजरात
बग्याल चारागाह	उत्तराखंड
खज्जियार	हिमाचल प्रदेश
पहलगाम	जम्मू एवं काश्मीर

4. भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है?

- (a) अरावली (b) हिमालय  
(c) सतपुड़ा (d) नीलगिरि

उत्तर-(a)

अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किमी. में विस्तारित है। इसका निर्माण प्री-कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत शृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर (1722 मी.) है।

5. निम्नलिखित में से कौन-सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है?

- (a) जबलपुर (b) अहमदाबाद  
(c) उज्जैन (d) वाराणसी

उत्तर—(a)

विकल्प में दिए गए शहरों की अक्षांशीय स्थिति इस प्रकार से है—	
(स्थान)	(अक्षांश)
जबलपुर	23°11' उत्तर
अहमदाबाद	23°02' उत्तर
उज्जैन	23°09' उत्तर
वाराणसी	25°18' उत्तर

उपर्युक्त शहरों की अक्षांशीय स्थिति के अनुसार, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट का शहर जबलपुर होगा; क्योंकि जबलपुर के अक्षांश एवं कर्क रेखा मध्य अक्षांशीय अंतर सबसे कम है।

6. उत्तर प्रदेश की सीमा-रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है?

- (a) 6 (b) 7  
(c) 8 (d) 9

उत्तर—(d)

उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 9 राज्यों (8 राज्य + 1 केंद्रशासित प्रदेश) को स्पर्श करती है। प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड तथा केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली को स्पर्श करती है।

7. सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए—

- (i) पटपरा जमाव (ii) खेतौन्ही जमाव  
(iii) बाघोर जमाव (iv) सिहावल जमाव
- कूट :
- (a) (i), (iv), (ii), (iii) (b) (iv), (i), (iii), (ii)  
(c) (i), (ii), (iii), (iv) (d) (iv), (iii), (ii), (i)

उत्तर—(b)

(जमाव)	(कालक्रम)
सिहावल जमाव	निम्न पुरापाषाण काल
पटपरा जमाव	मध्य पुरापाषाण काल
बाघोर जमाव	उच्च पुरापाषाण काल
खेतौन्ही जमाव	लघु पाषाण काल

8. निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं?

- (a) हुविष्क (b) कनिष्क  
(c) समुद्रगुप्त (d) अगाथोक्लीज

उत्तर—(d)

हिंद-यवन शासक मिनाण्डर की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र स्ट्रेटो प्रथम अवयस्क था। अतः उसकी पत्नी अगाथोक्लीज ने शासन संभाला। अगाथोक्लीज द्वारा चलवाए गए चांदी के सिक्कों पर संकर्षण (बलराम) एवं वासुदेव के चित्र अंकित हैं।

9. वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए—

1. इंद्रावत के देवता थे।
2. पापियों को दंड देते थे।
3. नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे।
4. वर्षा के देवता थे।

कूट :

- (a) 1 एवं 2 सही हैं। (b) 1 एवं 3 सही हैं।  
(c) 2 एवं 4 सही हैं। (d) 1 एवं 4 सही हैं।

उत्तर—(d)

ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र को वृतासुरहंता (वृतासुर नामक राक्षस का वध करने वाला), पुरभिद (बादलों को भेदने वाला), सोमापा (सोम का अत्यधिक पान करने वाला), शतक्रति (एक सौ शक्तियों का स्वामी) आदि नामों से जाना जाता है।

10. निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?

- (a) कुमारगुप्त I : मंदसौर अभिलेख  
(b) पतिक : तक्षशिला अभिलेख  
(c) प्रभावती गुप्ता : उदयगिरि गुहा अभिलेख  
(d) समुद्रगुप्त : एरण अभिलेख

उत्तर—(c)

सही सुमेलन है—	
कुमारगुप्त I	मंदसौर अभिलेख
पतिक	तक्षशिला अभिलेख
चंद्रगुप्त द्वितीय	उदयगिरि गुहा अभिलेख
समुद्रगुप्त	एरण अभिलेख

प्रभावती गुप्ता का उदयगिरि से कोई अभिलेख नहीं प्राप्त हुआ है।



11. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-

सूची - I	सूची -II
A. हड़प्पा	1. शवाधान R- 37
B. लोथल	2. गोदी
C. कालीबंगा	3. नर्तकी की मूर्ति
D. मोहनजोदड़ो	4. जुता हुआ खेत

कूट :

	A	B	C	D
(a)	1	2	3	4
(b)	2	1	4	3
(c)	3	4	1	2
(d)	1	2	4	3

उत्तर—(d)

सही सुमेलन है-

हड़प्पा	शवाधान R-37
लोथल	गोदी
कालीबंगा	जुता हुआ खेत
मोहनजोदड़ो	नर्तकी की मूर्ति

12. निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने 'गुरुमुखी' प्रारंभ की ?

- (a) गुरु नानक (b) गुरु अमरदास  
(c) गुरु रामदास (d) गुरु अंगद

उत्तर—(d)

'गुरुमुखी' पंजाबी शब्द 'गुरामुखी' से बना है, जिसका अर्थ है-'गुरु के मुख से'। गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला का सृजन दूसरे सिख गुरु अंगद द्वारा सोलहवीं शताब्दी में 'गुरु ग्रंथ साहिब' लिखने के लिए प्रयुक्त किया गया था।

13. बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने-

- (a) कृषि को उन्नत किया।  
(b) सिर्फ सामंतों/दरबारियों को फायदा पहुंचाया।  
(c) बहुत सफलता प्राप्त की।  
(d) शासक को जनमानस से दूर किया।

उत्तर—(c)

अलाउद्दीन का आर्थिक सुधार एक बड़ी सेना का भरण-पोषण, कालाबाजारी को रोकना और विद्रोहों पर अंकुश लगाने के लिए था। इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल्य नियंत्रण के लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने मलिक कबूल को शहना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया और उसको मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक और विस्तृत अधिकार दिए जिससे नियमों को उसने बड़ी कठोरता से लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी बंद हो गई।

14. सल्तनत काल में 'दीवान-ए-अमीर-कोही' विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था ?

- (a) सेना (b) राजस्व  
(c) कृषि (d) मनोरंजन

उत्तर—(c)

मुहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग 'दीवान-ए-अमीर-ए-कोही' की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था।

15. निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था, जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया ?

- (a) इल्तुतमिश (b) बलबन  
(c) मुहम्मद बिन तुगलक (d) बहलोल लोदी

उत्तर—(c)

मुहम्मद तुगलक का शासनकाल क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें उसकी प्रमुख योजना मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी। सुल्तान ने तांबे तथा इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए, जिनका मूल्य तत्कालीन जारी चांदी और सोने के सिक्के के बराबर था, जिसे 'सांकेतिक मुद्रा' कहा गया। ऐसा प्रयोग करने वाला मुहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला सुल्तान था। यह योजना बाजार में अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण असफल रही।

16. निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था, जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया ?

- (a) अमीर खुसरो (b) अमीरहसन  
(c) अबूतालिब कलीम (d) फैजी

उत्तर—(a)

प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत में सात सुल्तानों का काल देखा था। नई फारसी काव्य शैली सबक-ए-हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को 'तूती-ए-हिंद' अथवा 'हिंदोस्तान का तोता' कहता था। अमीर खुसरो की रचनाओं का महत्वपूर्ण तत्व उनका भारतीय पर्यावरण के इर्द-गिर्द रचनाओं का आविष्कार था।

17. किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया ?

- (a) अशोक (b) हर्षवर्धन  
(c) चंद्रगुप्त मौर्य (d) कुमारगुप्त

उत्तर—(c)

मेगस्थनीज सेल्युकस 'निकेटर' द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राजदरबार में सेल्युकस का राजदूत रह चुका था। मेगस्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना, उसे उसने 'इंडिका' नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया।

18. निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालक्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :

- |               |            |
|---------------|------------|
| 1. नागभट्ट II | 2. महीपाल  |
| 3. महेंद्रपाल | 4. वत्सराज |
- कूट :
- |                |                |
|----------------|----------------|
| (a) 2, 3, 1, 4 | (b) 4, 1, 3, 2 |
| (c) 1, 2, 3, 4 | (d) 3, 1, 4, 2 |

उत्तर—(b)

शासकों का सही कालानुक्रम है—वत्सराज (775-800 ई.), नागभट्ट द्वितीय (800-835 ई.) महेंद्रपाल प्रथम (885-910 ई.) एवं महीपाल (912-944 ई.)।

19. कृषि को सम्मुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है?

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| (a) बलबन             | (b) इत्तुतमिश  |
| (c) गयासुद्दीन तुगलक | (d) रजिया बेगम |

उत्तर—(c)

तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किये। उसने 'मुकद्दम' तथा 'खुतो' को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया, ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया, भू-राजस्व की दर को  $\frac{1}{3}$  किया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था।

20. 'अनुद्योगीकरण' के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई।
- ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए—

- कूट :
- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| (a) केवल 1        | (b) केवल 2   |
| (c) 1 तथा 2 दोनों | (d) न 1, न 2 |

उत्तर—(c)

भारत में अनुद्योगीकरण की प्रक्रिया 1813 ई. के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त करने से शुरू हुई। यद्यपि कंपनी का चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। चार्टर एक्ट, 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे।

21. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए—

सूची - I

- भीमसेन कायस्थ
- चन्द्रभान ब्रह्मन
- ईश्वरदास नागर
- सुजानराय भंडारी

सूची -II

- चहार चमन
- फुतूहात-ए-आलमगीरी
- खुलासत-उत-तवारीख
- तारीख-ए-दिलकुशा

कूट :

- |     | A | B | C | D |
|-----|---|---|---|---|
| (a) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (b) | 2 | 3 | 4 | 1 |
| (c) | 3 | 4 | 1 | 2 |
| (d) | 4 | 1 | 2 | 3 |

उत्तर—(d)

सही सुमेलन है—

भीमसेन कायस्थ	तारीख-ए-दिलकुशा
चन्द्रभान ब्रह्मन	चहार चमन
ईश्वरदास नागर	फुतूहात-ए-आलमगीरी
सुजानराय भंडारी	खुलासत-उत-तवारीख

22. निम्नलिखित में से कौन-सी घटना सबसे अंत में हुई?

- चौरी-चौरा की घटना
- दांडी मार्च
- गांधी-इर्विन समझौता
- सांप्रदायिक निर्णय (अवॉर्ड) की घोषणा

उत्तर—(d)

घटनाओं का कालक्रम है—

चौरी-चौरा की घटना	1922
दांडी मार्च	1930
गांधी-इर्विन समझौता	1931
सांप्रदायिक निर्णय (अवॉर्ड) की घोषणा	1932

23. सूची-I को सूची-II सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए—

सूची - I

- रेलवे आयोग (1901)
- अकाल आयोग (1899)
- सिंचाई आयोग (1901)
- पुलिस सुधार आयोग (1902)

सूची -II

- अध्यक्ष
- एंथनी मैक डोनल
- कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ
- एण्ड्र्यू फ्रेज़र
- टॉमस रॉबर्ट्सन

कूट :

	A	B	C	D
(a)	3	1	4	2
(b)	3	2	1	4
(c)	4	1	2	3
(d)	4	2	1	3

उत्तर—(c)

सही सुमेलन इस प्रकार है—	
(आयोग)	(अध्यक्ष)
रेलवे आयोग (1901)	टॉमस रॉबर्ट्सन
अकाल आयोग (1899)	एंथनी मैक डोनल
सिंचाई आयोग (1901)	कॉलिन स्कॉट मानक्रीफ
पुलिस सुधार आयोग (1902)	एण्ड्र्यू फ्रेजर

24. निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

(a) दिल्ली षड्यंत्र केस	अमीरचन्द्र
(b) काकोरी षड्यंत्र केस	अशफाकउल्ला
(c) लाहौर षड्यंत्र केस	जतिन दास
(d) नासिक षड्यंत्र केस	रास बिहारी बोस

उत्तर—(d)

दिल्ली षड्यंत्र केस-अमीरचन्द्र; काकोरी षड्यंत्र केस-अशफाकउल्ला; लाहौर षड्यंत्र केस-जतिन दास से संबंधित है, जबकि रास बिहारी बोस का संबंध भी दिल्ली षड्यंत्र केस से था, वे गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए थे। अतः विकल्प (d) सही उत्तर होगा।

25. 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 'स्वराज' अथवा 'स्वशासन' हेतु आंदोलन किया, नेतृत्व में—

(a) महात्मा गांधी के	(b) जी.के. गोखले के
(c) बाल गंगाधर तिलक के	(d) मोतीलाल नेहरू के

उत्तर—(a)

अखिल भारतीय राजनीति में गांधीजी का पहला साहसिक कदम रौलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधीजी ने रौलेट सत्याग्रह के लिए तीन राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। होमरूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। भारतीय आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफल रहने के तदुपरांत 5 नवंबर, 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधीजी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 'एक वर्ष के भीतर स्वराज' प्राप्त करने का नारा दिया।

26. ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में 'कल्लार' नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे?

(a) कोल्हापुर	(b) मिदनापुर
---------------	--------------

(c) मदुरै

(d) रंगपुर

उत्तर—(c)

'कल्लार' दक्षिण भारत के मुदिराजा (मुधुराजा) समुदाय से संबंधित थे। ब्रिटिश भारत में 'कल्लार' जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। यह जनजाति दक्षिण भारत के मदुरै क्षेत्र से संबंधित थे।

27. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए—

1. क्रिप्स मिशन	2. अगस्त प्रस्ताव
3. नेहरू रिपोर्ट	4. वैवल प्लान

इन घटनाओं का सही कालानुक्रम है—

(a) 3, 1, 2, 4	(b) 3, 2, 1, 4
(c) 2, 1, 3, 4	(d) 1, 3, 2, 4

उत्तर—(b)

घटनाओं का सही कालानुक्रम है—

नेहरू रिपोर्ट	1928
अगस्त प्रस्ताव	1940
क्रिप्स मिशन	1942
वेवल योजना	1945

28. सूची-I को सूची-II सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए—

सूची - I (स्थान)	सूची - II (अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष)
A. संबलपुर	1. 1848
B. सतारा	2. 1849
C. अवध	3. 1854
D. झांसी	4. 1856

कूट :

A	B	C	D
(a) 2	1	3	4
(b) 2	1	4	3
(c) 1	2	4	3
(d) 3	1	4	2

उत्तर—(b)

सही सुमेलन है—

सूची-I (स्थान)	सूची-II (अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष)
संबलपुर	1849 ई.
सतारा	1848 ई.
अवध	1856 ई.
झांसी	1854 ई. (1853 ई. में अधिकृत)

29. निम्नलिखित में से कौन-सी घटना सबसे पहले हुई?

- (a) लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार  
(b) संधाल विद्रोह  
(c) प्रथम एंग्लो-सिख युद्ध  
(d) इल्बर्ट बिल विवाद

उत्तर—(c)

सही सुमेलन है—

लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार	1877 ई.
संधाल विद्रोह	1856 ई.
प्रथम एंग्लो-सिख युद्ध	1845-46 ई.
इल्बर्ट बिल विवाद	1883 ई.

30. 1855 के "संधाल हूल" के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए—

1. भागलपुर के पास मेजर बरोज संधालों से लड़ाई में हार गए।  
2. गोक्को, गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था।  
3. इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है।  
4. एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संधालों का पूर्ण वर्चस्व था।

कूट :

- (a) केवल 1  
(b) 1, 3, 4  
(c) 1, 2, 3  
(d) केवल 2 तथा 3

उत्तर—(c)

जुलाई, 1855 ई. में संधालों ने विद्रोह का बिगुल बजाया। कलकत्ता के मेजर बरोज और पूर्णिया से सेना की एक टुकड़ी संधालों का दमन करने के लिए भेजी गई, जो भागलपुर के निकट पीर पैटी के मैदान में संधालों से संघर्ष में पराजित हो गई। बाद में विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया। गोड्डा वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत संधाल परगना में आता है। गोक्को यहां का एक महत्वपूर्ण नेता था। महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल थे। गंगा घाटी क्षेत्र पर संधालों का वर्चस्व नहीं था। यह विद्रोह भागलपुर से वर्द्धमान तक फैल गया था।

31. निम्न में से कौन-सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था?

- (a) खिलाफत का प्रश्न  
(b) नमक कानून  
(c) पंजाब में अत्याचार  
(d) रौलेट एक्ट

उत्तर—(b)

सितंबर, 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी की प्रेरणा से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें दो अन्यायपूर्ण

कार्यों के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया—(1) खिलाफत मुद्दे के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण (2) पंजाब के निर्दोष लोगों की रक्षा न करने तथा उनसे बर्बर व्यवहार करने वाले अपराधी अधिकारियों को दंडित करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता। जबकि नमक कानून से संबंधित सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में प्रारंभ हुआ था।

32. सूची-I को सूची-II सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए—

सूची - I  
(समाचार-पत्र)

सूची - II  
(संपादक)

- A. काल  
B. बंगाली  
C. सुधारक  
D. सोमप्रकाश
1. सुरेन्द्रनाथ बनर्जी  
2. गोपाल कृष्ण गोखले  
3. द्वारकानाथ विद्याभूषण  
4. शिवराम महादेव परांजपे

कूट :

	A	B	C	D
(a)	4	1	2	3
(b)	4	1	3	2
(c)	3	1	4	2
(d)	3	1	2	4

उत्तर—(a)

प्रश्नगत समाचार-पत्रों एवं उनके संपादकों का सुमेलन इस प्रकार है—

समाचार-पत्र	संपादक
काल	शिवराम महादेव परांजपे
बंगाली	सुरेन्द्रनाथ बनर्जी
सुधारक	गोपाल कृष्ण गोखले
सोमप्रकाश	द्वारकानाथ विद्याभूषण

33. निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है?

- (a) कर्नल सेंट लेगर  
(b) लेफ्टिनेन्ट कर्नल गिब्स  
(c) कर्नल वैसेस  
(d) उपरोक्त सभी

उत्तर—(d)

प्रश्न में दिए गए विकल्पों में कोई भी 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है।

34. रवीन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वर्ष?

- (a) 1913 में  
(b) 1920 में  
(c) 1922 में  
(d) 1936 में

उत्तर—(a)

रवीन्द्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार (साहित्य) प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय थे।

35. निम्नलिखित में से किन्हें "बम्बई त्रिमूर्ति" के नाम से जाना जाता है?

- (a) तिलक, गोखले, नौरोजी  
(b) मेहता, तिलक, तैय्यबजी  
(c) मेहता, तैलंग, तैय्यबजी  
(d) नौरोजी, तैलंग, देशमुख

उत्तर—(c)

फिरोजशाह मेहता, के.टी. तैलंग और बदरुद्दीन तैय्यबजी को 'बम्बई त्रिमूर्ति' के नाम से जाना जाता था। तीनों ने मिलकर 1885 ई. में बॉम्बे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी।

36. किसने लिखा था, "इस निर्णय से इंकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था?"

- (a) आर.सी. मजूमदार (b) सैयद अहमद  
(c) रॉबर्ट्स (d) कूपलैण्ड

उत्तर—(a)

भारत सरकार द्वारा आर.सी. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इंकार कर दिया तथा अपनी पुस्तक "The Sepoy Mutiny and the Rebellion of 1857" को स्वतंत्र रूप से प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को "तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था" कहा था।

37. निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा 'संन्यासी विद्रोह' को ख्याति प्रदान की?

- (a) दीनबंधु मित्र (b) बंकिमचंद्र चटर्जी  
(c) शिशिर कुमार घोष (d) हरीश चंद्र

उत्तर—(b)

बंकिमचंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास 'आनंदमठ' में 'संन्यासी विद्रोह' का उल्लेख किया है। बंगाल में अंग्रेजी राज्य के स्थापित होने से तथा उसके कारण नई अर्थव्यवस्था के स्थापित होने से जर्मीदार, कृषक तथा शिल्पी सभी नष्ट हो गए। 1770 ई. में भीषण अकाल पड़ा। उसे तथा कंपनी की पदाधिकारियों की कठोरता को लोगों ने विदेशी राज्य की ही देन समझा। तीर्थ स्थानों पर आने-जाने के विरुद्ध लगे प्रतिबंधों से संन्यासी लोग क्षुब्ध हुए। संन्यासियों ने जनता से मिलकर कंपनी की कोठियों तथा लोगों पर आक्रमण किए। वॉरेन हेस्टिंग्स एक लंबे अभियान के पश्चात ही इस विद्रोह को दबा पाने में सफल हुआ।

38. निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था?

- (a) जवाहरलाल नेहरू  
(b) एम.के. गांधी  
(c) सुभाष चन्द्र बोस  
(d) राजेन्द्र प्रसाद

उत्तर—(a)

अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन अप्रैल, 1936 में लखनऊ में हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। इसी अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को इस सभा का अध्यक्ष और एन.सी. रंगा को महासचिव चुना गया था।

39. 'सत्यार्थ प्रकाश' किसके द्वारा लिखा गया है?

- (a) राजा राममोहन राय (b) बाल गंगाधर तिलक  
(c) स्वामी विवेकानन्द (d) दयानंद सरस्वती

उत्तर—(d)

प्रसिद्ध पुस्तक 'सत्यार्थ प्रकाश' दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने विचारों का वर्णन किया है। उन्होंने 1875 ई. में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। उन्होंने "पुनः वेद की ओर चलो" का नारा लगाया।

40. निम्नलिखित में से किस समाचार-पत्र/पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे?

- (a) इंडियन ओपिनियन (b) यंग इंडिया  
(c) नवजीवन (d) युगांतर

उत्तर—(d)

युगांतर समाचार-पत्र का संपादन भूपेन्द्र नाथ दत्त तथा बारीन्द्र कुमार घोष ने शुरू किया था। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन के संपादक महात्मा गांधी थे।

41. निम्न में से किसे राममोहन राय के धार्मिक/सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया?

- (a) दिग्दर्शन (b) समाचार चन्द्रिका  
(c) संवाद कौमुदी (d) बंगाल गजट

उत्तर—(b)

राममोहन राय के धार्मिक/सामाजिक विचारों के विरोध में भवानीचरण बंधोपाध्याय ने 1822 ई. में समाचार चन्द्रिका (पत्रिका) का प्रकाशन शुरू किया। इससे पूर्व वे संवाद कौमुदी के संपादक थे।

42. निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए :

1. वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 2. रौलेट अधिनियम

3. सती प्रथा पर प्रतिबंध  
कूट :  
(a) 1, 2, 3, 4  
(c) 3, 4, 1, 2
4. वुड्स डिस्पैच  
(b) 3, 1, 2, 4  
(d) 3, 1, 4, 2

उत्तर—(c)

घटनाओं और उनका कालक्रम इस प्रकार है—	
घटना	कालक्रम
सती प्रथा पर प्रतिबंध	1829
वुड्स डिस्पैच	1854
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट	1878
रौलेट अधिनियम	1919

43. निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की?

- (a) बी.जी. गोखले  
(c) बी.आर. अम्बेडकर
- (b) एम.के. गांधी  
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर—(b)

अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना वर्ष 1932 में एम.के. गांधी ने की थी।

44. निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए—

1. अगस्त प्रस्ताव  
2. क्रिप्स मिशन  
3. भारत छोड़ो आन्दोलन  
4. देसाई-लियाकत समझौता
- (a) 1, 2, 3, 4  
(c) 4, 1, 3, 2
- (b) 1, 3, 2, 4  
(d) 3, 2, 1, 4

उत्तर—(a)

घटनाओं का सही कालक्रम इस प्रकार है—	
अगस्त प्रस्ताव	1940
क्रिप्स मिशन	मार्च, 1942
भारत छोड़ो आन्दोलन	अगस्त, 1942
देसाई-लियाकत समझौता	1945

45. निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?

- (a) पश्चिमी उ.प्र. में अकाल — 1871-72  
(b) उड़ीसा, बंगाल, बिहार में अकाल — 1865-66  
(c) मद्रास, मैसूर, हैदराबाद में अकाल — 1876-78  
(d) बंगाल में अकाल — 1943

उत्तर—(a)

अकाल का सही कालक्रम इस प्रकार है—	
पश्चिमी उ.प्र. में अकाल	1860-61
उड़ीसा, बंगाल, बिहार में अकाल	1865-66

मद्रास, मैसूर, हैदराबाद में अकाल	1876-78
बंगाल में अकाल	1942-43
इस प्रकार विकल्प (a) सही सुमेलित नहीं है।	

46. 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था?

- (a) लॉर्ड लिनलिथगो  
(c) लॉर्ड डफरिन
- (b) लॉर्ड वेलेजली  
(d) लॉर्ड सैलिसबरी

उत्तर—(c)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना (1885) के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन (कार्यकाल 1884-1888) था। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह 'सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था' है।

47. निम्नलिखित में से कौन, कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनैतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी?

- (a) दि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन  
(b) दि इंडियन एसोसिएशन  
(c) मद्रास नेटिव एसोसिएशन  
(d) लैंड होल्डर्स सोसाइटी, कलकत्ता

उत्तर—(\*)

प्रश्नानुसार विकल्प में दी गई सभी संस्थाएं कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनैतिक संस्थाएं थीं। लैंडहोल्डर्स सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1837 में, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में, दि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 ई. में तथा दि इंडियन एसोसिएशन 1876 ई. में स्थापित हुई थी। अतः कोई भी उत्तर सही नहीं है। हालांकि दूसरी दृष्टि से देखा जाए, तो कांग्रेस की स्थापना (1885) के ठीक पूर्वकाल में लैंडहोल्डर्स सोसाइटी अस्तित्व में नहीं थी। इस संस्था को 1851 ई. में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में समाहित कर दिया गया था। जबकि अन्य संस्थाओं का अस्तित्व विद्यमान था। इस संदर्भ से प्रश्न का उत्तर विकल्प (d) हो सकता है।

48. कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की?

- (a) जोनाथन डंकन  
(c) वॉरेन हेस्टिंग्स
- (b) विलियम जॉंस  
(d) चार्ल्स ग्रांट

उत्तर—(b)

एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ई. में विलियम जॉंस ने की थी।

49. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, हेग, नीदरलैंड्स में दूसरी बार न्यायाधीश बनने वाले भारतीय हैं—

- (a) नीरू चड्ढा  
(c) एच.एल. दत्तू
- (b) दलवीर भंडारी  
(d) हरीश साल्वे

उत्तर—(b)

दलवीर भंडारी भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर 27 अप्रैल, 2012 को निर्वाचित हुए थे। नवंबर, 2017 में वे इस पद पर दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुन लिए गए। भंडारी को जनरल एसेंबली में 183 मत मिले।

50. 19 फरवरी, 2018 को अकेले 'मिग-21 बाइसन' उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनीं?

- (a) अवनी चतुर्वेदी (b) मोहना सिंह  
(c) भावना कंत (d) शिवांगी सिंह

उत्तर—(a)

19 फरवरी, 2018 को भारतीय वायु सेना की फ्लाईंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनीं। उन्होंने गुजरात के जामनगर एयरबेस से अकेले ही मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाकर इतिहास रचा। इसके कुछ दिनों बाद फ्लाईंग ऑफिसर भावना कंत लड़ाकू विमान उड़ाने वाली दूसरी भारतीय महिला पायलट बनीं।

51. 9 फरवरी, 2018 को सियोल, दक्षिण कोरिया में शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों के परेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. उत्तर कोरिया के खिलाड़ियों ने भाग नहीं लिया।  
2. रूस का झंडा वहां नहीं था।

उपरोक्त में सही कथन है/हैं—

- (a) केवल 1 (b) केवल 2  
(c) 1 तथा 2 दोनों (d) न तो 1 और नहीं 2

उत्तर—(b)

उत्तर कोरिया के दो फिगर स्केटर्स ने प्योंगचांग शीतकालीन ओलंपिक खेल, 2018 में भाग लिया था। IOC ने 2014 के डोपिंग विवाद के चलते इस शीतकालीन ओलंपिक में रूस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। रूसी एथलीटों ने ओलंपिक झंडे के तहत 'रूस के ओलंपिक एथलीट्स' (OAR) नाम से प्रतिभाग किया था।

52. निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय विपरीत लिंग (ट्रांसजेंडर) न्यायाधीश हैं?

- (a) साधना शर्मा, छत्तीसगढ़  
(b) चित्रा बरुचा, तमिलनाडु  
(c) ओमन कुट्टी, केरल  
(d) जोयीता मंडल, पश्चिम बंगाल

उत्तर—(d)

जुलाई, 2017 में पश्चिम बंगाल की जोयीता मंडल भारत की प्रथम विपरीत लिंग (ट्रांसजेंडर) न्यायाधीश बनीं। उन्हें उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर की लोक अदालत में नियुक्त किया गया है।

53. वर्ष 2017 में एक बड़ा आतंकवादी हमला, जिसमें 500 से अधिक लोग मारे गए, हुआ था—

- (a) मोगादीशु, सोमालिया में  
(b) बीर अल-आबेद, मिस्र में  
(c) काबुल, अफगानिस्तान में  
(d) वाडी अल शती जिला, लीबिया में

उत्तर—(a)

14 अक्टूबर, 2017 को सोमालिया की राजधानी मोगादीशु में ट्रक द्वारा आतंकवादी हमला किया गया। इस हमले में 587 लोगों की मृत्यु हो गई और 316 से अधिक लोग घायल हो गए।

54. 31 मार्च, 2018 को भारत का सबसे तेज सुपरकंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन है?

- (a) पीयूष (b) प्रशांत  
(c) प्रत्युष (d) पुष्कर

उत्तर—(c)

जनवरी, 2018 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक बहुपेटाफ्लॉप्स प्रणाली के तहत उच्च क्षमता कंप्यूटिंग (HPC) का उद्घाटन किया। इस सुविधा की अधिकतम अभिकलनात्मक क्षमता (Computational Power) 6.8 पेटाफ्लॉप्स है। यह सुपरकंप्यूटर केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन दो संस्थानों में स्थापित है। इसमें से एक 'प्रत्युष' जिसकी अभिकलनात्मक क्षमता 4.0 पेटाफ्लॉप्स है, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे (ITTM, Pune) में, जबकि दूसरा 'मिहिर' जिसकी अभिकलनात्मक क्षमता 2.8 पेटाफ्लॉप्स है, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, नोएडा (NCMRWF, Noida) में स्थापित है। अतः स्पष्ट है कि 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, भारत का सबसे तेज सुपरकंप्यूटर 'प्रत्युष' है, जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ 'सूर्य' होता है।

55. विश्व का सबसे लंबा शीशे का पुल जो जनता के लिए हाल में चालू किया गया है, चीन के निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है?

- (a) शैनडोंग (b) हेबेई  
(c) सिचुआन (d) जियांगसु

उत्तर—(b)

24 दिसंबर, 2017 को चीन के हेबेई प्रांत के पिंगसन काउंटी में होंगियांगू प्राकृतिक स्थल पर पूर्णतः शीशे से निर्मित बना पुल आम जनता के लिए खोल दिया गया। यह विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल है, जिसकी कुल लंबाई 488 मीटर (1601 फीट) और चौड़ाई 4 मीटर है।

56. ट्राई के अनुसार 31 दिसंबर, 2017 को निम्नलिखित में से किस दूरसंचार प्रदाता की बाजार हिस्सेदारी (प्रतिशत में)

अधिकतम थी?

- (a) वोडाफोन (b) एयरटेल  
(c) रिलायंस जिओ (d) बीएसएनएल

उत्तर—(b)

ट्राई (TRAI) के अनुसार 31 दिसंबर, 2017 को दूरसंचार प्रदाता की बाजार हिस्सेदारी में एयरटेल की हिस्सेदारी अधिकतम 24.85 प्रतिशत थी। इसके बाद वोडाफोन 18.2 प्रतिशत, आइडिया सेल्युलर 16.83 प्रतिशत और रिलायंस जिओ 13.71 प्रतिशत का स्थान था।

57. संयुक्त राष्ट्र द्वारा 14 मार्च, 2018 को प्रकाशित वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट, 2018 को ध्यान में रखते हुए सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए :

सूची - I (देश)	सूची -II (रिपोर्ट में स्थान)
A. डेनमार्क	1. 1
B. फिनलैंड	2. 2
C. नॉर्वे	3. 3
D. आइसलैंड	4. 4

कूट :

	A	B	C	D
(a)	2	3	1	4
(b)	3	1	2	4
(c)	1	4	3	2
(d)	1	2	3	4

उत्तर—(b)

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क (SDSN) द्वारा 14 मार्च, 2018 को प्रकाशित वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट, 2018 में वर्ष 2015-17 के लिए 156 देशों की रैंकिंग जारी की गई, जिसके अनुसार देशों की रैंकिंग इस प्रकार है—

देश	रिपोर्ट में स्थान
डेनमार्क	3
फिनलैंड	1
नॉर्वे	2
आइसलैंड	4

भारत को रिपोर्ट में 133वां स्थान मिला है।

58. ब्लूमबर्ग/फोर्ब्स के अनुसार, 2017 में अधिकतम परिसंपत्ति अर्जित करने वाला भारतीय खरबपति है—

- (a) गौतम अदानी (b) लक्ष्मी मित्तल  
(c) मुकेश अंबानी (d) रतन टाटा

उत्तर—(c)

ब्लूमबर्ग के अनुसार, वर्ष 2017 में अधिकतम परिसंपत्ति अर्जित करने वाले भारतीय खरबपति रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी हैं। उनकी कुल आय 40.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। मार्च, 2017 में फोर्ब्स द्वारा खरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी की कुल परिसंपत्ति 23.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। वह भारतीय खरबपतियों में शीर्ष तथा कुल 33वें स्थान पर थे। मार्च, 2018 में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में भी अंबानी 40.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परिसंपत्ति के साथ भारतीयों में शीर्ष स्थान तथा कुल 19वें स्थान पर हैं।

59. 'मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस' 26 फरवरी से 01 मार्च, 2018 के बीच आयोजित हुई थी—

- (a) बेलिंग्टन, न्यूजीलैंड में  
(b) बार्सिलोना, स्पेन में  
(c) दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में  
(d) पेरिस, फ्रांस में

उत्तर—(b)

GSMA मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन 26 फरवरी से 1 मार्च, 2018 के मध्य बार्सिलोना, स्पेन में हुआ था। वर्ष 2019 में भी इसका आयोजन 25-28 फरवरी के मध्य स्पेन में ही होगा।

60. निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय शहर है, जिसका अपना लोगो है?

- (a) बंगलुरु (b) मैसुरु  
(c) मुंबई (d) इंदौर

उत्तर—(a)

बंगलुरु भारत का पहला शहर है, जिसका अपना लोगो (Logo) है। इसे 24 दिसंबर, 2017 बंगलुरु हब्बा स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान जारी किया गया। इस लोगो को नाम्मुर (Nammur) नाम की स्टार्टअप कंपनी ने डिजाइन किया। इस लोगो की टैगलाइन है— 'बंगलुरु-बी यू'। इस उपलब्धि के साथ यह न्यूयॉर्क, पेरिस और मैनचेस्टर जैसे शहरों की सूची में शामिल हो गया है, जिनका अपना लोगो है।

61. पर्यटन एवं संस्कृति का द्वितीय डब्ल्यू.टी.ओ./यूनेस्को सम्मेलन (11-12 दिसंबर, 2017) हुआ था—

- (a) रियाद, सऊदी अरब में (b) कुवैत सिटी, कुवैत में  
(c) मस्कट, ओमान में (d) अबूधाबी, यू.ए.ई. में

उत्तर—(c)

पर्यटन एवं संस्कृति का दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (WTO)/यूनेस्को विश्व सम्मेलन 11-12 दिसंबर, 2017 के मध्य मस्कट, ओमान में आयोजित किया गया। इसका फोकस बिंदु सतत विकास था।



62. 18 फरवरी, 2018 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों (टेस्ट, एकदिवसीय तथा टी-20) में पांच विकेट लेने वाला प्रथम भारतीय गेंदबाज कौन बना?

- (a) रविचन्द्रन अश्विन (b) रवीन्द्र जडेजा  
(c) जसप्रीत बुमराह (d) भुवनेश्वर कुमार

उत्तर—(d)

फरवरी, 2018 में द. अफ्रीका के दौरे पर भुवनेश्वर कुमार टी-20 श्रृंखला के एक मैच में पांच विकेट प्राप्त कर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में पांच विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय एवं विश्व के छठवें गेंदबाज बने। इससे पूर्व अजंता मेंडिस, लसिथ मलिंगा (श्रीलंका), टिम साउथी (न्यूजीलैंड), उमर गुल (पाकिस्तान) और इमरान ताहिर (द. अफ्रीका) यह कारनामा कर चुके हैं।

63. 20 फरवरी, 2018 को जारी यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा देश नवजात शिशुओं के लिए सर्वाधिक जोखिम भरा है?

- (a) सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक (b) अफगानिस्तान  
(c) पाकिस्तान (d) सीरिया

उत्तर—(c)

यूनिसेफ ने 20 फरवरी, 2018 को 'एवरी चाइल्ड अलाइव' (द अर्जेंट नीड टू एंड न्यूबॉर्न डेथ्स) शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार, बच्चों के जन्म लेने के लिए सर्वाधिक जोखिम भरा देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जन्म प्रति 1000 बच्चों में से 46 की उसी समय मृत्यु हो जाती है। रिपोर्ट में बच्चों के जन्म के लिए जापान को सबसे सुरक्षित देश बताया गया है। वर्ष 2016 में भारत में प्रति 1000 जीवित जन्मों में नवजात मृत्यु दर 25.4 रही।

64. अम्मा स्कूटर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. यह कामकाजी महिलाओं के लिए एक 75% सब्सिडी वाली योजना है।
2. यह तमिलनाडु की ए.आई.ए.डी.एम.के. सरकार की योजना है।
3. स्वर्गीय जयललिता की 69वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको प्रवर्तित किया था।
4. इससे केवल चेन्नई में रहने वाली कामकाजी महिलाओं को लाभ मिलेगा।

उपरोक्त में से सही कथन हैं—

- (a) केवल 1 तथा 2 (b) केवल 2 तथा 3  
(c) केवल 2 तथा 4 (d) केवल 1, 3 तथा 4

उत्तर—(c)

24 फरवरी, 2018 को तमिलनाडु की दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की 70वीं जयंती के अवसर पर चेन्नई में रहने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए रियायती दर पर स्कूटर देने की 'अम्मा स्कूटर

योजना' का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। इस योजना में महिलाओं को दो पहिया वाहन खरीदने पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी और इसकी अधिकतम सीमा 25000 रुपये होगी।

65. भारतीय मूल के लोगों का प्रथम प्रवासी सांसद सम्मेलन हुआ था—

- (a) नई दिल्ली में (b) ढाका में  
(c) भोपाल में (d) राजशाही में

उत्तर—(a)

भारतीय मूल के लोगों का प्रथम प्रवासी सांसद सम्मेलन 9 जनवरी, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

66. मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली भारतीय महिलाएं हैं—

1. मानुषी चिल्लर
  2. ऐश्वर्या रॉय
  3. प्रियंका चोपड़ा
  4. डायना हेडेन
- इनकी जीत का सही कालक्रम है—
- (a) 4, 3, 2, 1 (b) 2, 4, 3, 1  
(c) 3, 2, 4, 1 (d) 3, 4, 2, 1

उत्तर—(b)

मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली भारतीय महिलाओं का कालक्रमानुसार है—

1. रीता फारिया	1966
2. ऐश्वर्या रॉय	1994
3. डायना हेडेन	1997
4. युक्ता मुखी	1999
5. प्रियंका चोपड़ा	2000
6. मानुषी चिल्लर	2017

अतः विकल्प (b) सही उत्तर होगा।

67. बिश्केक (किर्गिजस्तान) में संपन्न हुई एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में 2 मार्च, 2018 को स्वर्ण पदक जीतकर किसी एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का इतिहास निम्नलिखित में से किसने बनाया?

- (a) साक्षी मलिक (b) संगीता  
(c) विनेश फोगट (d) नवजोत कौर

उत्तर—(d)

भारतीय महिला पहलवान नवजोत कौर ने 2 मार्च, 2018 को किर्गिजस्तान के बिश्केक में संपन्न सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, 2018 में 65 किग्रा. भार वर्ग के फाइनल में जापान की मिया इमाई को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। वह यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय पहलवान बनीं।

68. सौभाग्य योजना संबंधित है—

- (a) लड़कियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता से  
(b) लड़कियों की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति से

- (c) गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से  
(d) एक नवजात बालिका की पैदाइश पर वित्तीय सहायता के प्रावधान से

उत्तर—(c)

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना 'सौभाग्य' 25 सितंबर, 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लांच की गई। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों (APL और BPL दोनों) तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों (BPL) को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।

69. वर्ष 2017-18 में भारत को कच्चा तेल आपूर्ति करने वाला अग्रणी देश है—

- (a) सऊदी (b) ईरान  
(c) इराक (d) कुवैत

उत्तर—(c)

दिसंबर, 2017 में इराक, सऊदी अरब को पछाड़ते हुए भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला शीर्ष देश बन गया। 2017-18 की अप्रैल-अक्टूबर अवधि में इराक ने 2.58 करोड़ टन तेल की आपूर्ति की, जबकि सऊदी अरब ने इसी अवधि में 2.19 करोड़ टन कच्चे तेल की आपूर्ति की।

70. 90वें ऑस्कर, 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है—

- (a) डार्कस्ट आवर  
(b) ए फैंटास्टिक वूमन  
(c) श्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग  
(d) द शेप ऑफ वाटर

उत्तर—(d)

90वें ऑस्कर, 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म 'द शेप ऑफ वाटर' (The shape of water) है। यह वर्ष 2017 की एक अमेरिकी काल्पनिक ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्देशक गुइलेरमो डेल टोरो हैं।

71. भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रवाला राज्य है—

- (a) उत्तर प्रदेश (b) मध्य प्रदेश  
(c) आंध्र प्रदेश (d) पंजाब

उत्तर—(a)

भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में लगभग 83.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र नलकूप एवं कूप से सिंचित किया जाता है, जो भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का 28.19 प्रतिशत है। इसके बाद राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि आते हैं।

72. निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है?

- (a) मूंगफली (b) सोयाबीन  
(c) सूरजमुखी (d) तिल

उत्तर—(d)

प्रश्नगत दिए गए फसलों में पाई जाने वाली औसत तेल की मात्रा इस प्रकार है—

फसल	तेल का औसत प्रतिशत
मूंगफली	लगभग 48.2%
सोयाबीन	लगभग 40%
सूरजमुखी	लगभग 42%
तिल	लगभग 52%

इस प्रकार तेल की सर्वाधिक मात्रा वाली फसल तिल है।

73. 'पीली क्रांति' भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

- (a) कृषि उत्पादन (b) तिलहन उत्पादन  
(c) मछली उत्पादन (d) दलहन उत्पादन

उत्तर—(b)

पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। अन्य प्रमुख क्रांतियां तथा उनके उत्पादन इस प्रकार हैं : काली (कृष्ण) क्रांति-पेट्रोलियम उत्पादन, नीली क्रांति-मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति-खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति-मांस और टमाटर उत्पादन, भूरी क्रांति-उर्वरक एवं श्वेत क्रांति-दुग्ध उत्पादन।

74. लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है :

- (a) तमिलनाडु (b) राजस्थान  
(c) गुजरात (d) आंध्र प्रदेश

उत्तर—(c)

भारत में लवण प्रभावित मृदाओं में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात है। इसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब का स्थान है। भारत में क्षारीय मृदा से प्रभावित सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में है।

75. निम्नलिखित में से किस देश ने नौसैनिक अभ्यास 'मिलन-2018' में भाग लेने के लिए भारत के आमंत्रण को ठुकरा दिया था?

- (a) म्यांमार (b) मॉरीशस  
(c) ओमान (d) मालदीव

उत्तर—(d)

फरवरी, 2018 में मालदीव ने नौसैनिक अभ्यास 'मिलन, 2018' में भाग लेने के लिए भारत के आमंत्रण को ठुकरा दिया था। मालदीव ने इसके लिए कोई कारण नहीं बताया। 6-13 मार्च, 2018 के मध्य पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार में यह नौसैनिक अभ्यास संपन्न हुआ, जिसमें भारत के अतिरिक्त म्यांमार, मॉरीशस तथा ओमान सहित 16 देशों ने भाग लिया।

76. टाइम पत्रिका के अनुसार, वर्ष 2017 का व्यक्ति/संस्था है-

- (a) नरेंद्र मोदी (b) डोनाल्ड ट्रम्प  
(c) एंजेला मर्केल (d) द साइलेन्स ब्रेकर्स

उत्तर—(d)

दिसंबर, 2017 में अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पत्रिका 'टाइम' (TIME) द्वारा 'द साइलेंस ब्रेकर्स' को वर्ष 2017 का 'टाइम पर्सन ऑफ द ईयर' चुना गया। साइलेंस ब्रेकर्स शब्द ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्होंने यौन शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई और ऐसे बड़े-बड़े व्यक्तियों के चरित्र का पर्दाफाश किया, जिनके बारे में लोग कुछ बोलने से भी डरते हैं।

77. निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?

- | सूची-I<br>(विश्व दिवस)       | सूची-II<br>(तिथि) |
|------------------------------|-------------------|
| (a) अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस | 08 मार्च          |
| (b) विश्व जल दिवस            | 22 अप्रैल         |
| (c) विश्व कुष्ठ निवारण दिवस  | 30 जून            |
| (d) विश्व कैंसर दिवस         | 4 फरवरी           |

उत्तर—(b)

विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2018 के इस दिवस का मुख्य विषय (Theme) 'प्रकृति के लिए पानी' (Nature for Water) था।

78. शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है-

- (a) आंध्र प्रदेश (b) तमिलनाडु  
(c) कर्नाटक (d) पश्चिम बंगाल

उत्तर—(c)

भारत में शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। इसके बाद क्रमशः आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु का स्थान आता है।

79. निम्नलिखित में से कौन-सी संस्था कृषि पदार्थों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है?

- (a) नेफेड (b) स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन  
(c) इफको (d) एम.एम.टी.सी.

उत्तर—(c)

नेफेड (NAFED), स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (STC) और एम.एम.टी.सी. (MMTC) भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाली संस्थाएं हैं, जबकि इफको (IFCO) रासायनिक उर्वरक के उत्पादन, निर्यात एवं आयात करने वाली संस्था है।

80. भारतीय निर्यात की मंद प्रगति का/के क्या कारण है/हैं?

- (a) ऊंचे मूल्य (b) विदेशी प्रतियोगिता  
(c) निम्न स्तर का माल (d) उपर्युक्त समस्त

उत्तर—(d)

किसी भी देश का निर्यात उस देश में उत्पादित वस्तुओं के विशिष्ट गुणों पर निर्भर करता है। जैसे वस्तु की गुणवत्ता एवं मूल्य निर्यात को प्रभावित करते हैं। उसी प्रकार निर्यात में विदेशी प्रतियोगिता का भी प्रभाव पड़ता है।

81. एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार है-

- (a) जकार्ता, इंडोनेशिया (b) बीजिंग, चीन  
(c) काठमांडू, नेपाल (d) मेरठ, भारत

उत्तर—(b)

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (2012) की रिपोर्ट के अनुसार, एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार, भारत को पीछे छोड़ता हुआ चीन (बीजिंग) है।

82. भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी-

- (a) अप्रैल, 2000 में (b) अप्रैल, 2001 में  
(c) अप्रैल, 2002 में (d) अप्रैल, 2003 में

उत्तर—(a)

निकासी एवं नियंत्रण में अभिन्न कमियों, विश्वस्तरीय अवसरचनाओं के अभाव, अस्थायी आर्थिक स्थिति से उत्पन्न त्रुटियों को दूर करने एवं भारत में अधिकाधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से अप्रैल, 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा की गई।

83. वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है-

- (a) नोएडा में (b) नई दिल्ली में  
(c) गाजियाबाद में (d) गुरुग्राम में

उत्तर—(a)

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है। इसकी पहली कल्पना वर्ष 1962 में की गई थी। यह संस्थान भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन वर्ष 1972 में स्वायत्तशासी समिति के रूप में पंजीकृत है। यह संस्थान पूर्व में राष्ट्रीय श्रम संस्थान के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1995 में इसका पुनर्नामकरण भूतपूर्व राष्ट्रपति वी.वी. गिरि के नाम पर किया गया।

84. निम्नलिखित में से कौन-सा समूह रेशोवाली फसलों से संबंधित है?

- (a) पटसन, चना, अलसी (b) मसूर, जई, डैचा  
(c) कपास, जूट, सनई (d) जूट, गेहूं, कपास

उत्तर—(c)

कपास, जूट, सनई का संबंध रेशो वाली फसलों से है। ज्ञातव्य है कि भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में एवं जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है।

85. निम्न में कौन एक सही सुमेलित नहीं है?

फसल	रोग
(a) धान	उकठा
(b) सरसों	सफेद गेरुई
(c) बाजरा	कंडुवा
(d) मूंगफली	टिक्का

उत्तर—(a)

उकठा रोग (Wilting) मुख्यतः पौधों के पत्तियों संबंधित है। इस रोग के कारण पत्तियां सूखने लगती हैं। उकठा रोग मुख्य रूप से दलहनी एवं तिलहनी फसलों का रोग है। यह मुख्यतः अरहर, गन्ना एवं चना आदि फसलों को प्रभावित करता है। इस रोग का संबंध धान से नहीं है। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं।

86. निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों में से कौन 20° से. पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है?

(a) अमोनियम सल्फेट	(b) यूरिया
(c) डाइअमोनियम फॉस्फेट	(d) अमोनियम क्लोराइड

उत्तर—(b)

प्रश्नगत रासायनिक उर्वरकों में 20° से. पर यूरिया जल में अधिक घुलनशील होता है।

87. अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है—

(a) डब्ल्यू.टी.ओ.	(b) विश्व बैंक
(c) आई.एम.एफ.	(d) आई.एफ.सी.

उत्तर—(a)

विश्व व्यापार संगठन (WTO) एक अंतर-सरकारी संगठन है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी, 1995 को मराकेश समझौते के अधीन की गई। 15 अप्रैल, 1994 को 124 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन है। वर्तमान में इसके 164 सदस्य देश तथा 23 पर्यवेक्षक देश हैं।

88. आंतरिक व्यापार संबंधित है—

(a) घुड़दौड़ से	(b) करारोपण से
(c) सार्वजनिक खर्च से	(d) शेयर बाजार से

उत्तर—(d)

'इनसाइड ट्रेडिंग' (आंतरिक व्यापार) शेयर बाजार से संबंधित है। इसके अंतर्गत कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति कंपनी की आंतरिक सूचनाओं का उपयोग कर शेयर ट्रेडिंग में अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं। यह अवैध कार्य माना जाता है।

89. गैट का गोल (राउंड) अधिवेशन सामान्यतः प्रतिवर्ष होता है—

(a) लंदन में	(b) न्यूयॉर्क में
--------------	-------------------

(c) नई दिल्ली में

(d) जेनेवा में

उत्तर—(d)

GATT का गोल (राउंड) अधिवेशन सामान्यतः जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में आयोजित किया जाता था। वर्ष 1947-1994 के मध्य गैट के अधीन वार्ताओं के आठ चक्र आयोजित हुए। गैट (प्रशुल्क एवं व्यापार का सामान्य समझौता) एक अंतरिम समझौते के रूप में 1 जनवरी, 1948 से लागू हुआ। इसमें शामिल 23 देशों को एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन हेतु दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एक समिति का गठन करना था। विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना 1 जनवरी, 1995 की मराकेश समझौते (15 अप्रैल, 1994 को हस्ताक्षरित) के अधीन की गई। इस संगठन द्वारा गैट (GATT) का स्थान लिया गया। दिसंबर, 2017 तक WTO के 11वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आयोजित हुए, जिनमें से तीन का आयोजन जेनेवा (1998, 2009 एवं 2011) में किया गया है।

90. सूची-I को सूची-II सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए—

सूची - I  
(क्षेत्र)

सूची -II  
(खनिज)

A. सोनभद्र	1. तांबा
B. इलाहाबाद	2. शीशा बालू
C. ललितपुर	3. नॉन-प्लास्टिक फायर क्ले
D. मिर्जापुर	4. चूना पत्थर

कूट :

	A	B	C	D
(a)	4	3	1	2
(b)	3	1	2	4
(c)	3	2	4	1
(d)	4	2	1	3

उत्तर—(d)

सही सुमेलन इस प्रकार है—

सूची-I (क्षेत्र)	सूची-II (खनिज)
सोनभद्र	चूना पत्थर
इलाहाबाद	शीशा बालू
ललितपुर	तांबा
मिर्जापुर	नॉन-प्लास्टिक फायर क्ले

91. 31 दिसंबर, 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं?

(a) 12	(b) 13
(c) 14	(d) 15 से अधिक

उत्तर—(d)

31 दिसंबर, 2017 तक उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 16 विश्वविद्यालय हैं। वे हैं-लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (1921), छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (1965), डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (1975), चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (1965), महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (1974), संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (1958), बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी (1975), महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली (1975), डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (1927), दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर (1957), वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर (1987), राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, लखनऊ (2005)। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ (2010), इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (2016), सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर (2015), जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया (2016)।

**नोट**-उच्च शिक्षा विभाग, उ.प्र. ने अपनी वेबसाइट पर अंतिम अपडेशन 17 नवंबर, 2017 तक ही किया है। उसी के आधार पर यह आंकड़े लिए गए हैं।

92. वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि में भारत को विश्व के व्यापार का मुख्य सहयोगी बनाना है-

- (a) 2018 तक (b) 2019 तक  
(c) 2020 तक (d) 2021 तक

उत्तर-(c)

वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि में भारत को विश्व के व्यापार का मुख्य सहयोगी बनाने का वर्ष 2020 तक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों में भारत के बढ़ते महत्व के अनुरूप नेतृत्व की भूमिका में लाना है। वाणिज्य विभाग का लक्ष्य भारत के व्यापार और सेवाओं में निर्यात को वर्ष 2019-20 तक 900 अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है।

93. राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य, उ.प्र. स्थित है-

- (a) कानपुर में (b) लखनऊ में  
(c) आगरा में (d) इलाहाबाद में

उत्तर-(c)

राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य, उ.प्र. की स्थापना 1949 में आगरा में हुई थी।

94. भारत में जिंसा (कमोडिटीज) के निर्यात की श्रेणी है/हैं-

- (a) परंपरागत निर्यात-वस्तु  
(b) अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु

- (c) अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु  
(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर-(d)

वर्तमान में भारतीय निर्यात को मोटे तौर पर चार वर्गों में बांट सकते हैं-

1. कृषि और संबंधित उत्पाद जिसमें कॉफी, चाय, खली, गरम मसाले, सूखे मेवे, फल, सब्जियां आदि।
2. अयस्कों और खनिजों में मैंगनीज अयस्क, अभ्रक, कच्चा लोहा आदि।
3. इंजीनियरिंग वस्तुएं, निर्मित वस्तुओं में सूती वस्त्र, सिले-सिलाए वस्त्र, पटसन की वस्तुएं, चमड़े के सामान आदि।
4. खनिज, ईंधन और लुब्रिकेन्ट्स आदि।

भारत ने धीरे-धीरे स्वतंत्रता पूर्व परंपरागत उत्पाद निर्यात करने वाले देश से वर्तमान में गैर-परंपरागत उत्पादित वस्तुओं के निर्यातक के रूप में स्वयं को परिवर्तित कर लिया है। फिर भी परंपरागत वस्तुओं का अभी भी निर्यात हो रहा है, लेकिन गैर-परंपरागत वस्तुओं की तुलना में कम।

95. निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है?

- (a) हारमोनियम वादक श्री राम श्रीवास्तव  
(b) ब्रज रास नृत्य  
(c) मिर्जापुर बिरहा  
(d) गायकी मुबारक अली खां

उत्तर-(c)

बिरहा, भोजपुरी में गाया जाने वाला पूर्वी उ.प्र. का लोकप्रिय लोकगीत है। मिर्जापुर में कजरी गायी जाती है। शेष विकल्प सही हैं।

96. निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्यिक फसल है?

- (a) जूट (b) गन्ना  
(c) कपास (d) तिलहन

उत्तर-(b)

गन्ना उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्यिक फसल है। वर्ष 2016-17 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार, 144.8 मिलियन टन उत्पादन के साथ उ.प्र. देश में प्रथम स्थान पर है, जो देश के कुल उत्पादन का 41.1 प्रतिशत है। उ.प्र. के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले हैं-मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बलिया, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, फैजाबाद, बस्ती एवं गोरखपुर।

97. निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है?

- (a) थीम पार्क, आगरा (b) मेगा फूड पार्क, बरेली  
(c) टेक्सटाइल पार्क, वाराणसी (d) डिफेंस पार्क, शाहजहांपुर

उत्तर-(a)

'थीम पार्क' आगरा की स्थापना हेतु अभिनेता संजय खान एवं तत्कालीन सपा सरकार (मुख्यमंत्री अखिलेश यादव) के बीच करार हुआ था। इस थीम पार्क की स्थापना संजय खान की कंपनी मेसर्स किंगडम इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा की जानी थी। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संजय खान को नोटिस भेजी गई है। यू.एस.आई.डी.सी. द्वारा अब यहां पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनायी जाएगी।

98. निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा एक सही सुमेलित नहीं है?

- (a) ताला उद्योग – अलीगढ़  
(b) कालीन उद्योग – भदोही  
(c) चूड़ी उद्योग – शाहजहांपुर  
(d) चिकन उद्योग – लखनऊ

उत्तर—(c)

चूड़ी उद्योग, फिरोजाबाद से संबंधित है, शेष युग्म सही हैं।

99. उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है?

- (i) गन्ना (ii) धान  
(iii) आलू (iv) मक्का  
सही उत्तर का चयन कीजिए:  
(a) (i) और (ii) (b) (ii) और (iii)  
(c) (iii) और (iv) (d) (i) और (iii)

उत्तर—(d)

वर्ष 2016-17 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार, गन्ना (144.8 मिलियन टन) उत्पादन में उ.प्र. का प्रथम स्थान है। इसी प्रकार आलू उत्पादन (वर्ष 2015-16 के अंतिम आंकड़े) में 13851.76 हजार मीट्रिक टन के साथ उ.प्र. का प्रथम स्थान है। वर्ष 2016-17 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार, गेहूँ उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान (30.1 मिलियन टन) है।

100. जनगणना 2011 के अनुसार, सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित चार जिलों का सही अवरोही क्रम है—

- (a) गौतमबुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, गाजियाबाद  
(b) गौतमबुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा  
(c) गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, औरैया, कानपुर नगर  
(d) गाजियाबाद, कानपुर नगर, औरैया, गौतमबुद्ध नगर

उत्तर—(b)

जनगणना 2011 के अनुसार, सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले चार जिले हैं—गौतमबुद्ध नगर (80.12%), कानपुर नगर (79.65%), औरैया (78.95%), इटावा (78.41%)।

101. "उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्वकाल है।" इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हैं?

- (i) बुद्ध (ii) राम  
(iii) नवाब (iv) महाराज  
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए—  
(a) (i) (ii) और (iii) (b) (ii), (iii) और (iv)  
(c) (iii), (iv) और (i) (d) (iv), (i) और (ii)

उत्तर—(c)

इतिहास को उपलब्ध स्रोतों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है—(i) प्रागैतिहासिक काल तथा (ii) ऐतिहासिक काल। ऐसा काल जिसका ज्ञान पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हो, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जबकि ऐतिहासिक काल का लिखित साक्ष्य उपलब्ध है।

प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बुद्ध, नवाब तथा महाराज के संबंध में पर्याप्त प्रमाणिक लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, जबकि राम के संबंध में जानकारी रामायण महाकाव्य से ही हो पाती है। यह भी लिखित महाकाव्य है, लेकिन इसे प्रमाणिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। रामायण कालीन स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों का रामायण में उल्लिखित घटनाओं से सामंजस्य स्थापित अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। अभी इस पर शोध कार्य जारी है। साक्ष्यों में सामंजस्य का अभाव इसलिए भी है कि रामायण महाकाव्य की रचना, घटना के बहुत बाद में की गई है। अतः उस काल से संबंधित स्तरों से मिले साक्ष्य से इसकी पुष्टि नहीं हो पाती। चूंकि रामायण को ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं माना जाता, साथ ही राम के बारे में जानकारी अन्य किसी ग्रंथ से न होने के कारण 'राम' को ऐतिहासिक पूर्वकाल में नहीं रखा जा सकता। हालांकि इस पर अभी और शोध की आवश्यकता है।

102. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई है, लगभग—

- (a) 300 किमी. (b) 250 किमी.  
(c) 350 किमी. (d) 400 किमी.

उत्तर—(a)

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई 302 किमी. है। यह एक्सप्रेस-वे आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई और लखनऊ जिलों को जोड़ता है।

103. उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं—

- (a) विंध्य क्षेत्र में (b) सिंगरौली क्षेत्र में  
(c) बुंदेलखंड क्षेत्र में (d) उपरोक्त सभी

उत्तर—(b)

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में डायसपोर एवं पाइरोफा-लाइट तथा विंध्य क्षेत्र में एंडालुसाइट एवं कैल्साइट (Calcite) पाया जाता है।

104. 2011 की जनगणना के अनुसार, उ.प्र. में पुरुष/महिला अनुपात क्या है?

- (a) 898/1000 (b) 836/1000  
(c) 912/1000 (d) 950/1000

उत्तर—(c)

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, उ.प्र. पुरुष/महिला अनुपात 912/1000 है। लिंगानुपात की दृष्टि से उ.प्र. का राज्यों में 26वां स्थान है।

105. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के अंतर्गत ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कहते हैं—

- (a) ऊषा (b) आशा  
(c) ए.एम.डब्ल्यू (d) पूजा

उत्तर—(b)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) का प्रारंभ 12 अप्रैल, 2005 को किया गया। इसके अंतर्गत ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा (ASHA-Accredited Social Health Activist) की नियुक्ति का प्रावधान है, जिनकी आयु 25-45 वर्ष हो।

106. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन-सा एक ऐसा समुदाय है, जिसमें 'खाप पंचायत व्यवस्था' एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पायी जाती है?

- (a) राजपूत (b) गुज्जर  
(c) जाट (d) जाटव

उत्तर—(c)

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 'खाप पंचायत व्यवस्था' जाट समुदाय में पायी जाती है। यह व्यवस्था परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पायी जाती है। 'खाप पंचायत' की अपनी सामाजिक व्यवस्था है, जिसका उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता है। यहां तक कि 'ऑनर किलिंग' के रूप में हत्या भी की जाती है।

107. निम्नलिखित में से किस समिति ने 'त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली' की संस्तुति की?

- (a) बलवंत राय मेहता समिति (b) अशोक मेहता समिति  
(c) राव समिति (d) सिंघवी समिति

उत्तर—(a)

भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही राजस्थान की विधानसभा ने 2 सितंबर, 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पं. जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त पंचायतों में सुधार हेतु वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति, वर्ष 1985 में जी.वी.के. राव समिति तथा वर्ष 1986 में डॉ. एल.एम. सिंघवी समिति का भी गठन किया गया।

108. उत्तर प्रदेश में 'सिंगल विंडो क्लीयरेंस विभाग' के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए—

1. औद्योगिक सेवाएं  
2. औद्योगिक स्वीकृति  
3. औद्योगिक अनुमोदन  
4. औद्योगिक टोस अपशिष्ट प्रबंधन

कूट :

- (a) 1 सही है।  
(b) 1 और 2 सही हैं।  
(c) 1, 2 और 3 सही हैं।  
(d) 1, 2, 3 और 4 सही हैं।

उत्तर—(c)

उत्तर प्रदेश बजट 2018-19 के अनुसार, औद्योगिक इकाइयों से संबंधित स्वीकृतियों, अनुमोदनों, अनुमतियों तथा लाइसेंसों की ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस विभाग की स्थापना मुख्यमंत्री कार्यालय में की जा रही है।

109. डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी अब बनाता/प्रदान करता है—

- (a) डीजल इंजन  
(b) बिजली इंजन  
(c) डीजल एवं बिजली इंजन दोनों  
(d) डीजल इंजन एवं बिजली आपूर्ति

उत्तर—(c)

डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी डीजल एवं बिजली दोनों प्रकार के इंजन बनाता है।

110. प्रथम 'दीनदयाल हस्तकला संकुल' व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है—

- (a) आगरा में (b) वाराणसी में  
(c) कानपुर में (d) गोरखपुर में

उत्तर—(b)

प्रथम 'दीनदयाल हस्तकला संकुल' व्यापार सुविधा केंद्र, जो वाराणसी में अवस्थित है, को प्रधानमंत्री द्वारा 22 सितंबर, 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा इस केंद्र की आधारशिला नवंबर, 2014 में रखी गई थी।

111. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

1. यह लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।  
2. यह लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-

- (a) केवल 1 सही है।  
 (b) केवल 2 सही हैं।  
 (c) 1 तथा 2 दोनों सही हैं।  
 (d) न तो 1 न ही 2 सही है।

उत्तर—(a)

उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की स्थापना राज्य वित्तीय निगम एक्ट, 1951 के अंतर्गत वर्ष 1954 में की गई थी। यह निगम राज्य में लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

112. सूची-I को सूची-II सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-

सूची - I (विश्व दिवस)	सूची -II (दिनांक)
A. विश्व पृथ्वी दिवस	1. 22 मार्च
B. विश्व नगर दिवस	2. 11 जुलाई
C. विश्व जनसंख्या दिवस	3. 31 अक्टूबर
D. विश्व जल दिवस	4. 22 अप्रैल

कूट :

	A	B	C	D
(a)	4	3	2	1
(b)	1	2	3	4
(c)	3	4	1	2
(d)	2	1	4	3

उत्तर—(a)

सही क्रम इस प्रकार है-

विश्व पृथ्वी दिवस	22 अप्रैल
विश्व नगर दिवस	31 अक्टूबर
विश्व जनसंख्या दिवस	11 जुलाई
विश्व जल दिवस	22 मार्च

113. निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :

- (i) भारत में शिशु लिंग-अनुपात (0-6 वर्ष) 2001-11 में घटा है।  
 (ii) हरियाणा का शिशु लिंग-अनुपात 2001-11 में बढ़ा है।  
 (iii) भारत का ग्रामीण लिंग-अनुपात नगरीय लिंग अनुपात से अधिक है।  
 (iv) भारत में पुरुष शिशु मृत्यु-दर, महिला शिशु मृत्यु-दर से अधिक है।

कूट :

- (a) (i) और (ii)  
 (b) (ii) और (iii)

(c) (i), (ii) और (iii)

(d) (i), (iii) और (iv)

उत्तर—(c)

जनगणना, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, भारत में शिशु लिंगानुपात (0-6 वर्ष) 2001 के 927 से घटकर 919 पर आ गया है, जो कि वर्ष 1961 के बाद से न्यूनतम है। हरियाणा का शिशु लिंगानुपात वर्ष 2001 के 819 से बढ़कर 834 हो गया है। जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या) 943 है, जो वर्ष 2001 से 10 अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 949 तथा शहरी क्षेत्रों में 929 है। भारत में पुरुष मृत्यु दर प्रति 100 महिला शिशु पर 97 है।

114. उ.प्र. के निम्नलिखित में से किस जनपद में "अगरिया" जनजाति निवास करती है?

- (a) गाजियाबाद (b) गाजीपुर  
 (c) मिर्जापुर (d) सोनभद्र

उत्तर—(d)

'अगरिया' जनजाति उ.प्र. में सोनभद्र जिले में निवास करती है। सोनभद्र जिले में अन्य निवासित जनजातियाँ हैं-गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोड़, खरवार, खैरवार, परहिया, बैगा, पंखा, पनिका, चैरो, भूईया।

115. "किस्सा राधा कन्हैया" के लेखक कौन हैं?

- (a) सैयद आगा हसन काश्मीरी  
 (b) नवाब वाजिद अलीशाह  
 (c) बाबू गोपालचन्द्र एलियस गिरधरदास  
 (d) पंडित प्रताप नारायण मिश्र

उत्तर—(b)

उत्तर प्रदेश के आधुनिक रंगेतिहास में 1843 ई. में लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा लिखित "किस्सा राधा कन्हैया" है।

116. "वूमेन पॉवर लाइन-1090 योजना" प्रारंभ हुई-

- (a) 12-12-2012 को  
 (b) 15-11-2012 को  
 (c) 16-11-2013 को  
 (d) 20-11-2014 को

उत्तर—(b)

महिला उत्पीड़न की घटनाओं को सख्ती से रोकने के निमित्त उ.प्र. सरकार द्वारा वूमेन पॉवर लाइन 1090 की स्थापना की गई है। 15 नवंबर, 2012 से यह सेवा निरंतर कार्य कर रही है। वूमेन पॉवर लाइन सेवा को और अधिक प्रभावी बनाने के निमित्त वर्ष 2014 में 'Women Security App. 1090' सेवा भी प्रारंभ की गई है।



117. सूची-I को सूची-II सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-

सूची-I	सूची-II
A. गद्दीस	1. मेघालय
B. टोडा	2. हिमाचल प्रदेश
C. खासी	3. मणिपुर
D. नागा	4. तमिलनाडु

कूट :

	A	B	C	D
(a)	1	2	4	3
(b)	3	1	2	4
(c)	4	3	2	1
(d)	2	4	1	3

उत्तर-(d)

सही सुमेलन है-	जनजाति	प्रदेश
	गद्दीस	हिमाचल प्रदेश
	टोडा	तमिलनाडु
	खासी	मेघालय
	नागा	मणिपुर

118. निम्नलिखित में से किसका नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है?

- (a) नोटेस्टीन (b) थॉम्पसन  
(c) ली (d) डबुलडे

उत्तर-(c)

दिए गए विकल्पों में ली (Lee) का नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है। ली ने प्रवास (Migration) के निवास को स्थायी अथवा अर्धस्थायी परिवर्तन के रूप में माना है। इसमें इसी से संबंधित कोई प्रतिबंध नहीं है तथा यह स्वेच्छा से एवं अनिच्छा से हो सकता है। साथ ही यह वाह्य एवं आंतरिक स्वरूप लिए हो सकता है।

119. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-

**कथन (A) :** भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी प्रव्रजन सर्वाधिक है।

**कारण (R) :** ग्रामीण से ग्रामीण प्रव्रजन मुख्यतया महिला प्रव्रजन है।

कूट :

- (a) (A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की व्याख्या करता है।  
(b) (A) तथा (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की व्याख्या नहीं करता है।

(c) (A) सही है, किंतु (R) गलत है

(d) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर-(b)

जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रव्रजन कहलाता है। प्रव्रजन सामान्यतः दो प्रकार का होता है-स्थायी एवं अस्थायी। गमन-आगमन के आधार या प्रव्रजन ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से शहरी, शहरी से ग्रामीण तथा शहरी से शहरी हो सकता है। ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में स्त्रियों की संख्या सर्वाधिक है, जबकि इसके विपरीत आर्थिक कारणों की वजह से अंतरराज्यीय प्रवास ग्राम से नगरों में पुरुषों की संख्या सर्वाधिक है। अतः उपरोक्त व्याख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि कथन (A) तथा (R) दोनों ही सत्य हैं लेकिन कथन (R), कथन (A) की व्याख्या नहीं कर रहा है।

120. अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-

**कथन (A) :** भारत के उत्तरी-पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत कम है।

**कारण (R) :** भारत के उत्तरी-पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है।

कूट :

(a) (A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की व्याख्या करता है।

(b) (A) तथा (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की व्याख्या नहीं करता है।

(c) (A) सही है, किंतु (R) गलत है।

(d) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर-(b)

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (NER) में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। भारत के इन उत्तर-पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की संख्या बहुत ही कम है। कुछ उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे-अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड आदि में तो अनुसूचित जाति की संख्या ही नहीं है, जबकि शेष राज्यों में इनकी संख्या मात्र हजारों में ही है। वहीं देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.9 प्रतिशत भाग पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों में समाविष्ट है। अतः उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन कथन (R) कथन (A) की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए यह नहीं कहा जा सकता है कि क्षेत्रफल कम होने की वजह से इन राज्यों में अनुसूचित जातियों की संख्या कम है।

121. निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई थी?

- (a) केरल (b) गोवा  
(c) नगालैंड (d) मेघालय

उत्तर—(c)

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, नगालैंड की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि (-0.6) अंकित की गई थी।

122. पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया?

- (a) 1986 (b) 1981  
(c) 1987 (d) 1978

उत्तर—(a)

पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम [The Environment (Protection) Act] भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था।

123. निम्नलिखित में से कौन-सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है?

- (a) कार्बन डाइऑक्साइड (b) ओजोन  
(c) नाइट्रोजन (d) नियोन

उत्तर—(c)

वायुमंडल में स्थायी गैस उन गैसों को कहते हैं, जिनका प्रतिशत दिन प्रतिदिन नहीं बदलता है। इन गैसों में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं आर्गन को रखा जाता है। वायुमंडल में तीन गैसों को छोड़कर बाकी सभी गैसों की प्रतिशतता अत्यंत न्यून होती है और कुछ गैसों की प्रतिशतता परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए इन सभी को अस्थायी गैसों की श्रेणी में रखा जाता है।

124. ग्रीनवाश इंगित करता है—

- (a) झूम कृषि की प्रोन्नति  
(b) नदी जल का शुद्धीकरण  
(c) हरियाली हटाना  
(d) पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना

उत्तर—(d)

ग्रीनवाश उस स्थिति को संदर्भित करता है, जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है।

125. निम्नलिखित में से कौन-सा एक स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है?

- (a) अच्छा शासन  
(b) स्वच्छ हरितनगर

- (c) जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण  
(d) सुव्यवस्थित (स्मार्ट) गतिशीलता

उत्तर—(c)

स्मार्ट शहर का उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र के विकास को साकार करना और तकनीक का उपयोग कर विशेषकर ऐसी तकनीक जिसके स्मार्ट परिणाम मिले। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। क्षेत्र आधारित विकास से मलिन बस्तियों को बेहतर नियोजित शहरों में रूपांतरित करने सहित और मौजूदा क्षेत्रों का रूपांतरण (पुनः संयोजन और पुनः विकास) होगा। शहरी क्षेत्रों की बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए शहरों के इर्द-गिर्द नए क्षेत्र (हरित क्षेत्र) विकसित किए जाएंगे। स्मार्ट समाधानों के प्रयोग से शहर अवसंरचना और सेवाओं में सुधार करने हेतु तकनीक, सूचना और आंकड़ों का उपयोग कर सकेंगे। इस तरह से व्यापक विकास से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। रोजगार सृजित होगा और सभी विशेषकर गरीब एवं उपेक्षित लोगों की आय में बढ़ोत्तरी होगी, जिससे शहर समावेशी बनेंगे।

126. निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली (ENVIS) का 'जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र' स्थित है?

- (a) आई.आई.टी., खड़गपुर  
(b) आई.आई.टी., नई दिल्ली  
(c) आई.आई.पी.एस., मुंबई  
(d) एन.आई.आर.एस., देहरादून

उत्तर—(c)

पर्यावरण सूचना प्रणाली (ENVIS) का 'जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र' (मीडिया, पर्यावरण शिक्षा और सतत विकास) जनसंख्या विज्ञान के अंतरराष्ट्रीय संस्थान (IIPS), मुंबई (देवनार) में स्थित है।

127. निम्नलिखित केंद्रशासित राज्यों में कौन सबसे कम नगरीकृत है?

- (a) लक्षद्वीप  
(b) अंडमान एवं निकोबार द्वीप  
(c) दादरा एवं नगर हवेली  
(d) पुडुचेरी

उत्तर—(b)

दिए गए केंद्रशासित राज्यों में अंडमान एवं निकोबार सबसे कम नगरीकृत है।

केंद्रशासित राज्य	नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत
लक्षद्वीप	78.07
पुडुचेरी	68.33
दादरा एवं नगर हवेली	46.72
अंडमान एवं निकोबार द्वीप	37.70

128. भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया?

- (a) 1990 (b) 1995  
(c) 2000 (d) 2005

उत्तर—(c)

फरवरी, 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 घोषित की थी। इस नीति में 3 उद्देश्य, 4 नई संरचनाएं, 12 नीति संबंधी विषय, वर्ष 2010 के लिए 14 राष्ट्रीय सामाजिक जनसांख्यिकीय लक्ष्य, छोटे परिवार की प्राप्ति हेतु 16 प्रोत्साहक उपाय तथा 101 क्रियात्मक उपाय अर्थात् कुल मिलाकर 150 मुख्य तथ्य सम्मिलित हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख तथ्य अशोधित जन्म दर को वर्ष 2010 तक कम करके 21.0 प्रति हजार तक लाना था।

129. जर्मन वाच द्वारा प्रकाशित 2017 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मंस इंडेक्स (CCPI) के अनुसार, विश्व के 58 देशों में भारत का स्थान है?

- (a) 23वां (b) 22वां  
(c) 21वां (d) 20वां

उत्तर—(d)

नवंबर, 2016 में जर्मन स्वतंत्र एनजीओ जर्मन वाच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा 'क्लाइमेट चेंज परफॉर्मंस इंडेक्स' (CCPI), 2017 जारी की गई। 58 देशों की इस सूची में भारत को 20वां स्थान प्राप्त हुआ था। नवंबर, 2017 में जारी CCPI, 2018 इंडेक्स में 60 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत का स्थान 14वां (स्कोर-60.02) था। स्वीडन 74.32 स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा। कोई भी देश प्रथम तीन स्थानों में जगह नहीं बना पाया।

130. राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान (नीरी) कब और कहाँ स्थापित किया गया?

- (a) 1970, धनबाद (b) 1958, नागपुर  
(c) 1956, नई दिल्ली (d) 1960, चेन्नई

उत्तर—(b)

राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान (National Environmental Engineering Research Institute-NEERI) की स्थापना वर्ष 1958 में नागपुर में की गई थी। वर्तमान में इसके निदेशक डॉ. राकेश कुमार हैं।

131. 'अम्प्लैण्ड' शब्द का क्या अर्थ है?

- (a) नगर का हृदय-क्षेत्र  
(b) सैटेलाइट नगर  
(c) नगर का प्रतिवेशी (आस-पास का) क्षेत्र  
(d) नगर का निवास-क्षेत्र

उत्तर—(c)

'अम्प्लैण्ड' शब्द का अर्थ नगर का प्रतिवेशी (आस-पास का) क्षेत्र होता है। इसे हिन्टरलैण्ड (Hinterland) भी कहा जाता है।

132. निम्नलिखित राज्यों में से कौन 2011 की जनगणना के अनुसार, कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर है?

- (a) तमिलनाडु (b) मिजोरम  
(c) नगालैंड (d) गुजरात

उत्तर—(b)

जनगणना 2011 के अनुसार, सर्वाधिक साक्षरता दर एवं नगरीकरण वाले 5 राज्य

राज्य	साक्षरता दर	राज्य	नगरीकरण
केरल	94.0	गोवा	62.2
मिजोरम	91.3	मिजोरम	52.1
गोवा	88.7	तमिलनाडु	48.4
त्रिपुरा	87.2	केरल	47.7
हिमाचल प्रदेश	82.8	महाराष्ट्र	45.2
तमिलनाडु	80.1	—	48.4
नगालैंड	79.6	—	28.9
गुजरात	78.0	—	42.6

उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर स्पष्ट है कि साक्षरता दर तथा नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से मिजोरम द्वितीय स्थान पर है।

133. निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर (% नगरीय जनसंख्या) 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम है?

- (a) अरुणाचल प्रदेश (b) सिक्किम  
(c) बिहार (d) नगालैंड

उत्तर—(c)

राज्य	नगरीकरण प्रतिशत में जनगणना, 2011 के आधार पर
नगालैंड	28.9
अरुणाचल प्रदेश	22.9
सिक्किम	25.2
बिहार	11.3

उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर स्पष्ट है कि बिहार राज्य में नगरीकरण का स्तर (प्रतिशत) निम्नतम है।

134. 23 जनवरी, 2018 को दाओस (स्विट्जरलैंड) में 'वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम' के वार्षिक सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें वैश्विक चुनौतियों के रूप में रेखांकित किया था?

1. पर्यावरण परिवर्तन 2. आतंकवाद  
3. संरक्षणवाद 4. शीतयुद्ध  
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए—

कूट :

- (a) केवल 1, 2 तथा 3 (b) केवल 2, 3 तथा 4  
(c) केवल 1, 3 तथा 4 (d) केवल 1, 2 तथा 4

उत्तर—(a)

‘विश्व आर्थिक मंच’ का वार्षिक सम्मेलन 23-26 जनवरी, 2018 के मध्य दावोस (स्विट्जरलैंड) में संपन्न हुआ। 23 जनवरी, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पर्यावरण परिवर्तन (Climate Change), आतंकवाद (Terrorism) तथा संरक्षणवाद (Protectionism) को मुख्य वैश्विक चुनौतियों के रूप में रेखांकित किया।

135. अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए—

कथन (A) : भारत एक नगरीय जनाधिक्य वाले देश का उदाहरण है।

कारण (R) : भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है।

कूट :

- (a) (A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की व्याख्या करता है।  
(b) (A) तथा (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की व्याख्या नहीं करता है।  
(c) (A) सही है, किंतु (R) गलत है।  
(d) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर—(d)

जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, देश की लगभग 121 करोड़ की आबादी में 83.4 करोड़ (68.9%) लोग गांवों में तथा 37.7 करोड़ (31.1%) लोग शहरों में निवास करते हैं। हालांकि जनसंख्या के रूप में भारतीय शहरों में रहने वाले लोग कई विकसित देशों की तुलना में बहुत ही अधिक हैं, फिर भी प्रतिशतता के आधार पर भारत अभी भी विकसित देशों जैसे- हांगकांग, सिंगापुर से बहुत ही पीछे है, जहां की नगरीय जनसंख्या लगभग 100% है। अतः प्रतिशतता के आधार पर हम देखें तो विकसित देशों के मुकाबले भारत अभी जनाधिक्य वाले देशों के उदाहरण में शामिल नहीं है, फिर भी भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति काफी तेज है। हालांकि नगरीकरण के इस तेज प्रवृत्ति की तुलना में शहरी सुविधाओं जैसे- बिजली, पानी, शौचालय परिवहन आदि की उपलब्धता नहीं बढ़ पा रही है, जिससे शहरों में समस्याओं का जनाधार बढ़ता जा रहा है। उपरोक्त व्याख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि कथन (A) गलत है, किंतु कारण (R) सही है।

136. 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में कितने दस लाखी नगर हैं?

- (a) 35 (b) 46  
(c) 53 (d) 57

उत्तर—(c)

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में दस लाखी नगरों की संख्या 53 है।

137. संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, विश्व की जनसंख्या का कितना अनुमानित प्रतिशत 2016 में नगरीय अधिवासों में निवास करता था?

- (a) 53.5 (b) 54.5  
(c) 55.5 (d) 56.5

उत्तर—(b)

संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी ‘वर्ष 2016 में विश्व के शहर’ (The World's Cities in 2016) में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016 में विश्व की जनसंख्या का 54.5 प्रतिशत नगरीय अधिवासों (Urban settlements) में निवास करती था। जबकि वर्ष 2030 में इसके बढ़कर 60 प्रतिशत होने की संभावना है।

138. सूची-I को सूची-II सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए—

सूची - I (महासागर)	सूची -II (सबसे गहरे स्थान)
A. प्रशांत महासागर	1. जावा ट्रेन्च
B. अटलांटिक महासागर	2. यूरेशियन बेसिन
C. हिंद महासागर	3. मेरियाना ट्रेन्च
D. आर्कटिक महासागर	4. प्यूर्टोरिको ट्रेन्च

कूट :

	A	B	C	D
(a)	4	3	2	1
(b)	3	4	1	2
(c)	1	3	4	2
(d)	2	4	3	1

उत्तर—(b)

प्रश्नगत महासागर एवं उनसे संबंधित महासागरीय गर्त निम्नानुसार हैं—

(महासागर)	(गर्त)
प्रशांत महासागर	मेरियाना गर्त
अटलांटिक महासागर	प्यूर्टोरिको गर्त
आर्कटिक महासागर	यूरेशियन बेसिन
हिंद महासागर	जावा गर्त

139. सूची-I को सूची-II सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-

सूची - I (खनिज)	सूची - II (देश)
A. चांदी	1. चिली
B. अभ्रक	2. रूसी संघ
C. लौह अयस्क	3. मेक्सिको
D. तांबा	4. भारत

कूट :

	A	B	C	D
(a)	3	4	2	1
(b)	2	3	4	1
(c)	3	2	1	4
(d)	3	1	4	2

उत्तर-(a)

प्रश्नगत देश एवं उनसे संबंधित खनिज का सुमेलन निम्नानुसार है-

(देश)	(खनिज)
चिली	तांबा
भारत	अभ्रक
रूसी संघ	लौह अयस्क
मेक्सिको	चांदी

140. निम्नलिखित झीलों में से कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है?

- (a) मिशिगन (b) सुपीरियर  
(c) ओन्टारियो (d) ईरी

उत्तर-(a)

संयुक्त राज्य अमेरिका की महान झीलों में मिशिगन पूर्णतः अमेरिका (U.S.A.) में स्थित है। मिशिगन शहर के किनारे अमेरिका का प्रसिद्ध शहर शिकागो बसा है।

141. निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है?

- (a) सिस्मोग्राम (b) सिस्मोग्राफ  
(c) सिस्मोस्कोप (d) सिस्मोमीटर

उत्तर-(b)

वैज्ञानिकों द्वारा सामान्यतः भूकंप तरंगों के मापन के लिए सिस्मोग्राफ (Seismograph) का प्रयोग किया जाता है। सिस्मोमीटर से भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है।

142. निम्नलिखित में कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम (अवरोही क्रम में) प्रस्तुत करता है?

- (a) एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप  
(b) अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका

- (c) उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप  
(d) उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप

उत्तर-(a)

प्रश्नगत महाद्वीपों का क्षेत्रफल इस प्रकार है-

एशिया	44,579,000 वर्ग किमी.
अफ्रीका	30,065,000 वर्ग किमी.
उत्तरी अमेरिका	24,256,000 वर्ग किमी.
यूरोप	9,938,000 वर्ग किमी.

143. निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है?

- (a) गैबन (b) गीनी  
(c) गीनी बिसाऊ (d) गुयाना

उत्तर-(d)

गैबन, गीनी और गीनी बिसाऊ अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं, जबकि गुयाना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अतः विकल्प (d) सही उत्तर है।

144. कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है?

- (a) कृष्णा (b) सतलज  
(c) गोदावरी (d) नर्मदा

उत्तर-(b)

कोल बांध परियोजना का निर्माण सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किया जा रहा है। इस बांध की ऊंचाई (फाउंडेशन सहित) 167 मीटर होगी। इस बांध द्वारा निर्मित जलाशय के जल का उपयोग विद्युत उत्पादन हेतु किया जाएगा। इसका निर्माण राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC) द्वारा किया जा रहा है।

145. भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत (Silk yarn) उत्पादित करता है?

- (a) तमिलनाडु (b) पंजाब  
(c) मध्य प्रदेश (d) कर्नाटक

उत्तर-(d)

Statistical Year Book-2017 के अनुसार, भारत का अधिकतम सिल्क सूत उत्पादक राज्य कर्नाटक है। उसके बाद क्रमशः आंध्र प्रदेश एवं असम का स्थान आता है।

146. सूची-I को सूची-II सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-

सूची - I (कोयला क्षेत्र)	सूची - II (राज्य)
A. राजमहल	1. पश्चिम बंगाल
B. सोहागपुर	2. छत्तीसगढ़

- C. विश्रामपुर 3. मध्य प्रदेश  
D. रानीगंज 4. झारखंड

कूट :

	A	B	C	D
(a)	1	2	3	4
(b)	4	3	2	1
(c)	1	4	3	2
(d)	3	2	4	1

उत्तर—(b)

प्रश्नगत कोयला क्षेत्र एवं राज्यों का सही सुमेलन इस प्रकार है—  
राजमहल झारखंड  
सोहागपुर मध्य प्रदेश  
विश्रामपुर छत्तीसगढ़  
रानीगंज पश्चिम बंगाल

147. निम्नलिखित में से कौन 2015-16 में भारत के बृहत्तम चीनी उत्पादन करने वाले राज्यों के सही अवरोही क्रम को प्रदर्शित करता है?

- (a) महाराष्ट्र, उ.प्र., कर्नाटक, तमिलनाडु  
(b) उ.प्र., महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु  
(c) महाराष्ट्र, उ.प्र. तमिलनाडु, कर्नाटक  
(d) उ.प्र., कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु

उत्तर—(a)

वर्ष 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार, भारत के शीर्ष चीनी उत्पादक राज्यों का क्रम इस प्रकार है—  
1. महाराष्ट्र (34.5%)  
2. उत्तर प्रदेश (26.4%)  
3. कर्नाटक (16.9%)  
4. तमिलनाडु (4.7%)  
5. आंध्र प्रदेश (3.5%)

148. निम्नलिखित देशों में कौन 2016-17 में विश्व में चाय का बृहत्तम निर्यातक (मूल्य डॉलर में) था?

- (a) श्रीलंका (b) भारत  
(c) चीन (d) केन्या

उत्तर—(c)

दिए गए विकल्पों में चीन वर्ष 2016-17 में विश्व में चाय का बृहत्तम निर्यातक (मूल्य डॉलर में) था।  
2016-17 में 5 निर्यातक देश (मूल्य डॉलर में)  
1. चीन 1.6 बिलियन  
2. श्रीलंका 1.5 बिलियन  
3. केन्या 1.4 बिलियन  
4. भारत 591.2 मिलियन

149. प्रतिदर्श पंजीयन सर्वेक्षण (SRS), 2016 के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) निवास अनुसार क्या थी?

- (a) 3.4 (b) 3.1  
(c) 2.3 (d) 2.8

उत्तर—(c)

प्रतिदर्श पंजीयन सर्वेक्षण (SRS), 2016 के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) 2.3 थी।

150. पी. सेनगुप्ता और जी. सदास्युक (1968) ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था?

- (a) 58  
(b) 63  
(c) 60  
(d) 65

उत्तर—(c)

रजिस्ट्रार जनरल ऑफ जनगणना (Census), भारत सरकार ने 1968 में डॉ. (मिस) पी. सेनगुप्ता और रशियन भूगोलवेत्ता डॉ. गलीना सदास्युक के अध्ययन पर आधारित एक प्रबंध (Mono-graph) प्रकाशित किया, जिसमें भारत को 4 दीर्घ (Macro), 11 बड़े (Mega) और 60 लघु (Micro) कृषि क्षेत्रों में बांटा गया था।

## विज्ञापन



## गुप्तकाल

13 अंकों में आविष्कार/खोज, 4 अंकों में राष्ट्रगान, 5 अंकों में संसद, 3 अंकों में मुद्राओं तथा 11 अंकों में धरातलीय आकृतियों के पश्चात अब ज्ञानिकी के तहत पृथक-पृथक शीर्षकों में जानकारीयां प्रदान की जा रही हैं, जिसके तहत परिवहन के विभिन्न घटकों, महासागरीय नितल के उच्चावच, स्थानीय पवन, आर्द्रता, कुहरा एवं बादल, वर्षा, चक्रवात, भूकंप, बाढ़ एवं सूखा, भारत की प्रमुख बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं, भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों/केंद्रों, पाषाण काल, हड़प्पा काल, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव, शैव, शाक्त धर्म, उत्तर भारत की राजनैतिक दशा (600 ई.पू.-325 ई.पू.), मौर्य साम्राज्य तथा मौर्योत्तर काल के विषय में तथ्यों को प्रस्तुत करने के बाद विगत अंक में गुप्तकाल के विषय में जानकारी प्रदान की गई थी, जिसे इस अंक में भी जारी रखा जा रहा है।

### □ कुमारगुप्त प्रथम

➔ कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक बना।

⊙ इसकी माता का नाम ध्रुवदेवी था।

➔ कुमारगुप्त के अब तक सर्वाधिक (लगभग 18) अभिलेख प्राप्त हुए हैं।

➔ बिलसद अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का प्रथम अभिलेख है।

⊙ इसमें कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है।

➔ करमदण्डा अभिलेख शिव प्रतिमा के अधोभाग में उत्कीर्ण है।

⊙ कुमारगुप्त के मंत्री पृथ्वीसेन ने इस प्रतिमा की स्थापना की थी।

➔ सांची अभिलेख में हरिस्वामिनी द्वारा सांची के आर्यसंघ को धन दान में दिए जाने का उल्लेख है।

➔ तुमैन अभिलेख (ग्वालियर, मध्य प्रदेश) में कुमारगुप्त को 'शरद कालीन सूर्य की भांति' कहा गया है।

➔ बंगाल के तीन स्थानों से कुमारगुप्त कालीन ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं।

⊙ ये ताम्रपत्र हैं-धनद्वैह ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र तथा वैग्राम ताम्रपत्र।

➔ कुमारगुप्त की स्वर्ण, रजत तथा ताम्र मुद्राएं प्राप्त होती हैं।

⊙ इसके शासनकाल में ही मध्य भारत में रजत (चांदी) सिक्कों का प्रचलन हुआ।

⊙ गरुड़ के स्थान पर इन मुद्राओं पर मयूर की आकृति प्राप्त होती है।

➔ इनके शासनकाल में विविध प्रकार की मुद्राएं प्राप्त होती हैं; ये हैं— अश्वारोही प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, अश्वमेध प्रकार, व्याघ्रनिहन्ता प्रकार, गजारोही प्रकार, कार्तिकेय प्रकार आदि।

⊙ मुद्राओं पर इनकी विविध उपाधियां मिलती हैं। ये उपाधियां हैं— श्रीमहेंद्र, अश्वमेधमहेंद्र, महेंद्रादित्य, महेंद्रसिंह आदि।

➔ कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा में बौद्ध महाविहार की स्थापना की गई।

➔ इसके शासन के अंतिम दिनों में 'पुष्यमित्र' नामक जाति ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया था।

### □ स्कंदगुप्त 'क्रमादित्य' (लगभग 455-467 ई.)

➔ स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम के पश्चात गुप्त शासक बना।

⊙ इसने लगभग 12वर्षों तक शासन किया।

⊙ इसके समय में हूणों ने आक्रमण किया, किंतु हूण पराजित हुए।

➔ भितरी स्तंभ लेख (गाजीपुर, उत्तर प्रदेश) में पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है।

➔ सुपिया के लेख (रीवा, मध्य प्रदेश) में गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है।

➔ जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त के समय सुराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल पर्णदत्त था।

⊙ इस लेख से ज्ञात होता है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण गिरनार के पुरपति चक्रपालित द्वारा कराया गया था।

➔ स्कंदगुप्त के स्वर्ण एवं रजत सिक्के प्राप्त हुए हैं।

⊙ उसके कुछ सिक्कों पर उसकी उपाधि 'क्रमादित्य' उत्कीर्ण है।

## ➔ स्कंदगुप्त के पश्चात गुप्त साम्राज्य

- ➔ स्कंदगुप्त के पश्चात पुरुगुप्त, गुप्त वंश का शासक बना।
  - ⊙ परमार्थकृत 'वसुबंधुजीवनवृत' से ज्ञात होता है कि पुरुगुप्त बौद्ध मतानुयायी था।
- ➔ स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में बुधगुप्त सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था।
  - ⊙ स्वर्ण मुद्राओं पर इसकी उपाधि 'श्रीविक्रम' मिलती है।
  - ⊙ दामोदरपुर ताम्रपत्र में इसे 'परमभट्टारक महाराजाधिराज' कहा गया है।
- ➔ ह्वेनसांग के विवरण से ज्ञात होता है कि बुधगुप्त बौद्ध मतानुयायी था।
  - ⊙ इसने नालंदा महाविहार को धन दान में दिया था।
- ➔ बुधगुप्त के पश्चात नरसिंहगुप्त शासक बना।
  - ⊙ भितरी मुद्रालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इसकी माता का नाम 'महादेवी चंद्रदेवी' था।
- ➔ नालंदा मुद्रालेख में नरसिंहगुप्त को 'परमभागवत' कहा गया है।
- ➔ सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरण से प्राप्त होता है।
  - ⊙ यह 510 ई. का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है।
- ➔ यह अभिलेख गुप्त शासक भानुगुप्त के समय का है।

## ➔ शासन व्यवस्था

- ➔ गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी।
- ➔ गुप्त शासक परमभट्टारक, महाराजाधिराज, एकराट, परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण करते थे।
- ➔ गुप्त शासक कार्यपालिका का प्रधान, न्याय का प्रधान न्यायाधीश एवं सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था।
- ➔ गुप्तकाल में सामंत तथा अधीन शासक 'महाराज' की उपाधि धारण करते थे।
- ➔ सामंत शासक अपने लेखों में अपने को 'पादानुध्यात' कहते थे।
- ➔ चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन उदयगिरि गुहालेख में 'सनकानिक महाराज' का उल्लेख हुआ है।

गुप्तकाल के प्रमुख पदाधिकारी	
महासेनापति	सेना का सर्वोच्च अधिकारी
महासांधिविग्रहिक	युद्ध एवं शांति का मंत्री
दण्डपाशिक	पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी
विनयस्थितिस्थापक	धर्म संबंधी मामलों का प्रधान अधिकारी
उपरिक	भुक्ति (प्रांत) के शासक
गोप्ता	सीमांत प्रदेशों के शासक
पुरपाल	नगर का प्रधान अधिकारी
भटाश्वपति	घुड़सवारों की सेना का प्रधान अधिकारी
महापीलुपति	हाथियों की सेना का प्रधान अधिकारी

➔ सामान्यतः राजा का बड़ा पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी चुना जाता था।

- ⊙ राजा के छोटे पुत्रों को प्रांतीय शासक नियुक्त किया जाता था।
- ⊙ कुमारगुप्त के छोटे भाई गोविंदगुप्त को मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था।
- ➔ प्रशासन की सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था।
- ➔ प्रांत को देश, अग्नि तथा भुक्ति कहा जाता था।
- ➔ गुप्त प्रशासन के प्रमुख प्रांत थे-मगध, सुराष्ट्र, पश्चिमी मालवा (अवंति), पूर्वी मालवा (एरण), पुण्ड्रवर्धन, तीरभुक्ति आदि।
- ➔ भुक्ति को अनेक जिलों में विभाजित किया गया था।
  - ⊙ जिला को 'विषय' कहा जाता था।
  - ⊙ इसका प्रधान अधिकारी 'विषयपति' कहलाता था।
- ➔ 'पुस्तपाल' कार्यालय के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को कहा जाता था।
- ➔ विषयपति, जिले का शासन एक समिति की सहायता से चलाता था। इसके सदस्य थे-

नगर श्रेष्ठि	नगर के महाजनों का प्रमुख
सार्थवाह	व्यवसायियों का प्रधान
प्रथम कुलिक	प्रधान शिल्पी
प्रथम कायस्थ	मुख्य लेखक

- ➔ जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि गिरनार नगर का 'पुरपाल' (नगर का प्रधान अधिकारी) चक्रपालित था।
  - ⊙ यह सुराष्ट्र के राज्यपाल पर्णदत्त का पुत्र था।
- ➔ शासन की सबसे छोटी इकाई 'ग्राम' थी।
  - ⊙ इसका प्रशासन 'ग्राम सभा' द्वारा चलाया जाता था।
  - ⊙ 'ग्राम सभा' को बिहार में 'ग्राम जनपद' तथा मध्य भारत में 'पंचमण्डली' कहा जाता था।
- ➔ गुप्तकालीन अभिलेखों में न्यायाधीशों को सर्वदण्डनायक, महादण्डनायक, दण्डनायक आदि कहा गया है।
- ➔ कुछ न्यायालयों की मुद्राएं भी वैशाली तथा नालंदा से प्राप्त हुई हैं।
  - ⊙ इन मुद्राओं के ऊपर धर्माधिकरण, न्यायाधिकरण तथा धर्मशासनाधिकरण अंकित है।
- ➔ फाह्यान के विवरण से ज्ञात होता है कि मृत्युदण्ड नहीं दिया जाता था।
- ➔ 'रणभाण्डगारिक' सेना के सामानों की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी था।
- ➔ 'अग्रहार' ब्राह्मणों तथा मंदिरों को दान में दी गई भूमि को कहते थे।
- ➔ 'ध्रुवाधिकरण' भूमि कर संग्रह करने वाला अधिकारी था।
- ➔ 'महाक्षपटलिक' तथा 'करणिक' नामक पदाधिकारी भूमि आलेखों को सुरक्षित रखते थे।
- ➔ भूमि संबंधी विवादों का निपटारा 'न्यायाधिकरण' नामक पदाधिकारी करते थे।



- ➔ 'उद्वंग' तथा 'भाग' भूमिकर था।
- ➔ 'शौल्किक' नामक पदाधिकारी सीमा शुल्क विभाग का अधीक्षक होता था।
- ➔ **सामाजिक जीवन**
- ➔ गुप्तकालीन समाज में परंपरागत चार वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र) के अतिरिक्त कुछ अन्य जातियां भी अस्तित्व में आ चुकी थीं।
- ➔ समाज में ब्राह्मणों का मुख्य कर्म धार्मिक एवं साहित्यिक था, परंतु कुछ ब्राह्मणों ने अपने पेशे को छोड़कर अन्य जातियों के पेशे को अपना लिया था।
- ➔ मृच्छकटिकम् गुप्तकालीन रचना है।
  - ⊙ इसमें चारुदत्त नामक ब्राह्मण को 'सार्थवाह' (व्यापारी) कहा गया है।
- ➔ बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि बहुसंख्यक ब्राह्मण व्यापार-वाणिज्य का कार्य करते थे।
  - ⊙ स्मृति ग्रंथों में इसे ब्राह्मण वर्ण का 'आपद्धर्म' कहा गया है।
- ➔ फाह्यान अछूतों को 'चाण्डाल' कहता है।
  - ⊙ उसके अनुसार, वे गांवों एवं नगरों के बाहर निवास करते थे।
- ➔ गुप्तकाल में कन्याओं का विवाह सामान्यतः 12-13 वर्ष की अवस्था में होता था।
- ➔ नारद और कात्यायन स्मृति के अनुसार, कन्या भी पिता की संपत्ति की अधिकारिणी थी।
- ➔ **आर्थिक जीवन**
- ➔ गुप्तकाल में कृषि की उन्नति पर विशेष ध्यान दिया गया था।
- ➔ वस्त्र उद्योग गुप्तकाल का सर्वप्रमुख उद्योग था।
  - ⊙ इसके अतिरिक्त अन्य उद्योग थे-मूर्तिकारी, चित्रकारी, हाथी दांत की वस्तुएं बनाना, शिल्प कार्य, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि।
- ➔ एक ही प्रकार के व्यवसाय/शिल्प का कार्य करने वाले लोगों की समिति को 'श्रेणी' कहते थे।
- ➔ पट्टवाय श्रेणी (रेशमी सूत बुनने वालों की समिति) का उल्लेख मन्दसौर के लेख में तथा तैलिक श्रेणी का उल्लेख इंदौर लेख में मिलता है।
- ➔ श्रेणियां बैंकों का भी कार्य करती थीं।
  - ⊙ बैंक के रूप में वे अपने सदस्यों को धन सूद पर देती थीं।
- ➔ प्रत्येक श्रेणी का एक प्रधान तथा चार या पांच सदस्यों वाली एक कार्यकारिणी होती थी।
- ➔ प्रत्येक श्रेणी की अपनी अलग मुहर होती थी।
- ➔ वैशाली से एक संयुक्त श्रेणी की 274 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं।
  - ⊙ इसमें व्यापारी, साहूकार और सौदागर सम्मिलित हैं।
- ➔ गुप्त शासकों ने सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के चलवाए।
  - ⊙ इस समय सोने तथा चांदी के सिक्कों का अनुपात 1:16 था।
  - ⊙ सामान्य लेन-देन कौड़ियों में होता था।

- ➔ गुप्तकाल में प्रमुख व्यापारिक नगर थे-पाटलिपुत्र, विदिशा, प्रतिष्ठान, भड़ौच, उज्जयिनी, मथुरा, अहिच्छत्र, ताम्रलिप्ति, प्रयाग, वैशाली, कौशाम्बी आदि।
- ➔ ताम्रलिप्ति बंदरगाह से चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था।
- ➔ भृगुकच्छ (भड़ौच) से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था।
- ➔ गुप्तकाल में निर्यात की प्रमुख वस्तुएं थीं-कपड़ा, हाथी दांत की वस्तुएं, नारियल, सुगंधित द्रव्य, पत्थर, नील, गरम मसाले, दवाएं आदि।
- ➔ व्यापारियों की समिति को 'निगम' कहा जाता था।
- ➔ व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान को सामान लेकर जाते समय समूह में चलते थे। इसे 'सार्थ' तथा इसके नेता को 'सार्थवाह' कहा जाता था।
- ➔ **धार्मिक जीवन**
- ➔ गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उनकी उपाधि 'परमभागवत' थी।
  - ⊙ वैष्णव धर्म के अनुयायी होते हुए भी गुप्त शासक धर्म सहिष्णु थे।
- ➔ समुद्रगुप्त ने वसुबंधु नामक बौद्ध विद्वान को अपने पुत्र की शिक्षा के लिए नियुक्त किया था।
- ➔ चंद्रगुप्त द्वितीय ने शैव वीरसेन तथा बौद्ध आम्रकार्दव को क्रमशः प्रधानमंत्री तथा प्रधान सेनापति नियुक्त किया था।
- ➔ फाह्यान बौद्ध धर्म का मतानुयायी था। इसने गुप्त शासकों की धार्मिक सहिष्णुता की प्रशंसा की है।
- ➔ पांच जैन तीर्थकरों की पाषाण प्रतिमाओं का निर्माण स्कंदगुप्त के शासनकाल में करवाया गया था।
- ➔ नालंदा में विख्यात बौद्ध विहार का निर्माण कुमारगुप्त के शासनकाल में ही हुआ था।

गुप्तकालीन प्रमुख पुस्तकें एवं उसके लेखक	
पुस्तक	लेखक
रघुवंश, कुमारसंभव, मेघदूत, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञानशाकुन्तलम	कालिदास
किरातार्जुनीय	भारवि
मृच्छकटिकम्	शूद्रक
अमरकोश	अमरसिंह
नीतिसार	कामन्दक
पंचतंत्र	विष्णु शर्मा
मुद्राराक्षस	विशाखदत्त
चांद्रब्याकरण	चंद्रगोमिन
आर्यभट्टीयम्	आर्यभट्ट
बृहत्संहिता, बृहज्जातक	वाराहमिहिर

➔ हरिषेण, वीरसेन शाब तथा वत्सभट्टि का नाम गुप्तकालीन कवियों में प्रमुख है।

☉ हरिषेण की प्रमुख कृति 'प्रयाग प्रशस्ति' है, जो गद्य-पद्य मिश्रित (चम्पू शैली) है।

☉ उदयगिरि गुहालेख में वीरसेन 'शाब' को 'शब्द, अर्थ, व्याकरण, न्याय, राजनीति आदि का मर्मज्ञ, कवि एवं पाटलिपुत्र का निवासी कहा गया है।

➔ वत्सभट्टि ने मंदसौर प्रशस्ति की रचना की।

☉ यह कुमारगुप्त प्रथम का दरबारी कवि था।

➔ आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, जिनकी प्रमुख कृति 'आर्यभटीयम्' है।

➔ आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है।

➔ पंचसिद्धान्तिका, लघुजातक वाराहमिहिर की कृति हैं।

➔ गुप्तकालीन धातु विज्ञान की प्रगति का प्रमाण चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली लौह स्तंभ है।

➔ **कला और स्थापत्य**

➔ गुप्तकाल में कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उन्नति हुई।

➔ भीतरगांव मंदिर का निर्माण ईंटों द्वारा किया गया है।

➔ अजंता की 16वीं, 17वीं तथा 19वीं गुफा गुप्तकालीन मानी जाती है।

गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर	
विष्णु मंदिर	तिगवां, मध्य प्रदेश
विष्णु मंदिर	एरण, मध्य प्रदेश
पार्वती मंदिर	नचना कुठार, मध्य प्रदेश
शिव मंदिर	भूमरा, मध्य प्रदेश
दशावतार मंदिर	देवगढ़, उत्तर प्रदेश
भीतरगांव मंदिर	कानपुर, उत्तर प्रदेश
लक्ष्मण मंदिर	मध्य प्रदेश

➔ 16वीं एवं 17वीं गुफा विहार तथा 19वीं गुफा चैत्य है।

➔ अजंता के समान बाघ पहाड़ी (म.प्र.) से नौ गुफाएं प्राप्त होती हैं।

☉ इनमें से कुछ गुप्तकालीन हैं।

➔ गुप्तकालीन तीन बौद्ध मूर्तियां उल्लेखनीय हैं।

☉ ये हैं-मथुरा की बुद्ध मूर्ति, सारनाथ की बुद्ध मूर्ति तथा सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति (वर्तमान में बर्मिंघम संग्रहालय में)।

➔ गुप्तकाल के चतुर्दिक विकास के कारण इतिहासकारों ने इस काल को 'स्वर्ण युग' की संज्ञा दी।

➔ गुप्तकाल को 'क्लासिकल युग' अथवा 'भारत का पेरीक्लीन युग' के नाम से भी जाना जाता है।

# विज्ञापन



- Q.** 10-12 अक्टूबर, 2018 के मध्य 'थोक बाजार विश्व संघ' (WUWM) का 33वां सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा?
- A.** गुरुग्राम, हरियाणा में।
- Q.** 10 अगस्त, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस एकल खिड़की एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को लांच किया, उसका क्या नाम है?
- A.** परिवेश (PARIVESH-Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive, Virtuous & Environmental Single-window Hub)।
- Q.** 10 अगस्त, 2017 को नीति आयोग ने द्वीपों के सर्वांगीण विकास के लिए निवेशकों का सम्मेलन (Investors' Conference) कहां आयोजित किया?
- A.** नई दिल्ली में।
- Q.** 'अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग' पुस्तक के लेखक कौन हैं?
- A.** डॉ. गौतम चटर्जी।
- Q.** 9 अगस्त, 2017 को राज्य सभा का उपसभापति कौन निर्वाचित हुआ?
- A.** हरिवंश नारायण सिंह।
- Q.** 8 अगस्त, 2018 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने 'भारतीय निर्यातक संगठन महासंघ' (FIEO) द्वारा विकसित कौन-सा ऐप लांच किया?
- A.** निर्यात मित्र मोबाइल ऐप।
- Q.** 7 अगस्त, 2018 को तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया। उनका नाम क्या था?
- A.** मुत्तुवेल करुणानिधि।
- Q.** वर्ष 2018 में पूरे देश में 'पर्यटन पर्व' का आयोजन कब किया जाएगा?
- A.** 16-27 सितंबर, 2018 के मध्य।
- Q.** अगस्त, 2018 में यूपी रेरा (UPRERA) का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया?
- A.** उ.प्र. के पूर्व मुख्य सचिव राजीव कुमार को।
- Q.** 3 अगस्त, 2018 को भारत कितने वर्षों की अवधि के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (AIBD) का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया?
- A.** 2 वर्षों के लिए।
- Q.** अगस्त, 2018 में प्रतिष्ठित 'फील्ड्स मेडल, 2018' से सम्मानित होने वाले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई गणितज्ञ कौन हैं?
- A.** अक्षय वेंकटेश।
- Q.** अगस्त, 2018 में हिंदी अकादमी, दिल्ली द्वारा किसे वर्ष 2017-18 के शलाका सम्मान से सम्मानित किया गया?
- A.** गीतकार जावेद अख्तर को।
- Q.** 31 जुलाई, 2018 को 'भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण' (IWAI) द्वारा कार्गो मालिकों एवं लॉजिस्टिक्स संचालकों को जोड़ने हेतु समर्पित पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल का क्या नाम है?
- A.** फोकल (FOCAL-Forum of Cargo-Owners and Logistics-Operators)।
- Q.** जुलाई, 2018 में पर्यटन संबंधी प्रमुख अमेरिकी पत्रिका ट्रैवल+लीसुर (Travel+Leisure) द्वारा जारी 'वर्ल्ड्स टॉप 15 सिटीज इनडेक्स' में तीसरा स्थान किस शहर का था?
- A.** उदयपुर (राजस्थान, भारत) का।
- Q.** 11 अगस्त, 2018 को किसने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया?
- A.** न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने।
- Q.** 3 अगस्त, 2018 को चीन द्वारा अपने प्रथम हाइपरसोनिक एयरक्रॉफ्ट का सफल परीक्षण किया गया। इसका क्या नाम है?
- A.** जिंगकांग-2 अथवा स्टारी स्काई-2 (Starry Sky-2)।
- Q.** 1 अगस्त, 2018 को असम और तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया। उनका क्या नाम था?
- A.** भीष्म नारायण सिंह।
- Q.** 'नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस' कब मनाया जाता है?
- A.** 18 जुलाई को।
- Q.** केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा ने राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का आरंभ कब किया?
- A.** 28 जुलाई, 2018 को।
- Q.** 25-27 जुलाई, 2018 के मध्य 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ?
- A.** जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में।
- Q.** 26 जुलाई, 2018 से झारखंड में कौन-सा टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया?
- A.** मीजल्स-रूबेला (MR) टीकाकरण अभियान।
- Q.** जुलाई, 2018 में 'वैश्विक दिव्यांगता शिखर सम्मेलन, 2018' कहां आयोजित किया गया?
- A.** लंदन में।
- Q.** जुलाई, 2018 में पहली बार भारतीय वायु सेना ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग लिया। इस अभ्यास का नाम क्या है?
- A.** पिच ब्लैक-18 अभ्यास।

- Q. 23-27 जुलाई, 2018 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन देशों की राजकीय यात्रा संपन्न की। ये तीन देश कौन-कौन से हैं?
- A. रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका।
- Q. 23 जुलाई, 2018 को केंद्र सरकार द्वारा मॉब लिंगिंग की समस्या से निपटने के लिए उपयुक्त समाधान सुझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया?
- A. केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में।
- Q. 21 जुलाई, 2018 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान की सर्वाधिक उन्नत प्रणाली 'सफर' का चांदनी चौक (दिल्ली) में उद्घाटन किया। 'सफर' का पूर्ण रूप क्या है?
- A. SAFAR-System of Air Quality and Weather Forecasting.
- Q. 18 जुलाई, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्तर प्रदेश में नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। यह मेडिकल कॉलेज कहां पर स्थापित किया जाएगा?
- A. सलेमपुर, देवरिया में।
- Q. 17 जुलाई, 2018 को केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जो एनसीसी (NCC) और एनएसएस (NSS) के सशक्तीकरण के उपाय सुझाएगी?
- A. पूर्व स्कूल शिक्षा सचिव अनिल स्वरूप की अध्यक्षता में।
- Q. 3-5 दिसंबर, 2018 के मध्य एटीटीए (ATTA : Adventure Travel Trade Association) द्वारा एडवेंचर नेक्स्ट, 2018' का आयोजन कहां किया जाएगा?
- A. भोपाल, मध्य प्रदेश में।
- Q. 16 जुलाई, 2018 को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले मशहूर हस्तियों की सूची, 2018 जारी की। इस सूची में भारत के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले सेलेब्रिटी कौन हैं?
- A. अक्षय कुमार (76वां स्थान, 40.5 मिलियन डॉलर)।
- Q. 10-15 जुलाई, 2018 के मध्य संपन्न थाईलैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला एकल स्पर्धा के फाइनल में किसने भारत की पी.वी. सिंधु को पराजित कर प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया?
- A. नोजोमी ओकुहारा (जापान) ने।
- Q. 15 जुलाई, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिर्जापुर (उ.प्र.) में कौन-सी नहर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की?
- A. बाणसागर नहर परियोजना।
- Q. भारत कितनी अवधि के लिए विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष बना?
- A. 2 वर्ष (जुलाई, 2018 से जून, 2020 तक) के लिए।
- Q. 12-15 जुलाई, 2018 के मध्य संपन्न घाना इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब किसने जीता?
- A. हरशील दानी (भारत) ने।
- Q. 14 जुलाई, 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्य सभा के लिए चार सदस्यों को मनोनीत किया। यह चार सदस्य कौन-कौन हैं?
- A. सोनल मानसिंह, रघुनाथ महापात्रा, राकेश सिन्हा और राम शकल।
- Q. 16 जुलाई, 2018 को केंद्र सरकार ने ताजमहल के आस-पास औद्योगिक प्रदूषण के मुद्दे के समाधान हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया?
- A. सी.के. मिश्रा (केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन सचिव) की अध्यक्षता में।
- Q. 15 जुलाई, 2018 को केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दंड प्रावधानों की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में एक दस सदस्यीय समिति गठित की?
- A. कॉरपोरेट मामले मंत्रालय के सचिव इंजेती श्रीनिवास की अध्यक्षता में।
- Q. 15-30 जुलाई, 2018 के मध्य हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में कौन-सा अभियान संचालित किया गया?
- A. सघन डायरिया नियंत्रण अभियान।
- Q. 14 जुलाई, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मंदुरी हवाई-पट्टी के निकट एक मैदान से किस एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास किया गया?
- A. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का।
- Q. वे भारतीय कौन हैं, जिन्हें वर्ष 2018 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई?
- A. भरत वाटवानी और सोनम वांगचुका।
- Q. 19 जुलाई, 2018 को भारत के एक प्रसिद्ध गीतकार एवं कवि का निधन हो गया। उनका नाम क्या था?
- A. गोपालदास नीरजा।
- Q. 6 जुलाई, 2018 को केंद्र सरकार द्वारा किसे 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (NGT) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया?
- A. उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल को।
- Q. 23 जुलाई, 2018 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नामित किया गया?
- A. सैयदा ताहिरा सफदर को।
- Q. 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन, 2018 का मुख्य विषय क्या है?
- A. हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति।
- Q. विश्व जनसंख्या दिवस (11 जुलाई), 2018 का मुख्य विषय क्या था?
- A. परिवार नियोजन एक मानव अधिकार है।
- Q. विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है?
- A. 28 जुलाई को।
- Q. वाराणसी नगर निगम परिसर में नवनिर्मित अंतरराष्ट्रीय सहयोग कन्वेंशन सेंटर 'रुद्राक्ष' किस देश के सहयोग से निर्मित किया गया है?
- A. जापान के।
- Q. 13 जुलाई, 2018 को भारत-चीन समुद्री मामलों पर द्वितीय वार्ता कहां संपन्न हुई?
- A. बीजिंग, चीन में।
- Q. 15 जुलाई, 2018 को प्रतिष्ठित 'संगीत कलानिधि पुरस्कार, 2018' के लिए किसे चुना गया?
- A. कर्नाटक संगीत की गायिका अरुणा साईराम को।
- Q. 14 जुलाई, 2018 को भारत ने विश्व में अपने सबसे बड़े वीजा केंद्र का उद्घाटन कहां किया?
- A. ढाका, बांग्लादेश में।

- Q. 19 जुलाई, 2018 को फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा वर्ष 2018 के सर्वाधिक प्रभावशाली युवा लोगों की वार्षिक सूची '40 अंडर 40' जारी की गई। इस सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ?
- A. केविन सिस्ट्रॉम (सह-संस्थापक एवं सीईओ इंस्टाग्राम) तथा मार्क जुकरबर्ग (सीईओ फेसबुक) को।
- Q. 19 जुलाई, 2018 को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने वर्ष 2022 में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में कितनी नई स्पर्धाएं शामिल किए जाने की घोषणा की है?
- A. सात नई स्पर्धाओं को।
- Q. 16 जुलाई, 2018 को ICC ने बॉल टेंपरिंग एवं खेल भावना के उल्लंघन के कारण किस देश की क्रिकेट टीम के कोच, कप्तान एवं मैनेजर को जुलाई-अगस्त, 2018 में द. अफ्रीका के साथ आयोजित दोनों टेस्ट मैचों तथा चार वनडे मैचों से निलंबन की सजा सुनाई?
- A. श्रीलंका के।
- Q. 26 जुलाई, 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छत्तीसगढ़ में किस योजना का शुभारंभ किया, जिसमें 50 लाख लोगों को निःशुल्क स्मार्ट फोन वितरित किया जाएगा?
- A. संचार क्रांति योजना का।
- Q. 25 जुलाई, 2018 को यूनिसेफ 18वां बाल फिल्म महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ?
- A. कोलकाता, प. बंगाल में।
- Q. देश का प्रथम सरकारी जिला अस्पताल कौन-सा है, जहां जुलाई, 2018 में प्रथम कॉक्लियर (Cochlear) इंप्लान्ट सर्जरी की गई?
- A. सेठ गोविंददास चिकित्सालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)।
- Q. जुलाई, 2018 में हरियाणा में बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम शीघ्र घोषित करने हेतु हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कौन-सी प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है?
- A. ऑनलाइन मार्क्स पंचिंग प्रणाली।
- Q. हरियाणा में पहला राजकीय कैंसर केयर सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है?
- A. सिविल अस्पताल, अंबाला छावनी में।
- Q. 24 जुलाई, 2018 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस मिशन का शुभारंभ किया, जिसके अंतर्गत महानदी, तेल और इब नदियों के तट पर कुल 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे?
- A. ग्रीन महानदी मिशन का।
- Q. 24 जुलाई, 2018 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कौन-सी योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत किसानों की आय में तीन से पांच गुना वृद्धि होने का अनुमान है?
- A. मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी सौर योजना को।
- Q. 16-22 जुलाई, 2018 के मध्य संपन्न अंतरराष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल स्पर्धा के फाइनल में भारत के रामकुमार रामनाथन को किसने पराजित कर खिताब जीत लिया?
- A. स्टीव जॉनसन (अमेरिका) ने।
- Q. 15 जुलाई, 2018 को संपन्न बैंक बीआरआई इंडोनेशिया ओपन, 2018 गोल्फ प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता?
- A. जस्टिन हार्डिंग (द. अफ्रीका) ने।
- Q. जुलाई, 2018 में संपन्न दक्षिण अफ्रीका ओपन शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता?
- A. सहज ग्रोवर (भारत) ने।
- Q. 11 जुलाई, 2018 को बीएसएनएल ने किस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से देश की पहली इंटरनेट टेलीफोन सेवा की शुरुआत की?
- A. मोबाइल एप्लीकेशन 'विंग्स' के माध्यम से।
- Q. 10 जुलाई, 2018 को उ.प्र. मंत्रिपरिषद की बैठक में मिट्टी का कार्य करने वाले कारीगरों व शिल्पियों के व्यवसाय में वृद्धि करने, तकनीकी विकास को बढ़ावा देने तथा विपणन आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक स्वशासी निकाय के रूप में कौन से बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया?
- A. उ.प्र. माटी कला बोर्ड के गठन का।
- Q. जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारतीय नागरिकों को शामिल करने के लिए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने कौन-सी वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है?
- A. 'जल बचाओ-वीडियो बनाओ-पुरस्कार पाओ' प्रतियोगिता।
- Q. 9 जुलाई, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जाई-इन ने कहाँ पर सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की एक मोबाइल उत्पादन यूनिट का उद्घाटन किया?
- A. नोएडा में।
- Q. 10 जुलाई, 2018 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) द्वारा जारी 'कारोबार में सुगमता' रैंकिंग में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले राज्य कौन-कौन हैं?
- A. क्रमशः आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं हरियाणा।
- Q. जुलाई, 2018 में भारतीय रेलवे ने पश्चिमी रेलवे के राजकोट डिवीजन से कौन-सी प्रथम कंटेनर सेवा का शुभारंभ किया?
- A. डबल स्टैक डुवार्फ कंटेनर सेवा का।
- Q. 8 जुलाई, 2018 को मेघालय के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया। उनका नाम क्या था?
- A. एम.एम. जैकब।
- Q. 9-10 जुलाई, 2018 के मध्य किस मंत्रालय ने 'नया भारत के लिए डाटा' पर एक अंतरराष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया?
- A. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने।
- Q. 9 जुलाई, 2018 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहाँ पर ज़ोन एप्लीकेशन अनुसंधान केंद्र एवं साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया?
- A. देहरादून में।
- Q. 9 जुलाई, 2018 को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एचसीएल टेक्नोलॉजी के आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र को कहाँ स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की?
- A. विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में।

सम-सामयिक **घटना चक्र**

अतिरिक्तांक



**G S**

**प्वाइन्टर**

(पूर्वावलोकन सार)

निःशुल्क

सितम्बर, 2018

अंक के साथ

**आर्थिक एवं**

**सामाजिक विकास**

शृंखला का अगला अंक - **राज्य आधारित**

# GS प्वाइंटर

## सामान्य अध्ययन

2017, अगस्त माह से सम-सामयिक घटना चक्र मुख्य पत्रिका के साथ निःशुल्क अतिरिक्तांक की शृंखला प्रारंभ की गई है। शृंखला में सामान्य अध्ययन के विभिन्न विषयों पर GS 'प्वाइंटर' क्रमशः प्रस्तुत किया जाएगा।

## आर्थिक एवं सामाजिक विकास

### A. आर्थिक विकास

#### राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास

- \* किसी देश की आर्थिक संवृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है  
—प्रति व्यक्ति वास्तविक आय
- \* किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है —प्रति व्यक्ति आय से
- \* सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) है —राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन
- \* किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय  
—किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी
- \* कथन (A) : आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है।  
कारण (R) : वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।  
—(A) सही है, किंतु (R) गलत है।
- \* मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है— जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो
- \* भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है —मिश्रित अर्थव्यवस्था

- \* भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है  
—मिश्रित अर्थव्यवस्था पर
- \* यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए  
—एक श्रम-आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में
- \* भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है —कृषि की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय तथा वृहद बेरोजगारी
- \* देश की वृद्धि में अनार्थिक तत्व है —सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, अंतरराष्ट्रीय घटक तथा वैज्ञानिक घटक आदि।
- \* 1951-52 से 2015-16 की अवधि में स्थिर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सर्वाधिक रही —वर्ष 2007-08 में
- \* भारतीय अर्थव्यवस्था ने सर्वाधिक संवृद्धि दर प्राप्त की है  
—वर्ष 2006-07 में (9.6%)
- \* वर्ष 2015-16 में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर राज्यों का अवरोही क्रम है  
—महाराष्ट्र > गुजरात > पंजाब > उत्तर प्रदेश
- \* वर्ष 2015-16 में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु राज्यों का उनके प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (Per Capita Net State Domestic Product) के संदर्भ में अवरोही क्रम (Descending Order) है —महाराष्ट्र > कर्नाटक > गुजरात > तमिलनाडु

- \* वर्तमान में भारत के राज्यों में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है  
—बिहार की
- \* वर्तमान में भारतीय राज्यों में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है  
—गोवा की
- \* वर्तमान में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा हरियाणा में से औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है  
—हरियाणा की
- \* कथन (A): यद्यपि 1947 के बाद की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ गई है, परंतु प्रति व्यक्ति आय स्तर में कोई सुदृष्ट सुधार नहीं हुआ है।  
कारण (R): भारत की जनता का काफी बड़ा भाग अब भी गरीबी की रेखा के नीचे रह रहा है। —(A) गलत है, परंतु (R) सही है।
- \* भारत में ग्रामीण आय प्रायः नगरीय आय से कम है। इसके लिए कारण जिम्मेदार हैं  
—किसानों की निरक्षरता, वैज्ञानिक कृषि का नगण्य ज्ञान, विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का कम मूल्य तथा उद्योगों की तुलना में कृषि में कम निवेश
- \* भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है। इसका मुख्य कारण है  
—उच्च पूंजी-उत्पाद अनुपात, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर आदि
- \* उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के कारणों में शामिल हैं—  
—तेजी से बढ़ती जनसंख्या, साहसीपन का अभाव तथा अपर्याप्त अधो: संरचनात्मक सुविधाएं आदि
- \* किसी देश में आर्थिक संवृद्धि अनिवार्य रूप से होगी, यदि उस देश में होता है  
—पूंजी निर्माण
- \* भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी संवृद्धि दर कम होने का कारण है  
—पूंजी-उत्पाद अनुपात का अधिक होना
- \* श्रम की न्यून कार्यक्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर और प्राकृतिक संसाधनों की कमी में से एक लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है  
—प्राकृतिक संसाधनों की कमी
- \* वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारतीय आर्थिक संवृद्धि दर है, लगभग  
—6.5 प्रतिशत
- \* अगस्त, 2018 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018-2019 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर है  
—7.4 प्रतिशत
- \* भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय (Per Capita Income) में धीमी वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहे —जनसंख्या में तेज वृद्धि, मूल्यों में भारी वृद्धि के साथ ही कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी गति
- \* एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय (Y) है  
—C+I+G+(X-M)
- \* रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अगस्त, 2018 की मौद्रिक नीति के अनुसार, 2018-19 में विकास दर संभावित है  
—7.4 प्रतिशत
- \* एशियाई विकास रिपोर्ट-2018 के अनुसार, वर्ष 2017 में भारत की संवृद्धि दर थी  
—6.6 प्रतिशत
- \* यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाएं, तो वास्तविक आय  
—अपरिवर्तित रहेगी
- \* वर्तमान मूल्यों (Current Prices) पर प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) की वृद्धि दर (Growth Rate) स्थिर मूल्यों (Constant Prices) पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है  
—मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का
- \* 1867-68 ई. में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया-  
—दादाभाई नौरोजी ने
- \* भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया  
—दादाभाई नौरोजी द्वारा
- \* वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे  
—पी.सी. महालनोबिस
- \* भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किया जाता है  
—केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (CSO) द्वारा
- \* भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम करता है  
—भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन
- \* नई जी.डी.पी. आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-05 के स्थान पर बदलकर कर दिया गया है  
—वर्ष 2011-2012
- \* इस समय (2015 से) भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है  
—वर्ष 2011 - 12
- \* भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है-  
—भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा
- \* सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है, तो ध्यान में रखा जाता है  
—सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि
- \* भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू बचत (सकल) की औसत दर वर्तमान में आकलित की गई है  
—30 से 40 प्रतिशत के पास
- \* वर्ष 2015-16 में भारत की सकल घरेलू बचत दर  
—32.3 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद का
- \* भारत में बचत में सर्वाधिक योगदान करता है  
—घरेलू क्षेत्र
- \* भारत में घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा है—भौतिक परिसंपत्तियों का



- \* भारत में निम्नलिखित चार प्रमुख क्षेत्रों से बचत का उदय होता है भारत में सकल घरेलू बचत में 1. गृहस्थ, 2. निजी निगम क्षेत्र, 3. सार्वजनिक निगम एवं अन्य लोक उपक्रम तथा 4. सरकार क्षेत्रों के योगदान का अवरोही क्रम है —**गृहस्थ क्षेत्र, निजी निगम क्षेत्र तथा सार्वजनिक निगम/लोक उपक्रम एवं सरकारी क्षेत्र**
- \* भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नांकित कथन है —**इसे जन-उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए।**
- \* यह विचार कि " भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए " व्यक्त किया गया था —**अमर्त्य सेन द्वारा**
- \* हिंदू वृद्धि दर संबंधित है —**राष्ट्रीय आय से**
- \* अवस्फीति के साथ, स्फीति के साथ, स्टैगप्लेशन के साथ तथा अतिस्फीति के साथ में से आर्थिक विकास सामान्यतया युग्मित होता है —**स्फीति के साथ**
- \* GNP (सकल राष्ट्रीय उत्पाद) में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण है —**कीमतों की तुलना में मजदूरी का कम होना**
- \* सही सुमेलित हैं-
 

<b>आर्थिक विकास</b>	-	<b>संरचनात्मक परिवर्तन</b>
<b>आर्थिक वृद्धि</b>	-	<b>सकल घरेलू उत्पाद</b>
<b>संपोषित विकास</b>	-	<b>पर्यावरण</b>
<b>जीवन की गुणवत्ता</b>	-	<b>स्वास्थ्य</b>
- \* भारत की अर्थव्यवस्था है —**विकासशील**
- \* भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है —**एक विकासशील अर्थव्यवस्था**
- \* सत्य कथन है —**सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत एक दशक में कमी आई है।**
- \* तेल क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र न्यायिक प्रणाली का तथा शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं आदि के सुधारों में से आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन (जेनरेशन) में सरकार द्वारा विहित किए गए सुधारों का भाग नहीं है —**न्यायिक प्रणाली में सुधार**
- \* वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी —**उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण**
- \* भारत में आर्थिक उदारीकरण (Economic Liberalisation) शुरू हुआ —**औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ**

- \* भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने का एक कारण है —**आर्थिक विकास के लिए कृषि से उद्योग की दिशा में अंतरण के महत्व की जनता को अधिकतर जानकारी नहीं है।**
- \* भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति के दो घटकों-स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के विषय में सही कथन हैं —**संरचनात्मक समायोजन क्रमिक, बहुपद प्रक्रम है, जबकि स्थिरीकरण त्वरित अनुकूलन प्रक्रम है**
- \* भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत (पायनियर) कहा जाता है —**डॉ. मनमोहन सिंह को**

## सतत आर्थिक विकास

- \* धारणीय विकास, भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है —**धारण क्षमता के साथ**
- \* सतत विकास का आधार है —**पर्यावरणीय दृष्टिकोण**
- \* सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय है —**वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ-साथ भविष्य का आर्थिक विकास**
- \* स्थायी विकास अंतर-पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है —**प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में**
- \* मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है —**कुशलता में विकास**
- \* समावेशी संवृद्धि के लिए आवश्यक हैं —**अधो-संरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता**
- \* राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, ग्रामीण विकास, कृषि विकास तथा कृषकों को पर्याप्त साख में से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है —**राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से**
- \* आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार 'धारणीय विकास और जलवायु-परिवर्तन' का नवीन अध्याय जोड़ा गया था —**वर्ष 2011-12 में**
- \* मूलतः 'समावेशी शासन' के अंग कहे जा सकते हैं —**सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना, जन-स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोत्तरी करना तथा 'दोपहर का भोजन' योजना का सशक्तीकरण करना**
- \* समावेशी शासन से तात्पर्य है कि —**समाज के सभी वर्गों को समान रूप से शासन के द्वारा प्रदत्त सुविधाएं प्रदान की जाएं।**

- \* आर्थिक विकास से संबद्ध जनांकिकीय संक्रमण की विशिष्ट अवस्थाओं का सही क्रम है  
—उच्च मृत्यु-दर के साथ उच्च जन्म-दर,  
निम्न मृत्यु-दर के साथ उच्च जन्म-दर  
तथा निम्न मृत्यु-दर के साथ निम्न जन्म-दर

## कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

- \* भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है  
—17.4 प्रतिशत (2016-17 में)
- \* राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के 2014 के अनुमानानुसार, ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत है  
57.8%
- \* भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है  
—लगभग 60 प्रतिशत
- \* विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है  
—कृषि निर्यात का संवर्धन
- \* उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं  
—कृषि क्षेत्र में
- \* भारत के श्रमिक बल में प्रायः अपने जीवनयापन के लिए वर्तमान में कृषि पर निर्भर हैं  
—लगभग 60 प्रतिशत
- \* विकास का भारतीय मॉडल सुरक्षा करता है  
—व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों का
- \* आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा  
—निरंतर कम होता रहा है
- \* जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह तथा अबुल कलाम आजाद में से भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था  
—चरण सिंह
- \* जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार तथा बहुफसलीय योजना में से भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है  
—बहुफसलीय योजना
- \* 'सोयाबीन' खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है  
—मध्य प्रदेश में
- \* तंबाकू, कपास, सोयाबीन तथा रबर में से एक नकदी फसल नहीं है  
—सोयाबीन
- \* कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन (2017) विश्व में सर्वाधिक है  
—ऑस्ट्रेलिया में
- \* गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था है  
—ताज निकलने की अवस्था

- \* देश में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम है  
—उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब
- \* भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ  
—1985 में
- \* व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई-  
—वर्ष 1999 में
- \* राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया  
—बजट 2004-05 में
- \* उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी  
—वर्ष 1992 में
- \* कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में शुरू किया गया था  
—जल उपयोग दक्षता विकास के लिए
- \* हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है  
—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से
- \* उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है  
—लखनऊ में
- \* आठवीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था, वह संख्या है  
—15
- \* राष्ट्रीय हॉर्टीकल्चर मिशन आरंभ किया गया था  
—5 मई, 2005 से (दसवीं पंचवर्षीय योजना में)
- \* राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) से आच्छादित है  
—पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर तथा उत्तराखंड) सहित देशभर के 18 राज्य और 4 केंद्रशासित प्रदेश (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी तथा दादरा और नगर हवेली)
- \* 'राष्ट्रीय बागवानी मिशन' का उद्देश्य है  
—बागवानी क्षेत्र में ऊंची संवृद्धि प्राप्त करना, शस्योत्तर व्यवस्था करना तथा मानव संसाधन विकास करना
- \* 1 जुलाई, 2001 से प्रारंभ कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है  
—पेंशन तथा बीमा लाभ
- \* 'लघु कृषक-विकास योजना' आरंभ की गई  
—वर्ष 1971 से
- \* गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत (FRP) को अनुमोदित करता/करती है  
—आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति
- \* वर्ष 1997-98 के बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में सत्य है  
—न्यूनतम समर्थन मूल्य > C2 लागतें
- \* 'कृषि लागत और कीमत आयोग' (CACP) वर्तमान में MSP के अंतर्गत घोषणा करता है  
—कुल 23 फसलों के मूल्यों की
- \* 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' प्रारंभ हुआ था  
—वर्ष 2007-08
- \* अक्टूबर, 2007 में प्रारंभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) का उद्देश्य है  
—धान, गेहूं और दलहन के उत्पादन में बढ़ोत्तरी, मृदा उत्पादकता और उर्वरता का संरक्षण तथा खेत के स्तर पर आर्थिक लाभ को बढ़ाना, ताकि किसानों में आत्मविश्वास पैदा हो सके

- \* राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत फसलें सम्मिलित हैं  
—चावल,गेहूँ, दलहन, मोटे अनाज व वाणिज्यिक फसलें
- \* भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रभावी हुआ  
—वर्ष 2007-08 की रबी फसल से
- \* भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है, लगभग  
—14.01 करोड़ हेक्टेयर
- \* भारतीय कृषि उत्पादन ने ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई है  
—वर्ष 2004-05 (-1.6%), 2009-10 (-4.0%),  
2012-13 (-2.0%) तथा वर्ष 2014-15 (-0.2%) में
- \* वह पंचवर्षीय योजना जिसमें कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया  
—तीसरी पंचवर्षीय योजना में
- \* भारत की औसत फसल गहनता है, लगभग —139%
- \* 'नीली क्रांति' संबंधित है —मत्स्य उत्पादन से
- \* पीत क्रांति या 'पीली क्रांति' संबंधित है  
—तोरिया-सरसों उत्पादन से (तिलहन)
- \* विश्व में 'हरित क्रांति के जनक' हैं —नॉर्मन ई. बोरलॉग
- \* भारतीय 'हरित क्रांति' की जन्मस्थली है —पंतनगर
- \* सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है —इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके
- \* ऑपरेशन फ्लड का संबंध है —दुग्ध उत्पादन से
- \* ऑपरेशन फ्लड-II का संबंध है —दुग्ध आपूर्ति से
- \* 1950-90 की अवधि में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर तीन गुने से अधिक हो गया है, फिर भी सही अर्थ में आत्मनिर्भरता, जिसका तात्पर्य है भूख से मुक्ति, नहीं प्राप्त की जा सकी है। इसके कारण हैं  
—हरित क्रांति का देश के छोटे-छोटे खंडों तक ही सीमित रहना, गरीबों की कमाई की तुलना में खाद्य के भाव का बहुत अधिक होना तथा मोटे अनाजों की तुलना में गेहूँ और धान पर अत्यधिक बल देना
- \* हरित क्रांति से भारत के सर्वाधिक लाभांशित राज्य हैं  
—पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश
- \* प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित हैं  
—भारतीय कृषकों को सार्वभौमिक (ग्लोबल) कृषि व्यापार में सहभागिता, फसल पश्चात खाद्यान्न में क्षति को कम से कम करना तथा फसलों के भंडारण में सुधार
- \* कृषि करने की वह प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है  
—जैविक खेती
- \* कथन (A) : भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है।  
कारण (R) : अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता है।  
—(A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
- \* भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है —खाने योग्य तेल
- \* निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है —अलफांजो
- \* भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (एनएएफईडी) संबंधित है—  
—कृषि विपणन से
- \* राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है  
—नेफेड (NAFED)
- \* 'गहन कदन्न संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल' (Initiative for Nutritional Security Through Intensive Millets Promotion) का उद्देश्य है —उन्नत उत्पादन और कटाई-उपरांत प्रौद्योगिकियों को निदर्शित करना एवं समूह उपागम (कलस्टर अप्रोच) के साथ एकीकृत रीति से मूल्यवर्धन तकनीकों को निदर्शित करना
- \* भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को विनियमित किया जाता है  
—राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम से
- \* संघ सरकार के 2011-12 के बजट में किसानों के लिए बैंक ऋण के समयानुसार भुगतान पर प्रभावी ब्याज दर है —4 प्रतिशत
- \* किसी फार्म के चल लागत पूंजी में बीज, उर्वरक, सिंचाई जल तथा भूमि-राजस्व में से एक शामिल नहीं है —भूमि राजस्व
- \* कृषि वित्त के प्रमुख सिद्धांत हैं —उद्देश्य, व्यक्ति, उत्पादकता नियोजन तथा संगठन आदि।
- \* भारत में कृषि वित्त के स्रोतों को बांटा जाता है —दो वर्गों में  
(A) संस्थागत स्रोत- (i) सहकारी समितियां एवं बैंक, (ii) व्यापारिक बैंक, (iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, (iv) सरकार (B) गैर-संस्थागत स्रोत —महाजन तथा साहूकार, संबंधी और रिश्तेदार, व्यापारी, जमींदार, आढ़तिए आदि।
- \* किसानों को उनकी अल्पावधि और दीर्घावधि आवश्यकताओं के लिए अनेक स्रोतों से ऋण प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाले ऋण के मुख्य स्रोतों में सम्मिलित हैं  
—प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और गैर-सरकारी उधारदाता
- \* दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है—भूमि विकास बैंक द्वारा
- \* हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत रहा  
—वाणिज्यिक बैंक

- \* भारत में कृषि-साख के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम है  
—वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- \* कृषि तथा संबंधित क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर रहा है  
—विदेशी निजी बैंक
- \* "...लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों में, जो वास्तव में काम करते हैं, परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना भर देना" उपर्युक्त अंश संबंधित है  
—सामुदायिक विकास से
- \* "भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है, परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की है" कथन का तात्पर्य है  
—खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है, परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं है।
- \* भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए प्रभावी कारण है  
—ग्रामीण निर्धनता
- \* सुमेलित हैं-  
बड़े सामंतों को आवंटित भूमि - जागीरदारी प्रणाली  
मालगुजारी के इजारेदारों अथवा - जमींदारी प्रणाली  
तहसीलदारों को आवंटित भूमि  
उप-किराएदारी पर देने, - रैयतवाड़ी प्रणाली  
गिरवी रखने, हस्तांतरण करने,  
उपहार देने या विक्रय करने के  
अधिकार सहित प्रत्येक किसान  
को आवंटित भूमि  
ग्राम्य स्तर पर की गई भू-राजस्व - महलवाड़ी प्रणाली  
बंदोबस्त
- \* बजट 2018-19 के अनुसार, खाद्यान्न पर दिया जाने वाला अनुदान है  
—292824.89 करोड़ रुपये (GDP का 9%)
- \* कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) के उद्देश्य हैं  
—कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, कृषकों के लिए सार्थक  
वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चय तथा लोक वितरण  
पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित  
दरों पर उपलब्ध करवा कर उनके हितों की रक्षा करना।
- \* समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित  
करती है  
—कृषि मूल्यों में स्थिरता, कृषकों को प्रेरणादायक  
मूल्य तथा सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडारण
- \* न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में सही कथन है-  
—यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम  
मूल्य सुनिश्चित करते हुए खाद्य सुरक्षा मिशन में  
सहायता प्रदान करती है।
- \* कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई, वर्ष  
—1965 में
- \* गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है  
—कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
- \* खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है  
—कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
- \* मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है  
—अधिप्राप्ति मूल्य (Procurement Prices)
- \* सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के  
निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है, वे  
जानी जाती हैं  
—वसूली कीमतों के नाम से
- \* विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है  
—चीन
- \* भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है—  
—वाराणसी में
- \* वर्ष 2016-17 में भारत में निर्यातित प्याज की मात्रा थी, लगभग  
—24.16 लाख टन
- \* भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य है—कर्नाटक
- \* मूंग, मसूर, उड़द, मटर तथा अरहर दलहनों में से वर्ष 2016-17 में  
सर्वाधिक आयात किया गया था  
—मटर (49.02%)
- \* वर्तमान में देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाला कृषि  
उत्पाद है  
—कच्ची कपास
- \* खली, कच्ची कपास, चावल तथा मसाले में से भारत के कृषि निर्यात की  
सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है  
—कच्ची कपास
- \* सुनहले चावल में प्रचुरता सृजित की गई है  
—विटामिन 'ए' की
- \* राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना (NATP) का पोषण, भारत में जिस  
अंतरराष्ट्रीय वित्तप्रदायी अभिकरण द्वारा होता है, वह है  
—विश्व बैंक
- \* 13 जनवरी, 2016 को घोषित 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' बीमाकृत  
करती है  
—चक्रवात एवं गैर-मौसमी वर्षा से होने  
वाले कटाई-उपरांत घाटे को
- \* खरीफ 2007 मौसम-आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की  
गई थी  
—कर्नाटक में
- \* विश्व में एकमात्र देश जो रेशम के ज्ञात सभी पांच व्यापारिक प्रकार  
उत्पादन करता है  
—भारत
- \* भारत विश्व में चीनी का उत्पादक है  
—दूसरा सबसे बड़ा
- \* भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण हैं  
—जनसंख्या का  
दबाव, प्रछन्न बेरोजगारी तथा भू-जोत का छोटा आकार
- \* भारत की काली मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है  
—कपास की फसल उत्पादन के लिए

## उद्योग क्षेत्र

- \* भारत की सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है —चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने हेतु
- \* भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व है —राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा खाद्यान्न आपूर्ति के लिए
  - \* 1- भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ की गई,
  - \* 2- उत्तर प्रदेश में शस्य-जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या 9 है,
  - \* 3- काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ किया गया,
  - \* 4- तथा नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है।
- उपर्युक्त कथनों में सभी सत्य हैं।
- \* 'हरियाली योजना' संबंधित है —जल प्रबंधन से
- \* 'विशेष कृषि उपज योजना' का संबंध है —कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल (थ्रस्ट) से
- \* 'राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना' मुख्य रूप से संबंधित है —निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से
- \* 'राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम' प्रारंभ किया गया था —वर्ष 2008 में
- \* भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम आरंभ किया गया था —वर्ष 2011-12 में
- \* भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है—राज्य सरकारों द्वारा
- \* कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है —स्थायकत्वहीन (लोचहीन)
- \* किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था —वर्ष-1998-99 में
- \* किसान क्रेडिट कार्ड योजना —किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है।
- \* भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी —पंतनगर में
- \* केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है —मैसूर में
- \* नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट (NAARM) स्थित है —हैदराबाद में
- \* भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है —झांसी में
- \* वर्ष 2000 में 'नीरू-मीरू' जल संग्रहण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था —आंध्र प्रदेश में
- \* कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग उदाहरण है —पूँजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकीय प्रगति का
- \* वर्ष 2017-18 में भारत की जी.वी.ए. में उद्योग का अंश —25 से 30 प्रतिशत के मध्य था
- \* सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार, मध्यम उद्यम के रूप में उसे परिभाषित किया जाता है, जिसकी निवेश राशि होती है —रु. 5 करोड़ से रु. 10 करोड़ तक
- \* 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी। ये आलोचनाएं हैं —अनिश्चित औद्योगिक विकास, विदेशी प्रतियोगिता से खतरा तथा विदेशी निवेश में गलत विश्वास
- \* वर्ष 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश की सीमा है —क्रमशः 25 लाख एवं 10 लाख रुपये
- \* सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (एमएसएमईडी) पारित हुआ —वर्ष 2006 में
- \* जोखिम पूंजी से तात्पर्य है —नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी
- \* कथन (A) : अद्यतन अनेक भारतीय उद्योगों ने ISO-9001 तथा ISO-9002 प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिए हैं।
- कारण (R) : भारत सरकार की लाइसेंसिंग प्रणाली में काफी उदारता आई है। —(A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- \* स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी —वर्ष 1948 में
- \* भारत में औद्योगिक विकास हेतु 'संयुक्त क्षेत्र' का विचार रखा गया —1956 की औद्योगिक नीति में
- \* वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार, लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था —18 उद्योगों को
- \* अब उन उद्योगों की संख्या, जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है, घट कर रह गई है —5 उद्योग
- \* उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई —प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा वर्ष 1991 में
- \* भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में, औद्योगीकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधुनिक संरचनाओं (इन्फ्रास्ट्रक्चर) पर बल देने की शुरुआत की गई —आठवीं पंचवर्षीय योजना से

- \* भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार था  
—उद्योग अधिनियम, 1951
- \* 31 मार्च, 2016 को पंजीकृत कारखानों की संख्या सर्वाधिक थी  
—तमिलनाडु में
- \* कुछ समय पहले भारत सरकार ने 'व्हाइट गुड्स' उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया, 'व्हाइट गुड्स' में सम्मिलित हैं  
—प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं
- \* कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं  
—यमुना नगर, गुवाहाटी तथा बल्लारपुर
- \* 1. भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा गैर-तेल आयातक है।  
2. भारतीय परियोजना एवं उपस्कर निगम लिमिटेड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है।  
—उपर्युक्त कथनों में दोनों कथन सत्य हैं।
- \* भारत में मिल-निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है  
—गुजरात से
- \* A. R.I.L. भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है।  
B. N.Y.S.E. में M.T.N.L. सूचीबद्ध है।  
C. B.S.N.L. भारत में प्रथम ऐसा सेवा संस्थान है जिसने एक ही समय में देशव्यापी सेलुलर सेवा शुरू की।  
—भारत के संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं
- \* कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है —अभिदत्त पूंजी पर
- \* कंपनी के तुलन-पत्र से बताना संभव है —कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं के आकार और संघटन को
- \* एफ.एम.सी.जी. (फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स) में शामिल नहीं किया जाता है —स्वचालित वाहन (कार व मोटरसाइकिल) को
- \* सही सुमेलित हैं—  
(उद्योग) (औद्योगिक केंद्र)  
पर्ल फिशिंग - तूतीकोरिन  
ऑटोमोबाइल्स - पुणे  
पोत निर्माण - मर्मुगावो  
इंजीनियरी सामान - पिजौर
- \* निजीकरण की सर्वाधिक सर्वांगीण और परिपूर्ण रीति है  
—निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण
- \* भारत सरकार की वर्तमान विनिवेश नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं—  
—सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नागरिकों को हिस्सेदारी प्रदान करना; सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार का प्रबंधन पर नियंत्रण और बहुमत शेयरधारिता (कम से कम 51%) बनाए रखना; तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करना।
- \* वर्ष 2005 में गठित 'राष्ट्रीय निवेश निधि' (NIF) का मुख्य उद्देश्य है  
—सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करना
- \* द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में भिलाई इस्पात कारखाना बनाया गया  
—रूस के सहयोग से
- \* राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी—जर्मनी के सहयोग से
- \* सही सुमेलित हैं—  
(इस्पात संयंत्र) (सहयोगी देश)  
राउरकेला - जर्मनी  
भिलाई - पूर्व यू.एस.एस.आर.  
दुर्गापुर - यू.के.  
बोकारो - यू.एस.एस. आर
- \* सही सुमेलित हैं—  
भिलाई - छत्तीसगढ़  
बोकारो - झारखंड  
दुर्गापुर - पश्चिम बंगाल  
राउरकेला - ओडिसा
- \* भारतीय हीरा संस्थान स्थापित किया गया है —सूरत में
- \* सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं—भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (भोपाल),  
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री (जबलपुर) तथा एल्केलॉयड फैक्ट्री (नीमच)
- \* बी.एस.एन.एल. की स्थापना हुई थी —वर्ष 2000 में
- \* भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं  
—बामर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन  
ऑफ इंडिया तथा एजुकेशनल कन्सल्टैंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड
- \* वर्तमान में लघु उद्योग क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश (फॉरेन इक्विटी होल्डिंग) की निर्धारित सीमा है  
—100 प्रतिशत
- \* सही सुमेलित हैं—  
(स्थान) (औद्योगिक केंद्र)  
विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) - पोत - निर्माण  
मूरी (झारखंड) - एल्युमीनियम  
गुड़गांव (हरियाणा) - मोटर गाड़ियां  
पनकी (उत्तर प्रदेश) - उर्वरक
- \* सही सुमेलित हैं—  
(केंद्र) (उद्योग)  
आंवला - उर्वरक  
मोदीनगर - रबर  
बाराबंकी - पॉली फाइबर  
कानपुर - विस्फोटक

- \* सही सुमेलित हैं-
 

बायो-टेक्नोलॉजी पार्क	-	लखनऊ
ट्रोनिका सिटी	-	गाजियाबाद
प्लास्टिक सिटी	-	कानपुर
लेदर टेक्नोलॉजी पार्क	-	उन्नाव
- \* उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की है —आबिद हुसैन समिति ने
- \* आबिद हुसैन समिति का संबंध था —लघु एवं मध्यम उद्योग से
- \* वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2016-17 में भारत की औद्योगिक विकास दर थी —5.6 प्रतिशत
- \* 'प्रारंभ में स्टार्ट-अप की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए नए युग के वित्तीय विकल्पों' हेतु सलाह दी है- —प्रणव मुखर्जी ने
- \* भारत सरकार की एक पहल 'SWAYAM' का लक्ष्य है
  - नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना
- \* 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का लोगो है —शेर
- \* प्रधानमंत्री MUDRA योजना का लक्ष्य है
  - लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना
- \* 'उद्यमी' हेल्पलाइन स्थापित की गई है
  - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए
- \* 8 अप्रैल, 2015 से प्रारंभ भारत सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य है
  - छोटे व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
- \* 1. इसका प्रयोजन SC/ST एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है।
- 2. यह SIDBI के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है।
- स्टैण्ड अप इंडिया के संदर्भ में —उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं।
- \* राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की गई है —रुण लघु उद्योगों की पुनःसंरचना तथा औद्योगिक पुनःसंरचना के प्रक्रम में छंटने के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले कामगारों की सहायता के लिए
- \* राष्ट्रीय नवीकरण निधि का उद्देश्य है —उद्योगों का प्रौद्योगिकीय उन्नयन होने अथवा बीमार इकाइयों के बंद हो जाने से प्रभावित हुए कामगारों के हितों की सुरक्षा करना
- \* राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन किया गया था
  - सामाजिक सुरक्षा हेतु
- \* अधिकांश मामलों में लघु उद्योग, वृहद उद्योगों जितने दक्ष और प्रतियोगी नहीं हैं। फिर भी सरकार छोटे व्यवसाय/प्रतिष्ठानों के प्रति तरजीही व्यवहार करती है और इनके अनेक प्रकार के उत्पादों के लिए आरक्षण प्रदान करती है, क्योंकि लघु उद्योग
  - प्रति इकाई पूंजी परिनियोजन के आधार पर अपेक्षाकृत अधिक रोजगार प्रदान करने के साथ ही अल्प कुशल कर्मियों को, कोई भी काम प्रदान करते हैं।
- \* सही सुमेलित हैं-
 

(नगर)		(उद्योग)
कोयम्बटूर	-	सूती वस्त्र
राउरकेला	-	लौह-इस्पात
कपूरथला	-	रेल डिब्बा
बरौनी	-	तेलशोधन
- \* 'गोल्डेन हैंड शेक' संबंधित है —स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से
- \* हजीरा उर्वरक कारखाना आधारित है —प्राकृतिक गैस पर
- \* कच्छ की खाड़ी में स्थित 'कांडला' प्रसिद्ध है
  - निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए
- \* वर्ष 2017-18 सीमेंट, कोयला, बिजली तथा इस्पात उद्योगों में से अधिकतम संवृद्धि दर थी —इस्पात उद्योग की
- \* सही सुमेलित हैं-
 

सिंगरौली (मध्य प्रदेश)	-	कोयला
कजरहट (चुनार, उ.प्र.)	-	सीमेंट
कोयाली (बड़ोदरा, गुजरात)	-	तेल
आणन्द (गुजरात)	-	दूध
- \* नायक समिति का संबंध है —लघु उद्योगों से
- \* क्रिसिल एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ मूल्यांकन करता है —कंपनी की साख की स्थिति का
- \* आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत उद्योग माना जाता है
  - लोहा व इस्पात
- \* 'आठ मूल उद्योगों के सूचकांक' (इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज) में सर्वाधिक महत्व दिया गया है —विद्युत उत्पादन को
- \* समाचारों में कभी-कभी देखे जाने वाले 'आधार क्षय एवं लाभ स्थानांतरण' (Base Erosion and Profit Shifting) पद का संदर्भ है
  - बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर-अपवचन पर प्रतिबंध लगाना
- \* भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु-स्तर का उद्योग है —हथकरघा उद्योग
- \* सहकारी इकाइयों की दशा में विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई है
  - सूती वस्त्र क्षेत्र में

- \* श्रम गहन उद्योग वह है, जहां —अधिक श्रमिकों को रखा जाता है
- \* औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में तथा संबंधित समस्याओं में सहायता करने के लिए एक एजेंसी है —उद्योग बंधु
- \* समूह जो औद्योगिक संबंध के सह-भागीदार हैं —श्रमिक एवं उनके संगठन, प्रबंधक एवं उनके संगठन तथा राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकार
- \* भारत के जिस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं, वह है —कपड़ा उद्योग
- \* कृषि क्षेत्र के बाद भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है —कपड़ा उद्योग (वस्त्र क्षेत्र)
- \* वर्तमान में भारतीय लघु उद्योगों के सम्मुख प्रमुख समस्याएं हैं —पूंजी का अभाव, विपणन की समस्या, कच्चे माल का अभाव, आधारभूत संरचना की बाधा, सीमा शुल्क नीति, विलंबित भुगतान, रूग्णता की समस्या, निम्न स्तरीय आंकड़ों की उपलब्धता आदि।
- \* भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघुस्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वे —अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं
- \* वित्त, विपणन, कच्चा माल तथा हड़ताल एवं तालाबंदी में से एक लघु उद्योगों (SSIs) की समस्या नहीं है —हड़ताल एवं तालाबंदी
- \* कथन (A) : पिछले कुछ वर्षों से भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में सम्विलय तथा अधिग्रहण की घटनाएं हो रही हैं। कारण (R) : भारत में एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम में पर्याप्त ढील दी गई है। —(A) सही है, परंतु (R) गलत है।
- \* कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सबसे पहले बना —भारत में
- \* वर्ष 2017-18 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है —उत्तर प्रदेश
- \* चीनी को नियंत्रण-मुक्त करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे —सी. रंगराजन
- \* सही सुमेलित हैं-
 

कटनी	-	सीमेंट उद्योग	
सूरत	-	सूती वस्त्र	
चुर्क	-	सीमेंट उद्योग	
ध्रुव रिएक्टर	-	कलपक्कम	
- \* सही सुमेलित हैं-
 

		(उद्योग)	(उत्पादक केंद्र)
जूट का सामान	-	टीटागढ़	
रेशमी वस्त्र	-	बंगलौर	
ऊनी वस्त्र	-	लुधियाना	
ऊनी कालीन	-	भदोही	
- \* रेनूकूट स्थित एल्युमीनियम की फैक्ट्री, हिंडाल्को का वहां स्थित होने का मूल कारण है —बिजली की प्रचुर आपूर्ति
- \* गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से पेट्रोरसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं —गुजरात में
- \* कथन (A) : तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है। कारण (R) : इसमें कपड़ा एवं वस्त्र, औषधियों एवं पेट्रोरसायन की बहुत-सी औद्योगिक इकाइयां पाई जाती हैं। —(A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
- \* प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का अर्थ है —नीति निर्णय लेने में भागीदारी
- \* भिलाई, रांची, आसनसोल तथा दुर्गापुर औद्योगिक कस्बों में से छोटा नागपुर पठार पर स्थित है —रांची
- \* भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है —सूती कपड़ा
- \* भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ, वह है —कुटीर उद्योग
- \* यद्यपि कुछ गैस आधारित उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं, फिर भी भारत में प्राकृतिक गैस के प्रभूत भंडार अप्रयुक्त पड़े हैं। प्राकृतिक गैस के इन विशाल संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है —उर्वरक के उत्पादन में
- \* SAIL, BHEL, ONGC तथा ESSAR OIL में से वह एक जो अन्य जैसा नहीं है —ESSAR OIL
- \* बॉगाईगांव रिफाइनरी, मंगलौर रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी तथा एस्सार ऑयल लिमिटेड में से निजी क्षेत्र में है —एस्सार ऑयल लिमिटेड
- \* अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण होता है —तेल कंपनियों द्वारा
- \* नेपालगंज जाना जाता है —अखबारी कागज उद्योग के लिए
- \* देवास प्रसिद्ध है —करेंसी नोट की छपाई के लिए
- \* किसी उद्योग के स्वरूप और आकार को निर्धारित करते हैं —पूंजी निवेश, व्यवसाय आवर्त तथा बिजली की खपत



- \* सही सुमेलित हैं-  
(विनिर्माण उद्योगों की स्थापना) (वर्ष तथा स्थान)  
प्रथम सूती मिल की स्थापना 1854 बंबई के पास (महाराष्ट्र)  
प्रथम मशीन निर्मित कागज 1832 दिसरा (पश्चिम बंगाल)  
का विनिर्माण  
प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1904 मद्रास के पास (तमिलनाडु)
- \* भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग हैं —अपतट में
- \* भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में विनिर्माण, खनन, विद्युत तथा निर्माण में से एक गतिविधि सम्मिलित नहीं है —निर्माण
- \* औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक वर्ष बनाया गया —वर्ष 1982 में
- \* सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों बी.एस.एन.एल., एन.टी.पी.सी., बी.एच.ई.एल. तथा भारतीय स्टेट बैंक में से एक में सरकार की 100% शेयर पूंजी है —बी.एस.एन.एल. में
- \* सही सुमेलित हैं-  
(उद्यम) (औद्योगिक समूह)  
VSNL - टाटा समूह  
मुद्रा विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड - अडानी समूह  
सी.एम.सी.(CMC) लिमिटेड - टाटा समूह  
आई.पी.सी.एल. (IPCL) - रिलायंस समूह
- \* कथन (A) : सूचना प्रौद्योगिकी भारत में बहुत ही तेजी से क्रिया-कलाप का एक अति महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र बनती जा रही है।  
कारण (R) : सॉफ्टवेयर देश के महत्वपूर्ण निर्यातों में से एक है और भारत का हार्डवेयर में बहुत सशक्त आधार है।  
—(A) सही है, परंतु (R) गलत है।
- \* भारत में प्रथम 'राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र' (National Investment and Manufacturing Zone) का गठन किए जाने के लिए प्रस्ताव दिया गया था —आंध्र प्रदेश में
- \* कथन (A) : भारतवर्ष में विनिवेश, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया का एक समाहित अंग है।  
कारण (R) : इससे प्राप्त आय को राज्य द्वारा घोषित नीति के अनुसार, उपयोग में लाया जा रहा है। —(A) तथा (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- \* कथन (A) : सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को विनिवेश कर रही है।  
तर्क (R) : सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पाईं।  
—(A) सही है, किंतु (R) गलत है।
- \* भारत में उदार औद्योगिक नीति अपनाई गई —वर्ष 1991 में
- \* वह वित्तीय वर्ष जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ —वर्ष 1991-92
- \* ऑयल (OIL) एक उपक्रम है, जो संलग्न है —तेल अनुसंधान में
- \* 1.एम.एम.टी.सी. लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है।  
2.नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना एम. एम. टी. सी. ने उड़ीसा सरकार के साथ संयुक्त रूप से की है।  
उपर्युक्त कथनों में से सही है/हैं —कथन 1 और 2 दोनों
- \* कोल इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में से नवरत्न में शामिल है —भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
- \* एचएएल (HAL) संबंधित है —वायुयानों के उत्पादन से
- \* 'नवरत्न' का विचार संबंधित है —सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यमों से
- \* केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा 'लघु रत्न' श्रेणी I उद्योग को वित्तीय स्वायत्तता दी गई है —अधिकतम 500 करोड़ रुपये तक की
- \* अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना की गई थी —प्रथम योजना में
- \* मीरा सेठ समिति का संबंध था —हथकरघा के विकास से
- \* सत्यम समिति संबंधित है —वस्त्र नीति से
- \* असंगठित सेक्टर के उद्योग के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष थे —अर्जुन सेनगुप्ता
- \* राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 1969 में की गई, मदद करता है —औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करने में, सामाजिक आधारभूत सुविधाएं देने में, परियोजना रिपोर्ट, परियोजना प्रोफाइल एवं प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करने में
- \* भारत में 'जिला खनिज प्रतिष्ठान' (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस) का उद्देश्य है —खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना
- \* भारत के राज्यों में, राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से जिनके विकास के लिए सहायता दी है, वे हैं —मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योग
- \* वर्तमान में विश्व कपड़ा निर्यात में भारत का स्थान है —द्वितीय

- \* सही सुमेलित हैं-
 

रिलायंस	-	मुकेश अंबानी
एयरटेल	-	सुनील भारती मित्तल
नैनो कार	-	रतन टाटा
विप्रो	-	अजीम प्रेमजी
- \* भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत एवं भारी उद्योग हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है।
 

—दोनों कथन सत्य हैं
- \* भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए मेगा फूड पार्क्स योजना का उद्देश्य है
 

—खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना (ढांचागत) सुविधाओं में सुधार लाना
- \* भारत सरकार 'मेगा फूड पार्क' की अवधारणा को प्रोत्साहित कर रही है
 

—खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु
- \* भारतीय खाद्य निगम, खनिज एवं धातु व्यापार निगम, खादी व ग्रामोद्योग निगम तथा भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण में से एक भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है
 

—खनिज एवं धातु व्यापार निगम
- \* सही सुमेलित हैं-
 

(संगठन का प्रकार)		(महत्वपूर्ण लक्षण)	
एकल व्यापारी		असीमित दायित्व	
साझेदारी		संविदात्मक संबंध	
सहकारिताएं		कमजोर वर्गों की उन्नति	
सार्वजनिक सीमित कंपनी		जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या	
- \* बी.आई.एफ.आर. संबंधित है
 

—रूग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से
- \* भारत में 8 उद्योगों को मूल उद्योगों (Core industries) का दर्जा प्राप्त है। ये आठ मूल उद्योग हैं
 

—कच्चा तेल, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कोयला, विद्युत, सीमेंट तथा तैयार इस्पात।
- \* भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास की जिम्मेदारी है
 

—आई.टी.डी.सी. पर
- \* 'वित्तीय उत्प्रेरक' की समुचित व्याख्या है
 

—यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्यवाही है, जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
- \* विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार की नई नीतिगत पहलें हैं
 

—राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना, एकल खिड़की मंजूरी (सिंगल विंडो क्लियरेंस) की सुविधा प्रदान करना तथा प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना आदि
- \* रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है
 

—हथकरघा
- \* उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को, जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, वे हैं
 

—उ.प्र. लघु उद्योग निगम, उ.प्र. औद्योगिक विकास निगम तथा उ.प्र. वित्तीय निगम द्वारा
- \* औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र हुआ है
 

—पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र
- \* सही सुमेलित हैं-
 

गोस्वामी समिति	-	औद्योगिक रुग्णता की समस्या	
जानकी रमन समिति	-	शेयर घोटाले की जांच पड़ताल	
मल्होत्रा समिति	-	बीमा क्षेत्र में सुधार	
तारापोर समिति	-	बैंकों में पूंजीगत खातों में रुपये की परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु ग्राहक सेवा	
- \* सही सुमेलित हैं-
 

(सरकारी नीति)		(वर्ष)	
सूचना तकनीक नीति		-	2000
खनिज नीति		-	2011
होटल नीति		-	2006
औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति		-	2010

## तृतीयक क्षेत्र (सेवाएं)

- \* भारत में तृतीयक क्षेत्र (Tertiary sector) में सम्मिलित है
 

—व्यापार, परिवहन, वित्त एवं वास्तविक (स्थावर) संपदा, परिवहन, संचार और होटल आदि
- \* वानिकी, विनिर्माण, कृषि तथा विपणन में से तृतीयक क्रिया-कलाप है
 

—विपणन
- \* भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है
 

—कृषि
- \* बैंकिंग एवं बीमा, निर्माण, परिवहन तथा संचार में से वह सेवा क्षेत्र जिसकी वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही है
 

—संचार सेवा क्षेत्र
- \* भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GDP) का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है
 

—सेवा क्षेत्र से

- \* वर्तमान (वर्ष 2017-18) में सेवाओं का GVA तथा सकल रोजगार में भागीदारी क्रमशः है —55.2% तथा 30.6%
- \* भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का सही हासमान क्रम है —सेवा—उद्योग—कृषि
- \* वर्ष 2012 से 2017 तक अवधि में भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर का क्रम विश्व में था —दूसरा
- \* वर्ष 1980 से भारत के सकल घरेलू उत्पाद की कुल राशि में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी ने —न घटने की प्रवृत्ति दर्शाई है
- \* वर्ष 2011-2017 के मध्य कृषि, उद्योग तथा सेवा (सर्विसेज) में से एक क्षेत्र की वृद्धि दर निरंतर बढ़ी है —सेवा क्षेत्र की
- \* जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, वैसे-वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश —बढ़ता है
- \* संघीय बिक्री कर —अंतरराज्यीय व्यापार तथा केंद्रशासित प्रदेशों पर लगाया जाता है
- \* 'पैन' के प्रारंभ में पांच अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे AFZPK 7190K इसमें P दर्शाता है —व्यक्तिगत
- \* आयकर विभाग द्वारा जारी PAN कार्ड प्रयोग नहीं किया जा सकता है —पते का प्रमाण के रूप में
- \* अक्टूबर, 2015 में 'ई-सहयोग' योजना प्रारंभ की गई थी —आयकर विभाग द्वारा
- \* रेलवे बजट 2016-17 के अनुसार, रेलवे के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा —श्रेष्ठ अनुसंधान संगठन
- \* संघीय बजट 2018-19 में अधिकतम धन प्रावधानित किया गया है —ब्याज पर (575795 करोड़ रुपये)

## राजकोषीय नीति एवं राजस्व

- \* भारत में राजकोषीय नीति निर्धारित करता है —वित्त मंत्रालय
- \* भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है —वित्त मंत्रालय द्वारा
- \* वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है —वित्त मंत्रालय
- \* 'बजट' एक लेख-पत्र है —सरकार की राजकोषीय नीति का
- \* भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई थी —वी.पी. सिंह द्वारा
- \* सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है —वित्त मंत्रालय
- \* धनी अधिक धनी होते जा रहे हैं और निर्धन अधिक निर्धन, यह जानने के लिए आवश्यक है —विविध अवधियों में विविध वर्गों के आय आदाताओं की आय के वितरण की
- \* व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय बचत-पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि, इंदिरा विकास-पत्र तथा राष्ट्रीय बचत योजना में से एक अन्य से भिन्न है —इंदिरा विकास-पत्र
- \* किसान विकास-पत्र, राष्ट्रीय बचत-पत्र, लोक भविष्य निधि तथा यूनित लिंकड इंश्योरेंस योजना में से वह जिस पर कोई आयकर छूट नहीं है —किसान विकास-पत्र पर
- \* भारत में पहली बार 'व्यय कर' लगाने का सुझाव दिया था —कॉल्डॉर ने
- \* व्यय, राजस्व, बैंकिंग विभाग तथा आर्थिक मामलों में से वह एक जो वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है —बैंकिंग विभाग
- \* संघ बजट 2018-19 में पूंजी प्राप्तियां —आयगत प्राप्तियों से कम हैं
- \* आय के तीन सबसे बड़े स्रोत हैं —वस्तु एवं सेवाकर (23%), निगम कर (19%), आयकर (16%)
- \* केंद्रीय सरकार के सकल कर राजस्व के मामले में सही अवरोही क्रम है —वस्तु एवं सेवा कर (23%), निगम कर (19%), आयकर (16%), संघ उत्पाद शुल्क (8%)
- \* सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर तथा मार्ग कर में से भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है —मार्ग कर (Toll Tax)
- \* बजट 2018-19 के अनुसार, भारत में कर राष्ट्रीय उत्पाद अनुपात अनुमानित है, लगभग —12.1 प्रतिशत
- \* केंद्र सरकार के चालू खाते में आय के स्रोत हैं —निगम कर, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ आदि
- \* भारत में संघीय बजटों में सबसे अधिक होता है —आगम (रेवेन्यू) व्यय
- \* भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है —सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय, विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदत्त ऋण और अग्रिम
- \* गैर-योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं —सब्सिडी, ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय तथा पिछली योजनाओं में निर्माण आधारिक संरचना का अनुरक्षण व्यय आदि
- \* साल-दर-साल लगातार घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा कार्रवाइयां की जा सकती हैं —राजस्व व्यय को घटाकर तथा सहायिकी (सब्सिडी) को युक्तिसंगत बनाकर

- \* केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है  
—**व्याज की अदायगी**
- \* हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है  
—**व्याज की अदायगी**
- \* शासन के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार कीजिए :  
1. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह को प्रोत्साहन देना  
2. उच्च शैक्षिक संस्थानों का निजीकरण करना  
3. अधिकारी तंत्र की डाउनसाइजिंग करना  
4. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री/ऑफलोडिंग  
भारत में राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण पाने के उपायों के रूप में काम आ सकते हैं  
—**3 तथा 4**
- \* वर्ष 2018-2019 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा स्थिर रखा गया है  
—**3.3 प्रतिशत**
- \* वर्ष 2011-12 से 2014-15 के मध्य राजकोषीय घाटा/जी.डी.पी. अनुपात सर्वाधिक रहा है, वित्तीय वर्ष  
—**2011-12 में (5.7%)**
- \* वर्ष 2018-19 में केंद्र सरकार की आगम आय में तट कर तथा उत्पाद कर का योगदान है  
—**12 प्रतिशत**
- \* वर्ष 2018-19 में संघीय सरकार के कर आगम साधनों में सबसे बड़ा स्रोत है  
—**वस्तु एवं सेवा कर**
- \* 2011-12 वित्तीय वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में 'अति वरिष्ठ नागरिकों' की एक नई श्रेणी आयकर के उद्देश्य से बनाई गई है। इस श्रेणी में वे व्यक्ति आच्छादित होंगे, जिनकी उम्र होगी  
—**80 वर्ष या इससे अधिक**
- \* अभिकथन (A) : भारत में शून्य आधार बजट प्रवर्तित किया गया है।  
कारण (R) : शून्य आधार बजट तकनीक के अंतर्गत बजट प्रावधान करने से पूर्व प्रत्येक योजना की विवेचनात्मक समीक्षा की जाती है।  
—**(A) और (R) दोनों सही हैं, और (A), (R) की सही व्याख्या है।**
- \* किसी देश में आय का पुनर्वितरण (Redistribution) करने का सर्वोत्तम मार्ग है  
—**प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान**
- \* सामान्य रूप से भारत में प्रति पांच वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है  
—**केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए**
- \* केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है  
—**वित्त आयोग की सिफारिश पर**
- \* भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है  
—**केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना**
- \* नवंबर, 2017 को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है  
—**डॉ. एन.के. सिंह को**
- \* चौदहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे  
—**डॉ. वाई.वी. रेड्डी**
- \* सही सुमेलित हैं-  
(वित्त आयोग) (अध्यक्ष)  
नवां - एन.पी.के. साल्वे  
दसवां - के.सी. पंत  
ग्यारहवां - ए.एम. खुसरौ  
बारहवां - सी. रंगराजन
- \* योजना आयोग तथा वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है  
—**दोनों द्वारा की गई संस्तुतियां शासन पर बाध्य हैं**
- \* केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध है  
—**करों से**
- \* भारतीय आयकर अधिनियम की धारा-88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश की है  
—**केलकर समिति ने**
- \* जिस नवीनतम कमेटी ने कर सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसे जाना जाता है  
—**केलकर समिति के नाम से**
- \* पंचायतों हेतु वित्तीयन के लिए सही स्रोत हैं  
—**वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान, केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन तथा राज्य वित्त आयोग द्वारा आवंटन**
- \* 14वें वित्त आयोग के अनुसार, वितरण योग्य संसाधनों में से राज्यों को वितरण हेतु प्राप्त होगा  
—**42 प्रतिशत**
- \* तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी केंद्रीय करों में न्यूनतम प्रतिशत होगी  
—**32.0 प्रतिशत**
- \* भारत के तेरहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों की सृजित आय को राज्यों के मध्य बंटवारे की संस्तुति करते समय सर्वाधिक भार दिया  
—**वित्तीय क्षमता अंतराल को**
- \* चौदहवें वित्त आयोग के संदर्भ में सही कथन हैं  
—**इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया है।**
- \* इंडीग्रेटेड लो कॉस्ट सेनीटेशन (आईएलसीएस) योजना के संबंध में सही कथन है —**यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्तपोषित है, जिसमें केंद्रीय योगदान 75 प्रतिशत है**
- \* आर्थिक मंदी के संदर्भ में सरकार द्वारा कार्य किए जा सकते हैं —**कर दरों में कटौती करना तथा सरकारी व्यय को बढ़ाना**
- \* संघ सरकार के बजट घाटों का घटता हुआ सही क्रम है  
—**राजकोषीय घाटा > आगम घाटा > प्रारंभिक घाटा**

- \* सही सुमेलित हैं-  
(पद) (व्याख्या)  
राजकोषीय घाटा ऋणादानों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता  
बजटीय घाटा कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता  
राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता  
प्राथमिक घाटा ऋणादानों और ब्याज अदायगियों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता
- \* राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है  
—कुल व्यय (राजस्व प्राप्तियां + ऋणों की वसूली + विनिवेश से प्राप्तियां)
- \* यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए, तो अवशेष को कहा जाएगा —सकल प्राथमिक घाटा
- \* राजकोषीय घाटा है —बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व
- \* भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान है  
—राजकोषीय घाटे (Fiscal deficit) का
- \* यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए, तो यह बराबर होता है —राजकोषीय घाटे के
- \* राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं —प्रभावी राजस्व घाटा
- \* प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया —केंद्रीय बजट 2011-12 में
- \* बजट के हिसाब-किताब की जांच भारतीय संसद करती है  
—सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा
- \* कथन (A) : राजकोषीय घाटा, बजटीय घाटे से बड़ा होता है।  
कारण (R) : राजकोषीय घाटे का अर्थ है, सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा अन्य देयताओं से लेकर अपने खर्च पूरे करना। —(A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A)का सही स्पष्टीकरण है।
- \* सही सुमेलित हैं-  
कैपिटल गेन टैक्स - संपत्ति विक्रय  
सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी - फैक्ट्री निर्मित वस्तु  
कस्टम ड्यूटी - आयात  
कॉर्पोरेट टैक्स - आय
- \* भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है —उपकर  
\* आयकर के लगाने, उद्ग्रहण करने और वितरण करने के संबंध में सही कथन है कि —संघ कर लगाता है, उद्ग्रहण करता है और कर प्राप्तियों का स्वयं और राज्यों के बीच वितरण करता है।  
\* भारत में आयकर के संबंध में सही कथन है  
—यह एक प्रगतिशील तथा प्रत्यक्ष कर है  
\* स्टाम्प शुल्क का आरोपण केंद्र करता है, किंतु  
—संग्रह और विनियोजन राज्य करते हैं  
\* कथन (A) : भारत में केंद्र सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे का एक इतिहास रहा है।  
कारण (R) : भारतीय कृषि में पाश्चात्य देशों की तुलना में राज सहायता की मात्रा अधिक रही है।  
—(A) सही है, किंतु (R) गलत है।  
\* भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) का समावेश किया गया था —वर्ष 1996-97 में  
\* 'मोडवेट' संबंधित है —उत्पाद कर से  
\* संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है —उत्पाद कर से  
\* 'मूल्य आधारित कर' (वैल्यू ऐडेड टैक्स) की विशेषता है  
—यह बहु-बिंदु लक्ष्य आधारित कर (टैक्सेशन) प्रणाली है, जो उत्पादन/वितरण शृंखला में लेन-देन के हर चरण में हुए मूल्य-संवर्धन पर लगाया जाता है। यह वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम उपभोग पर लगाया जाता है, जिसका वहन अंततः उपभोक्ताओं को करना पड़ता है।  
\* सेनवैट (CENVAT) का संबंध है —केंद्रीय उत्पादन शुल्क से  
\* सही सुमेलित हैं-  
(समितियां) (अध्यक्ष)  
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में - सी. रंगराजन  
शेयरों का विनिवेश  
औद्योगिक रूग्णता - ओंकार गोस्वामी  
कर सुधार - आर.जे.चेलैया  
बीमा क्षेत्र में सुधार - आर.एन.मल्होत्रा  
\* संपदा कर भारत में पहली बार लागू किया गया —वर्ष 1957 में  
\* संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है —घरेलू उधारों से  
\* केंद्रीय बजट 2016-17 के अनुसार, 15% का अधिकर देय होगा  
—रु. 1 करोड़ से ऊपर आय होने पर

- \* सेवा कर की वर्तमान दर भारत में है **—15 प्रतिशत**
- \* भारत में सेवा कर प्रारंभ किया गया था **—वर्ष 1994-95 में**
- \* निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
  1. जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य हैं।
  2. जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति की देहली निर्धारण भी करेगी।
  3. राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प होगा, यदि वे ऐसा चाहें। उपर्युक्त कथनों में से सही है/हैं **—केवल (1) और (2)**
- \* भारत में जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) लागू है **—1 जुलाई, 2017 से**
- \* भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर लागू हुआ **—हरियाणा में (वर्ष 2005 में)**
- \* राज्य/केंद्रशासित क्षेत्र जिसमें बिक्री कर लागू नहीं है **—अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप में**
- \* पेमेंट ऑफ ट्रेड्यूटी एक्ट, 1972 के अनुसार, ट्रेड्यूटी भुगतान की अधिकतम सीमा है **—रु. 10 लाख**
- \* राष्ट्रीय निवेश निधि जिसमें विनिवेश प्राप्तियां पहुंचती हैं, के संदर्भ में
  1. केंद्रीय वित्त मंत्रालय राष्ट्रीय निवेश निधि की परिसंपत्ति का प्रबंधन करता है।
  2. राष्ट्रीय निवेश निधि, भारत की संचित निधि के अंतर्गत रखी जाती है।
  3. कुछ परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां, निधि प्रबंधकों के रूप में नियुक्त की जाती हैं।
  4. वार्षिक आय का निश्चित अनुपात चुनिंदा सामाजिक क्षेत्रों का वित्तपोषण करने के लिए प्रयुक्त होता है।
 उपर्युक्त कथनों में से सत्य कथन है/हैं **—3 एवं 4 सत्य हैं**
- \* कथन (A) : हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है।  
कारण (R) : इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है।  
**—(A) तथा (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या है।**
- \* घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है। परंतु यदि यह विफल हुई, तो इससे स्थिति उत्पन्न होती है **—मुद्रास्फीति की**
- \* घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है **—मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी का**
- \* भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था उपयोग की जाती है **—आर्थिक विकास के लिए**
- \* भारत में आमदनी पर कर की शुरुआत की थी **—जेम्स विल्सन ने**
- \* वह कर जो खरीददारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता **—आयकर**
- \* आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है **—सीमा कर (शुल्क) के रूप में**
- \* आयकर, उत्पादन कर, चुंगी कर तथा बिक्री कर में से प्रत्यक्ष कर है **—आयकर**
- \* उत्पाद शुल्क है, एक **—अप्रत्यक्ष कर**
- \* विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी तथा संपदा कर में से प्रत्यक्ष कर है **—संपदा कर**
- \* बिक्री कर, आमदनी कर, आबकारी कर तथा चुंगी कर में से कौन अप्रत्यक्ष कर है **—बिक्री कर**
- \* विक्रय कर, जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं, **—राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर है**
- \* अनुषंगी लाभ कर, ब्याज कर तथा प्रतिभूति लेन-देन कर में से प्रत्यक्ष कर है **—तीनों**
- \* भारत में हाल में हुए कर सुधार जिस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित थे, उसके अध्यक्ष थे **—आर. जे. चेलैया**
- \* चेलैया समिति का संबंध है **—प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से**
- \* आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा की थी **—केलकर कमेटी ने**
- \* भारत में सामूहिक अतिरिक्त लाभ कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर, पूंजी लाभ कर तथा कंपनियों के लाभ पर कर से एक का संबंध निगम की आय से नहीं है **—पूंजी लाभ कर**
- \* उपहार कर, मनोरंजन कर, व्यक्तिगत आयकर तथा निगम कर में से वह कर जो केंद्र सरकार नहीं लगाती है **—मनोरंजन कर**
- \* मनोरंजन कर, राज्य उत्पादन शुल्क, कृषि आयकर तथा निगम कर (कॉर्पोरेशन टैक्स) में से राज्य सरकारों द्वारा जो कर नहीं लगाया जाता है, वह है **—निगम कर (कॉर्पोरेशन टैक्स)**
- \* शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है **—राज्य सरकारों द्वारा**
- \* भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य है **—पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता एवं धन तथा आय का न्यायोचित वितरण**
- \* वर्ष 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए, राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया था **—प्रो. कीन्स ने**

- \* वित्तीय (फिस्कल) नीति का संबंध है —कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीति से
  - \* उत्पादन नीति, कर नीति, विदेश नीति तथा ब्याज दर नीति में से वह एक जो राजकोषीय नीति का भाग है —कर नीति
  - \* वित्त मंत्रालय द्वारा 'आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना, 1997' लागू की गई थी —1 जुलाई, 1997 से
  - \* संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में 'मांग की राशि को घटाकर एक रुपया करना है', को कहा जाता है —नीति कटौती प्रस्ताव
  - \* कंपनी कर वह है, जो लगता है —कंपनी की आय पर
  - \* सही सुमेलित हैं-
 

<p>(प्रकाशक)</p> <p>उद्योग मंत्रालय - थोक मूल्य सूचकांक</p> <p>केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय - राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी</p> <p>भारतीय रिजर्व बैंक - करेंसी और वित्त संबंधी रिपोर्ट</p> <p>वित्त मंत्रालय - आर्थिक समीक्षा संगठन</p>	<p>(प्रकाशन)</p>
---	------------------
  - \* सही सुमेलित हैं-
 

<p>राष्ट्रीय कृषि नीति - 2000</p> <p>समुद्रीय मत्स्य नीति - 2004</p> <p>नवीन विदेशी व्यापार नीति - 2015</p> <p>सातवां वित्तीय आयोग - 1978</p>	
---	--
  - \* सही सुमेलित हैं-
 

<p>ओपन-जनरल लाइसेंस - विदेशी व्यापार</p> <p>TRYSEM - रोजगार</p> <p>थोक मूल्य सूचकांक - मुद्रास्फीति</p> <p>नकदी - रिजर्व अनुपात - ऋण नियंत्रण</p>	
---	--
  - \* आयकर, सार्वजनिक ऋण, वैट (मूल्य-वर्धित कर) तथा अर्थ-साहायकी (परिदान) में से वह एक जो सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है —अर्थ-साहायकी (परिदान)
  - \* निष्पादक बजट की अवधारणा ली गई है —संयुक्त राज्य अमेरिका से
  - \* भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया —31 मार्च, 1997 को
  - \* निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव तथा स्थगन प्रस्ताव में से जिस एक का संबंध संघीय बजट से है, वह है —कटौती प्रस्ताव
  - \* राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 जिसे राजस्थान में व्यवस्थापित कर दिया गया है, इस उद्देश्य से कि —सरकार में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना है
  - \* राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत वर्ष में पारित किया गया था —वर्ष 2003 में
  - \* एफ.आर.बी.एम. विधेयक के अनुसार, 2020-21 तक कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को लाना है —12.7 प्रतिशत तक
  - \* संघ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अक्टूबर, 2016 में यह घोषित किया कि आय घोषणा योजना (आई.डी.एस.), 2016 के अंतर्गत 30 सितंबर, 2016 तक घोषित काला धन है, लगभग —65,250 करोड़ रुपये
  - \* बजट अनुमान 2018-19 में विनिवेश से प्राप्ति का अनुमान है —80000 करोड़ रुपये की
  - \* विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निजी प्रेषित धन तथा पोर्टफोलियो निवेश में से पूंजीगत लेखा की रचना नहीं करता है —विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा पोर्टफोलियो निवेश
- ## आयोजना
- \* नियोजन आवश्यक है —संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए, विकास के लाभ को सम-आचरण द्वारा आगे बढ़ाने के लिए, क्षेत्रीय असंतुलन के दूरीकरण को प्रमुखता देने के लिए तथा उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए
  - \* निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
    - A. आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है।
    - B. भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। —उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं।
  - \* 'गरीबी हटाओ' विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था —पांचवीं पंचवर्षीय योजना में
  - \* विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था —चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में
  - \* समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था —द्वितीय पंचवर्षीय योजना में
  - \* बारहवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था —2012 से 2017
  - \* बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि, वानिकी एवं मत्स्यपालन की वृद्धि दर अनुमानित थी —4.0%
  - \* 12वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक धनराशि विनिहित की गई थी—सामाजिक सेवाओं की मद में
  - \* बारहवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था —तीव्रतर, धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास

- \* आदेशात्मक और निर्देशात्मक योजना में आधारभूत अंतर है  
—आदेशात्मक योजना में आदेष्टा सोपान बाजार तंत्र का स्थान पूरी तरह से ले लेता है, जबकि निर्देशात्मक योजना में उसे बाजार प्रणाली के कार्यकरण को सुधारने का केवल एक साधन माना जाता है।
- \* ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य भाव था  
—तीव्रतर एवं अधिक सम्मिलित वृद्धि
- \* नीति आयोग के विषय सत्य कथन हैं  
—इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है तथा यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है।
- \* सही कथन है —वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्यों और दायित्वों की परस्पर अतिव्याप्ति नहीं है।
- \* भारतीय नियोजन के इतिहास में 'रोजगार-विहीन वृद्धि का दशक' कहलाने योग्य है —वर्ष 1991-2000
- \* प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी —कृषि का विकास
- \* सही सुमेलित हैं-
- | (योजना)       | (कार्यक्रम)   |
|---------------|---|
| प्रथम योजना   | - सामुदायिक विकास                                   |
| द्वितीय योजना | - तीव्र औद्योगीकरण                                  |
| तृतीय योजना   | - आधारभूत उद्योगों का प्रसार                        |
| चतुर्थ योजना  | - स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ संवृद्धि |
| पंचम योजना    | - न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम                        |
- \* प्रमुख व्यूह रचना के रूप में महिला अंश योजना प्रारंभ की गई थी  
—नवीं पंचवर्षीय योजना में
- \* भारत में मध्य-अर्धशतक (Mid - Fifties) में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था  
—भारी उद्योगों की स्थापना करना, जो पूंजी सघन थे
- \* सही सुमेलित हैं-
- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| प्रथम पंचवर्षीय योजना  | - 1951-56 |
| तृतीय पंचवर्षीय योजना  | - 1961-66 |
| चतुर्थ पंचवर्षीय योजना | - 1969-74 |
| छठीं पंचवर्षीय योजना   | - 1980-85 |
- \* 'सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ संवृद्धि' पर बल दिया गया था  
—7वीं पंचवर्षीय योजना में
- \* नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में लागू किया गया  
—1 अप्रैल, 1951 से
- \* द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी —महालनोबिस मॉडल पर
- \* भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :  
A. द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया  
B. तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगीकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया।  
—उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं।
- \* राष्ट्रीय विकास परिषद —राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है।
- \* राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबद्ध है —भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन से
- \* राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष होता है —भारत का प्रधानमंत्री
- \* राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था, वह थी  
—6 अगस्त, 1952
- \* भारत में 'योजना आयोग' की स्थापना हुई थी —वर्ष 1950 में
- \* भारत सरकार ने नीति (NITI) आयोग की स्थापना की है  
—योजना आयोग का स्थान लेने के लिए
- \* योजना आयोग के स्थान पर 'नीति आयोग' का गठन हुआ  
—1 जनवरी, 2015 को
- \* नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2014-15 में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है  
—बिहार (17.06%)
- \* 'नेशनल प्लानिंग कमेटी' का गठन किया था —सुभाषचंद्र बोस ने
- \* वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था  
—श्रीमन नारायण अग्रवाल ने
- \* भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य था  
—स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना
- \* भारत में 'अनवरत योजना' कार्यशील थी —वर्ष 1978-79 में
- \* निर्धारित अवधि से एक वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना है  
—पांचवीं पंचवर्षीय योजना
- \* आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया  
—पांचवीं पंचवर्षीय योजना में
- \* पांचवीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था —गरीबी हटाओ
- \* पिछड़े देशों के लिए 'रोलिंग प्लान' का सुझाव दिया गया था  
—गुन्नार मिर्डल द्वारा
- \* निम्नलिखित कथनों पर विचार करें  
A. एक वर्ष के लिए योजना है,  
B. 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है,  
C. अर्थव्यवस्था की आवश्यकतानुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है,  
D. 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए भावी योजना है।  
उपर्युक्त चारों कथन संदर्भित हैं  
—चल योजना (Rolling Plan) के संदर्भ में



- \* राष्ट्रीय नियोजन में 'रोलिंग प्लान' की अवधारणा लागू की गई थी  
—जनता सरकार के द्वारा
- \* आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुना गई थी  
—पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान
- \* बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था  
—वर्ष 1975 में
- \* योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है —चयनित आधारभूत उद्योग से
- \* आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी —दसवीं पंचवर्षीय योजना में
- \* ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई थी  
—निर्माण कार्यों में
- \* सही सुमेलित हैं—  
(योजना) वृद्धि (% में)

छठी योजना	-	3.9 %
सातवीं योजना	-	5.7 %
आठवीं योजना	-	3.2 %
नौवीं योजना	-	2.5 %

- \* आर्थिक नियोजन एक विषय है —समवर्ती सूची का
- \* कथन (A) : 'नीचे से ऊपर नियोजन' एक लक्ष्य है जो अभी भी प्राप्त होना है।  
कारण (R) : गांव एक इकाई के रूप में आर्थिक व्यवहार्यता के लिए बहुत उपयुक्त है।  
—(A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
- \* भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है —7
- \* योजना अवकाश की अवधि का संबंध है —1966-69 से
- \* मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है  
—आठवीं पंचवर्षीय योजना में
- \* सातवीं योजना में आई.आर.डी.पी. के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी  
—संपूर्ण परिवार का अंगीकरण
- \* भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया  
—चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में
- \* आठवीं पंचवर्षीय योजना पूर्ववर्ती योजनाओं से भिन्न है। इस योजना में विशेष महत्वपूर्ण अंतर यह है कि —इस योजना में अद्यः संरचना विकास के लिए पर्याप्त बल दिया गया है
- \* सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा था  
—भोजन, काम और उत्पादकता
- \* भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ, इस योजना के वास्तुकार थे  
—पी.सी. महालनोबिस

- \* निम्न को उनके कालक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए :  
1. प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद को दी गई।  
2. राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया।  
3. स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया।  
4. भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना।  
उपर्युक्त कथनों का क्रम है —4, 3, 1, 2
- \* योजना पत्रिका का प्रकाशन होता है —प्रकाशन विभाग द्वारा
- \* 'प्लानिंग एंड द पुअर' पुस्तक के लेखक हैं —बी.एस. मिनहास

## मुद्रा एवं बैंकिंग

- \* एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है  
—गांधीनगर में
- \* भारत का औद्योगिक वित्त निगम कार्य करता है  
—एक विकास बैंक के रूप में
- \* निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए  
1. भारत का औद्योगिक वित्त निगम  
2. भारत का औद्योगिक ऋणादान और निवेश निगम  
3. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक  
4. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया  
उपर्युक्त संस्थाओं की स्थापना का क्रम है —1, 2, 4, 3
- \* भारत की निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं पर विचार कीजिए :  
1. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई)  
2. भारतीय औद्योगिक प्रत्यय एवं निवेश निगम (आईसीआईसीआई)  
3. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई)  
4. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)  
उपर्युक्त संस्थाओं की स्थापना का सही कालक्रम है —1, 2, 3, 4
- \* सही सुमेलित हैं—  
(संस्था) (स्थापना वर्ष)

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI)	-	1948
भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम (ICICI)	-	1955
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI)	-	1964
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	-	1982
औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड	-	1987
भारतीय लघु उद्योग विकास निगम (SIDBI)	-	1990

- \* मार्चात, 2017 में भारत में शहरी सहकारी बैंकों की संख्या थी  
—2104

- \* कंपनी अंश (शेयर) पर मर्यादित (Ltd.) होने का अर्थ है  
—धारकों का उत्तरदायित्व सीमित होना
- \* भारत सरकार द्वारा शेयर का पूंजी विनिवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति की गई —वर्ष 1993 में
- \* सरकार की 'संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना' (Sovereign Gold Bond Scheme) एवं 'स्वर्ण मुद्राकरण योजना' (Gold Monetization Scheme) का/के उद्देश्य है/हैं  
—भारतीय गृहस्थों के पास निष्क्रिय पड़े स्वर्ण को अर्थव्यवस्था में लाना तथा स्वर्ण-आयात पर भारत की निर्भरता में कमी लाना
- \* भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है —मुद्रा व्यापार सहयोग निधि
- \* सेंसेक्स, बी.एस.ई., निफ्टी तथा सैप्स में से वह एक जो अप्रासंगिक है —सैप्स
- \* राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना की गई थी  
—छठीं पंचवर्षीय योजना में
- \* नाबार्ड (कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक) की स्थापना हुई  
—जुलाई, 1982 में
- \* नाबार्ड का मुख्यालय है —मुंबई में
- \* कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है —नाबार्ड (NABARD)
- \* नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है —कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए
- \* नाबार्ड, व्यापारिक बैंक, आर.आर.बी. तथा सहकारिता बैंक में से वह जो स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है —नाबार्ड
- \* किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम से आच्छादित है  
—उपभोग साख एवं निवेश साख
- \* किसानों हेतु किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) योजना लागू की गई  
—वर्ष 1998-1999 में
- \* भारत में 'नाबार्ड' बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है —अनुसूचित व्यापारिक बैंकों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा राज्य भूमि विकास बैंकों को
- \* 'सिडबी' (SIDBI) की स्थापना की गई है  
—लघुस्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु
- \* प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई —वर्ष 1975 में
- \* A. लघु एवं सीमांत कृषकों को साख प्रदान करना,  
B. ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करना,  
C. अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक होना,  
D. भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना।  
उपर्युक्त में से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है  
—भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना
- \* मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित 'नया पैसा' 'पैसा' हो गया  
—1 जून, 1964 से
- \* भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली शुरू की गई —वर्ष 1957 से
- \* सही सुमेलित हैं-  
डोव जोन्स - न्यूयॉर्क  
हैंग सेंग - हांगकांग  
FTSE-100 - लंदन
- \* S & P 500 संबंधित है —बड़ी कंपनियों के स्टॉक सूचक से
- \* सही सुमेलित हैं-  
जापान - निक्की  
सिंगापुर - एस.टी.आई  
यू.के. - एफ.टी.एस.ई.  
यू.एस.ए. - नास्डाक
- \* भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय है —मुंबई में
- \* नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक हैं  
—भारतीय स्टेट बैंक, एल.आई.सी. और जी.आई.सी. तथा आई.डी.बी.आई.
- \* 'निक्की' है —टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक
- \* संवेदी सूचकांक (Sensex) में चढ़ाव का तात्पर्य है —बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों के मूल्य में समग्र चढ़ाव
- \* 'बी.एस.ई. सेंसेक्स' शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव का एक सूचकांक है। इस सूचकांक में जितनी कंपनियों को सम्मिलित किया जाता है, उनकी संख्या है —30
- \* बी.एस.ई. ग्रीनेक्स में कंपनियां सम्मिलित हैं —25
- \* भारत के प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार करने वाला बाजार है —राष्ट्रीय शेयर बाजार
- \* भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव का कारण है  
—विदेशी कोषों का अंतःप्रवाह और बाह्य प्रवाह, विदेशी पूंजी बाजारों में उच्चावचन तथा मौद्रिक नीति के परिवर्तन आदि
- \* 'दलाल स्ट्रीट' स्थित है —मुंबई में
- \* बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य है —कीमते
- \* भारत में आयोग द्वारा विनियमित होता है —जिंस फ्यूचर्स व्यापार
- \* कथन (A) : सभी व्यापारी मूल्य-बढ़ोत्तरी से लाभ कमाते हैं।  
कारण (R) : मूल्य बढ़ोत्तरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। —(A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

- \* मुद्रास्फीति के कारण —वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है
- \* द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है, तो —ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी
- \* साहूकार, ऋणी, बचत खाता एकाउंट रखने वाले तथा राजकीय पेंशनर में से मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है —ऋणी
- \* मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है, जब —वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रहे
- \* भारत में मुद्रास्फीति दर की माप होती है —उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिकों का जीवन-निर्वाह लागत सूचकांक के आधार पर
- \* भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है —थोक मूल्य सूचकांक
- \* फिलिप्स वक्र व्यक्त करता है —मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के संबंध को
- \* अवस्फीति —यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है
- \* स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप्य कभी-कभी 'आधार प्रभाव' (Base Effect) पर लगाया जाता है। यह 'आधार प्रभाव' है —विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है
- \* वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं —21
- \* कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु प्रयोग किया जाता है —औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का
- \* भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है —उपभोक्ता कीमत सूचकांक
- \* शहरी गैर-श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित किया जाता है —केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) द्वारा
- \* भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है —सावधि जमाएं
- \* भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में सम्मिलित है —विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर.)
- \* भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है —स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- \* भारतीय व्यावसायिक बैंक जिसने सबसे पहले चलती-फिरती ATM सेवा प्रारंभ की —आईसीआईसीआई बैंक
- \* भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन के पद पर कार्यरत हैं —श्री रजनीश कुमार
- \* भारतीय बैंक जिसने चीन में अपनी शाखा सबसे पहले खोली है —भारतीय स्टेट बैंक
- \* 'सिमपली क्लिक' क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है —एस.बी.आई. द्वारा
- \* निजी भारतीय बैंकों में से जिसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की है —एक्सिस बैंक
- \* दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन में संलग्न है —आई.सी.आई.सी.आई. (ICICI), आई.डी.बी.आई. (IDBI) तथा आई.एफ.सी.आई. (IFCI)
- \* वह बैंक जो मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है —सिडबी (SIDBI)
- \* शब्द बुल (Bull) तथा बियर (Bear) जुड़े हैं —शेयर बाजार से
- \* वित्तीय निवेशों के विशिष्ट व्यवहार में, मंदड़िया (Bear) शब्द द्योतक है —उस निवेशक का, जो यह महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है।
- \* तेजड़िया, मंदड़िया, दलाल और स्टैग में से वह जो शेयर बाजार में सटोरिया नहीं है —दलाल
- \* इन्साइड ट्रेडिंग संबंधित है —शेयर बाजार से
- \* पूंजी-बाजार से आशय है —शेयर बाजार से
- \* विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है —ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो।
- \* जिला साख योजना बनाई जाती है —लीड बैंक के अंतर्गत
- \* लीड बैंक का कार्य किया जाता है —इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा
- \* लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि —प्रत्येक बैंक घघन विकास के लिए पृथक-पृथक जिलों को अपनाएं
- \* अग्रणी बैंक (लीड बैंक) योजना प्रारंभ हुआ था —दिसंबर, 1969 में
- \* 'गिल्ट-एज्ड' बाजार संबंधित है —सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से
- \* 'स्मार्ट मनी' शब्द का प्रयोग होता है —क्रेडिट कार्ड में
- \* 'प्लास्टिक मनी' कहा जाता है —क्रेडिट कार्ड को
- \* दिल्ली मेट्रो का रेल कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक बटुआ, राष्ट्रीयकृत बैंक का साख-पत्र तथा एयरटेल मुद्रा में से पूर्व भुगतानित भुगतान उपकरण नहीं है —राष्ट्रीयकृत बैंक का साख-पत्र

- \* 'प्रतिच्छाया बैंकिंग' है —गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना
- \* भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है —सी.आर.आर. और एस.एल.आर. को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश तथा ब्याज दर का अविनियमन
- \* वित्त क्षेत्रक सुधार पर नरसिम्हन समिति ने सुझाव दिया —एस.एल.आर. और सी.आर.आर. कम करने का
- \* भारत में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार समिति, 2008 के अध्यक्ष थे —रघुराम राजन
- \* ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण —क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक प्रदान करते हैं
- \* वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोक-लुभावन ऋण (टीजर लोन) आर्थिक चिंता का विषय हैं, क्योंकि —लोक-लुभावन ऋण (टीजर लोन) अधोमुख ऋणों (सब-प्राइम लेंडिंग) का ही एक रूप समझे जाते हैं तथा बैंकों को यह जोखिम रहता है कि भविष्य में उनके ऋण चुकता न हों।
- \* यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है, तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा —वृद्धि
- \* रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा-निर्गमन करता है —स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, तथा भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले में
- \* भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझावों हेतु एक समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष थे —वाई.एच. मालेगाम
- \* 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (माइक्रो-फाइनेंस इंस्टीट्यूशन) स्थापित किए गए —मालेगाम समिति
- \* नरसिम्हन समिति का संबंध है —बैंकिंग संरचना सुधारों से
- \* भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विमल जालान पैनल गठित किया गया था —नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन-पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए
- \* भारत के 'विनिवेश आयोग' का प्रथम अध्यक्ष —जी. वी. रामकृष्ण
- \* निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति मिली —वर्ष 1993 में
- \* यूनिट स्कीम 1964 चर्चा का विषय रही है, क्योंकि —इसका शुद्ध मूल्य शेयर बाजार में लंबी मंदी के कारण काफी कम हो गया है
- \* वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष बनाया गया था —अभिजीत सेन को
- \* थोक मूल्य सूचकांक के मापन में सबसे अधिक भार (Weightage) दिया जाता है —विनिर्मित उत्पाद क्षेत्र को
- \* भारत सरकार द्वारा जारी की गई थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index-WPI) की नई शृंखला है —2011-12
- \* 'औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक' (कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स) निकालता है —श्रम ब्यूरो
- \* औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है —2011-12
- \* I. यह शीर्ष बैंक है।  
II. यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है।  
III. यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है।  
IV. यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है।  
RBI के संदर्भ में उपर्युक्त कथनों में से सत्य कथन हैं —कथन I, II एवं IV
- \* भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :  
1. वह केंद्र सरकार का बैंकर है।  
2. वह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है।  
3. वह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है।  
4. वह भारत सरकार के ऋणादान कार्यक्रम को संचालित करता है।  
—उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं
- \* सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी के कारण हैं —द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट तथा प्रभावी मांग में वृद्धि
- \* भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है —तरलता विनियमन, विलय एवं अधिग्रहण पर नियंत्रण, शाख विस्तार आदि
- \* भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई —वर्ष 1935 में
- \* साख नियंत्रण, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में, मौद्रिक नीति का निर्माण तथा साख सृजन में से वह एक जो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है —साख सृजन करना
- \* करेंसी का नियमन, विदेशी व्यापार का नियमन, साख का नियमन तथा देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली एवं प्रबंध में से वह एक जो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है—विदेशी व्यापार का नियमन करना
- \* भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण करता है —भारतीय रिजर्व बैंक

- \* भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंकरों के बैंक (केंद्रीय बैंक) के रूप में कार्य करता है, इसका अर्थ है
  - अन्य बैंक RBI के पास अपनी जमा संचित रखते हैं, आवश्यकता के समय RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है तथा RBI वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है।
- \* भारत का केंद्रीय बैंक है —रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
- \* बैंकरों का बैंक है —भारतीय रिजर्व बैंक
- \* भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख-रखाव किया जाता है
  - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा
- \* भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 'सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं' का उद्देश्य है
  - केंद्रीय बैंक को, बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की सक्षमता प्रदान करना
- \* 'सीमांत स्थायी सुविधा दर' तथा 'निवल मांग और सावधि देयताएं' पदबंध कभी-कभी समाचार में आते रहते हैं। उनका प्रयोग किया जाता है
  - बैंक कार्य के संबंध में
- \* वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देता है
  - सांविधिक तरलता अनुपात (स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो) के माध्यम से
- \* 'कोर बैंकिंग समाधान' (Core Banking Solutions) पद कभी-कभी समाचारों में देखा जाता है। यह है
  - बैंक की शाखाओं का वह तंत्र जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है, चाहे उन्होंने अपना खाता कहीं भी खोल रखा हो
- \* जब भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक नकदी अनुपात (स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो) को 50 आधार अंक (बेसिस प्वाइंट) कम कर देता है, तो संभावना होती है
  - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं
- \* 'वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद्' (Financial Stability and Development Council) के संदर्भ में सत्य कथन हैं
  - संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है, और अर्थव्यवस्था के समष्टि सविवेक (मैक्रोप्रूडेंशियल) पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण (मॉनिटरिंग) करता है।
- \* बैंक दर, सी.आर.आर., पी.एल.आर. तथा एस.एल.आर. में से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है
  - पी.एल.आर. को
- \* बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। इसे कहते हैं
  - SLR (सांविधिक तरल अनुपात)
- \* मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में करता है
  - भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
- \* भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग कहलाता है
  - नकद आरक्षित अनुपात (CRR)
- \* जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है, तो इसका तात्पर्य है
  - वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी
- \* भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है
  - जम्मू-कश्मीर तथा सिक्किम सरकार के बैंकिंग व्यापार का संचालन
- \* सही सुमेलित हैं-
 

(बैंकों के नाम)	(मुख्यालय की स्थिति)
इलाहाबाद बैंक	- कोलकाता
भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक	- लखनऊ
इंडियन ओवरसीज बैंक	- चेन्नई
- \* 'राज्य भविष्य निधि' के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है, उसको जमा किया जाता है
  - सार्वजनिक लेखा निधि में
- \* वाणिज्यिक बैंकों में गैर-निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ है
  - ऐसे ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती
- \* 1. बाजार ऋणादान, 2. ट्रेजरी बिल्स, 3. भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां
  - उपर्युक्त में से आंतरिक ऋण के घटक हैं —तीनों
- \* जनवरी, 2005 में 'फाइनेंशियल इन्क्लूजन' पर बनाई गई समिति के अध्यक्ष थे
  - सी. रंगराजन
- \* वित्तीय सम्मिलन को प्रोत्साहित किया जा सकता है
  - योग्य लाभार्थियों को 'विशिष्ट साख पत्र' जारी करके, निम्न आय वर्ग के लोगों को 'शून्य' अथवा न्यूनतम अवशेष से बैंकिंग सेवाएं तथा कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके।
- \* वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक हैं
  - निम्न आय, निरक्षरता तथा बैंक शाखाओं का अभाव आदि

- \* वित्तीय समावेशन पर संस्तुतियां दी गई हैं  
—रंगराजन समिति द्वारा
- \* रंगराजन समिति का गठन किया गया था —बैंकिंग सुधार के लिए
- \* भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इन बैंकों की स्थापना की सिफारिश की है  
—नचिकेत मोर समिति ने
- \* वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है  
—बैंकिंग अधो:संरचना को सिकोड़ना
- \* 'स्वाभिमान' नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। इसका प्रमुख उद्देश्य है  
—ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना
- \* भारत में शुरू की गई 'स्वाभिमान योजना' संबंधित है  
—ग्रामीण बैंकिंग से
- \* कभी-कभी समाचारों में आने वाले 'बिटकॉइंस' (Bitcoins) के संदर्भ में सत्य कथन हैं  
—बिटकॉइन के पते वाला कोई भी व्यक्ति, बिटकॉइन के पते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइंस भेज सकता है या उससे प्राप्त कर सकता है। इसकी ऑनलाइन अदायगी, दोनों तरफ में से किसी भी तरफ की पहचान जाने बिना की जा सकती है।
- \* सेबी (SEBI), सेल (SAIL), सिडबी (SIDBI) तथा नाबार्ड (NABARD) में विपणन संस्था है  
—सेल (SAIL)
- \* भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई —वर्ष 1956 में
- \* 1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 2. अग्रणी बैंक योजना, 3. नाबार्ड तथा 4. भारतीय स्टेट बैंक के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम है  
—4, 2, 1, 3
- \* भारत में सुलभ मुद्रा बनती है  
—जनता के पास करेंसी, बैंकों की मांग जमाराशियों तथा भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमाराशियों के योग से
- \* 1. बैंकों के पास मांग जमा, 2. बैंकों के पास सावधिक जमा, 3. बैंकों के पास बचत जमा तथा 4. करेंसी उपर्युक्त परिसंपत्तियों का तरलता के घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम है  
—4-1-3-2
- \* भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है  
— बृहद मुद्रा/आरक्षित मुद्रा के रूप में
- \* विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है, कहलाती है  
—गर्म मुद्रा (Hot Money)
- \* बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा के सृजन का प्रभाव  
—सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना होती है
- \* भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था —अवध कॉमर्शियल बैंक
- \* भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी  
—अप्रैल, 2000 में
- \* सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है  
—इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) का
- \* इरडा (IRDA) नियमन करती है  
—बीमा कंपनियों का
- \* आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है  
—बीमा क्षेत्र से
- \* बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट का अधिनियमन तथा पहली पंचवर्षीय योजना लागू करने, में से सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी  
—बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट का अधिनियमन
- \* 'एक्चुअरीज' शब्द संबंधित है  
—बीमा से
- \* 'पुनर्क्रय विकल्प' का प्रयोग किया जाता है  
—भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मुद्रा बाजार में साख नियमन के लिए
- \* रेपो दर को नियमित करता है  
—भारतीय रिजर्व बैंक
- \* विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है  
—भारतीय रिजर्व बैंक
- \* अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक, जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है, उसे कहा जाता है  
—रेपो दर
- \* वह दर, जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं, जानी जाती है  
—रिवर्स रेपो दर से
- \* बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि  
—केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है
- \* किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है, तो वह  
—अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा
- \* भारत में सहयोग निधियों का नियमन करती है  
—सेबी (SEBI)
- \* सेबी अधिनियम पारित हुआ था  
—वर्ष 1992 में
- \* भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है  
—भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी)
- \* भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने नियामक शक्तियां सौंपी है  
—सेबी (SEBI) को
- \* भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष (Accounting year) है  
—जुलाई-जून
- \* किसी कंपनी के डिबेंचर धारक उसके  
—लेनदार होते हैं
- \* चर आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई साधन हैं  
—मुद्रा नीति के

- \* भारत में 'मुद्रा एवं साख' का नियंत्रण किया जाता है  
—भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा
- \* अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी —केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करने तथा सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिए गए ऋण के परिणामस्वरूप
- \* भारतीय रिजर्व बैंक के ओपेन मार्केट ऑपरेशन से आशय है  
—सिक्वोरिटीज में व्यापार करना
- \* भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 'खुला बाजार प्रचालन' निर्दिष्ट करता है  
—RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय को
- \* किसी बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (एन.बी.एफ.आई.) के बीच अंतर यह है कि —बैंक अपने ग्राहकों की पूरी शृंखला के साथ वित्त संबंधी अनेक क्रिया-कलापों में संलग्न होता है, जबकि गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का मुख्यतः बड़े उद्यमों की आवधिक ऋण आवश्यकताओं से संबंध होता है।
- \* भारत में गैर-बैंकिंग कंपनियों (NBFCs) के संदर्भ में सत्य कथन है —ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप (डिमांड डिपोजिट) स्वीकार नहीं कर सकते।
- \* भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य है  
—कृषि, लघु (माइक्रो) एवं छोटे उद्यम तथा दुर्बल वर्ग को ऋण देने से
- \* भारतीय यूनिट ट्रस्ट के उद्देश्य हैं —लोगों की बचत को एकत्र करना, अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना तथा धन को इस प्रकार विनियोजित करना जिससे औद्योगिक विकास का संवर्धन हो
- \* भारत में चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन है —न्यूनतम सीमा या मार्जिन निर्धारण, नैतिक दबाव, साख की राशनिंग, उपभोक्ता उधार का नियमन तथा साख स्वीकृतिकरण योजना आदि
- \* भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मौद्रिक नीति के घटक हैं —बैंक-दर, खुली बाजार कार्रवाई (ओपेन मार्केट ऑपरेशन), सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा परिवर्तनीय कोष अनुपात आदि
- \* सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु 'छाया कीमतों' की अवधारणा को प्रतिपादित किया था —जे. टिनबरगिन ने
- \* भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया था —जुलाई, 1969 में
- \* भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में शामिल हैं —ग्राहकों की ओर से शेयरों एवं प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री तथा वसीयतों के लिए निष्पादक तथा न्यासी के रूप में कार्य करना आदि।
- \* निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :  
1. गोरवाला समिति की संस्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई।  
2. छः वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल, 1980 को हुआ। उपरोक्त कथनों में से —दोनों कथन सत्य हैं
- \* मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ब्याज दर को कम करना तथा वस्तुओं की राशनिंग में से मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है —ब्याज दर को कम करना
- \* भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में सही है —घटा हुआ मुद्रा परिचलन (मनी सर्कुलेशन), मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है।
- \* किसानों को साख, जनता की जमा (डिपॉजिट), भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण, उद्योगों की मांग जमा (डिपॉजिट) में से एक वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति है —किसानों को साख
- \* कथन (A) : सरकार के बजट में घाटे का एक बड़ा स्रोत अर्थ साहाय्य है।  
कारण (R) : भारतीय कृषि में विकसित देशों की तुलना में अर्थ साहाय्यों का स्तर बहुत अधिक है। —(A) सत्य है, परंतु (R) गलत है।
- \* एकजिम बैंक, आईडीबीआई, नाबार्ड तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में से भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है —सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- \* भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक एक पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी के रूप में स्थापित हुआ —भारतीय रिजर्व बैंक के
- \* भारत में भविष्य निधि है —संविदा आधारित बचत
- \* भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप —बाजार की तरलता बढ़ जाती है
- \* बैंक दर, ब्याज की वह दर है जिस पर —भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है
- \* बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है, जो —भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है
- \* अगस्त, 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक की नीति समीक्षा के समय रेपो रेट था —6.50%

- \* भारतीय रिजर्व बैंक सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है  
—कथन सही नहीं है
- \* एक रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है  
—वित्त मंत्रालय के सचिव का
- \* भारतीय रिजर्व बैंक को — करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है  
—रु. 10,000 तक
- \* रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए —115 करोड़ रु. का
- \* भारत में 'मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली' आधारित है  
—न्यूनतम कोष प्रणाली पर
- \* भारत में सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत है  
—रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
- \* प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी, यह अवस्थित था  
—झांग (पंजाब) में
- \* भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है  
—लंबी अवधि के लिए
- \* राज्य सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, प्राथमिक ऋण समितियां तथा भूमि विकास बैंक में से कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है  
—भूमि विकास बैंक
- \* भूमि विकास बैंक भाग है  
—सहकारी साख संरचना का
- \* केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्यक्षेत्र है  
—जनपद स्तर पर
- \* सहकारी साख समितियों का ढांचा है  
—त्रि-स्तरीय
- \* उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं  
—सदस्यों द्वारा
- \* मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है  
—अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना
- \* वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है —राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
- \* भारत में निजी बैंक, विकास बैंक, निर्यात-आयात बैंक तथा पेंशन फंड्स में से वह संस्था जिसका महत्व सर्वाधिक कम हुआ है—पेंशन फंड्स का
- \* 'वाणिज्य प्रपत्र' साख का स्रोत है—कॉर्पोरेट (निगम) उद्योग के लिए
- \* लघु अवधि ऋण की अवधि है  
—अधिकतम 15 माह
- \* मूल्य स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व, आय एवं परिसंपत्तियों का साम्यिक वितरण तथा विदेशी विनिमय दर स्थिरता में से मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है  
—आय एवं परिसंपत्तियों का साम्यिक वितरण
- \* भारत में कागज़ी मुद्रा प्रथम बार शुरू की गई थी  
—वर्ष 1862 में
- \* अंतरराष्ट्रीय नकदी (लिक्विडिटी) की समस्या संबंधित है  
—डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं (हार्ड करेंसीज) की अनुपलब्धता से
- \* 'काली मुद्रा' है  
—यह अवैध आय है, जिस पर आय कर नहीं दिया गया है
- \* ADR, GDR तथा SDR में से कृत्रिम मुद्रा समझी जाती है—SDR
- \* भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में सही कथन नहीं है  
—बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी हैं
- \* कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए 'किसान क्लब' बनाए हैं  
—भारतीय स्टेट बैंक ने
- \* पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक है  
—न्यू बैंक ऑफ इंडिया
- \* समाचारों में प्रायः आने वाला 'बेसल III (Basel III) समझौता'  
—बैंकिंग क्षेत्रों के, वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करना तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास है
- \* बेसल II संबंधित है  
—किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों से
- \* विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ —1882 ई. में
- \* भारत में कार्य संचालन (Operate) कर रहे हैं, विदेशी बैंकों में से सबसे अधिक शाखाएं हैं  
—स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की
- \* सही सुमेलित हैं-  
ए. बी. एन. एमरो बैंक - नीदरलैंड्स  
बारक्लेज बैंक - लंदन (यू. के.)  
कूकमिन बैंक - द. कोरिया
- \* प्रतिभूति घोटाले से बंद हुआ —बैंक ऑफ कराड
- \* किसी मुद्रा का अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य निर्धारित होता है  
—संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं/सेवाओं की मांग तथा संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से
- \* भूटान, मलेशिया, मालदीव तथा सेशेल्स देशों में से वह एक जिसकी मुद्रा रुपया है  
—सेशेल्स
- \* बांग्लादेश की मुद्रा है  
—टका
- \* चीन की मुद्रा है  
—युआन (रेमिनबी)
- \* सही सुमेलित हैं-  
(मुद्रा) (देश)  
रिंगिट - मलेशिया  
बहत - थाईलैंड  
रुपियाह - इंडोनेशिया  
वॉन - दक्षिण कोरिया



- \* सही सुमेलित हैं—  
(देश) (मुद्रा)  
मेक्सिको - पेसो  
ऑस्ट्रिया - शिलिंग (वर्तमान में यूरो)  
जापान - येन  
सऊदी अरब - रियाल
- \* भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं —भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा
- \* भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है —क्रिसिल, केयर तथा इक्रा
- \* पूंजीगत लाभ से तात्पर्य है  
—किसी वस्तु या संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक रूप से वृद्धि होने या उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में होने वाली वृद्धि
- \* भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सी.आर.आर. में वृद्धि से  
—अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है।

## B. सामाजिक विकास

### मानव विकास

- \* भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण हैं —ग्रामीण जनसंख्या, विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति तथा लिंगानुपात आदि
- \* भारत के मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था  
—मध्य प्रदेश ने
- \* प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई और अमर्त्य कुमार सेन से दिल्ली में विमोचन कराया —मध्य प्रदेश ने
- \* मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है  
—जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का
- \* भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव (Sample Village) के लिए देता है —आधारिक संरचना, सुख-साधन शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधित सूचकांक
- \* कथन (A) : मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है।  
कारण (R) : इसकी बेरोजगारी दर देश में उच्चतम है।  
—(A) तथा (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- \* संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया है  
—महबूब-उल-हक द्वारा

- \* विकास के मानवीय पक्ष पर सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया  
—संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने
- \* यू.एन.डी.पी. का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बना है  
—दस प्रत्ययों (Indicators) से
- \* मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं, साक्षरता दर, जन्म के समय आयु संभावितता तथा  
—वास्तविक क्रय शक्ति पर प्रति व्यक्ति सकल देशी उत्पादन
- \* मानव विकास सूचकांक (ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स) में शामिल नहीं है  
—सामाजिक असमानता
- \* स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के साथ जीवन प्रत्याशा तथा सकल नाम निवेश (एनरोलमेंट) दर में से मानव विकास सूचकांक का एक भाग नहीं है  
—सकल नाम निवेश (एनरोलमेंट) दर
- \* मानव निर्धनता सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था  
—वर्ष 1997 की रिपोर्ट में
- \* मानवीय गरीबी सूचकांक विकसित किया गया —वर्ष 1997 में
- \* वयस्क शिक्षा जितनी ही अधिक होगी, शिशु मृत्यु दर उतनी ही कम होगी  
—यह कथन असत्य है
- \* सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है —भूटान ने
- \* दक्षिण एशिया का वह देश जिसने 'सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता' को अपने नागरिकों की 'कुशल क्षेम' को सूचकांक के रूप में माना है —भूटान ने
- \* निम्नलिखित पर विचार कीजिए :  
1. शिक्षा का अधिकार, 2. समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार तथा 3. भोजन का अधिकार में से 'मानव अधिकारों के अंतर्गत आते हैं  
—उपर्युक्त तीनों
- \* हरित सूचकांक (ग्रीन इंडेक्स) विकसित किया गया था  
—विश्व बैंक का पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुस्थिर विकास प्रभाग द्वारा
- \* दिसंबर, 2013 में जारी शैक्षिक विकास सूचकांक 2012-13 के तहत शीर्ष पांच स्थान प्राप्तकर्ता राज्य/केंद्रशासित प्रदेश हैं  
—पुडुचेरी, लक्षद्वीप, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एवं कर्नाटक

## रोजगार एवं कल्याण योजनाएं

- \* बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है, क्योंकि  
—गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है
- \* भारत में शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत सर्वाधिक है —केरल में
- \* कथन (A) : विकास की जंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है।  
कारण (R) : यह तब ही होता है, जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है।  
—(A) तथा (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

- \* कथन (A) : शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है।  
कारण (R) : ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है।  
—(A) तथा (R) दोनों सही हैं  
और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।
- \* बंधुआ मजदूर (उन्मूलन) अधिनियम स्थापित किया गया  
—वर्ष 1975 में
- \* 'बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम' पास हुआ था —वर्ष 1976 में
- \* भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है —संरचनात्मक
- \* छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है —ऐसा कार्य जिसको कम व्यक्ति भी कर सकते हैं, में अधिक व्यक्तियों का लगे रहना।
- \* प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि  
—श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है
- \* भारत में छिपी हुई बेरोजगारी लक्षण है, मुख्यतया—प्राथमिक क्षेत्र का
- \* भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है —कृषि क्षेत्र में
- \* भारत में बेरोजगारी मापन की विधियों में से एन.एस.एस.ओ. द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है —चालू मासिक स्तर विधि
- \* भारत में एन.एस.एस.ओ. द्वारा बेरोजगारी के आकलन के लिए प्रयुक्त की जा रही है —चालू दैनिक प्रास्थिति, चालू साप्ताहिक प्रास्थिति तथा सामान्य प्रधान प्रास्थिति
- \* भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है —एन.एस.एस.ओ.
- \* विनिर्माण, निर्माण, वित्तीय सेवाएं तथा मिश्रित खेती में से क्षेत्रक की वृद्धि दर की रोजगार प्रत्यास्थता बहुत कम है —विनिर्माण क्षेत्र की
- \* 'कौशल विकास पहल' क्रियाशील हुआ है —मई, 2007 में
- \* 'अपना गांव, अपना काम' योजना प्रारंभ की गई  
—1 जनवरी, 1991 को
- \* 'अपना गांव, अपना काम' योजना का उद्देश्य है  
—गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न कर गरीबी दूर करना
- \* प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में  
A. योजना में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करती है।  
B. योजना के अंतर्गत रु. 8000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।  
C. योजना के अंतर्गत प्रत्येक एलपीजी गैस कनेक्शन पर बीपीएल परिवार को रु. 2,800 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।  
D. योजना देश भर में 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाएगी।  
उपर्युक्त कथनों में से —कथन A, B तथा D सत्य हैं
- \* 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना को भारत में प्रारंभ किया गया  
—जनवरी, 2015 में
- \* 01 जून, 2015 से लागू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में सत्य कथन हैं  
—यह एक निजी दुर्घटना प्रतिपूर्ति योजना है, जो 18 से 70 वर्ष के बीच किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है तथा इसकी वार्षिक बीमा किस्त की देय राशि रु. 12 है
- \* 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' प्रारंभ की गई है  
—देश में वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इंकलूजन) को प्रोत्साहित करने हेतु
- \* 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' आरंभ की गई —28 अगस्त, 2014 में
- \* पहल (PAHAL) योजना के संदर्भ में सही कथन हैं  
—यह जैम (JAM- जनधन, आधार तथा मोबाइल) का प्रथम प्रकार है। इसके तहत डीबीटी (DBT) के माध्यम से एलपीजी (LPG) अनुदान को हस्तांतरण सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में होता है।  
का प्रथम प्रकार है तथा उपभोक्ताओं के बैंक खातों में होता है।
- \* नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम आरंभ किया गया —महाराष्ट्र में
- \* रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रत्याभूत करने के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार करती है —गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार के कम से कम एक पुरुष और एक महिला को
- \* भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है  
—आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन तथा जनसंख्या वृद्धि
- \* तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तथा जनशक्ति नियोजन का अभाव में से एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है —प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि
- \* 'कुरुक्षेत्र' के बारे में सत्य है  
—यह ग्रामीण विकास हेतु एक अग्रणी पुस्तिका है
- \* TRYSEM, CRY, JRY तथा IRDP में से कोई एक स्कीम 'ग्रामीण विकास' के लिए नहीं है —CRY
- \* ई.ए.एस. (EAS), ट्राईसेम (TRYSEM), जे.आर.वाई. (JRY) तथा आर.एल.ई.जी.पी. (RLEGP) योजनाओं को लागू करने का सही कालानुक्रमिक क्रम है —ट्राईसेम (1979), आर.एल.ई.जी.पी. (1983), जे.आर.वाई. (1989) तथा ई.ए.एस. (1993)
- \* ट्राईसेम एक कार्यक्रम है —ग्रामीण विकास का

- \* आर.एल.ई.जी.पी., आई.आर.डी.पी., एन.आर.ई.पी. तथा एम.आर.टी.पी. में से निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है  
—एम.आर.टी.पी.
- \* ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा ग्रामीण उद्योग में से एक कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष (RIDF) के अंतर्गत नहीं आता  
—ग्रामीण उद्योग
- \* ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंध को संचालित करती है  
—नाबार्ड
- \* वह राज्य जिसने 'अटल खाद्यान्न योजना' प्रारंभ की —उत्तराखंड ने
- \* 'अटल पेंशन योजना' के संबंध में सत्य कथन हैं  
—यह एक न्यूनतम गारंटीड पेंशन योजना है, जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाता है, साथ ही इसमें अभिदाता (सब्सक्राइबर) की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि सुनिश्चित रहती है
- \* 11 अक्टूबर, 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस की वर्षगांठ पर प्रारंभ किया गया  
—सांसद आदर्श ग्राम योजना कार्यक्रम
- \* निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है  
—शौच स्वच्छता
- \* 'गोकुल ग्राम योजना' संबंधित है  
—गुजरात से
- \* 'DWCRA' योजना संबंधित है  
—गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिला सदस्यों को ऊपर उठाना
- \* सही सुमेलित हैं-  
(भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं) (उनका सारतत्व)
- नई रोशनी कार्यक्रम - महिला सशक्तीकरण
- दिशा सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण
- प्रधानमंत्री जन-धन योजना - वित्तीय समावेशन
- स्वावलंबन योजना - नई पेंशन प्रणाली
- \* लड़कियों के लिए 'भाग्यश्री' योजना प्रारंभ किया —महाराष्ट्र ने
- \* राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई  
—श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा
- \* हथकरघा क्षेत्र में 'राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना' प्रारंभ की गई  
—कपड़ा मंत्रालय द्वारा
- \* 'स्वावलंबन योजना' प्रारंभ की गई थी  
—वर्ष 2010 में
- \* महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करवाने वाली योजना का नाम है —स्वावलंबन योजना
- \* 'असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम' पारित हुआ  
—वर्ष 2008 में
- \* 'स्वाधार' योजना है —कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए
- \* 1 मई, 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई  
—उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से
- \* भारत सरकार द्वारा चलाया गया 'मिशन इंद्रधनुष' संबंधित है  
—बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से
- \* गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य देख-रेख की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा जून, 2011 में प्रवर्तित महत्वाकांक्षी योजना का नाम है —जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
- \* भारत निर्माण में कार्यों की मदें सम्मिलित हैं  
—सिंचाई से त्वरित गति से लाभ देने वाले प्रोग्राम, नदी परियोजनाओं की इंटरलिंगिंग तथा जल 'बॉडीज' (Water bodies) की मरम्मत, पुनरुद्धार तथा जीर्णोद्धार की योजना
- \* 2005-06 में प्रारंभ की गई 'भारत निर्माण' योजना में सम्मिलित है  
—ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई एवं निर्धन आवासों का निर्माण
- \* भारत निर्माण योजना का संबंध है  
—अवस्थापना विकास से
- \* 'भारत निर्माण' विकसित करने का कार्यक्रम है  
—भारतीय ग्रामीण जीवन को
- \* भारत निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है —सर्व शिक्षा अभियान
- \* राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है —भारत निर्माण का
- \* अटल नदीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) में मुख्य रूप से जोर दिया गया है  
—जलापूर्ति, सीवरेज सुविधाएं, सार्वजनिक यातायात सुविधाएं, पार्क एवं मनोरंजन केंद्रों का निर्माण मुख्यतया बच्चों के लिए तथा जल प्लावन को रोकने हेतु बाढ़ के पानी का निर्गम
- \* अटल शहरी पुनरुद्धार एवं परिवर्तन मिशन (अमृत) का संबंध पुनः चमकाने से है  
—शहरी अवस्थापना को
- \* 'एक रुपये में एक किग्रा. चावल' योजना शुरू की है —तमिलनाडु ने
- \* 'स्वच्छ भारत' कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने 6 नवंबर, 2015 को उपकर लगाया है। इस उपकर की दर है  
0.50 प्रतिशत
- \* संगम योजना का उद्देश्य है  
—विकलांगों की सहायता
- \* 'संकल्प' परियोजना जुड़ी है, —एच.आई.वी./एड्स के समापन से
- \* राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना की गई  
—वर्ष 1979 में
- \* जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई —सातवीं पंचवर्षीय योजना में
- \* जवाहर रोजगार योजना के विषय में सही कथन है  
—इस योजना के अधीन जनित रोजगार का 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित है।

- \* जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य है —ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं, बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना।
- \* जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल है —ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों के सृजन पर
- \* भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं। यदि उस गांव की जनसंख्या हो —500
- \* प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्य हैं —गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना तथा पक्की सड़क बनाना
- 94. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है —सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु, उन गांवों में जो सड़क से भली-भांति संबद्ध नहीं हैं
- \* 'प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना' का ध्येय है —ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें आदि।
- \* दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रारंभ की गई है —ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु
- \* स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना में सम्मिलित किया गया है —आई.आर.डी.पी., ट्राइसेम तथा दवाकरा (DWCRA) को
- \* स्वर्ण जयंती स्व-रोजगार योजना का स्थापना वर्ष है —1999
- \* जून, 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में प्रवर्तित किया गया है —स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना को
- \* MGNREGA, NRLM, RMSA, तथा STEP में से कौन-सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है —RMSA
- \* महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ था —वर्ष 2005 में
- \* 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का प्रयास करता है —'स्वयं सहायता समूहों' को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके
- \* सही सुमेलित हैं-
 

कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना	-	2001
स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना	-	1999
रोजगार गारंटी योजना	-	2006
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	-	2000
- \* सही सुमेलित हैं-
 

सर्व शिक्षा अभियान	-	2001
साक्षर भारत मिशन	-	2009
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड	-	1987
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन	-	1988
- \* सही सुमेलित हैं-
 

(कार्यक्रम)	(शुरू करने का वर्ष)
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	- 1999
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	- 1997
जवाहर रोजगार योजना	- 1989
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	- 2005
- \* राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है, क्योंकि —यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है।
- \* राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत, एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है, उनकी संख्या है —100 दिन
- \* राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGS) प्रारंभ में 200 जनपदों में शुरू की गई थी। वर्ष 2007-08 के बजट में इसके विस्तार का प्रस्ताव था —330 जनपदों में
- \* राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रारंभ में लागू किया गया —200 जिलों में
- \* राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना समूचे देश में लागू की गई —1-4-2008 से
- \* नरेगा (NREGA) को मनरेगा (MNREGA) नाम दिया गया —2 अक्टूबर, 2009 को
- \* नरेगा (NREGA) के संबंध में जो असत्य है —सरकार के अन्य कार्यक्रमों की भांति इस कार्यक्रम में भी पारदर्शिता एवं जवाबदेही संभव नहीं है
- \* राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) नहीं करता है —प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर एक वयस्क को एक वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी
- \* आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना तथा असंगठित वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा अधिनियम में से एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है —स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

- \* मध्याह्न भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, लुक ईस्ट नीति तथा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रमों में से भारत सरकार का सामाजिक विकास कार्यक्रम नहीं है  
—लुक ईस्ट नीति
- \* स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो 1-12-1997 से लागू हुई, का उद्देश्य है  
—शहरी बेरोजगारी अथवा अल्प रोजगार गरीबों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना है
- \* सही सुमेलित हैं-
 

औद्योगिक वित्त	- सिडबी
सामाजिक सुरक्षा उपाय	- भारत निर्माण
ग्रामीण साख	- नाबार्ड
शहरी रोजगार	- एस.जे.एस. आर. वाई.
- \* भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ  
—2 अक्टूबर, 1952 को
- \* सामुदायिक विकास कार्यक्रम (जिसे 2 अक्टूबर, 1952 से प्रारंभ किया गया) ने रास्ता तैयार किया  
—अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास का
- \* भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं  
—एस.के. डे
- \* राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है  
—हैदराबाद में
- \* आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है  
—ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हों, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना
- \* 'कर्मचारी राज्य बीमा योजना' के अंतर्गत 'सामाजिक सुरक्षा' कवच प्राप्त कर सकते हैं  
—होटल तथा रेस्तरां, मोटर परिवहन उद्योग, समाचार-पत्र प्रतिष्ठान तथा निजी चिकित्सा संस्थान के कर्मचारी
- \* आम भारतीय बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है  
—ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को
- \* आम आदमी बीमा योजना (ए.ए.बी.वाई.) को प्रारंभ किया गया  
—2 अक्टूबर, 2007 को
- \* प्रस्तावित जननी सुरक्षा स्कीम प्रतिस्थापित करेगी  
—राष्ट्रीय मातृत्व लाभ परियोजना को
- \* राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में, प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 'आशा' (ASHA) के कार्य हैं-  
—स्त्रियों को प्रसव-पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र तक साथ ले जाना, गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट का प्रयोग करना तथा पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना
- \* राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था  
—12 अप्रैल, 2005 को
- \* राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया  
—दसवीं पंचवर्षीय योजना में
- \* राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा हुई  
—वर्ष 1983 में
- \* कापार्ट का संबंध है  
—ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से
- \* कापार्ट (CAPART) एक स्ववित्त संस्था है, जो कार्य करती है  
—ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत
- \* ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ किया गया,  
—वर्ष 1948 में
- \* निर्मल भारत अभियान योजना का संबंध है  
—गांवों के विकास से, मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों से तथा निम्न आय समूहों के लिए भवन निर्माण से।
- \* शौचालय क्रांति है  
—गांव तथा नगरों में लोगों को बहाव वाले शौचालय बनाने हेतु अनुदान तथा ऋण उपलब्ध कराने की सरकारी योजना।
- \* 'समेकित बाल विकास सेवाएं' नामक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ  
—वर्ष 1975 में
- \* 'आधार' एक कार्यक्रम है  
—भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए
- \* यू.आई.डी. योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव है  
—थेम्बली (नंदुरबार, महाराष्ट्र)
- \* कथन (A) : संप्रति भारत में गरीबी की व्यापकता के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है।  
कारण (R) : गरीबी निवारण कार्यक्रमों में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं।  
—(A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- \* राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य है  
—अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन
- \* 'न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम' का उद्देश्य है, आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना  
—ग्रामीण-नगरीय जनसंख्या को
- \* 'न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम' की संकल्पना पर्यायवाची है  
—अधोसंरचना-विकास दृष्टिकोण का
- \* ग्रामीण जलापूर्ति, सामाजिक वानिकी, प्राथमिक शिक्षा तथा नगरों की मलिन बस्तियों का सुधार में से एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है  
—सामाजिक वानिकी

- \* शहरी व्यष्टि उद्यम, शहरी मजदूरी के बदले रोजगार तथा आवास तथा आश्रय का उन्नयन भाग है  
—नेहरू रोजगार योजना का
- \* सही सुमेलित हैं-  
(कार्यक्रम) (प्रारंभ का वर्ष)  
ट्राइसेम - अगस्त, 1979  
एन.आर.ई.पी. - अक्टूबर, 1980  
जे.आर.वाई. - अप्रैल, 1989  
एस.जी.एस.वाई. - अप्रैल, 1999
- \* सही सुमेलित हैं-  
जनश्री बीमा योजना - 2000  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन - 2005  
एम.जी. नरेगा - 2009  
आम आदमी बीमा योजना - 2007
- \* भारतीय सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम में शामिल नहीं है  
—राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष
- \* 'समन्वित ग्रामीण विकास योजना' (I.R.D.P.) का मुख्य लक्ष्य है  
—ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना
- \* समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) शुरू हुआ था  
—वर्ष 1980 में
- \* ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा ग्रामीण उद्योग में से एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है  
—ग्रामीण उद्योग
- \* प्राथमिक शिक्षा कोष (पी.एस.के.) की स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी  
—केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए शिक्षा उपकर हेतु
- \* न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण तथा भूमि-सुधार में से एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है  
—अर्थव्यवस्था का उदारीकरण
- \* भारत में 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजना लागू की गई  
—महिला एवं बाल-कल्याण मंत्रालय
- \* 'प्रधानमंत्री आवास योजना' की समयावधि है —2015 - 2022
- \* इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता है  
—अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना
- \* राजीव आवास योजना का लक्ष्य है —मलिन बस्ती मुक्त भारत
- \* भारत सरकार ने 'सबके लिए आवास' योजना की शुरुआत की है  
—वर्ष 2022 तक
- \* केंद्रीय सरकार ने बालिका-शिशु के लिए जो योजना जारी की है, उसका नाम है  
—धन-लक्ष्मी
- \* कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किया गया था  
—वर्ष 2004 में
- \* 'जननी सुरक्षा योजना' कार्यक्रम का प्रयास है  
—संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, प्रसूति की लागत वहन करने हेतु मां को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना आदि
- \* संयुक्त राष्ट्र संघ ने 'सबके लिए शिक्षा' का लक्ष्य निर्धारित किया था  
—वर्ष 2015 तक
- \* सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा सभी को उपलब्ध कराना था  
—वर्ष 2007 तक
- \* सर्व शिक्षा अभियान है —6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चे के लिए
- \* शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है, उन बच्चों के अधिकार के निहित हैं, जो  
—प्राथमिक स्तर तक के हैं
- \* 'सर्व शिक्षा अभियान' में नामांकित होने योग्य है —6-14 वर्ष
- \* भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया  
—वर्ष 2001 में
- \* वर्ष 1995 में 'मध्याह्न भोजन' योजना चलाई गई थी  
—प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण हेतु
- \* प्राथमिक शिक्षा के लिए पौष्टिक अवलंब का राष्ट्रीय कार्यक्रम (नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन) आरंभ हुआ था  
—वर्ष 1995 में
- \* मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है  
—मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा
- \* स्कूल मैनेजमेंट (व्यवस्थापक), पंचायती राज संस्था, स्वयं सेवा समूह तथा ठेकेदार में से एक मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है  
—ठेकेदार
- \* 'मिड-डे-मील' योजना प्रारंभ हुई थी  
—वर्ष 1995 में
- \* उत्तर प्रदेश में 'मिड-डे-मील' कार्यक्रम आरंभ किया गया  
—वर्ष 1995 में
- \* भारत में अक्षयपात्र फाउंडेशन संबंधित है  
—प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन से
- \* उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए 'स्कूल चलो अभियान' शुरू हुआ  
—वर्ष 2000 में

- \* कथन (A) : उत्तर प्रदेश में 'शिक्षा मित्र योजना' ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है।  
कारण (R) : मानकानुसार अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है।

—(A) और (R) दोनों सही हैं और (A) की सही व्याख्या (R) है।

- \* जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ —वर्ष 1994 में
- \* केंद्र सरकार द्वारा एक नीति संबंधी लिए गए निर्णय के अनुसार, केंद्र सरकार बच्चों के मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार के अंतर्गत प्रभावी रूप से व्यय भार वहन करेगी —68 प्रतिशत

- \* केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए गए —वर्ष 1963 में
- \* ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है —प्राथमिक शिक्षा से
- \* भारत में, वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई 'इन्क्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसएबल्ड एट सेकेण्डरी स्टेज' योजना प्रदान की जाती है

—राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत

- \* स्वच्छ भारत अभियान द्वारा 'स्वच्छ भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है —वर्ष 2019 तक
- \* स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को प्रारंभ किया गया है —अक्टूबर, 2014 में

- \* 'विजन 2020 फॉर इंडिया' दस्तावेज संबंधित है —आर्थिक विकास से
- \* विजन 2020 है —भारत सरकार का एक कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का।

- \* ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किया था —डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने
- \* पूरा (प्रोवाइडिंग अर्बन एमीनिटीज इन रुरल-एरियाज) ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया —डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने

- \* प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं —केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को।

- \* दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान अवस्थित है —देहरादून में

- \* सही सुमेलित हैं—  
(संस्थान) (स्थान)
- राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान - देहरादून
- राष्ट्रीय अस्थिरोग विकलांग संस्थान - कोलकाता
- अली यावरजंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान - मुंबई
- राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान - सिकंदराबाद

- \* केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय है —चित्रकूट में
- \* विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है —8 सितंबर को
- \* 'वीमेन्स डे' (नारी दिवस) मनाया जाता है —8 मार्च को
- \* सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस मनाया जाता है —20 मार्च को
- \* विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है —15 मार्च को
- \* एड्वागोमी है —प्रौढ़ शिक्षा (Adult Education)का दूसरा नाम
- \* रूडसेट संस्थान के प्रारंभ करने का उद्देश्य है —बेरोजगार

ग्रामीण युवकों को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता एवं उद्यमिता प्रशिक्षण देना।

- \* वर्ष 2013 में 'रोशनी' शब्द समाचारों में था। यह संबंधित है —जनजातीय युवकों के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम से
- \* खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले खोला गया था —आंध्र प्रदेश में
- \* राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 के अनुसार, इस नीति से लाभांशित होंगे —15-29 वर्ष आयु वर्ग के युवा
- \* भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम को कहते हैं —15 सूत्रीय कार्यक्रम
- \* 'नालंदा परियोजना' कार्यक्रम है —अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का

- \* सही सुमेलित हैं—  
राष्ट्रीय महिला कोष - निर्धन महिलाओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना
- महिला समृद्धि योजना - ग्रामीण महिलाओं में बचत को प्रोत्साहन देना
- इंदिरा महिला योजना - महिलाओं की शक्ति संपन्नता
- महिला सामाख्या योजना - महिला समानता के लिए शिक्षा
- \* भारत में महिला समृद्धि योजना शुरू की गई —वर्ष 1993 में

## गरीबी (Poverty)

- \* 'निर्धनता का दुश्चक्र' की अवधारणा संबंधित है —नक्सल से
- \* कथन (A) : गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को एक अभिज्ञित समूह के रूप में मानने की आवश्यकता है।  
कारण (R) : इससे कार्यक्रम अभिकरणों को लक्षित करने में सहूलियत होती है। —(A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।
- \* कथन (A) : भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं।  
कारण (R) : अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा-सूखा भोजन करते हैं। —(A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

- \* जुलाई, 2013 में योजना आयोग द्वारा जारी गरीबी के नवीनतम आकलन के अनुसार  
—वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक गरीबी

प्रतिशतता वाला राज्य छत्तीसगढ़ (39.93%) है

- \* कथन (A): बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है।  
कारण (R): यहां विकास के स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है।  
—(A) तथा (R) दोनों सही हैं एवं (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

- \* भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है  
—बहु-आयामी गरीबी सूचकांक

- \* योजना आयोग द्वारा अप्रैल, 2011 में प्रसारित आंकड़ों के अनुसार, भारत में 2009-2010 में गरीबी का प्रतिशत घट कर हो गया है  
—32%

- \* भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण (नोडल एजेंसी) था  
—योजना आयोग

- \* दत्त समिति, लकड़ावाला समिति, चैलेय्या समिति तथा चक्रवर्ती समिति में से किसी एक के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है  
—लकड़ावाला समिति के आधार पर

- \* तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का अनुपात आकलित किया  
—37.2 प्रतिशत

- \* गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। निर्मला देशपांडे, वी. सिद्धार्थ, सुरेश तेंदुलकर तथा प्रो. जानकीरमन में से इस समिति के अध्यक्ष थे  
—सुरेश तेंदुलकर

- \* सही सुमेलित हैं-

सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 5 राज्य

(राज्य)	(गरीबों की संख्या (लाख में))
उत्तर प्रदेश	598.19
बिहार	358.15
मध्य प्रदेश	234.06
महाराष्ट्र	197.92
प. बंगाल	184.98
संपूर्ण भारत	2697.83

- \* सही सुमेलित हैं

—सर्वाधिक गरीबी प्रतिशतता वाले 5 राज्य

राज्य	निर्धनता अनुपात (प्रतिशत में)
छत्तीसगढ़	39.93
झारखंड	36.96
मणिपुर	36.89
अरुणाचल प्रदेश	34.67
बिहार	33.74
संपूर्ण भारत	21.92

- \* आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल तथा पंजाब राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा से नीचे न्यूनतम प्रतिशत का योगदान है  
—केरल में

- \* भारतवर्ष में गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं  
—29.5 प्रतिशत लोग

- \* विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 50 प्रतिशत से अधिक निर्धन इन चार राज्यों में निवास करते हैं

—बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में

- \* भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्यता की संस्तुति की गई है  
—2400 कैलोरी

- \* भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है  
—कैलोरी प्राप्ति से

- \* भारतीय योजना आयोग के अनुसार, गरीबी रेखा के लिए सही है  
—ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति रु. 26 प्रतिदिन तथा नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति रु. 32 प्रतिदिन

- \* भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है  
—परिवार का उपभोग व्यय

- \* भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित हैं  
—NSSO के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर।

- \* भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है  
—उपभोग आंकड़ा

- \* गरीबी रेखा निकालने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है  
—साक्षरता, को जबकि प्रति व्यक्ति औसत आय, भोजन में कैलोरी तथा एच.सी.आर. को प्रयोग में लाया जाता है।

- \* अपर्याप्त संवृद्धि दर, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, बेरोजगारी तथा बढ़ती निवेश दर में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है

—बढ़ती निवेश दर



- \* जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है  
—शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता
- \* विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था  
—समाज के कमजोर वर्ग के लिए
- \* सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है  
—गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना
- \* राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, निपुणता विकास कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना तथा असंगठित श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 में से एक सामाजिक संरक्षण का तरीका नहीं है  
—निपुणता विकास कार्यक्रम
- \* दीपक पारेख कमेटी अन्य चीजों के साथ-साथ गठित की गई थी  
—अवसंरचना के विकास और वित्तीयन हेतु उपाय सुझाने के उद्देश्य के लिए
- \* हाल में भारत सरकार ने महिला सशक्तीकरण के माध्यम से निर्धनता उन्मूलन हेतु महिला आत्म-सहायता समूहों को एक निम्न ब्याज दर पर ऋण देने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। वह ब्याज दर है  
—7.00%
- \* कथन (A) : मध्य प्रदेश को भारत का इथिओपिया कहा जाता है।  
कारण (R) : उसके प्रमुख लक्षण अत्यधिक बाल मृत्यु दर एवं कुपोषण हैं।  
—(A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
- \* अत्यधिक कुपोषण के कारण 'भारत का इथिओपिया' कहा जाता है  
—मध्य प्रदेश को
- \* आई.आर.डी.पी., ट्राइसेम, एन.आर.ई.पी. में से ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु योजना है  
—आई.आर.डी.पी., ट्राइसेम तथा एन.आर.ई.पी. (तीनों)
- \* 'गरीबी उन्मूलन' का नारा दिया गया था  
—छठी पंचवर्षीय योजना में
- \* सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया  
—भारत ने
- \* भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया — वर्ष 1952 में
- \* गरीबी उपशमन पर दक्षेस (SAARC) की मंत्रिस्तरीय सभा हुई थी  
—इस्लामाबाद में
- \* UNDP के समर्थन से 'ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व' द्वारा विकसित 'बहु-आयामी निर्धनता सूचकांक' में सम्मिलित है/हैं  
—पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति तथा सेवाओं से वंचन

## C. वैदेशिक क्षेत्र

### आयात-निर्यात

- \* कथन (A) : आर्थिक उदारीकरण की एक महत्वपूर्ण नीति साधन है, पूंजीगत माल पर आयात शुल्क में कमी।  
कारण (R) : आयात शुल्क में कमी से स्थानीय उद्यमियों को विश्व बाजार का सामना करने के लिए प्रौद्योगिकी का सुधार करने में सहायता मिलेगी।  
—(A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (A) की सही व्याख्या (R) नहीं करता है।
- \* माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है  
—भारतीय रिजर्व बैंक
- \* विगत कुछ वर्षों में मूल्य के संदर्भ में भारतीय निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण मद रहा है  
—अभियांत्रिकी माल
- \* वर्तमान में भारत से निर्यात अधिकतम होता है  
—अभियांत्रिकी माल का
- \* भारत के निर्यात व्यापार में सबसे बड़ा प्रतिशत हिस्सा है  
—इंजीनियरिंग संबंधी वस्तुओं का (24.4%)
- \* वर्तमान (2016-17) में भारतीय निर्यात में रत्नों एवं गहनों का प्रतिशत है, लगभग  
—15.7 प्रतिशत
- \* भारत सरकार की नई विदेशी व्यापार नीति की समयावधि है  
—1 अप्रैल, 2015 - 31 मार्च, 2020
- \* भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय की जाती है  
—पेट्रोलियम पदार्थ के आयात पर
- \* हाल के वर्षों में भारत में आयात की सबसे बड़ी मद है  
—पेट्रोलियम पदार्थ
- \* हीरे के निर्यात से भारत को काफी अधिक आय होती है। इसमें योगदान है  
—विशेषज्ञों की उपलब्धि जो आयातित हीरों की कटाई और पॉलिश करते हैं ताकि बाद में उनका निर्यात हो सके
- \* तिरुपुर, विश्व के अनेक क्षेत्रों में सुप्रसिद्ध है—बुने हुए वस्त्र के निर्यात हेतु
- \* भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है  
—निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए
- \* 'स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र' उसे कहते हैं, जहां  
—उद्यमियों को अवसंरचनात्मक (इन्फ्रास्ट्रक्चरल) सुविधाएं सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

- \* विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी —**अप्रैल, 2000** में
- \* एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित हुआ था —**कांडला** में
- \* भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र (ई.पी.जेड) का सृजन हुआ था —**कांडला** में
- \* कांडला, मुंबई, विशाखापत्तनम तथा तिरुवनंतपुरम में से वह एक जगह जहां 'मुक्त व्यापार क्षेत्र' नहीं है —**तिरुवनंतपुरम**
- \* बड़ोदरा प्रसिद्ध है —**पटोला सिल्क के लिए**
- \* निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र स्थापित किया गया —**सूरत** में
- \* विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम प्रभावी हुआ —**वर्ष 2006** में
- \* विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया —**मई, 2005** में
- \* फरवरी, 2006 में प्रभावी हुए SEZ एक्ट, 2005 के कुछ उद्देश्य हैं —**अवसंरचना तथा सुविधाओं का विकास, विदेशी स्रोतों से निवेश को प्रोत्साहन**
- \* 'सेज' (विशेष आर्थिक क्षेत्र) का उद्देश्य नहीं है —**विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना**
- \* वर्ष 1950 में अंतरराष्ट्रीय निर्यात में भारत का योगदान 1.85 प्रतिशत था, परंतु आज यह है, लगभग —**2.00 प्रतिशत**
- \* अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अधिकतम हिस्सेदारी है —**संयुक्त राज्य अमेरिका की**
- \* भारत को सर्वाधिक एल. एन. जी. की आपूर्ति करता है —**कतर**
- \* वर्तमान में भारत में सबसे अधिक सीधा विदेशी निवेश आकर्षित किया है —**सेवा क्षेत्र ने**
- \* ओ.ई.सी.डी., ओपेक, पूर्वी यूरोप तथा विकासशील देशों में से भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है —**ओपेक से**
- \* ऑयल पूल खाते की समाप्ति प्रभावित हुई —**1 अप्रैल, 2002** से
- \* भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग (मूल्य में) प्राप्त होता है —**चीन से**
- \* वर्तमान में भारत का शेष विश्व से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रतिशत हिस्सा जिन दो देशों के सबसे अधिक है, वे हैं —**चीन और यू.ए.ई.**
- \* भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग (मूल्य में) भेजा जाता है —**संयुक्त अरब अमीरात को**
- \* भारत का 50 प्रतिशत से अधिक आयात आता है —**एशियाई देशों से**
- \* भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है —**यू.एस.ए.**
- \* भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार है —**यू.एस.ए. के साथ**
- \* वर्तमान समय में कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत का सबसे बड़ा साझेदार है —**संयुक्त राज्य अमेरिका**
- \* विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है —**संयुक्त राज्य अमेरिका**
- \* भारतीय संगठन जो भारत के आयात-निर्यात को प्रभावित करते हैं —**खनिज एवं धातु व्यापार निगम, आयात-निर्यात बैंक, राज्य व्यापार निगम तथा भारतीय खाद्य निगम आदि**
- \* भारत में निर्यात-आयात (एकजम) बैंक का गठन हुआ —**वर्ष 1982** में
- \* इसीजीसी संबंधित है —**निर्यात वित्तीय एवं बीमा से**
- \* निर्यातकों की विभिन्न जोखिमों हेतु बीमा प्रदान करता है —**एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन (ECGC)**
- \* विदेश व्यापार का संवर्धन करता है —**ईसीजीसी, एमएमटीसी तथा एसटीसी**
- \* भारत में FEMA के संदर्भ में सही कथन है —**FERA को 31 मई, 2002 तक दो वर्ष के लिए निश्चित कालिक (सनसेट) खंड दिया गया था ताकि प्रवर्तन निदेशालय अनिर्णीत विषयों की जांच पड़ताल पूरी कर ले।**
- \* स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है, जहां —**प्रशुल्क अनुपस्थित होता है**
- \* कथन (A) : मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। कारण (R) : अवमूल्यन से अंतरराष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर जाता है। —**(A) तथा (R) दोनों सही हैं एवं (R), (A) की सही व्याख्या है।**
- \* कभी-कभी समाचारों में दिखने वाले पद 'आयात आवरण' (इंपोर्ट कवर) का सर्वोत्तम वर्णन है —**यह उन महीनों की संख्या बताता है जितने महीनों के आयात का भुगतान देश के अंतरराष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जा सकता है**
- \* कथन (A) : नई EXIM नीति उदारवादी व बाजार परक है तथा भूमंडलीय व्यापार के अनुकूल है। कारण (R) : GATT ने अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। —**(A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।**
- \* सही सुमेलित हैं-  

(भारत से निर्यातित वस्तुएं)	(गंतव्य देश)
लौह-अयस्क	- जापान
चमड़े का सामान	- रूस
चाय	- यू.के.
सूती कपड़ा	- यू.एस.ए.

## भुगतान संतुलन

- \* भारत द्वारा 2017 में इस्पात का सबसे अधिक निर्यात किया गया —वियतनाम को (14%)
- \* इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना हुई —वर्ष 1996 में
- \* भारत द्वारा आयात की जाने वाली मर्चों का मूल्य की दृष्टि से हासमान क्रम इस प्रकार होगा —पेट्रोलियम > मोती और बहुमूल्य रत्न > विद्युत मशीनरी व उपकरण और उसके भाग > न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर मशीनरी और यांत्रिक उपकरण > कार्बनिक रसायन।
- \* वह देश जिसे प्रतिस्थापित करते हुए भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक (2015) हो गया —थाईलैंड
- \* वर्ष 2015 के आंकड़ों के अनुसार, संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश है —केन्या
- \* भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश है —सं.रा. अमेरिका
- \* कल्वर मोती का उत्पादन महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है —जापान का
- \* भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है —संयुक्त राज्य अमेरिका को
- \* वे पंजीकृत निर्यातक, जिनका अनेक वर्षों तक निर्यात निषादन उच्चस्तरीय रहा है, जाने जाते हैं —स्टार व्यापार गृह के रूप में
- \* विश्व पर्यटन संगठन की वर्ष 2016 की रिपोर्ट के अनुसार, उस वर्ष सर्वाधिक पर्यटकों ने यात्रा की —फ्रांस की
- \* अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है —सेवाओं का निर्यात
- \* एंट्रीपोर्ट व्यापार से तात्पर्य है —निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं
- \* सन् 2000 में नाथू ला दर्रा जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खुला। वे हैं —भारत और चीन
- \* आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है —इंडेंट से
- \* साख-पत्र (L/C) दिया जाता है —एक आयातकर्ता द्वारा
- \* ड्यूटी-ड्रॉ-बैंक का आशय है —निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी
- \* वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि में भारत को विश्व व्यापार में एक मुख्य प्रतिभागी बनना है —वर्ष 2020 तक
- \* 'बंद अर्थव्यवस्था' वह अर्थव्यवस्था है, जिसमें —न तो निर्यात होता है, न ही आयात
- \* 'भुगतान संतुलन' शब्द का प्रयोग किया जाता है —आयात एवं निर्यात के संदर्भ में
- \* किसी देश का 'भुगतान संतुलन' व्यवस्थित अभिलेख है —किसी निर्धारित समय के दौरान, सामान्यतः एक वर्ष में, किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन-देन
- \* भुगतान संतुलन को इस प्रकार पारिभाषित किया जाता है —एक देश के निवासीगण एवं शेष विश्व के बीच आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा
- \* भुगतान संतुलन में निहित होता है —दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार तथा ऋण
- \* भुगतान संतुलन के संदर्भ में चालू खाता बनता है —व्यापार संतुलन तथा अदृश्यों का संतुलन से
- \* विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है —भुगतान संतुलन से
- \* व्यापार संतुलन में सम्मिलित होता है —माल
- \* भारत के व्यापार संतुलन के बारे में सही कथन है —भारत का व्यापार संतुलन 1972-73 तथा 1976-77 के दो वर्षों को छोड़कर (जब वह धनात्मक था), 1949-50 से 2017-18 तक की संपूर्ण अवधि के लिए ऋणात्मक था।
- \* नई एकल यूरोपियन मुद्रा का नाम है —यूरो
- \* यूरो डॉलर क्या है —संयुक्त राज्य अमेरिका की परिसंघीय सरकार द्वारा जारी एक विशेष मुद्रा जिसका प्रयोग केवल यूरोप में होता है
- \* यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में नहीं स्वीकार किया है —ब्रिटेन, डेनमार्क तथा स्वीडन ने
- \* नई मुद्रा यूरो प्रारंभ की गई —वर्ष 1999 में
- \* 'यूरो' राष्ट्रीय मुद्रा है —यूरोपीय संघ के केवल 19 राज्यों की
- \* आर्थिक उदारीकरण नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है-भारतीय रुपये के लिए पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त करना। इसका समर्थन किया जा रहा है, क्योंकि —यह भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह को अधिक आकर्षित करेगी।
- \* रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है —रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप में परिवर्तित करके देने की अनुमति
- \* वर्तमान में रुपये की परिवर्तनीयता का अर्थ है कि —रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है।

- \* चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता को घोषित किया गया  
—वर्ष 1994 से
- \* रुपये की पूर्ण विनिमेयता का अभिप्राय है  
—अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के साथ इसका मुक्त प्रवाह तथा देश के भीतर और बाहर किसी निर्धारित स्थान पर किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के साथ इसका सीधा आदान-प्रदान
- \* भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है  
—भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में
- \* भारतीय रुपये को परिवर्तनीय बनाया गया है  
—चालू खाते में अगस्त, 1994 से
- \* तारापोर समिति संबंधित थी —पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से
- \* भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण जिस समिति के द्वारा किया गया, वह है —तारापोर समिति
- \* मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ है —अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में देश की मुद्रा का मूल्य घट जाना
- \* भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किया गया —वर्ष 1949 में
- \* चालू खाते के घाटे को घटाने में सहायक साबित हो सकते हैं  
—घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन तथा उन उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिससे देश में अधिक FDI तथा FII's से अधिक निधि आए।
- \* 'मुद्रा' के अवमूल्यन का परिणाम है —देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना
- \* जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, तो इसका प्रभाव होता है कि —आयात महंगे और निर्यात सस्ते हो जाते हैं
- \* एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है  
—व्यापार शेष को ठीक करने के लिए
- \* कथन (A) : मुद्रा का अवमूल्यन (Devaluation) निर्यातों को बढ़ाने के लिए किया जाता है।  
कारण (R) : विदेशी बाजार में घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं।  
—(A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
- \* वह विदेशी मुद्रा जिसका प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है —अनिवासी भारतीय जमाएं तथा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश
- \* भारतीय रुपये की पूंजीगत लेखा परिवर्तनीयता (Capital Account Convertibility) का अर्थ है कि —वित्तीय परिसंपत्ति के व्यापार के प्रयोजन से भारतीय रुपये का किसी भी प्रमुख मुद्रा से विनिमय किया जा सकता है।
- \* हवाला संव्यवहार उन भुगतानों से संबंधित है, जो —सरकारी माध्यम से गुजरे बिना विदेशी मुद्रा के बदले रुपये में और रुपये के बदले विदेशी मुद्रा में किए जाते हैं।
- \* जुलाई, 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था —20 प्रतिशत
- \* भारतीय रुपये का दो बार अवमूल्यन किया गया, वित्तीय वर्ष —1991 - 92 में
- \* विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (FEMA) प्रभावी हुआ —वर्ष 2000 से
- \* फेमा (विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम) को अंतिम रूप से लागू किया गया —वर्ष 2002 से
- \* भारत सरकार ने एफ.ई.आर.ए. (फेरा) को प्रतिस्थापित किया है —फेमा (FEMA) से
- \* मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव है —आयातकर्ता देश में मुद्रा अवस्फीति (Deflation) का न होना
- \* व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया —अर्थशास्त्री हाट्टे ने
- \* 'e-बिज' संबंधित है —सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार (प्लेटफॉर्म) से
- \* ई-व्यापार (E-Commerce) का अर्थ है —इंटरनेट पर व्यापार
- \* भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है —अमेजान
- \* 'सुपर 301' है —अमेरिकी व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 1998 की वह धारा जिसके तहत अमेरिका द्वारा किसी भी देश के विरुद्ध आर्थिक कार्यवाही की जाती है

## अंतरराष्ट्रीय संगठन

- \* उधार एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन) प्रशासित है —अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट) से
- \* 'वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट' एक वार्षिक प्रकाशन है —अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का
- \* 'व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक' (Ease of Doing Business Index) में भारत की रैंकिंग समाचार-पत्रों में कभी-कभी दिखती है। इस रैंकिंग की घोषणा की है —विश्व बैंक ने
- \* विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है —अंतरराष्ट्रीय विकास संघ
- \* विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार, निम्न आय अर्थव्यवस्थाएं (Low Income Economies) वे हैं, जिनके लिए 1994 में प्रति व्यक्ति GNP थी —US \$ 725 या कम

- \* 'विश्व आर्थिक संभावना' (ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स) रिपोर्ट आवधिक रूप से जारी करता है —विश्व बैंक
- \* मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है —विश्व बैंक द्वारा
- \* भारत के आर्थिक विकास पथ को 'रोजगारविहीन', 'जड़विहीन', 'निष्ठुर', 'आवाजविहीन' तथा 'भविष्यरहित' कहा है —यू.एन.डी.पी. ने
- \* संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है —चीन की
- \* 14 जुलाई, 2018 के आंकड़ों के अनुसार, GDP (Nominal) के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था है —विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
- \* पी.पी.पी. रेटिंग के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान है —तीसरा (पहला एवं दूसरा स्थान क्रमशः चीन एवं अमेरिका का है)
- \* अधिकांश अंतरराष्ट्रीय अभिकरण जो भारत के अंतर्शासनिक द्विपक्षीय करारों के अनुसार, विकास कार्यक्रमों के लिए राशि उपलब्ध कराते हैं, मुख्यतः देते हैं —तकनीकी सहायता, सुगम ऋण जो ब्याज सहित वापस चुकाने होंगे, अनुदान जो वापस नहीं चुकाने होंगे
- \* भारत में राज्यों के अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान दिए गए हैं —विश्व बैंक द्वारा
- \* एशियाई विकास बैंक, एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग, कोलम्बो योजना तथा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) में से भारत सदस्य है —एशियाई विकास बैंक तथा कोलम्बो योजना का
- \* 'हरा सूचकांक' विकसित किया गया है —विश्व बैंक द्वारा
- \* विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है, वह है —गैट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन
- \* डब्ल्यू.टी.ओ. का मुख्यालय अवस्थित है —जेनेवा में
- \* विवादों को सुलझाने हेतु संदर्भ बिंदु के रूप में प्रयुक्त अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के संबंध में WTO सहयोग करता है —कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन के साथ
- \* विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी —वर्ष 1995 में
- \* विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष पास्कल लेमी का स्थान लिया है —रॉबर्टो अजेवेडो ने
- \* भारत डब्ल्यू. टी.ओ (विश्व व्यापार संगठन) का सदस्य बना —वर्ष 1995 में
- \* विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में केंद्रीय मुद्दा रहा है —कृषि से
- \* विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत 'कृषि पर समझौते' के मुख्य तीन स्तंभों में है —बाजार पहुंच, आंतरिक समर्थन तथा निर्यात प्रतियोगिता
- \* कभी-कभी समाचारों में 'ऐबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स' शब्द देखने को मिलते हैं। ये तीनों संबंधित हैं —WTO से
- \* 'विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि' (स्पेशल सेफगार्ड मेकेनिज्म्स) मुहावरा प्रायः चर्चा में आता रहता है —विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में
- \* टैरिफ और व्यापार संबंधी साधारण करार (GATT) के अधीन सर्वाधिक अनुग्रह भाजन राष्ट्र (MFN) का अर्थ है —सभी देशों के प्रति अधिकतम अनुग्रह
- \* WTO का पूर्ववर्ती नाम था —GATT
- \* गैट का तात्पर्य है —जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड
- \* GATT कार्यालय स्थापित किया गया —वर्ष 1948 में जेनेवा में
- \* डंकल प्रस्ताव संबंधित है —बौद्धिक संपत्ति का अधिकार से
- \* आर्थर डंकल का नाम संबंधित है —गैट से
- \* डंकल प्रस्तावों के विषय में सही कथन हैं —भारत सरकार के लिए उसके सभी प्रस्तावों को सभी क्षेत्रों के लिए स्वीकार करना अनिवार्य है। कृषि के क्षेत्र में मुख्य प्रस्ताव है- कृषि संबंधी उपादानों की समाप्ति।
- \* व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के विषय हैं —व्यापार मार्का, औद्योगिक परिरूप तथा भौगोलिक संकेत/निर्देश आदि
- \* TRIPS समझौते का अनुपालन करने के लिए भारत ने जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स (रेजिस्ट्रेशन एवं प्रोटेक्शन) एक्ट, 1999 अधिनियमित किया। व्यापार चिह्न (ट्रेड मार्क) तथा भौगोलिक संकेत (जियोग्राफिकल इंडिकेशन) के बीच अंतर है —व्यापार चिह्न किसी व्यक्ति या कंपनी का अधिकार है जबकि भौगोलिक संकेत किसी एक समुदाय का अधिकार है, व्यापार चिह्न को अनुज्ञप्त किया जा सकता है, जबकि भौगोलिक संकेत को अनुज्ञप्त नहीं किया जा सकता
- \* ट्रिप्स समझौते में संरक्षण प्रदान करने के लिए सम्मिलित किया गया है —पेटेंट, भौगोलिक संकेतक, कॉपी राइट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट की रूपरेखा, ट्रेडमार्क आदि को
- \* कथन (A) : विश्व व्यापार संगठनों के दायित्व में भारत के कृषि-क्षेत्र में उपदान में कमी करना आवश्यक नहीं है। कारण (R) : भारत एक विकासशील देश है। —(A) गलत है, परंतु (R) सही है।

- \* 'एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर' (Agreement on Agriculture), 'एग्रीमेंट ऑन दि ऐप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स' (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures) और 'पीस क्लॉज' (Peace Clause) शब्द प्रायः समाचारों में आते हैं  
—विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में
- \* लाओ पी.डी.आर., चीन, म्यांमार तथा भारत में से एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट (एप्टा) का सदस्य नहीं है —म्यांमार
- \* हाल ही में IMF के SDR बास्केट में एक नई मुद्रा जुड़ी है  
—रेनमिनबी यूआन (चीन की मुद्रा)
- \* अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में सत्य कथन है  
—यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है
- \* अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य है  
—सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना
- \* ब्रेटनवुड्स सम्मेलन ने स्थापना की  
—आई.एम.एफ. (I.M.F.) तथा आई.बी.आर.डी. (I.B.R.D.) की
- \* अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई —ब्रेटनवुड्स समझौता से
- \* भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना —वर्ष 1945 में
- \* 'पत्र-स्वर्ण' का अर्थ है  
—अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार
- \* 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है  
—अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
- \* 'वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट' (Global Financial Stability Report) तैयार की जाती है  
—अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा
- \* अल्जीरिया, चीन, इंडोनेशिया तथा यू.ए.ई. देशों में से ओपेक का सदस्य नहीं है —चीन
- \* यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है —ब्रुसेल्स में
- \* यूरोपीय संघ के विषय में सत्य कथन हैं  
—यूरोपीय संघ को पूर्वकाल में यूरोपीय समुदाय के रूप में जाना जाता था, 'सिंगल यूरोपियन एक्ट' (1986) और 'मॉस्ट्रिच संधि' इसके निर्माण में मील के पत्थर बने तथा यूरोपीय संघ देशों के नागरिक दोहरी नागरिकता का उपभोग करते हैं।
- \* समाचारों में कभी-कभी देखे जाने वाला 'यूरोपीय स्थिरता तंत्र' (European Stability Mechanism) है  
—EU की एक एजेंसी, जो यूरो क्षेत्र (यूरोजोन) के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है
- \* आईएलओ (ILO) की सौवीं वार्षिक बैठक ने जिनके हितों की रक्षा का निर्णय लिया है, वे हैं —घरेलू नौकरों/श्रमिकों के हितों की
- \* सांस्कृतिक नेताओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए, 'क्रिस्टल पुरस्कार' प्रदान करता है —विश्व आर्थिक मंच
- \* पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल तथा थाईलैंड में से 'साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल को-ऑपरेशन' (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन 'सार्क') का सदस्य नहीं है —थाईलैंड
- \* यूनीसेफ, आई.एम.एफ, डब्ल्यू.एच.ओ. तथा सार्क में से एक शेष से भिन्न है सार्क
- \* दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की स्थापना हुई —वर्ष 1985 में
- \* भारत, पाकिस्तान, कंबोडिया तथा नेपाल में से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है —कंबोडिया
- \* विश्व की उभरती आर्थिक शक्तियों यथा- ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता वाले अंतमहाद्वीपीय समूह को जाना जाता है —ब्रिक्स (BRICS) के नाम से
- \* ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका तथा कनाडा में से BRICS देशों में से नहीं है —कनाडा
- \* ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था —रूस में
- \* सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं BRIC (ब्राजील, रूस, भारत, चीन) में दक्षिण अफ्रीका सम्मिलित हुआ—वर्ष 2011 में
- \* भूटान, रूस, भारत तथा चीन में से BRICS का सदस्य नहीं है —भूटान
- \* 'ब्रिक्स' राष्ट्रों में से प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है —रूस की
- \* नूतन विकास बैंक (BRICS बैंक) का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है —के.वी. कामथ को
- \* न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है —शंघाई में
- \* चीन, कजाखस्तान, रूस तथा वियतनाम देशों में शंघाई-5 का सदस्य नहीं है —वियतनाम
- \* शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की स्थापना हुई थी —26 अप्रैल, 1996 को
- \* ईरान, सऊदी अरब, ओमान तथा कुवैत में से 'खाड़ी सहयोग परिषद' (गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल) का सदस्य नहीं है —ईरान
- \* UNSC का तात्पर्य है —संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
- \* भारत, बांग्लादेश, लाओस तथा वियतनाम में से गंगा-मेकांग स्वर्णभूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है —वियतनाम
- \* मेकांग-गंगा सहयोग में जो छः देशों की पहल है, उनमें शामिल हैं  
—गंगा क्षेत्र से भारत तथा मेकांग क्षेत्र से 5 देशों - कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एवं वियतनाम

- \* संस्थाएं जो मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं  
—IBRD, IDA, IFC, MIGA तथा ICSID
- \* सही सुमेलित हैं-  
डब्ल्यू. टी. ओ. - सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना।  
आई.एम.एफ. - भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना।  
सार्क - दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।  
आई.डी.ए. - नम्य ऋणों की स्वीकृति।
- \* अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति (IMFC) के संदर्भ में सत्य कथन हैं  
—विश्व अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को उसके कार्य की दिशा पर सलाह देता है। IMF की बैठकों में विश्व बैंक प्रेक्षक की भांति भाग लेता है।
- \* संयुक्त राष्ट्र मुद्रा और वित्तीय सम्मेलन (यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस) जिसमें IBRD, GATT और IMF की स्थापना के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे, सामान्यतः कहलाता है  
—ब्रेटनवुड्स सम्मेलन
- \* विश्व बैंक (World Bank) की स्थापना की गई थी —वर्ष 1945 में
- \* विश्व बैंक का मुख्यालय है —वाशिंगटन में
- \* ASEAN, LAFTA, APEC तथा NAFTA में से जिस नवीनतम क्षेत्रीय आर्थिक गुट का निर्माण हुआ है, वह है —NAFTA
- \* सही सुमेलित हैं-  
(क्षेत्रीय आर्थिक संगठन) (निर्माण वर्ष)  
LAFTA - 1960  
ASEAN - 1967  
APEC - 1989  
NAFTA - 1994
- \* निम्नलिखित समझौतों पर विचार कीजिए-  
I. ISLFTA (भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता)  
II. SAFTA (दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र)  
III. CECA (भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता)  
IV. SAPTA (दक्षिण एशिया अधिमान्य व्यापार व्यवस्था)  
—उपर्युक्त समझौतों का सही कालानुक्रमिक है IV-I-II-III
- \* सही सुमेलित हैं-  
(संगठन) (मुख्यालय)  
1. एशियाई विकास बैंक - मनीला (फिलीपींस)  
2. एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग - सिंगापुर  
3. दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ - जकार्ता (इंडोनेशिया)
- \* जी-15 है —विश्व के विकासशील देशों का संगठन
- \* जी-7 समूह के सदस्य है  
—अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एवं जापान
- \* जी-8 मस्कोका पहल संबंधित है —मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य से
- \* भारत, चीन, ब्राजील एवं अन्य विकासशील देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन से भविष्य में बातचीत करने के लिए बनाए गए समूह को कहा जाता है —G-77
- \* संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या है —193
- \* संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या है  
—5 (चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका)
- \* संयुक्त राष्ट्र संघ से संबद्ध नहीं है —अंतरराष्ट्रीय निपटारा बैंक (बैंक फॉर इंटरनेशनल सैटिलमेंट)
- \* 'आसियान' इसके लिए है  
—एसोसिएशन ऑफ साउथ-ईस्ट एशियन नेशंस
- \* भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया तथा सिंगापुर देशों में से आसियान (ASEAN) का सदस्य नहीं है —भारत
- \* वियतनाम, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया तथा इंडोनेशिया में से वह देश जो 'आसियान' का सदस्य नहीं है —दक्षिण कोरिया
- \* 'रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप' (Regional Comprehensive Economic Partnership) पद प्रायः समाचारों में देशों के एक समूह के मामलों के संदर्भ में आता है। देशों के उस समूह को कहा जाता है —ASEAN
- \* ब्रुनेई सदस्य है —ASEAN (आसियान) राष्ट्र समूह का
- \* भारतीय विकास फोरम (IDF) पहले जाना जाता था —भारत सहायता क्लब
- \* UNCTAD के अनुसार ब्राजील, मेक्सिको तथा दक्षिण अफ्रीका में से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं —तीनों
- \* भारत और अमेरिका के मध्य विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफ.ए.टी.सी.ए.) क्रियाशील हुआ है —30 सितंबर, 2015 से
- \* 'स्टार्ट-I एवं स्टार्ट-II' संधियां हस्ताक्षरित की गईं  
—अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य

## विदेशी निवेश एवं ऋण

- \* भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में समाविष्ट होंगी-  
—भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां, भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारण तथा विदेशी कंपनियों द्वारा अनन्य रूप से वित्तपोषित कंपनियां जबकि पोर्टफोलियो निवेश नहीं
- \* मार्चात, 2018 में भारत का विदेशी ऋण पार हो चुका  
—529.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर
- \* वर्ष 2017 में विश्व के सर्वाधिक बाह्य ऋण (ऋण स्टॉक) भार वाले पांच देश (घटते क्रम में) क्रमशः हैं —संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस तथा नीदरलैंड
- \* इस समय सर्वाधिक बाह्य ऋणग्रस्त है —संयुक्त राज्य अमेरिका देश
- \* बाह्य ऋण के आकार और घटकों के आधार पर विश्व बैंक ने भारत का वर्गीकरण किया है —कम ऋणी देश के रूप में
- \* सही सुमेलित हैं-  
1. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में वृद्धि.....मुद्रा प्रसार  
2. भारत में निम्न आयात वृद्धि दर.....भारतीय उद्योगों में सुस्ती  
3. यूरो-निर्गम.....यूरोपीय देशों में भारतीय कंपनियों द्वारा धारित शेयर  
4. निवेश-सूची (पोर्टफोलियो) निवेश .....विदेशी संस्थागत निवेश
- \* प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) तथा संस्थागत विदेशी निवेशक (FII) दोनों ही, किसी देश में निवेश से संबद्ध हैं। दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण भिन्नता है —FII व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, जबकि FDI का लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होता है
- \* विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का बृहत्तम भाग गया है —सेवा क्षेत्र को
- \* भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) है —एक गैर-बैंकिंग वित्तीय पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी
- \* गत दशक में भारत में सबसे अधिक सीधा विदेशी निवेश अंतर्वाह आकर्षित किया है —सेवा क्षेत्र ने
- \* भारत के अंशपूंजी में निवेश हेतु विदेशी पूंजी का अंतर्प्रवाह सबसे अधिक होता है —मॉरीशस से
- \* भारत में आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) बड़ी मात्रा में मॉरीशस से आता है, न कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसी अनेक बड़ी और परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं से। इसका कारण है —भारत का मॉरीशस के साथ दोहरा करारोपण परिहार समझौता है।
- \* भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सर्वाधिक हिस्सा है —विदेशी मुद्रा का (डॉलर में)

- \* सहभागिता नोट [Participatory Notes (PNs)] संबंधित है —विदेशी संस्थागत निवेशक से
- \* भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है —निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण की नीति को

## D. विविध

### (Miscellaneous)

- \* भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में इस अधिकार की व्यवस्था नहीं है —समाज के कमजोर वर्गों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की दरों में छूट
- \* भारत के जनसंख्या प्रक्षेपण के संदर्भ में 'आयु भूकंप' अवधारणा का संबंध है, बाल आयु जनसंख्या से —यह कथन सही नहीं है
- \* विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है —15 मार्च को
- \* वर्ष 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय महिला थीं —श्रीमती हंसा मेहता
- \* आई.एस.ओ. 14001 है —एक अंतरराष्ट्रीय प्रमाण-पत्र, जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है।
- \* ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency) का स्टार लेबल पाया जाता है —छत के (सीलिंग) पंखे, विद्युत गीजर तथा नलिका रूप प्रतिदीप्ति (ट्यूबलर फ्लूओरेसेंट) लैंप आदि उपकरणों में
- \* व्यापार एवं माल निशान एक्ट पारित किया गया था —वर्ष 1958 में
- \* पी.ओ.सी.एस.ओ. कानून का संबंध है —बच्चों से
- \* भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं —देवेन्द्र कुमार सीकरी
- \* समय-समय पर 'इनर्जी स्टैटिस्टिक्स' नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है —केंद्रीय सांख्यिकी संगठन
- \* भारत सरकार द्वारा घोषित 'एबीसी सूचकांक' का संबंध है —स्वास्थ्य से
- \* जयंत पाटिल समिति संबंधित है —अत्यल्प वर्षा वाले क्षेत्रों के विकास से
- \* गाडगिल-मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार दिया गया है —जनसंख्या को
- \* FICCI का अध्यक्ष हैं —राशेश शाह
- \* अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री (चीफ इकोनोमिस्ट) के पद पर कार्यरत रहे —रघुराम राजन



- \* रघुराम राजन कमेटी संबंधित है —आर्थिक क्षेत्र में सुधार से
- \* सही सुमेलित हैं
  - टी.एस. कृष्णमूर्ति - भारत के भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त
  - के.सी. पंत - अध्यक्ष, भारत का 10वां वित्त आयोग
  - ए.एम. खुसरो - 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष
  - आर. सी. लाहोटी - भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति
- \* सही सुमेलित हैं-
 

(व्यक्ति)	(संबंधित क्षेत्र)
एम.एस. स्वामीनाथन	- हरित क्रांति
एल.के. झा	- कराधान
सी.टी. कुरियन	- दुग्ध उत्पादन
मोरारजी देसाई	- बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण
- \* सही सुमेलित हैं-
 

गोइपोरिया समिति	- बैंकिंग सेवा सुधार
नानजुनदप्पा समिति	- रेलवे किराया
रंगराजन समिति	- भुगतान संतुलन
रेखी समिति	- अप्रत्यक्ष करों से
- \* कभी-कभी समाचारों में आने वाली 'गाडगिल समिति रिपोर्ट' और 'कस्तूरीरंगन समिति रिपोर्ट' संबंधित हैं
  - पश्चिमी घाटों के संरक्षण से
- \* सही सुमेलित हैं-
 

दत्त समिति (1969)-	औद्योगिक लाइसेंसिंग
वांचू समिति (1971)	- प्रत्यक्ष कर
राजमन्नार समिति (1971)	- केंद्र-राज्य संबंध
चक्रवर्ती समिति (1985)	- मौद्रिक प्रणाली
- \* सही सुमेलित हैं-
 

(विशेषज्ञता)	(नाम)
कराधान	- पार्थसारथी सोम
कृषि	- अशोक गुलाटी
मौद्रिक नीति	- सी. रंगराजन
भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन व राज्य स्तरीय सुधार	- अरविंद पनगढ़िया
- \* रिजर्व बैंक के गवर्नर जो वित्त मंत्री भी हुए
  - सी. डी. देशमुख तथा मनमोहन सिंह
- \* विमल जालान प्रथम अध्यक्ष थे
  - व्यय प्रबंध आयोग के
- \* 'दृष्टि 2025' का संबंध है
  - खाद्य उत्पादन में वृद्धि से
- \* वे सूचक जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) रिपोर्ट में बनाने में उपयोग किया गया है
  - अल्पपोषण, शिशु वृद्धिरोधन तथा शिशु मृत्यु-दर
- \* 'अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान' (Intended nationally Determined Contributions) पद को कभी-कभी समाचारों में देखा जाता है
  - जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्ययोजना के संदर्भ में
- \* 'वैश्वीकरण' के संबंध में असत्य कथन है
  - इसने भारत में छोटे उद्यमियों में आशावाद का एक बोध पैदा किया है
- \* केंद्र सरकार द्वारा संचालित वह योजना, जिसके अंतर्गत मरुस्थल के किसानों को पंपसेट कम से कम किराए या पट्टे पर दिए जाते हैं
  - जल धारा योजना
- \* उत्तर प्रदेश भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है
  - संत रविदास नगर (भदोही) में
- \* नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च अवस्थित है
  - नई दिल्ली में
- \* राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सिज कंजर्वेशन एवं डेवलपमेंट कमीशन जिन समस्याओं से मुख्यतः जुड़े हुए हैं, उनका संबंध है
  - खेती योग्य भूमि की पहचान एवं उसके विकास से
- \* भूमि अधिग्रहण विधेयक लोक सभा में पारित हुआ था
  - 9 संशोधनों के पश्चात
- \* हरियाली कार्यक्रम का संबंध है
  - जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम के समर्थन से
- \* 'बहिनी दरबार' समाचार-पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है
  - मध्य प्रदेश से
- \* विश्व के जल संसाधनों का लगभग भारत के पास उपलब्ध है
  - 4.0%
- \* वर्तमान में ग्रीन हाउस गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन है
  - चीन में
- \* कमैया प्रणाली है
  - नेपाल में अनुबंधित श्रमिकों की एक प्रणाली जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है।
- \* मराकेश संधि का उद्देश्य है
  - दृष्टिबाधित एवं मुद्रण अयोग्य लोगों की प्रकाशित रचनाओं तक पहुंच को प्रोत्साहन देना।
- \* कल्प योजना संबंधित है
  - प्रारंभिक शिक्षा से
- \* 'नेट मीटरिंग' (Net metering) संबंधित है
  - परिवारों/उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग से

- \* सरकार की योजना 'UDAY' का एक प्रयोजन है  
—विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय कार्यापलट और पुनरुत्थान का प्रबंध करना
- \* गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्यों का उनके कुल विद्युत उत्पादन का अवरोही क्रम  
—महाराष्ट्र > गुजरात > तमिलनाडु > उत्तर प्रदेश
- \* भारत में वर्तमान प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बिजली का उपयोग है, लगभग  
—1075 किलोवाट/घंटा (अनुमान)
- \* वर्ष 2016 में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में सकल उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का अंश लगभग था  
—15%
- \* 'सेमफेक्स' योजना लागू की गई है  
—राजस्थान वित्त निगम (RFC) द्वारा
- \* कभी-कभी समाचारों में दिखने वाले डिजिलॉकर (Digilocker) एक पहल है  
—यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है, यह आपके ई-दस्तावेजों तक आपकी पहुंच को संभव बनाता है, चाहे भौतिक रूप से आपकी उपस्थिति कहीं भी हो।
- \* सही सुमेलित हैं-  
तेजी - बृहद् स्तर पर बढ़ती हुई आय, उत्पादन एवं रोजगार के साथ, उच्च स्तर का व्यावसायिक कार्यकलाप  
सुस्ती - धीमी गति के व्यावसायिक कार्यकलाप के साथ आय, उत्पादन एवं रोजगार में क्रमशः गिरावट  
मंदी - अल्प रोजगार एवं बेरोजगारी का अभूतपूर्व स्तर, आय, उत्पादन एवं रोजगार में तीव्र गिरावट  
सुधार - मूल्य, आय, उत्पादन एवं रोजगार के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि
- \* स्थिर मांग के साथ आपूर्ति में वृद्धि से पदार्थों की कीमत की संभावना सामान्यतः होगी  
—घटने की
- \* क्रेता का बाजार कहलाता है, जहां —मांग से पूर्ति अधिक होती है।
- \* बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है, जो रुझान पैदा करती है  
—उपभोक्तावाद की ओर
- \* पूर्तिपक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है —उत्पादक के दृष्टिकोण पर
- \* सब्जी वाली फसलों के लिए बाजार उपयुक्त होता है  
—अति अल्पकालीन
- \* जब कुल उत्पाद स्थिर होता है, तो सीमांत उत्पादन होगा —शून्य
- \* व्यावसायिक संपत्तियों के न्यासिता सिद्धांत का प्रतिपादन किया  
—महात्मा गांधी ने
- \* 'क्षतिपूर्ति' का सिद्धांत लागू नहीं होता  
—जीवन बीमा पर
- \* एक उपभोक्ता साम्यावस्था में कहा जाएगा, यदि  
—वह आय के एक निश्चित स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो
- \* जैव-डीजल मिशन का कार्यान्वयन (नोडल मंत्रालय के रूप में) कर रहा है  
—ग्रामीण विकास मंत्रालय
- \* भारत में क्षेत्रीय विषमताएं अत्यधिक हैं और हाल के वर्षों में बढ़ती रही हैं, क्योंकि  
—केवल चुने गए स्थलों में ही बार-बार निरंतर निवेश किया जाता रहा है, कुछ क्षेत्र कृषि जलवायवी रूप से विकास किए जाने के कम अनुकूल हैं तथा कुछ क्षेत्र कृषि भूमि संबंधी रूपांतरण की ओर बिल्कुल ही अनभिमुख बने हुए हैं और इसके परिणामस्वरूप सामाजिक और आर्थिक अवसरों के अभाव का सामना कर रहे हैं।
- \* कभी-कभी समाचारों में दिखने वाले 'आई.एफ.सी. मसाला बॉन्ड' (IFC Masala Bonds) के संदर्भ में सही कथन हैं  
—विश्व बैंक की एक शाखा मसाला बॉन्ड रुपया अंकित मूल्य वाले बॉन्ड हैं, जो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के लिए ऋण वित्तीयन के स्रोत हैं। विश्व बैंक की एक शाखा अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा प्रस्तावित किया जाता है।
- \* 'एगमार्क' का संबंध है  
—गुणवत्ता से
- \* 'ई-चौपाल' नामक ग्रामीण विपणन तंत्र प्रारंभ किया है  
—आई.टी.सी ने
- \* बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया था  
—एडम स्मिथ, रिक्तार्डो, जे.के. गलब्रेथ ने
- \* 'लुप्त होती महिलाएं' का विचार दिया  
—अमर्त्य सेन ने
- \* भारतीय पर्यटन के 'स्वर्ण त्रिभुज' में सम्मिलित शहर हैं  
—आगरा, दिल्ली तथा जयपुर
- \* विश्व का लगभग 50 प्रतिशत कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है  
—चीन से
- \* सही सुमेलित हैं-  
जे. पी. मौरगन चेज़ - वित्तीय सेवाएं  
रोश होल्डिंग ए. जी. - स्वास्थ्य सेवाएं  
डब्ल्यू. एल. रौस - प्राइवेट एंड कंपनी इक्विटी फ़र्म  
वारबर्ग पिकस - प्राइवेट इक्विटी फ़र्म

- \* मानव संसाधन, भ्रष्टाचार, सामाजिक संगठन तथा कृषि में विक्रय बचत में से एक गैर-आर्थिक घटकों में से नहीं है, जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं —**भ्रष्टाचार**
- \* अर्थशास्त्र के संबंध में सही कथन नहीं है —**यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है।**
- \* ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्तिकर्ता था —**कथन असत्य है**
- \* अथावाना का मतलब है —**भू-राजस्व विभाग**
- \* निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिए।  
1. आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947  
2. खनन एवं खनिज विकास (नियमन) अधिनियम, 1957  
3. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  
4. भारतीय वन अधिनियम, 1927
- भारत के संदर्भ में उपर्युक्त अधिनियमों में से जैवविविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं अथवा उस पर असर डालते हैं —**1, 2, 3 और 4 (सभी)**
- \* सही सुमेलित हैं—  
**ऑटोमोबाइल निर्माता** — **मुख्यालय**  
**बी.एम.डब्ल्यू.ए.जी.** — **जर्मनी**  
**डाएमलर ए.जी.** — **ब्रिटेन**  
**रेनॉल्ट एस.ए.** — **फ्रांस**  
**वोक्सवैगन ए.जी.** — **जर्मनी**
- \* भारतीय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (Advisory Council) के अध्यक्ष वर्तमान में हैं —**बिवेक देबराय**
- \* सही सुमेलित हैं—  
**विलियम डिकसर** — **चलचित्र फिल्म**  
**चार्ल्स बैवेज** — **क्रमादेश्य कंप्यूटर**  
**निकोलस स्टर्न** — **अर्थशास्त्री एवं शिक्षाविद्**  
**ब्रायन ग्रीन** — **रज्जु सिद्धांत**
- \* विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक हैं —**क्लॉस श्वाब**
- \* भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा छोटे व्यापारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया गया है —**ई-लाला**
- \* फरवरी, 2011 में संघीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा भारत का सबसे बड़ा 'नैपथा क्रैकर प्लांट' का उद्घाटन किया गया —**हरियाणा में**
- \* तेल का एक बैरल लगभग बराबर होता है —**159 लीटर के**
- \* PVR सिनेमा का पूरा सही नाम है —**प्रिया विलेज रोड शो**
- \* भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की है —**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत**
- \* उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम वित्तीयकरण नहीं करता है —**पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए**
- \* "भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका (सिटीजंस गाइड टू फाइटिंग करप्शन)" निकाली गई है —**केंद्रीय सतर्कता आयोग (सेंट्रल विजिलेंस कमीशन) द्वारा**
- \* सही सुमेलित हैं—  
**(करप्शन इंडेक्स वर्ष)** — **(भारत की रैंकिंग)**  
**2014** — **85**  
**2015** — **76**  
**2016** — **79**  
**2017** — **81**
- \* 'पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप' प्रतिमान के अंतर्गत भारत की प्रथम रेलवे लाइन बनाई जा रही है —**गुजरात में**
- \* रतन टाटा ने नैनो प्रोजेक्ट को सिंगूर से हटाकर स्थापित किया —**साणंद (गुजरात) में**
- \* राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी स्थापित की गई थी —**जुलाई, 1982 में**
- \* आर्थिक मामलों में सुधार के लिए सलाह हेतु राजस्थान सरकार ने एक संगठन का गठन किया है। इस संगठन का नाम है —**आर्थिक नीति एवं सुधार परिषद**
- \* अदम्य चेतना ट्रस्ट, हैवल्स इंडिया लि., हिंदुस्तान जिंक लि. तथा डी. एस.सी.एल.कोटा (श्रीराम ग्रुप) आदि ट्रस्ट कॉर्पोरेट संबंधित हैं —**मिड-डे-मील (मध्याह्न भोजन) योजना से**
- \* भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है —**अहमदाबाद में**
- \* राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है —**नोएडा में**
- \* भारतीय उद्योग महासंघ (CII) के नए अध्यक्ष हैं —**राकेश भारती मित्तल**
- \* 'इको मार्क' उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, जो —**पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं**
- \* देश का पहला इन्वेस्टमेंट एवं मैनुफैक्चरिंग जोन है —**आंध्र प्रदेश में**
- \* फॉर्च्यून पत्रिका के ग्लोबल 500 सूची में स्थान पाने वाली निजी क्षेत्र की सर्वप्रथम कंपनी थी —**रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड**

- \* इन्फोसिस, टी.सी.एस., विप्रो तथा एच.सी.एल. टेक में से भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है —टी.सी.एस.
- \* वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है —कृषि
- \* राजस्थान में राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक ने जिस शहर एवं तिथि से कार्य प्रारंभ किया, वह है —जयपुर (30 अगस्त, 1995) से
- \* फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार, 2018 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति है —अमेजान के जेफ बेजोस
- \* 'प्रोजेक्ट ऐरो' का संबंध है —डाकघर से
- \* 'बेनिलक्स देश' कहा जाता है —बेल्जियम, नीदरलैंड्स तथा लक्जमबर्ग
- \* भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ —वर्ष 1972 में
- \* पेटेंट द्वितीय संशोधन अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की गई —वर्ष 2002 में
- \* पैकेजिंग (सवेष्टन) की महत्ता बढ़ गई है, क्योंकि —यह उत्पादों को सुरक्षित, आकर्षक एवं विश्वसनीय बनाता है।
- \* सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई है —जनवरी, 2016 से
- \* भारत सरकार द्वारा फरवरी, 2014 में गठित सातवें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था —न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर को
- \* 'आर्थिक समीक्षा' को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व है —वित्त मंत्रालय का
- \* विद्यालय, स्वच्छता सुविधाएं, कोयले की खानें तथा सड़कें एवं रेल में से एक आर्थिक अवस्थापना नहीं है —कोयले की खानें
- \* सुपर बाजार होता है, एक —फुटकर विक्रय संगठन
- \* सूचकांक 'रेजीडेक्स' संबंधित है —भूमि कीमत से
- \* भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेजीडेक्स (RESIDEX) प्रारंभ किया गया था —वर्ष 2007 में
- \* गैर-घरेलू गैस सिलेंडरों में भरी एल.पी.जी. का भार होता है —19.0 किग्रा.
- \* 'आधार' एक कार्यक्रम है —भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु
- \* सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई थी —वर्ष 1993 में
- \* 'प्लानिंग एंड द पुअर' पुस्तक के लेखक हैं —बी.एस. मिनहास
- \* भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल (सी.ए.जी.) की रिपोर्ट का परीक्षण किया जाता है —पब्लिक एकाउंट्स कमेटी द्वारा
- \* भारत के सी.ए.जी. (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) कार्य करते हैं —लोक वित्त संरक्षक के रूप में
- \* एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के एकीकरण के बाद नई इकाई जानी जाती है —एअर इंडिया के नाम से
- \* आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है —एडम स्मिथ को
- \* अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, 2017 दिया गया है —रिचर्ड एच. थेलर
- \* राष्ट्र की संपदा में खान, बांध, मुद्रा-पूर्ति तथा पशु धन में से शामिल नहीं किया जाता है —मुद्रा-पूर्ति को
- \* सही सुमेलित हैं- (लघु रूप) - (क्षेत्र)
- OGL, FOB - विदेशी व्यापार
- SJRY, TRYSEM - रोजगार
- WPI, CPI - सूचकांक
- CRR, SLR - बैंकिंग
- \* 'दबाव समूह' अर्थबोध करता है —नीति संबंधी निर्णयों को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह।
- \* 'ट्रांजैक्शन शुल्क' जिसे ग्राहकों से वसूल करना सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक आदेश द्वारा रोक दिया गया है, संबंधित है —हवाई यात्रा से
- \* सही सुमेलित हैं- (संगठन) (मुख्यालय)
- यू.एन.ओ. - न्यूयॉर्क
- डब्ल्यू.टी.ओ. - जेनेवा
- आई.एल.ओ. - जेनेवा
- एफ.ए.ओ. - रोम
- \* वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं —एडम स्मिथ
- \* 'पूंजी का संग्रहण' (The Accumulation of Capital) पुस्तक के लेखक हैं —श्रीमती जॉन राविन्सन
- \* R.B.I. का मुख्यालय है —मुंबई में
- \* 'नोबेल पुरस्कार' विजेता भारत के अर्थशास्त्री हैं —अमर्त्य सेन
- \* भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया —वर्ष 2003 में
- \* तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था —वर्ष 1956 में
- \* यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिवेशन फंड का संबंध है —टेलीकॉम कंपनियों के देयताओं के समायोजन से
- \* भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है —मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में

- \* कभी-कभी समाचारों में आने वाला 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (Belt and Road Initiative) आता है —चीन से
- \* 'यमुना एक्सप्रेस-वे' है —ग्रेटर नोएडा से आगरा तक
- \* दुग्ध का विपणन करता है —जी.सी.एम.एम.एफ. (Gujarat Co-Operative Milk Marketing Federation Ltd.)
- \* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है —भोपाल में
- \* 'इंडियन इकोनॉमी : गांधीयन ब्लू प्रिंट' नामक पुस्तक लिखी है —चरण सिंह ने
- \* बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे —मदन मोहन मालवीय जी
- \* 'बंदी की द्विविधा' (प्रिजनर्स डाइलेमा) शब्द संबद्ध है —क्रीडा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक
- \* 'ट्रस्टीशिप' की अवधारणा प्रस्तुत की थी —महात्मा गांधी ने
- \* गांधीवादी अर्थव्यवस्था आधारित है —न्यास पर
- \* खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय है —मुंबई में
- \* निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
  1. गांधीवादी अर्थव्यवस्था आधारित है, न्यासिता के सिद्धांत पर।
  2. उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 अंतर्निहित है, नवीं अनुसूची में।
  3. 60वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में नागरिकों की मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई।
  4. 1982 में मेधा पाटेकर ने 'शेतकारी संगठन' का गठन किया। उपर्युक्त कथनों में से सही है/हैं —केवल 1 और 2
- \* जब भारत को विदेशी बैंकों में सोना रखना पड़ा उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे —चंद्रशेखर
- \* भाखड़ा-नांगल एक संयुक्त परियोजना है —हरियाणा-पंजाब और राजस्थान की
- \* जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं —जनांकिकीय संक्रमण
- \* स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए आवश्यक है —स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर
- \* वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि गुजर रही है —निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर से
- \* जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य कारण है —मृत्यु दर में कमी
- \* माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार, जनसंख्या में वृद्धि होती है —ज्यामितीय क्रम में
- \* जनसंख्या का घनत्व, रहन-सहन का स्तर, लिंगानुपात तथा ग्रामीण-शहरी जनसंख्या में से एक जनसंख्या की जनांकिकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है —रहन-सहन का स्तर
- \* भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है —औद्योगिक क्षेत्रों में
- \* बन्ध्याकरण के लिए जो जनसंख्या नियंत्रित करने का एक अधिक विश्वसनीय तरीका है, दम्पतियों का अपनी इच्छा से न कराने के कुछ कारण हैं —लड़कों के लिए इच्छा, शिशु मृत्यु की उंची दर, समझदारी की कमी तथा अति गरीब परिवारों में आर्थिक मजबूरियां आदि
- \* भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई —वर्ष 1872 में
- \* भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई —लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में
- \* भारत में प्रथम नियमित जनगणना की गई —वर्ष 1881 में
- \* सही सुमेलित हैं-
 

(अवधि)	(चरण)
1901-1921	- मंद वृद्धि
1921-1951	- स्थायी वृद्धि
1951-1981	- द्रुतगामी वृद्धि
1981-2001	- कम होने के निश्चित लक्षणों सहित तीव्र वृद्धि

## E. जनसांख्यिकी

### भारत : जनसंख्या

- \* 2011 की भारत की जनगणना के लिए आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था —अवर सेन्सस, अवर फ्यूचर
- \* (1) उच्च जन्म दर का उच्च मृत्यु दर से
- (2) निम्न जन्म दर का निम्न मृत्यु दर से
- (3) उच्च जन्म दर का निम्न मृत्यु दर से
- उपर्युक्त कथनों में से आर्थिक विकास से संबंधित विशिष्ट जनसांख्यिकीय संक्रमण का सही अनुक्रम है —1, 3 तथा 2
- \* सही सुमेलित हैं-
 

(दशक)	(जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में)
1971-81	- 24.66
1981-91	- 23.87
1991-2001	- 21.54
2001-2011	- 17.7

- \* भारत में दशक 2001-2011 में जनसंख्या की वृद्धि थी **-17.7%**
- \* भारत में 1971, 1981, 1991 तथा 2001 जनगणना वर्षों में से जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया  
**-वर्ष 1971 में (24.80%)**
- \* 1. भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है।  
2. वर्तमान वृद्धि दर से निकट भविष्य में इसके चीन से आगे हो जाने की संभावना है।  
3. विश्व के प्रत्येक छः व्यक्तियों में एक भारतीय है।  
4. भारत की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे स्तर में है।  
उपर्युक्त कथनों में से सही कथन है/हैं **-कथन 1, 2 एवं 3 सही हैं**
- \* कथन (A) : भारत की जनगणना हर दस वर्ष पर की जाती है।  
कारण (R) : दस वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है।  
**-(A) सही है, किंतु (R) गलत है।**
- \* भारत में जनसंख्या घनत्व **-निरंतर बढ़ा है**
- \* 2011 की जनगणना में जाति को सम्मिलित करने की सहमति देने वाले मंत्रियों के समूह (GoM) के प्रमुख थे **-प्रणब मुखर्जी**
- \* भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है **-उत्तर प्रदेश**
- \* 1. भारत के 28 राज्यों (दिल्ली तथा पांडिचेरी उनमें सम्मिलित नहीं हैं) में सिक्किम का क्षेत्रफल सबसे कम है।  
2. पांडिचेरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में से चंडीगढ़ की साक्षरता दर सबसे अधिक है।  
3. भारत के 28 राज्यों (दिल्ली तथा पांडिचेरी उनमें सम्मिलित नहीं हैं) में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक जनसंख्या महाराष्ट्र की है। उपर्युक्त में से सत्य कथन है/हैं **-कथन 3 सत्य है**
- \* कथन (A) : उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है (जनगणना 2011 अनंतिम आंकड़े)।  
कारण (R) : बिहार, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र क्रमशः अवरोही क्रम में उसके नीचे हैं। **-(A) सही है, परंतु (R) गलत है।**
- \* भारत के राज्यों में से जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय (2011) तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान है **-महाराष्ट्र का**
- \* उत्तर प्रदेश के पश्चात जिस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, वह है **-महाराष्ट्र**
- \* राज्यों का सही अवरोही क्रम उनकी जनसंख्या 2011 के अनुसार है **-उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल**
- \* आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल की जनसंख्या के आकार का अवरोही है **-महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश**
- \* भारत की एक-तिहाई से अधिक जनसंख्या जिन राज्यों में संकेंद्रित है, वे हैं **-उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार**
- \* कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तथा ओडिशा में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है **-ओडिशा**
- \* महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार तथा मध्य प्रदेश में से सबसे कम जनसंख्या है **-कर्नाटक**
- \* वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर मिजोरम, चंडीगढ़, सिक्किम तथा पुडुचेरी का उनकी जनसंख्या का अवरोही क्रम है **-पुडुचेरी > चंडीगढ़ > मिजोरम > सिक्किम**
- \* 2001-2011 के मध्य भारत के जिस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई, वह है **-नगालैंड**
- \* भारत में जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही **-1961-71 के दौरान**
- \* बीसवीं सदी के अंतिम दो दशकों (1981-2001) में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि (प्रतिशत परिवर्तन) अंकित की गई थी **-नगालैंड में**
- \* आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में से 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई **-आंध्र प्रदेश में**
- \* मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में से वर्ष 2001-2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही **-बिहार में**
- \* भारत में जनांककीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है **-वर्ष 1921**
- \* भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर दर्ज की गई है **-1971-81 के दशक में**
- \* निम्नलिखित में से कौन से सत्य कथन हैं।  
1. लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है।  
2. चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है।  
3. अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है।  
4. दादरा एवं नगर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई गई है। **-कथन 1, 3 एवं 4 सत्य हैं।**

- \* भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाले राज्य क्रमशः हैं —**बिहार तथा अरुणाचल प्रदेश**
- \* 2011 जनसंख्या के अनुसार, राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है —**अरुणाचल प्रदेश का**
- \* भारत के प्रमुख राज्यों के जनसंख्या घनत्व (2011) का सही अवरोही क्रम है —**बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल एवं उत्तर प्रदेश**
- \* जनगणना 2011 के अनुसार, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा केरल में से जनसंख्या घनत्व सबसे कम है —**उत्तर प्रदेश में**
- \* पंजाब, उड़ीसा, त्रिपुरा तथा आंध्र प्रदेश राज्यों का उनके जनसंख्या घनत्व का आरोही क्रम है—**ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा तथा पंजाब**
- \* जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, नगालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा मणिपुर राज्यों में से एक का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है —**मिजोरम का**
- \* भारत के केंद्रशासित प्रदेशों में आबादी का घनत्व सबसे कम है —**अंडमान और निकोबार में**
- \* राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा कर्नाटक राज्य में से वर्ष 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, वह है —**राजस्थान का**
- \* जनगणना 2011 के अनुसार, निम्नलिखित राज्य जनसंख्या घनत्व के संबंध में सही आरोही क्रम में है —**गुजरात (308) > कर्नाटक (319) > असम (398) > हरियाणा (573)**
- \* भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश के जिस शहर में जनघनत्व सर्वाधिक है, वह है —**गाजियाबाद**
- \* जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में जितने विकलांग लोग आत्मनिर्भर हैं, उनका प्रतिशत है —**2.1 प्रतिशत**
- \* 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में साक्षरता का प्रतिशत है —**73 प्रतिशत**
- \* साक्षर भारत कार्यक्रम का विशेष जोर है —**महिला साक्षरता पर**
- \* पूर्ण साक्षर प्रदेश का दावा किया है —**केरल ने**
- \* केरल राज्य के बाहर प्रथम पूर्ण साक्षर जनपद है —**वर्धमान (पश्चिम बंगाल)**
- \* औरैया, गाजियाबाद, इटावा, इलाहाबाद में से वह जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है —**औरैया**
- \* जनगणना 2011 के अनुसार, साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों है —**29वां**
- \* 2011 जनगणना के अनुसार, पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है —**मेघालय राज्य का**
- \* जनगणना 2011 के अनुसार, पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर वाले —**चार राज्य क्रमशः मेघालय, मिजोरम, केरल तथा नगालैंड**
- \* जनगणना 2011 के अनुसार, केरल, उत्तर प्रदेश, मिजोरम तथा गुजरात राज्यों में से पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है —**उत्तर प्रदेश में**
- \* जनगणना 2011 के अनुसार, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिलों का सही अवरोही क्रम है —**गौतमबुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा तथा गाजियाबाद**
- \* 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है —**गौतमबुद्ध नगर (80.12%)**
- \* 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के जिस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है, वह है —**श्रावस्ती (34.8%)**
- \* निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही कथन हैं
  1. न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है।
  2. सर्वाधिक लिंग-अनुपात वाला जिला देवरिया है।
  3. न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है।
  4. नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है। —**कथन 1 एवं 3 सही हैं**
- \* जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, भारत के राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर है, वह है —**बिहार**
- \* भोपाल, नरसिंहपुर, जबलपुर तथा इंदौर में से साक्षरता दर सर्वाधिक है —**जबलपुर में**
- \* सही सुमेलित हैं-
 

(राज्य)	-	(बाल लिंग अनुपात (2011))
उत्तर प्रदेश	-	902
मध्य प्रदेश	-	918
राजस्थान	-	935
बिहार	-	888
- \* भारत में बाल (0-6 वर्ष) जनसंख्या का लिंग अनुपात वर्ष 1961 से —**निरंतर घट रहा है**
- \* जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 0-6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों का यौन अनुपात है —**919**
- \* भारत के जिस राज्य में कुपोषण के शिकार बालकों का प्रतिशत उच्चतम है, वह है —**मध्य प्रदेश**
- \* 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत के जिस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है, वह है —**गोवा तथा मणिपुर (क्रमशः 11 एवं 11)**

- \* भारत के बड़े राज्यों में केरल की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है। इसका सर्वाधिक रूप में स्वीकृत कारण है  
—केरल ने साक्षरता और लोक स्वास्थ्य के संवर्धन में भारी निवेश किया है और सामाजिक नीतियों को उच्च प्राथमिकता दी है।
- \* बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है —महाराष्ट्र में
- \* A. क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल से बड़ा है।  
B. जनगणना 2001 के अनुसार, पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से अधिक है।  
उपरोक्त कथनों में से सही है/हैं —दोनों A और B
- \* भारत की गिनती 'जनांकिकीय लाभांश' (डेमोग्राफिक डिविडेंड) वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि  
—यहां 15-64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है
- \* जब जनसंख्या विशेषज्ञ 2016 के आस-पास भारत को मिलने वाली संभावित 'जनसांख्यिकीय बोनस' की बात करते हैं, तो उनका आशय  
—जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह में वृद्धि
- \* जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है  
—कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि
- \* निम्नलिखित में कौन-सी बात सही नहीं है  
(a) भारत में विश्व की 18.5 प्रतिशत जनसंख्या है।  
(b) भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है।  
(c) 2001-2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि 18.1 करोड़ की हुई है।  
(d) जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में है।  
उपर्युक्त कथनों में से जनगणना 2011 के अनुसार  
—कथन b, c तथा d सत्य हैं
- \* बाढ़ों में वृद्धि, प्रदूषण में वृद्धि, कृषि योग्य भूमि में कमी तथा वन्य जीवों में अभिवृद्धि में से एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है  
—वन्य जीवों में अभिवृद्धि
- \* जब दंपति रक्षण की दर में वृद्धि हो रही हो, तो  
—जन्म दर तभी घटेगी जब दंपति कम आयु के हों
- \* वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या) है —943
- \* वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारतीय राज्यों में न्यूनतम लिंगानुपात पाया गया है —हरियाणा में
- \* वर्ष 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है  
—1000 पुरुषों पर 10 महिलाओं से
- \* गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में से एक राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है —झारखंड का (949)
- \* धार्मिक समुदाय बौद्ध, जैन, ईसाई तथा मुसलमान का यौन अनुपात में अवरोही क्रम है —ईसाई, बौद्ध, जैन तथा मुसलमान
- \* 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार, भारत के जिस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है, वह है —सिख
- \* भारत में न्यूनतम यौन अनुपात जिस केंद्रशासित प्रदेश में पाया जाता है, वह है —दमन एवं दीव में (618)
- \* भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए उत्तरदायी कारक हैं  
—उच्च मातृ-मृत्यु दर, उच्च बालिका मृत्यु दर, बालिका भ्रूण हत्या तथा बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म
- \* वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, प्रति एक हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है —केरल में (1084)
- \* जनगणना 2011 के अनुसार, भारत के जिस राज्य में महिला लिंग अनुपात सर्वाधिक है, वह है —केरल
- \* 2011 में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा में से उच्चतम लिंगानुपात है —तमिलनाडु का (996)
- \* भारतीय संघशासित क्षेत्रों में से एक में लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या) 1000 से ऊपर है  
—पुडुचेरी में (1037)
- \* सही सुमेहित हैं-
- | (जनगणना वर्ष) | (भारत में लिंगानुपात) |
|---------------|-----------------------|
| 1951          | 946                   |
| 1971          | 930                   |
| 1991          | 927                   |
| 2011          | 943                   |
- \* 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में न्यूनतम यौन अनुपात पाया जाता है —दमन एवं दीव में (618)
- \* (i) 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था।  
(ii) 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था।  
(iii) 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में (पाली जिले के अलावा) लिंगानुपात 1000 से कम था।  
(iv) 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में (धौलपुर जिले के अलावा) लिंगानुपात 1000 से कम था।  
2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान में लिंगानुपात (1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या) के बारे में सही कथन हैं  
—(i), (ii) तथा (iii) सही हैं



- \* भारत की जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में से शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है  
—**छत्तीसगढ़ में**
- \* भारत की जनगणना (2011) के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, पंजाब तथा हरियाणा में से शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है  
—**केरल में**
- \* 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही आरोही क्रम है  
—**अरुणाचल प्रदेश (17), मिजोरम (52), सिक्किम (86) तथा मणिपुर (115)**
- \* भारत के राज्यों में सबसे कम घना आबाद (Dense Populated) राज्य है  
—**अरुणाचल प्रदेश**
- \* भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई है  
—**1991-2001 के बीच (लगभग 12.62% तथा 2001-2011 के बीच 8.20%)**
- \* कथन (A) : केरल में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है।  
कारण (R) : केरल की साक्षरता दर बहुत अधिक है।  
—**(A) और (R) दोनों सही हैं एवं (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।**
- \* कथन (A) : उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है।  
कारण (R) : यह भारत का सबसे घना बसा राज्य भी है  
—**(A) सही है, परंतु (R) गलत है।**
- \* 2011 की जनगणना के अनुसार, साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम है —**बिहार (61.8%), राजस्थान (66.1%), उत्तर प्रदेश (67.7%), मध्य प्रदेश (69.3%)**
- \* बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में से 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पुरुष, महिलाओं से संख्या में अधिक हैं  
—**सभी चारों राज्यों में**
- \* अद्यतन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत में स्त्री-पुरुष अनुपात  
—**घटता-बढ़ता रहता है**
- \* A. भारत राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को अंगीकार करने वाला विश्व में दूसरा देश है।  
B. भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, वर्ष 2010 तक 111 करोड़ की जनसंख्या पर प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है।  
C. भारत में प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने वाला केरल प्रथम राज्य है।  
उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन हैं  
—**B और C**
- \* भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के अनुसार जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य था  
—**वर्ष 2045**
- \* राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या (में) स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब वह लक्षित वर्ष रखा गया है  
—**वर्ष 2070**
- \* सर्वाधिक यौन अनुपात (2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार) वाले राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों का अवरोही क्रम  
—**केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश**
- \* वे देश समूह जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है  
—**चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया तथा ब्राजील**
- \* भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात (2011) है  
—**14.2%**
- \* भारत की वर्तमान आबादी में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशतता है  
—**लगभग 4.8 प्रतिशत**
- \* जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत है  
—**8.6 प्रतिशत**
- \* अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में उच्चतम है  
—**पंजाब में (31.9%)**
- \* अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है  
—**उत्तर प्रदेश में**
- \* वह राज्य जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है  
—**पंजाब में**
- \* भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है, क्रमशः  
—**मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में**
- \* जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है  
—**सरचिप (मिजोरम) (97.91%)**
- \* भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है  
—**7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से**
- \* जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आधारित भारत के चार सबसे कम साक्षरता वाले राज्यों का सही आरोही क्रम है  
—**बिहार 61.8 < अरुणाचल प्रदेश 65.4 < राजस्थान 66.1 < झारखंड 66.4**
- \* जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की 2001-11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर थी  
—**20.23 प्रतिशत**
- \* जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल है  
—**16.68 प्रतिशत का**
- \* 2011 जनगणना के अनुसार, भारत की जनसंख्या का वह प्रतिशत जो उत्तर प्रदेश में रहता है  
—**लगभग 17% (16.51%)**

- \* जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, देश में महिलाओं की साक्षरता दर है **—लगभग 64.6%**
- \* भारत में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है **—केरल में (93%), गोवा (86.6%)**
- \* जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में साक्षरता प्रतिशत है **—केरल (94.0) > हिमाचल प्रदेश (82.8) > तमिलनाडु (80.1) > मणिपुर (79.2)**
- \* वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार, राज्यों में स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है **—बिहार की (51.5%)**
- \* संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार, उच्चतम है **—लक्षद्वीप में (87.9%)**
- \* राज्य जिनमें 2011 जनगणना के अनुसार, महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं न्यूनतम है, वे हैं क्रमशः **—केरल और बिहार**
- \* जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की सकल प्रजननता दर (TFR) है **—2.4**
- \* शून्य जनसंख्या वृद्धि दर की प्राप्ति हेतु प्रतिस्थापन जनन स्तर प्रत्येक विवाहित जोड़े के लिए अनुमानित किया गया है **—2.1**
- \* यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान हैं तथा अंतः या बाह्य प्रजनन नहीं होता है, तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे कहा जाता है **—जनसंख्या की स्थिरता**
- \* 2001-2011 के दौरान भारतीय राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है **—दादरा व नगर हवेली**
- \* वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले शीर्ष पांच राज्य हैं **—केरल (94%) > मिजोरम (91.3%) > गोवा (88.7%) > त्रिपुरा (87.2%) > हिमाचल प्रदेश (82.8%)।**
- \* जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य हैं **केरल - 92.1%, मिजोरम - 89.3%, गोवा - 84.7%, त्रिपुरा - 82.7% तथा नगालैंड - 76.1%**
- \* वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत के जिस राज्य में स्त्री-पुरुष शिक्षा में निम्नतम अंतर है, वह है **—मेघालय**
- \* भारत में वर्तमान शिशु मृत्यु दर है, लगभग **—40 प्रति हजार**
- \* शिशु मृत्यु है **—हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात**
- \* भारत में वर्तमान में अशोधित मृत्यु दर है **—7 प्रतिशत**
- \* जनगणना 2011 के अनुसार, शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी **—गोवा एवं मणिपुर (प्रत्येक में 11)**
- \* भारत में सर्वप्रथम मृत्यु गणना की शुरुआत की है **—कर्नाटक ने**
- \* भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर पायी जाती है **—केरल में**
- \* भारत के 'बीमारू' राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है **—बिहार**
- \* जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, भारत 35 वर्ष की आयु से कम की जनसंख्या है **—65.6 प्रतिशत**
- \* जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत है **—48.53 प्रतिशत**
- \* कुल प्रजनन दर (Fertility rate) भारत में उच्चतम है **—बिहार में (3.4)**
- \* 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत है **—59.29 प्रतिशत**
- \* जनसंख्या के पिरैमिड में आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है **—0-14 वर्ष आयु समूह (65 से अधिक आयु के भी आश्रित समूह है)**
- \* जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है **—माहे (पुडुचेरी) (1184)**
- \* वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर है **—78.8 प्रतिशत**
- \* जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत, विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी **—29 वर्ष**
- \* जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का प्रतिशत है **—लगभग 29%**
- \* 2011 की जनगणना के आधार पर मुस्लिम आबादी सर्वाधिक है **—उत्तर प्रदेश में**
- \* भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाते हैं **—पश्चिम बंगाल डेल्टा, दक्कन ट्रेप (महाराष्ट्र और गुजरात), तमिलनाडु, पंजाब का मैदान और गंगा यमुना दोआब, दक्षिण-पूर्वी कर्नाटक पठार**
- \* जनांकिकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को करना चाहिए **—कुशलता विकास का प्रोत्साहन**
- \* फिलिप एम. हौसर के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों का देशांत गमन जाना जाता है **—जनसंख्या इम्प्लोजन**

## भारत : नगरीकरण

- \* एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है क्रमशः —सामाजिक मूल्यों, पारिवारिक संरचना, रहन-सहन के तरीके, तथा आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में
- \* शहरी वृद्धि सूचक हैं —कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोत्तरी का, शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि का, देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि का तथा शहरी क्षेत्रों से आय में वृद्धि का
- \* टी.के. ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है —आय के साधन तथा उभरते या बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान, सत्ता की संरचना तथा नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक पारिस्थितिकी का आधार
- \* जनसंख्या के जिस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है, वह है —अर्द्धशहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति
- \* भारत में मध्यम नगरीकरण की अवस्था से विशेषित है —1931-1961 का समय
- \* कथन (A) : भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफी नीचा है। कारण (R) : भारतीय नगर कम नियोजित हैं। —(A) एवं (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- \* कथन (A) : भारत में सन् 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है। कारण (R) : भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। —(A) तथा (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- \* भारत में शहरीकरण के संबंध में सही कथन नहीं है —भारत में सभी क्षेत्रों का शहरीकरण सर्वथा समान रूप से हुआ है।
- \* अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार किया गया है —जनसंख्या आकार, जनसंख्या घनत्व तथा व्यावसायिक संरचना
- \* भारत में नगरीकरण से —जन्म और मृत्यु दर दोनों घटी हैं।
- \* 2011 की जनगणना के आधार पर सही सुमेलित हैं- (प्रकृति) (राज्य)
 

सर्वाधिक शहरीकृत राज्य	-	तमिलनाडु
अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य	-	महाराष्ट्र
अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य	-	दिल्ली
सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य	-	अरुणाचल प्रदेश
- \* भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है —6
- \* नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है —औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का तथा परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का
- \* भारत के दो नगरीय केंद्र जो विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 शहरों में से हैं —मुंबई तथा दिल्ली
- \* मुंबई, कोलकाता, चेन्नई तथा दिल्ली महानगरों में से लिंगानुपात अधिकतम है —चेन्नई (985)
- \* 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या है —3892
- \* जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत था —31.16
- \* 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या है —लगभग 37 करोड़
- \* भारत में जिले हैं —640
- \* भारत की कुल नगरीय जनसंख्या (2011) में दसलाखी नगरों का प्रतिशत योगदान है —42.6 प्रतिशत
- \* 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत के प्रथम वर्ग के नगरों का योगदान कुल नगरीय जनसंख्या में है —लगभग 70 प्रतिशत
- \* गत 30 वर्षों में दिल्ली में सर्वाधिक प्रवासी आए हैं —उत्तर प्रदेश से
- \* 1. भारत के उत्तरी शहरों में सामान्यतः असंतुलित लिंगानुपात मिलता है।  
2. पश्चिमी शहरों के केंद्रीकरण के विपरीत पूर्वी शहर बिखरे हुए हैं।  
3. दक्षिण में श्रमशक्ति में महिलाओं की ईसाइयों की लघु संख्या तथा उच्च शिक्षा दर के कारण बृहत्तर भागीदारी है।  
4. पश्चिमी शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों से लघुतर प्रव्रजन होता है। उपर्युक्त कथनों में सत्य कथन है/हैं —1, 2 एवं 4
- \* 2011 की जनगणना के अनुसार, दस लाख जनसंख्या वाले नगरों की सर्वाधिक संख्या है —उत्तर प्रदेश एवं केरल में दोनों में (7-7)
- \* 2011 की जनगणना के अनुसार, दस लाखी प्लस के नगरीय समूह नहीं है —ओडिशा में
- \* भारत की एक-चौथाई से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन दो राज्यों में निवास करती है, वे हैं —महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश
- \* 2011 की जनगणना के अनुसार, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले देश के तीन राज्य हैं —महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु
- \* भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है —गोवा (62.2%) नगरीय आबादी

- \* 2011 की जनगणना के अनुसार, नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम है —**पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र**
- \* भारत के तीन सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम है —**तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात**
- \* भारत के सर्वाधिक नगरीकृत 5 राज्य हैं —**गोवा (62.2%), मिजोरम (52.1%), तमिलनाडु (48.4%), केरल (47.7%) एवं महाराष्ट्र (45.2%)**
- \* भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है —**सिक्किम**
- \* वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है —**हिमाचल प्रदेश में (90%)**
- \* भारत के स्थल-अवरुद्ध राज्यों हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब तथा मध्य प्रदेश में से 2011 की जनगणना के अनुसार, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है —**पंजाब में**
- \* नगरीकरण की दृष्टि से भारत है —**एक मध्यम-निम्न नगरीकृत देश**
- \* कथन (A): भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं।  
कारण (R): ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है।  
—(A) एवं (R) दोनों सही हैं एवं (R), (A) की सही व्याख्या है।
- \* जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है —**विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण**
- \* 2011 के जनगणना के अनुसार, भारत में दसलाखी नगरों की संख्या है —**53**
- \* 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में 53 दसलाखी जनसंख्या वाले नगर हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश में हैं —**7**
- \* भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, देश के मिलियन (दसलाखीय) नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर है —**कोटा**
- \* भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय युगों में दर्शित हुई —**मुंबई एवं दिल्ली**
- \* उत्तर प्रदेश के दसलाखी नगरों का उनकी जनसंख्या आकार के आरोही क्रम निम्न हैं —**इलाहाबाद > लखनऊ > आगरा > मेरठ**
- \* 2011 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या की दृष्टि से उ.प्र. के मुरादाबाद, इलाहाबाद, गाज़ियाबाद, लखनऊ जनपदों का सही अवरोही क्रम है —**इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, लखनऊ**
- \* नगरीय अवस्थापना में पेयजल, आवासन, स्वच्छता तथा परिवहन में से एक सम्मिलित नहीं है —**आवासन**
- \* भारत की जनगणना द्वारा लघु नगरों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं —**वर्ग IV, V और VI**
- \* 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु है —**15 वर्ष**
- \* जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, दिल्ली तथा लक्षद्वीप नगरीकरण के स्तर से सही अवरोही क्रम है —**दिल्ली (97.5%) > चंडीगढ़ (97.3 %) > लक्षद्वीप (78.1%) > दमन एवं दीव (75.2%)**
- \* दादरा तथा नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी में से 2011 की जनगणना के अनुसार, ग्रामों की संख्या न्यूनतम है —**दमन एवं दीव में**
- \* भारत की नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर उच्चतम थी —**1971-81 दशक में**
- \* A. भारत में उत्तर प्रदेश को सबसे लंबे सड़क मार्ग के लिए नहीं जाना जाता है।  
B. माल के आयात के लिए भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय की स्वीकृति देता है।  
C. नगरीकरण का अभिलक्षण है, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में लोगों का प्रवासन।  
D. इंडस परियोजना भारत सरकार के श्रम विभाग तथा कनाडा की संयुक्त परियोजना थी।  
उपर्युक्त कथनों में सत्य कथन हैं —**केवल A, B एवं C**
- \* नगरीय गलियारा संबंधित है —**नगरीय क्रियाकलापों को विस्तार देने से**
- \* नगरीकरण का कारण है —**ग्रामीण-नगरीय असंतुलन, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों की कमी, कृषि-भूमि की न बढ़ सकने वाली प्रकृति तथा नगरों की चुंबकीय विशेषताएं**
- \* 1. ग्रामीण से नगरी क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर  
2. शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या  
3. औद्योगीकरण की ऊंची दर  
4. ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर  
उपर्युक्त कथनों में नगरीकरण के कारणों के संबंध में सत्य कथन हैं/हैं —**कथन 1, 2 तथा 3 सही हैं**

- \* कथन (A): भारत में नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण की वृद्धि के साथ अपराधों में वृद्धि हुई है।  
कारण (R): औद्योगिक-नगरीय अर्थव्यवस्था परिवार एवं सांस्कृतिक अव्यवस्था का कारण है।

—(A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा  
(R), (A) की सही व्याख्या है।

- \* बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है  
—मेट्रोपोलिटन नगरों की मलिन-बस्ती जनसंख्या में वृद्धि, बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण तथा नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में तेजी से गिरावट
- \* मलिन बस्तियों में रहने वालों का जनसंख्या प्रतिशत अधिकतम है  
—मुंबई में
- \* वर्ष 2011 की जनगणनानुसार, सर्वाधिक स्लम प्रतिवेदित नगरों की संख्या की दृष्टि से शीर्ष पांच राज्य/के.शा.प्र. का अवरोही क्रम है  
—तमिलनाडु (507), मध्य प्रदेश (303), उत्तर प्रदेश (293), कर्नाटक (206) एवं महाराष्ट्र (189)
- \* शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजनाएं हैं  
—स्वच्छ भारत मिशन, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना तथा स्मार्ट सिटी योजना
- \* राष्ट्रीय नगरीय पुनर्नवीनीकरण मिशन जोड़ा गया था  
—जवाहरलाल नेहरू के नाम से
- \* जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के साथ संबद्ध नहीं है  
—शहरी विद्युतीकरण
- \* (a) इसे 2005 में प्रारंभ किया गया।  
(b) यह एक 10 वर्षीय कार्यक्रम था।  
(c) यह भारतीय शहरों में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए था।  
(d) यह समावेशी विकास को बढ़ाने के लिए था।  
उपर्युक्त कथनों में से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवीनीकरण मिशन के संबंध में सही नहीं है  
—यह एक 10 वर्षीय कार्यक्रम था
- \* जे.एन.एन.यू.आर.एम. का संबंध था  
—शहरी अधोसंरचना सुधार करने से
- \* स्मार्ट सिटीज मिशन में जल तथा मलजल (सीवरेज) का वित्तपोषण जिस राजस्व से होगा, वह है  
—संपत्ति कर

## विश्व : जनसंख्या एवं नगरीकरण

- \* 'लोक-नगरीय सातत्य' के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया, जो अध्ययन किए गए  
—मेक्सिको में
- \* रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को विशेषीकृत (Characterized by) किया जाता है  
—वृहद् परंपरा के विकास से
- \* विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है, जब विश्व की जनसंख्या अनुमानतः पांच अरब हो गई थी। वह दिन था  
—11 जुलाई, 1987
- \* विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि है  
—11 जुलाई
- \* विश्व की 50% जनसंख्या संकेंद्रित है  
—20° N तथा 40° N अक्षांशों के बीच
- \* विश्व में लिंग अनुपात घटने का डर है  
—लिंग निर्धारण के परीक्षण बढ़ने से
- \* 'नया जनसंख्या बम' का तात्पर्य है  
—तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या
- \* जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का  
—17.5 प्रतिशत है
- \* संयुक्त राष्ट्र आवास वैश्विक मानव बस्ती रिपोर्ट (यूएन-हैबिटेट्स ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट) 2009 के अनुसार, विगत तीन दशकों में शहरीकरण की सबसे तीव्र वृद्धि दर रही है  
—एशिया क्षेत्र में
- \* विश्व के नगरों की स्थिति पर यू.एन. हैबिटेट्स रिपोर्ट के अनुसार, उत्पादकता, अनुकूलतम जनसंख्या, जीवन की गुणवत्ता तथा समता में से एक नगरों की समृद्धि निर्धारित करने का आधार नहीं है  
—अनुकूलतम जनसंख्या
- \* अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है  
—नाइजीरिया
- \* दक्षिण एशिया के देशों प्रतिशत नगरीकरण का बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान तथा श्रीलंका अवरोही क्रम है  
—पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश तथा श्रीलंका
- \* विश्व के सर्वाधिक पांच जनसंख्या वाले देशों का क्रम है  
—चीन > भारत > अमेरिका > इंडोनेशिया > ब्राजील

- \* दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है —**अर्जेंटीना**
- \* सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है —**ऑस्ट्रेलिया** —**लगभग 19.7 करोड़ है**
- \* जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है, वह है —**अफ्रीका**
- \* दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश है —**इक्वेडोर**
- \* एक अनुमान के अनुसार, विश्व की 70 प्रतिशत आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी, वह है —**वर्ष 2050**
- \* जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद आते हैं —**संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया**
- \* जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्षों में) सर्वाधिक है —**जापान में**
- \* जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है —**एशिया महाद्वीप में**
- \* 2011 में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था —**उत्तरी अमेरिका**
- \* कनाडा, फिनलैंड, नॉर्वे तथा रूस में से जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है —**कनाडा में**
- \* चीन, भारत, इंडोनेशिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका देशों में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है —**चीन में**
- \* अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत तथा पाकिस्तान देशों में प्रजनन दर उच्चतम है —**अफगानिस्तान में**
- \* दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है —**श्रीलंका**
- \* धर्म के आधार पर विश्व की जनसंख्या अवरोही क्रम है —**ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, तथा बौद्ध**
- \* नील घाटी तथा जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने का प्राथमिक कारण है —**सघन कृषि**
- \* संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है —**सिंगापुर/मकाउ आदि**
- \* दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है —**मालदीव**
- \* विश्व में अधिकतम आयु संभावित है —**जापान में**
- \* दक्षिण एशिया के बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका तथा पाकिस्तान का साक्षरता की स्थिति में घटता क्रम है —**श्रीलंका (91.2%), भारत (73%), पाकिस्तान (54.4%) तथा बांग्लादेश (56.8%)**
- \* कथन (A) : संसार के दो प्रतिशत लोग अपनी मातृभूमि के बाहर निवास करते हैं।  
कारण (R) : ओशीनिया में प्रवासी लोगों की जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है। —**(A) तथा (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।**
- \* पाकिस्तान की जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार) —**लगभग 19.7 करोड़ है**
- \* इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस तथा सिंगापुर देशों में से उच्च जनसंख्या वृद्धि दर है —**सिंगापुर की**
- \* संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह है —**टोकियो-याकोहामा**
- \* कथन (A) : चीन की जनसंख्या वृद्धि नाटकीय ढंग से धीमी पड़ गई है।  
कारण (R) : एक बच्चा प्रति परिवार नीति के कारण उसकी प्रजनन दर में कमी आई है। —**(A) द्वारा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।**
- \* एशिया का सबसे बड़ा नगर है —**शंघाई**
- \* एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है —**कतर**
- \* कथन (A) : भारत की नगरीय जनसंख्या ब्रिटेन की कुल जनसंख्या से अधिक है।  
कारण (R) : ब्रिटेन का नगरीकरण स्तर भारत के नगरीकरण स्तर से उच्चतर है। —**(A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।**
- \* कथन (A) : एशियाई नगर अत्यधिक नगरीकृत हैं।  
कारण (R) : उनकी वृद्धि आर्थिक विकास को लांच गई है। —**(A) एवं (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।**
- \* आज कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिकतम है —**यूएसए में**
- \* संसार में निम्नतम प्रजनन दर है —**पुर्तगाल, बोस्निया तथा माल्डोवा की**
- \* एशिया में मातृ मृत्यु दर (Mortality rate) उच्चतम है —**नेपाल में**
- \* विश्व की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या संरक्षित नहीं है —**सामाजिक सुरक्षा द्वारा**
- \* विश्व की जैविक विविधता का सर्वोत्तम अनुमान मिलता है —**जो लगभग साढ़े चार करोड़ जातियां जीवित हैं, उनमें से कोई 100 प्रतिदिन लुप्त हो जाती हैं और उनमें से अधिकांश तो अज्ञात ही होती हैं, क्योंकि अब तक अधिक से अधिक पंद्रह लाख की ही पहचान हुई है।**

